नि० से० ख़ुरुचेव

१९५९-१९६५ के लिए सोवियत संघ के आर्थिक विकास के लक्ष्यांक

सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की
२१ वीं असाधारण कांग्रेस में पढ़ी गयी रिपोर्ट
(२७ जनवरी, १९५९)

☆

उपसंहार भाषण

(५ फरवरी, १९५९)

विदेशी भाषा प्रकाशन गृह
मास्को १९५९

विषय-सूची

१९५९-१९६५ के लिए सोवियत संघ के आर्थिक विकास के लक्ष्यांक

साथियो,

सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की २१ वीं कांग्रेस १९५९-१९६५ के अन्तर्गत सोवियत संघ के आर्थिक विकास के लक्ष्य के आंकड़ों पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गयी है। हमारी कांग्रेस सोवियत संघ में उत्तरोत्तर कम्यूनिस्ट निर्माण, अर्थ-व्यवस्था, संस्कृति, और जनता के जीवन-स्तर संबंधी कार्यक्रम का अध्ययन करेगी। यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इतिहास साक्षी है कि विशालता और महत्ता के दृष्टिकोण से इसकी बराबरी करनेवाला अब तक कोई कार्यक्रम नहीं। १९५८ के सितंबर में हुए केन्द्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन में यह आवश्यकता अनुभव की गयी कि विषय के अत्यधिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास की सप्तवर्षीय योजना पर वाद-विवाद करने के लिए यह असाधारण कांग्रेस आयोजित की जाये।

पार्टी की २०वीं कांग्रेस को हुए तीन वर्ष बीत गये। इन वर्षों के दौरान में हमारा सोवियत संघ दृढ़ विश्वास के साथ लेनिन के मार्ग पर कम्यूनिज़्म की ओर अग्रसर होता गया, इसने अपनी शक्ति एवं बल की और भी वृद्धि की, तथा विश्व शांति और मैत्री को सुदृढ़ करने के संघर्ष में अपनी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति और प्रतिष्ठा को नये शिखर पर ला बिठाया। २०वीं पार्टी कांग्रेस और केन्द्रीय समिति के बाद के पूर्णाधिवेशनों में किये गये निर्णयों पर अमल करते हुए सोवियत जनों ने

उद्योग, कृषि, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की है। नगरों और गांवों के श्रमिकों का जीवन-स्तर काफ़ी ऊंचा उठा है।

इस अवधि ने सोवियत संघ में कम्यूनिज़्म के निर्माण तथा समस्त अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट एवं कामगार आन्दोलन संबंधी २०वीं पार्टी कांग्रेस के निर्णयों का ऐतिहासिक महत्त्व स्पष्ट कर दिया है। समाजवादी संसार आज पहले से अधिक सबल, अधिक संयुक्त, और अविनाशी है। वह संसार के सर्वांगीण विकास पर निर्णायक प्रभाव डाल रहा है। यह कहने का पर्याप्त कारण है कि समाजवादी देश प्रगति के हर क्षेत्र में अग्रगामी हैं। सोवियत संघ, चीनी जनवादी जनतंत्र और अन्य समाजवादी देशों की अभूतपूर्व सफलताएं इस बात की साक्षी हैं कि अपने जीवन और अपने भाग्य के परम स्वामी श्रमिक जन क्या-क्या सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं।

शांति, लोकतंत्र, प्रगति और मानव के उज्ज्वल भविष्य के पथ को आलोकित करनेवाले मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारों की महान क्रान्तिकारी शक्ति के दर्शन समाजवादी देशों की युगान्तरकारी उपलब्धियों और सिद्धियों में किये जा सकते हैं।

साथियो, हमारी कांग्रेस में भाग लेने के लिए ७० देशों की कम्यूनिस्ट और कामगार पार्टियों के प्रतिनिधि पधारे हैं। मैं कांग्रेस की ओर से, समस्त पार्टी और समस्त सोवियत जनता की ओर से, अपने इन प्रिय अतिथियों, बिरादराना मार्क्सवादी-लेनिनवादी दलों के नेताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं **(देर तक जोर की तालियां)।**

१

सोवियत जनता की महान उपलब्धियां

साथियो, महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति की विजय के शीघ्र बाद ही, लेनिन ने हमारी पार्टी के कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए लिखा था: "समाजवादी पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर होने से पहले हमें वह लक्ष्य अवश्य निश्चित कर लेना है, जहां हमें अन्ततः पहुंचना है, और वह है कम्यूनिस्ट समाज की स्थापना।" (व्ला० इ० लेनिन, ग्रन्थ-संग्रह, चौथा रूसी संस्करण, खंड २७, पृष्ठ १०३)

अपने देश में कम्यूनिज़्म-निर्माण के इस महान लक्ष्य ने सोवियत जनों को महानतर कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित किया है।

देश के उद्योगीकरण और कृषि के समूहीकरण की नीति का पालन करने में, हमारे सोवियत जनों ने पार्टी और इसकी केन्द्रीय समिति के नेतृत्व में, जिसकी अध्यक्षता कई वर्षों तक जो० वि० स्तालिन ने की, महान परिवर्तन कर दिखलाये हैं। सारी कठिनाइयों को पार करते हुए और वर्ग-शत्रुओं एवं उनके एजेंटों – त्रोत्स्कीवादियों, दक्षिणपंथी अवसरवादियों, बुर्जुआ राष्ट्रवादियों आदि – के अवरोधों को छिन्न-भिन्न करते हुए हमारी पार्टी और समस्त सोवियत जनता ने ऐतिहासिक जीतें प्राप्त की हैं और एक नये, समाजवादी समाज की स्थापना की है। अतीत का यह पिछड़ा देश आज महान औद्योगिक व सामूहिक कृषिप्रधान समाजवादी देश बन चुका है। फ़िलहाल, अपने औद्योगिक उत्पादन के दृष्टिकोण से इसे यूरोप में पहला स्थान और संसार में दूसरा स्थान प्राप्त है।

साल-दर-साल हमारी आर्थिक योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होती जा रही हैं। १९१३ की तुलना में, कुल औद्योगिक उत्पादन ३६ गुना बढ़ा है, जबकि उत्पादन-साधनों के उत्पादन में ८३ गुनी और इंजीनियरिंग एवं धातु-उद्योगों के उत्पादन में २४० गुनी वृद्धि हुई है।

१९५८ की योजना राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की सभी शाखाओं में सफलतापूर्वक पूरी की गयी है। पिछले साल, औद्योगिक उत्पादन में १० प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि योजना में ७.६ प्रतिशत की वृद्धि करने का ही लक्ष्य था। सभी संघीय जनतंत्रों और सभी आर्थिक परिषदों ने उत्पादन-योजनाओं को आशातीत सफलता के साथ पूरा किया है। कृषि के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी सफलताएं मिली हैं। समस्त औद्योगिक निर्माण-योजना तथा रिहाइशी मकान निर्माण-योजना की पूर्त्ति में आशातीत सफलता मिली है।

१९५८ में, सोवियत संघ ने लगभग ५५० लाख टन इस्पात, ११३० लाख टन तेल और २३३ अरब किलोवाट-घंटा विद्युत्शक्ति पैदा की। १९१३ के रूस के वार्षिक उत्पादन की तुलना में आज हमारे इस्पात और तेल का मासिक उत्पादन कहीं अधिक है। हर तीसरे दिन इतनी बिजली पैदा की जाती है जितनी क्रान्तिपूर्व रूस में एक साल में पैदा की जाती थी।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में लगायी जानेवाली पूंजी की वृद्धि आर्थिक विकास का सबल प्रमाण है जिसे देखकर हम सब को बहुत प्रसन्नता और संतोष होता है। युद्धोत्तर काल में राज्य द्वारा लगायी गयी कुल पूंजी का जोड़ आज के मूल्य में १६०० अरब रूबल से अधिक है। केवल १९५८ में ही, २३५ अरब रूबल पूंजी लगायी गयी, जो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की कुल अवधियों में लगायी गयी पूंजी से भी अधिक है।

बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने प्राय: यह भविष्यवाणी की है कि सोवियत संघ जब युद्ध के बाद अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण कर लेगा तो अपने आर्थिक विकास को मन्द करने के लिए बाध्य हो जायेगा। लेकिन उनकी भविष्यवाणी पानी के बुलबुलों की तरह फूटकर विलीन हो गयी। सोवियत अर्थ-व्यवस्था द्रुतगति से ही विकास करती जा रही है।

विज्ञान और इंजीनियरिंग संबंधी नवीनतम सिद्धियों के व्यापक प्रयोग से ही विशाल पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन में ऐसी उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकी है। विद्युत्करण और इंजीनियरिंग उद्योग, ख़ासकर कल-यन्त्र और उपकरण बनानेवाले उद्योगों, रेडियो-विद्युत्-उपकरण और विद्युत्-इंजीनियरिंग के विकास से तथा व्यापक यन्त्रीकरण एवं स्वचालन संबंधी नये-यन्त्रों के निर्माण से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सतत प्राविधिक प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। केवल पिछले तीन वर्षों के दौरान में ४,५०० से अधिक नयी क़िस्म के यन्त्रों, मशीनों और उपकरणों की डिज़ाइन बनायी गयी है और उनका प्रयोग भी किया जा रहा है।

प्राविधिक प्रगति और राष्ट्रव्यापी समाजवादी होड़ के आधार पर श्रम-उत्पादिता की भी निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अपेक्षाकृत, काफ़ी छोटे कार्य-दिवस के बावजूद, १९१३ की तुलना में पिछले साल उद्योग में श्रम-उत्पादिता लगभग १० गुनी अधिक थी। १९४० की तुलना में, पिछले साल उद्योग में प्रतिकर्मी श्रम-उत्पादिता २.६ गुनी अधिक थी और निर्माणकार्य में वह २.४ गुनी अधिक थी।

उद्योग और निर्माणकार्य की व्यवस्था का पुनःसंगठन एक बहुत बड़ा कारण था जिसने आर्थिक विकास को बल और गति दी। आर्थिक परिषदों की स्थापना के तुरत बाद ही औद्योगिक व्यवस्था के नये स्वरूप के पर्याप्त लाभ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगे। उत्पादन की व्यवस्था में अधिक दक्षता आ गयी। औद्योगिक उत्पादन की गति बढ़ गयी, उद्योग

की स्थानीय क्षमताओं का और देश के प्राकृतिक स्रोतों का अधिक उपयोग किया गया, कामगारों, टेकनिशियनों और इंजीनियरों ने अधिक पहलक़दमी और सक्रियता दिखायी तथा समाजवादी होड़ पहले से अधिक व्यापक और तीव्र हो उठी। विशेषीकरण और समन्वयन का क्रमिक विकास करने के अच्छे अवसर पैदा किये गये। इस अवधि में, योजना की पूर्ति न कर सकनेवाले उद्यमों की संख्या में एक तिहाई कमी हुई।

आर्थिक परिषदों के गठन के पहले साल में ही उसके पिछले वर्ष की तुलना में औद्योगिक उत्पादन में १७ अरब रूबल की वृद्धि हुई। १९५७ और १९५८ में, श्रम-उत्पादिता में योजना के लक्ष्य से अधिक वृद्धि और उत्पादन-मूल्यों में योजना के लक्ष्य से अधिक कमी हुई। १९५८ में, उत्पादन-मूल्यों में योजना के लक्ष्य से अधिक कमी होने के कारण १० अरब रूबल से अधिक की बचत हुई। लेकिन हमें यह भूलना नहीं है कि अभी भी ऐसे कारख़ाने हैं, जो पिछड़े हुए हैं और अपनी योजनाएं पूरी नहीं कर पाते हैं। अतः, उद्योग की व्यवस्था को सुधारने, उद्योग-कार्यों की ख़ामियां ज़ाहिर कर उन्हें दूर करने तथा उद्योग की क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के लिए हमें अथक परिश्रम करना है।

हमारे देश ने समाजवादी कृषि में उल्लेखनीय प्रगति की है। सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति का जो पूर्णाधिवेशन पिछले दिसम्बर में हुआ, उसमें पिछले पांच वर्षों की कृषि संबंधी सफलताओं पर प्रकाश डाला गया, त्रुटियों की आलोचना की गयी और कृषि-उत्पादन की क्रमिक वृद्धि के आधारभूत कार्यों की रूप-रेखा निश्चित की गयी। दूसरे शब्दों में, इस पूर्णाधिवेशन ने जनता के सामने पार्टी की राजनीतिक रिपोर्ट पेश की कि पिछले पांच वर्षों में कृषि-विकास संबंधी योजनाएं किस तरह पूरी की गयी हैं।

यह याद रहे कि अतीत में जिस ढंग से कृषि की व्यवस्था की जाती थी, उसमें बड़ी ख़ामियां और ग़लतियां थीं। कई वर्षों तक बहुत-

से कोलख़ोज़ (सामूहिक फ़ार्म) आर्थिक रूप से कमज़ोर रहे, कृषि-उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई और उसका स्तर खाद्यान्न एवं खेती-बारी के कच्चे मालों संबंधी देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा न कर सका। उस समय हमारी कृषि की स्थिति बड़ी नाज़ुक थी और उसका परिणाम इतना ख़तरनाक होता कि कम्यूनिज़्म की ओर सोवियत संघ की प्रगति अवरुद्ध हो सकती थी। १९५३ के सितम्बर के पूर्णाधिवेशन में, केन्द्रीय समिति के बाद के पूर्णाधिवेशनों में और २० वीं कांग्रेस में, हमारी पार्टी ने कृषि-व्यवस्था की त्रुटियों की कटु आलोचना की, कोलख़ोज़ों और सोवख़ोज़ों (राजकीय फ़ार्मों) के विकास में जो अड़चनें थीं, उन्हें उखाड़ फेंका और कृषि-उत्पादन में शीघ्र वृद्धि के लिए कार्यक्रम बनाया।

पार्टी, कामगार वर्ग, सामूहिक किसान वर्ग, और सोवियत बुद्धिजीवियों, सबने पिछड़ी हुई कृषि को आगे बढ़ाने और उसके उत्तरोत्तर विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास किये। पार्टी ने जनता में व्यापक संगठनात्मक और राजनीतिक कार्य तीव्र गति से शुरू किया। समाजवादी कृषि के विकास संबंधी मुख्य आर्थिक समस्याओं का समाधान किया गया और कृषि-उत्पादन बढ़ाने में किसानों की भौतिक रुचि जगाने का सिद्धांत पुनःस्थापित किया गया। कोलख़ोज़ों और सोवख़ोज़ों को विशेषज्ञों, यन्त्र-चालकों और प्रबन्धकों से संपन्न किया गया। लाखों ट्रैक्टर, कम्बाइन, मशीनें और तरह-तरह के औज़ार ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे गये। पिछले पांच वर्षों में, कृषि पर राज्य ने १०० अरब रूबल की पूंजी लगायी।

केन्द्रीय समिति के आह्वान पर सोवियत जनों ने करोड़ों हेक्टेयर नयी ज़मीन पर खेती-बारी शुरू की। यह बड़ी बहादुरी का काम था। दिसम्बर में केन्द्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन में यह बताया गया कि पिछले पांच वर्षों में जोती गयी अछूती ज़मीन की पैदावार से देश को

अन्नों पूड अतिरिक्त अनाज मिला। इस मद में लगायी गयी सारी पूंजी लौट तो आयी ही, साथ ही केन्द्रीय सांख्यिकी विभाग और वित्तमंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार १८ अरब रूबल से अधिक की आमदनी भी हुई।

पार्टी द्वारा निर्मित और सोवियत जनों द्वारा अनुमोदित एवं समर्थित योजनाओं की सफल कार्यान्विति से ही पिछड़ी हुई कृषि को आगे बढ़ाना, कोलखोज़ों और सोवखोज़ों की आर्थिक स्थिति को अल्पावधि में ही सुदृढ़ करना, मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों का पुनर्गठन करना और कृषि-उत्पादन की ख़रीद के तरीक़ों और अवस्थाओं में सुधार करना संभव हो सका।

दिसम्बर में हुए केन्द्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन में यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी द्वारा निर्मित और कार्यान्वित योजना के फलस्वरूप कृषि में जो द्रुत विकास हुआ है वह वस्तुतः क्रान्तिकारी महत्त्व का है और उसका उल्लेखनीय परिणाम निकला है। १९५८ में राज्य ने साढ़े तीन अरब पूड अर्थात् १९५३ की तुलना में १ अरब ६० करोड़ पूड अधिक अनाज ख़रीदा। पिछले पांच वर्षों के अंदर, पूर्ववर्त्ती पंचवर्षीय अवधि की तुलना में अनाज के उत्पादन में ३९ प्रतिशत की मध्यक वार्षिक वृद्धि हुई है। साथियो, यह एक बहुत बड़ी सिद्धि है।

अन्य फ़सलों, ख़ासकर मीठे चुक़ंदर और कपास के उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। १९५८ में ५४० लाख टन चुक़ंदर पैदा हुआ जो १९५३ की तुलना में सौ प्रतिशत अधिक है। पिछले साल, कपास पैदा करनेवालों ने राज्य के हाथ ४४ लाख टन कपास बेची। हमारे देश में पहले इतनी अधिक कपास कभी पैदा नहीं की गयी थी।

कोलखोज़ों और सोवखोज़ों को पशु-पालन में भी विशेष सफलताएं प्राप्त हुई हैं। आप सब को मालूम है कि सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के जनवरी, १९५५ वाले पूर्णाधिवेशन में १९६०

तक कोल्खोज़ों में फ़ी गाय दूध का उत्पादन १७०० किलोग्राम करने और दूध की ख़रीद में ८० प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो १९५७ में, अर्थात् छ: साल के बदले तीन साल में ही पूरा कर लिया गया। १९५८ में, पशु-द्रव्यों की ख़रीद में १९५३ की तुलना में निम्न वृद्धियां हुई है: दूध – १०० प्रतिशत से अधिक; मांस – ५६ प्रतिशत; और ऊन – ६० प्रतिशत। सामाजिक उत्पादन के विकास और ख़रीद की क़ीमत के तरीक़े के समायोजन से कोलखोज़ों की आय में काफ़ी वृद्धि हुई है।

आज सोवियत संघ सशक्त, सर्वांगीण उद्योग, यातायात तथा उत्तम यन्त्रचालित समाजवादी कृषि से संपन्न है। हमारी सामाजिक सम्पत्ति और राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। सोवियत सत्ता की स्थापना के बाद राष्ट्रीय आय में प्रतिव्यक्ति १५ गुनी वृद्धि हुई है।

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के सामान्य उत्थान और श्रम-उत्पादिता के विकास के आधार पर सोवियत जनता की भौतिक सुख-सुविधाओं में तीव्र वृद्धि होती जा रही है। १९५८ में कारख़ाना-कामगारों और कार्यालय-कर्मचारियों की वास्तविक आय में १९४० की तुलना में लगभग दुगुनी और काम करनेवाले प्रति किसान की वास्तविक आय में १०० प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। जनता की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति पर लगायी जानेवाली पूंजी में हर साल वृद्धि होती जा रही है। हाल के वर्षों में, ख़ासकर पार्टी की २० वीं कांग्रेस के बाद, पार्टी और सरकार ने सोवियत जनता की भौतिक सुख-सुविधा के लिए जो महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं, वे सर्वविदित हैं।

साथियो, हमारे देश में सभी राष्ट्रों और जातियों की संस्कृतियों का अपूर्व विकास हो रहा है। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में, कालेज-शिक्षा या विशिष्ट माध्यमिक स्कूल-शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों की संख्या लगभग ७५ लाख है। यह संख्या १९१३ की तुलना में ३९ गुनी अधिक है।

सोवियत संघ में उच्च शिक्षा वाली संस्थाओं में छात्रों की संख्या संयुक्त रूप से ब्रिटेन, फ़ान्स, पश्चिमी जर्मनी और इटली की तुलना में लगभग चौगुनी अधिक है। अमेरिका के उच्च शिक्षालयों की तुलना में हमारे उच्च शिक्षालय लगभग तिगुने अधिक इंजीनियरों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। सोवियत कला और साहित्य कम्यूनिस्ट ढंग पर लोगों को शिक्षित करने में महत्त्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है।

सोवियत संघ में विज्ञान और इंजीनियरिंग के रचनात्मक विकास के लिए, आविष्कारों और अनुसंधानों के लिए, असीम संभावनाएं उत्पन्न हो चुकी हैं। १९५० से १९५८ तक राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में लगभग १ करोड़ ऐसे आविष्कार और सुधार लागू किये गये हैं जिनसे इंजीनियरिंग का विकास करने, उत्पादन-मूल्यों में कमी करने और लाखों व्यक्तियों की श्रम-स्थितियों का सुधार करने में मदद मिली है। पिछले तीन वर्षों में, इन सुधारों से लगभग २४ अरब रूबल की बचत हुई है।

सोवियत वैज्ञानिकों, रूपांककारों और इंजीनियरों ने देश को अपनी बहुमूल्य सेवाएं अर्पित की हैं और वे कम्यूनिज़्म-निर्माण के राष्ट्रव्यापी कार्य में हाथ बंटा रहे हैं। नाभिकीय भौतिकी और अणुशक्ति, जेट विमान-चालन और रॉकेट इंजीनियरिंग में सोवियत वैज्ञानिकों की सफलताओं से समस्त संसार परिचित हो चुका है। शांतिपूर्ण कार्यों के लिए अणुशक्ति का उपयोग करने की समस्या के समाधान में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं। सोवियत संघ ने अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों का क्रमिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है।

१९५७ में संसार का प्रथम कृत्रिम उपग्रह सफलतापूर्वक चलाकर हमारे वैज्ञानिकों और जनता ने अपनी महान विजय का परिचय देते हुए यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया कि सोवियत संघ का औद्योगिक और प्राविधिक स्तर कितना ऊंचा उठ गया है। समस्त संसार ने उत्साह के साथ क़बूल किया कि प्रकृति के ऊपर मानव की विजय के इतिहास

में एक नये युग का प्रारंभ हुआ है। हां, एक ऐसे युग का जो अन्तरिक्ष पर मानव के अधिकार की याद दिलाता रहेगा। इस विजय की सबसे बड़ी महत्ता यह थी कि इसने समस्त संसार को समाजवादी प्रणाली की प्रचंड रचनात्मक शक्ति से परिचित करा दिया।

नव वर्ष के, अर्थात् सप्तवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के प्रारंभ में ही सोवियत वैज्ञानिकों, रूपांककारों, इंजीनियरों और कामगारों ने सफलतापूर्वक चन्द्रमा की ओर बहुस्तरीय कॉस्मिक रॉकेट छोड़कर विश्वव्यापी महत्त्व का कार्य किया है। सोवियत जन अपनी मातृभूमि के प्रति देशभक्तिपूर्ण गर्व से छलछला रहे हैं। हमारा सोवियत संघ आधुनिक वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति का नेतृत्व करता जा रहा है और भविष्य का मार्ग आलोकित करता जा रहा है। इस महान वैज्ञानिक सिद्धि से समस्त प्रगतिशील मानवजाति हमारी खुशियों में हिस्सा बंटा रही है। इस उजागर सत्य को देखकर समाजवाद के दुश्मन भी अन्तरिक्ष-युग की इस महान सिद्धि को, सोवियत संघ की इस नयी विजय को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गये हैं **(ज़ोर की तालियां)**।

सोवियत संघ द्वारा उड़ाये गये प्रथम कृत्रिम उपग्रह और हाल में छोड़ा गया प्रथम सोवियत कॉस्मिक रॉकेट, जो सौर मंडल का पहला कृत्रिम ग्रह बना, वैज्ञानिक जानकारी के विकास में एक नये युग की सृष्टि करते हैं। साम्यवादी विकास के युग में यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है **(तालियां)**।

हम सोवियत जन ऐसी सफलताओं पर आनंदविभोर हुए बिना नहीं रह सकते। **संसार का प्रथम कृत्रिम उपग्रह सोवियत स्पूत्निक था। सौर मंडल का प्रथम कृत्रिम ग्रह सोवियत संघ में ही बना (देर तक ज़ोर की तालियां)**। सौर मंडल के असीम विस्तार में यह रॉकेट गर्व के साथ उड़ान भर रहा है और उसपर सोवियत संघ का राष्ट्रचिन्ह तथा ये शब्द अंकित हैं—"सोवियत संघ। जनवरी, १९५९।" **(तालियां)**।

साथियो, हमारी पार्टी और समस्त सोवियत जनता को इस बात का बहुत गर्व है कि अनुसंधान-संस्थानों, रूपांकन-कार्यालयों, कारखानों और परीक्षण-संस्थाओं के कर्मियों द्वारा चांद की ओर छोड़ा गया प्रथम बहुस्तरीय कॉस्मिक रॉकेट सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की २१वीं कांग्रेस को समर्पित किया गया था **(देर तक तालियां)**। मैं आपकी ओर से, पार्टी की ओर से और समस्त सोवियत जनता की ओर से, कांग्रेस के इस उच्च मंच पर से उस नये कॉस्मिक रॉकेट के निर्माताओं को उनकी महान विजय पर बधाइयां देता हूं और उनके प्रति सराहना और हार्दिक कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करता हूं और यह हार्दिक कामना प्रगट करता हूं कि वे स्वस्थ रहें और अपनी उत्तरोत्तर रचनात्मक सिद्धियों से सोवियत संघ के गौरव की, और कम्यूनिज़्म की विजय की पताका फहराते रहें **(देर तक ज़ोर की तालियां)**।

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था और संस्कृति का विकास करने में, श्रमिक जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में हमें काफ़ी सफलताएं मिली हैं। ये सफलताएं इसलिए मिली हैं कि कम्यूनिज़्म का निर्माण ही समस्त जनता का, राजनीतिक चेतना से प्रबुद्ध हर सोवियत जन का पुनीत लक्ष्य बन गया है। कम्यूनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने हाल में और भी आर्थिक विकास के लिए जो उपाय किये हैं, उनसे जनसाधारण के राजनीतिक और श्रम-प्रयास को बल मिला है और कामगार तथा किसान जनता की एकता और भी सुदृढ़ हुई है जो सोवियत सत्ता की ठोस नींव है। उन उपायों ने सोवियत संघ की मुक्त, समान और स्वतंत्र जातियों में परस्पर भाईचारे का संबंध और भी मज़बूत किया है।

सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ, जो श्रमिक जनता का बहुराष्ट्रीय राज्य है, समाजवादी राष्ट्रों का स्वैच्छिक संघ है, साल-दर-साल ज्यादा ताक़तवर होता जा रहा है। लेनिन की राष्ट्रीय नीति के पालन और पारस्परिक भ्रातृत्व-सहयोग का फल यह हुआ है कि अतीत

में आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए जातीय जनतन्त्र आज बड़े बड़े आधुनिक उद्योगों, बड़े पैमाने पर यन्त्रसज्जित कृषि, अनेक शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थाओं तथा असंख्य उच्चशिक्षाप्राप्त कर्मचारियों से संपन्न हो चुके हैं। हाल में संघीय जनतन्त्रों के अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि की गयी है। इनसे स्पष्ट है कि सोवियत लोकतन्त्र का और विकास हुआ है तथा अब और भी द्रुतगति से संघीय जनतन्त्र अपनी अर्थ-व्यवस्था और संस्कृति की उन्नति कर सकते हैं।

साथियो, कम्यूनिस्ट पार्टी आज पहले से अधिक संयुक्त होकर और रचनात्मक उत्साह से प्रेरित होकर अपनी २१वीं कांग्रेस मना रही है। सोवियत संघ की आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति आज जितनी दृढ़ और मजबूत है उतनी पहले कभी नहीं रही है। रचनात्मक श्रम में लवलीन हमारे देशवासी विश्वशांति क़ायम रखने और समस्त संसार के लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में उन्हें शांतिप्रिय लोगों का हार्दिक समर्थन प्राप्त है। समाजवाद का अजेय दुर्ग, सोवियत संघ, जो आक्रमणकारी शक्तियों को पराभूत करने के सारे साधनों से संपन्न है, विश्वशांति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का सबल संरक्षक है।

कम्यूनिज़्म के निर्माण में और लोक-शांति के लिए संघर्ष में हमें महान सफलताएं मिली हैं। लेकिन हमें व्ला० इ० लेनिन के ये शब्द न भूलने हैं कि जितनी सिद्धियां हम प्राप्त कर चुके हैं, उतनी से ही हमें संतुष्ट होकर नहीं रह जाना है, बल्कि हमें नयी सफलताओं और नयी विजयों की ओर अग्रसर होना है।

२

सोवियत संघ में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की सप्तवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य

साथियो, पार्टी के नेतृत्व में सोवियत जनता उत्थान की उस चरम अवस्था को पहुंच चुकी है और उसने आर्थिक, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के समस्त क्षेत्रों में इतने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर लिये हैं कि अब हमारे देश को विकास के एक नवीन एवं महत्त्वपूर्ण काल में पदार्पण करने का अवसर मिला है। **यह काल कम्यूनिस्ट समाज के व्यापक निर्माण का काल है।**

इस काल के प्रमुख लक्ष्य हैं—साम्यवाद के भौतिक और प्राविधिक आधार की स्थापना करना, सोवियत संघ की आर्थिक और प्रतिरक्षा-शक्ति को और अधिक सुदृढ़ बनाना और जनता की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की और भी अधिक पूर्त्ति करना। इस काल में हमें प्रमुख पूंजीवादी देशों के प्रतिव्यक्ति-उत्पादन तक न केवल पहुंचना ही है अपितु उससे आगे भी बढ़ना है। और यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक कार्य है। इन लक्ष्यों की पूर्त्ति के लिए जितनी कालावधि की आवश्यकता होगी वह सप्तवर्षीय योजना की सीमाओं से आगे है।

आगामी १५ वर्षों में सोवियत संघ की उत्पादक शक्तियों का जिन जिन प्रमुख दिशाओं में विकास होगा उनकी एक रूपरेखा नवम्बर १९५७ में सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के जयन्ती-अधिवेशन में तैयार की

गयी थी। सप्तवर्षीय योजना इस दीर्घकालीन आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

आगामी सात वर्षों के प्रमुख लक्ष्य हैं क्या?

आर्थिक क्षेत्र में—उत्पादक शक्तियों का चतुर्दिक विकास और, भारी उद्योगों की वृद्धि को प्रमुखता दिये जाने के आधार पर, अर्थ-व्यवस्था की समस्त शाखाओं में एक विशिष्ट उत्पादन-स्तर की प्राप्ति। इस उत्पादन-स्तर से कम्यूनिज़्म के लिए भौतिक और प्राविधिक आधार की स्थापना करने और पूंजीवादी देशों के साथ शान्तिपूर्ण आर्थिक प्रतियोगिता में सोवियत संघ की विजय सुनिश्चित बनाने के लिए हम एक निर्णायक क़दम उठा सकेंगे। देश की आर्थिक क्षमता में वृद्धि, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में और अधिक प्राविधिक प्रगति और सामाजिक श्रम-उत्पादिता में निरन्तर वृद्धि से रहन-सहन का स्तर काफ़ी ऊंचा होगा।

राजनीतिक क्षेत्र में—सोवियत समाजवादी व्यवस्था का और भी अधिक दृढ़ीकरण, सोवियत जनता की एकता और दृढ़ता, सोवियत जनतंत्र का विकास, साम्यवाद के निर्माण में आम जनता की क्रियाशीलता और पहलक़दमी, सार्वजनिक संस्थाओं को राज्य के मामले निपटाने के अधिकारों का विस्तार, पार्टी और समाजवादी राज्य के व्यवस्थात्मक और शैक्षणिक कार्यों में वृद्धि तथा किसानों और कामगारों की एकता और देश की जनता में पारस्परिक मित्रता की भावना को सुदृढ़ बनाना।

विचार-धारा के क्षेत्र में—पार्टी के सैद्धान्तिक और शैक्षणिक कार्यों को आगे बढ़ाना, कम्यूनिस्ट जागरूकता के स्तर में वृद्धि करना, विशेष रूप से युवकों के बीच, श्रम-कार्यों में साम्यवादी भावना और सोवियत देशभक्ति व अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना में विकास करना, जनता के मस्तिष्क से पूंजीवाद के अवशेषों का उन्मूलन करना और बूर्जुआ विचार-धारा से मोर्चा लेना।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में—ऐसी विदेश-नीति का निरन्तर अनुसरण करना, जिसका उद्देश्य भिन्न भिन्न सामाजिक प्रणालियों वाले

देशों के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के, लेनिन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना और उसे मज़बूत करना। 'शीत युद्ध' को समाप्त करना और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी करना भी बहुत आवश्यक है। विश्व समाजवादी प्रणाली और भ्रातृ-जनसमुदाय को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने के सभी प्रयास किये जाने चाहिए।

आगामी सात वर्षों की मूल समस्या यह है कि पूंजीवाद के साथ समाजवाद की शान्तिपूर्ण आर्थिक प्रतियोगिता में कम से कम समय में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने का प्रयास किया जाय।

आर्थिक विकास का कार्यक्रम इस बात का एक और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिछले वर्षों की ही भांति, आगामी सात वर्षों में भी सोवियत अर्थ-व्यवस्था शान्तिपूर्ण पद्धति पर ही पनपेगी। हम निरन्तर लेनिन की शान्ति-नीति का ही अनुकरण करते रहेंगे।

* * *

साथियो, हमारी पार्टी की महान जीवन्त शक्ति और अजेयता का मूल कारण है आम जनता से उसका अटूट संबंध। पिछले वर्षों में पार्टी ने कम्यूनिस्ट निर्माण की समस्त बड़ी बड़ी समस्याओं को राष्ट्रव्यापी विचार-विनिमय के लिए, एक क्रमबद्ध तरीक़े पर, जनता के समक्ष रखा है।

कांग्रेस से पहले, १९५९-१९६५ के राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लक्ष्य के आंकड़ों पर व्यापक रूप से विचार-विनिमय केन्द्रीय समिति के नवम्बर के पूर्णाधिवेशन के बाद से ही आरम्भ हो गया था। फ़ैक्ट्रियों, निर्माण-स्थलों, कोलख़ोज़ों, सोवख़ोज़ों, वैज्ञानिक और शिक्षा-संस्थाओं, सेना तथा नौसेना और अन्य स्थापनों में इन लक्ष्यों पर विचार करने के लिए ९,६८,००० सभाएं हुईं थीं जिनमें ७ करोड़

से भी अधिक लोगों ने भाग लिया था। इन सभाओं में ४६,७२,००० व्यक्तियों ने भाषण दिये थे, जिनमें रिपोर्ट की थीसिस की आलोचनाओं के साथ ही साथ उसमें परिवर्द्धन और सुझाव भी प्रस्तुत किये गये थे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय और स्थानीय पार्टी और सोवियतों की संस्थाओं, समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के सम्पादकों तथा रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण-केन्द्रों में ६,५०,००० से भी अधिक पत्र और लेख प्राप्त हुए थे जिनमें लक्ष्य के आंकड़ों के भिन्न भिन्न अंगों की आलोचना की गयी थी और सुझाव दिये गये थे। इनमें से ३,००,००० से अधिक पत्र प्रकाशित किये गये थे।

प्रादेशिक और क्षेत्रीय पार्टी कान्फ्रेंसों और संघीय जनतंत्रों की कम्यूनिस्ट पार्टियों की कांग्रेसों में लक्ष्य के आंकड़ों पर बड़े सक्रिय और व्यवहारिक ढंग से बहस हुई थी।

श्रमिक जनता की इन सभाओं, पार्टी कान्फ्रेंसों और कांग्रेसों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्टी ने, बल्कि समस्त सोवियत जनता ने, लक्ष्य के आंकड़ों पर अपनी सर्वसम्मत स्वीकृति दी है और कम्यूनिस्ट निर्माण के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में सप्तवर्षीय योजना का हृदय से स्वागत किया है (**जोर की तालियां**)। जनता ने अपना यह दृढ़ निश्चय प्रकट कर दिया है कि वह सप्तवर्षीय योजना के लक्ष्यों को न सिर्फ़ पूरा ही करेगी बल्कि उससे भी आगे बढ़ेगी। एक अच्छी सोवियत परम्परा के अनुसार, पार्टी कांग्रेस की तैयारियों और लक्ष्य के आंकड़ों के राष्ट्रव्यापी विचार-विनिमय के साथ साथ बड़े पैमाने पर समाजवादी प्रतियोगिता और निर्दिष्ट समय से पहले राज्य-योजनाओं और निश्चित कार्यों की पूर्त्ति हुई।

विचार-विनिमय के समय जो ढेरों सुझाव दिये गये थे उन सबका अपनी रिपोर्ट में सविस्तर विश्लेषण करना मेरे लिए सम्भव नहीं। किन्तु उनके मूल में सोवियत जनता का एक ही उद्देश्य निहित है—हमारे देश

की अर्थ-व्यवस्था और संस्कृति निरन्तर विकसित होती रहे और जनता के रहन-सहन का स्तर बढ़ता जाय (**तालियां**)।

बहुत सुझावों से ऐसे ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं जिनका संबंध हमारे देश के आर्थिक विकास से है – उत्पादक शक्तियों का वितरण, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की पृथक् पृथक् शाखाओं में पूंजी लगाने के सर्वोत्तम क्षेत्र, आदि, आदि। उनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण सुझावों पर पार्टी कान्फ्रेंसों और कांग्रेसों में विचार-विनिमय हुआ था और यह निश्चय किया गया था कि उनपर पूरा पूरा ध्यान दिया जाय। इनपर जनतंत्रों और क्षेत्रों की राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं के सिलसिले में विचार किया जा रहा है। कुछ सुझाव देश की सप्तवर्षीय योजना में भी शामिल किये जायेंगे।

विचार-विनिमय के समय जो सुझाव रखे गये थे मैं उनमें से कुछ की चर्चा करूंगा।

कुज़नेत्स्क के लोहे और इस्पात के कारखाने के स्थायी उत्पादन-सम्मेलन ने आगामी सात वर्षों की अपनी सम्भावनाओं का विश्लेषण करते समय कई ऐसे ऐसे ज़रूरी सुझाव दिये जिनका संबंध उनके कारखाने के विकास की योजना के मसविदे से था।

सप्तवर्षीय लक्ष्यों में कारखाने के इस्पात-उत्पादन में १७ प्रतिशत वृद्धि की व्यवस्था थी जबकि वेल्लित इस्पात के विस्तार संबंधी योजना के मसविदे में यह दिखाया गया था कि इस्पात का उत्पादन लगभग ४२ प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि योजना के मसविदे में इस्पात की वृद्धि और वेल्लित इस्पात-उत्पादन की क्षमता में परस्पर कोई मेल न था।

उत्पादन-सम्मेलन ने यह भी सुझाव दिया था कि योजना में कुज़नेत्स्क कारखाने में एक [illegible] वर्कशाप के निर्माण की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार वेल्लित इस्पात के उत्पादन का पूर्णोपयोग हो सकेगा और प्रति वर्ष लाखों टन अतिरिक्त इस्पात और

वेल्लित इस्पात का उत्पादन भी किया जा सकेगा। समान क्षमता के खुली भट्ठी के वर्कशाप की तुलना में एक तो धातु-परिवर्तन वर्कशाप के निर्माण पर एक-तिहाई लागत आयेगी और दूसरे समय भी कम लगेगा।

इस प्रस्ताव का एक विशेष राष्ट्रीय आर्थिक महत्त्व है। सोवियत संघ की राज्य-संयोजन-समिति ने इसका विवेचन किया था और स्वीकार किया था। कुज़नेत्स्क लोहे और इस्पात का कारख़ाना एक बड़ा आक्सीजन स्टेशन और एक धातु-परिवर्तन वर्कशाप बनायेगा जिसकी इस्पात-उत्पादन-क्षमता प्रतिवर्ष १२,००,००० टन की होगी। परिणाम यह होगा कि इस्पात का उत्पादन, मूलतः संयोजित १७ प्रतिशत की जगह, ४८ प्रतिशत बढ़ जायेगा।

क्रास्नोयार्स्क आर्थिक परिषद के सभापति साथी लोमाको, क्रास्नोयार्स्क प्रादेशिक पार्टी समिति के सेक्रेटरी साथी कोकारेव और उत्पादक शक्तियों के अध्ययनार्थ संघटित सोवियत संघ की विज्ञान-अकादमी की समिति के क्रास्नोयार्स्क खोजी दल के अध्यक्ष साथी ज़ुबकोव ने यह प्रस्ताव रखा था कि आगामी सात वर्षों में समृद्ध अंगारा-पित लौह-खनिज क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। इस बेसिन के लौह-खनिज के ज़ख़ीरे खुली खुदाई के लिए बड़े अनुकूल हैं। यह सबसे सस्ता तरीक़ा है। और अन्य ज़ख़ीरों की तुलना में, इस बेसिन के ज़ख़ीरों पर लागत कम आयेगी। उन लोगों के तख़मीनों के अनुसार इस क्षेत्र के लौह-खनिज पर प्रति-टन बैठनेवाली लागत ख़कास्सिया, केमेरोवो क्षेत्र और अल्ताई प्रदेश के लौह-खनिज से (जो सम्प्रति निर्माणाधीन पश्चिम-साइबेरियाई लोहे और इस्पात के कारख़ाने के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है) कम होगी। इन्हीं तख़मीनों के अनुसार अंगारा-पित के लौह-खनिज से निकला हुआ कच्चा लोहा देश-भर में सबसे सस्ता होगा।

क्रास्नोयार्स्क के साथियों का प्रस्ताव बड़ा ही दिलचस्प है। सोवियत संघ की राज्य संयोजन समिति को निर्देश दिये गये हैं कि वह यह अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट दे कि यदि क्रास्नोयार्स्क प्रदेश में लौह-खनिज के जखीरों का द्रुतगति से विकास किया जाय तो उससे क्या क्या लाभ होंगे।

कज़ाख़ सो० स० ज० की मंत्रि-परिषद के अध्यक्ष साथी कुनायेव तथा उसी जनतंत्र के कुछ अन्य साथियों ने यह सुझाव दिया था कि ४५० किलोमीटर लम्बी इरतिश–कराग़न्दा नहर का निर्माण करके मध्य कज़ाख़स्तान की जल-सप्लाई की समस्या हल की जाय। इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान रखना चाहिए तथा सोवियत संघ की राज्य संयोजन समिति और कज़ाख़स्तान की मंत्रि-परिषद को सम्मिलित रूप से उसका विवेचन करना, योजना पर बैठनेवाली लागत का तख़मीना लगाना और इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहिए।

'प्राव्दा' में प्रकाशित एक लेख में प्रोफ़ेसर व० उवारोव ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया था। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की अनेकानेक शाखाओं में गैस-टर्बाइनों की उपादेयता की जानकारी करनेवाले कुछ तथ्यों का उल्लेख करते हुए बताया था कि बड़े बड़े ताप-बिजलीघरों के लिए [illegible] गैस-टर्बाइनों तथा रेलवे यातायात, गैस पाइपलाइनों और अन्य प्रयोजनों के लिए गैस-टर्बाइनों के अधिष्ठापनों के डिज़ाइन बनाने के कार्यों को शीघ्र सम्पन्न करने तथा उनके निर्माण की व्यवस्था करने की ज़रूरत है।

विचार-विनिमय के समय जो ढेरों दिलचस्प सवाल उठाये गये थे उनमें से बहुतों का संबंध इंजीनियरिंग, लोहे और इस्पात, ईंधन, रसायन, हल्के उद्योग और खाद्य-सामानों के उद्योगों, खेतीबारी, पशुपालन तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की अन्य शाखाओं से था। सोवियत संघ की

राज्य संयोजन समिति और अन्य केन्द्रीय संस्थाओं को इन सभी प्रस्तावों पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से उनकी उपादेयता निर्दिष्ट करनी चाहिए और उनमें जो भी अच्छाइयां हैं उनका सप्तवर्षीय योजना की कार्यान्विति के समय इस्तेमाल करना चाहिए।

दूसरे क़िस्म के प्रस्तावों का संबंध स्थानीय बातों से है। स्थानीय संस्थाएं ऐसे प्रस्तावों को कार्यान्वित कर सकती हैं और उन्हें करना भी चाहिए। उद्यमों में उत्पादन के संगठन और टेक्नॉलाजी, मशीनों के उपयोग और कच्चे माल के और भी अधिक किफ़ायत के साथ इस्तेमाल के संबंध में भी बहुत-से सुझाव दिये गये हैं। उनमें त्रुटियों की आलोचना की गयी है और फ़ैक्ट्रियों, निर्माण-स्थलों, कोलख़ोज़ों और सोवख़ोज़ों में होनेवाले कार्यों को समुन्नत बनाने के विषय में ठोस प्रस्ताव रखे गये हैं।

उपयोगी सुझावों की संख्या बहुत अधिक थी। स्थानीय संस्थाओं का कार्य यह है कि वे इन सुझावों पर ध्यान दें और कोई ऐसी योजना बनायं कि सुझावों की समस्त अच्छी बातों को शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित किया जा सके।

तीसरे क़िस्म के सुझाव नयी खानों, फ़ैक्ट्रियों, कारख़ानों और उन अन्य उद्यमों के निर्माण के संबंध में हैं जिनकी व्यवस्था लक्ष्य के आंकड़ों में नहीं की गयी है। इस क़िस्म के अधिकांश सुझाव सिद्धान्ततः ठीक हैं किन्तु आगामी सात वर्षों में उन्हें इसलिए नहीं कार्यान्वित किया जा सकता कि उनके लिए बड़ी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। किन्तु सोवियत संघ की राज्य संयोजन समिति, जनतंत्रों की राज्य संयोजन समितियों और आर्थिक परिषदों तथा स्थानीय संस्थाओं को चाहिए कि वे इन सभी सुझावों की जांच करें और सप्तवर्षीय योजना की अवधि के आगे की दीर्घकालीन योजना तैयार करते समय उनपर अच्छी तरह विचार करें।

साथियो, १९५९-१९६५ के लिए सोवियत संघ के राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लक्ष्य के आंकड़ों की थीसिस के संबंध में सारे राष्ट्र ने जो विचार-विनिमय किया है उसके लिए मैं, सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति और सोवियत संघ की मंत्रि-परिषद की ओर से सन्तोष प्रकट करता हूं और जिन जिन लोगों ने विचार-विनिमय में भाग लिया है उन्हें धन्यवाद देता हूं। विचार-विनिमय के फलस्वरूप बहुत अधिक सामग्री प्राप्त हुई है जिससे सप्तवर्षीय योजना की बहुत-सी परियोजनाएं निर्दिष्ट करने और आगे की दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजनाएं बनाने में सहायता मिलेगी **(देर तक तालियां)**।

समाजवादी उद्योग और यातायात का विकास

साथियो, लक्ष्य के आंकड़ों से स्पष्ट है कि उद्योग के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से भारी उद्योग के क्षेत्र में विकास की गति बहुत तेज़ रहेगी और, उत्पादन में बहुत अधिक सर्वतोमुखी वृद्धि होगी।

आप स्वयं ही देखें कि जैसे ही हमने भारी उद्योगों की चर्चा आरम्भ की, सूर्य तेज़ी से चमकने लगा। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति भी हमारी सफलताओं का स्वागत कर रही है। सूर्य हमारी सप्तवर्षीय योजना का मार्ग प्रकाशित कर रहा है। हॉल में उपस्थित विदेशी पत्रकार इसकी गवाही देंगे **(देर तक जोर की तालियां)**।

योजना के अनुसार १९६५ में सकल औद्योगिक उत्पादन १९५८ की तुलना में लगभग ८० प्रतिशत अधिक होगा। 'क' वर्ग (उत्पादन साधनों का उत्पादन) में ८५-८८ प्रतिशत वृद्धि और 'ख' वर्ग (उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन) में ६२-६५ प्रतिशत वृद्धि होगी। यह वृद्धि बहुत अधिक है। आगामी सात वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में जितनी वृद्धि होगी वह पिछले २० वर्षों में हुई उत्पादन वृद्धि के बराबर होगी।

रिपोर्ट की थीसिस में सप्तवर्षीय योजना के विस्तृत आंकड़े दिये गये हैं। मैं केवल बड़े बड़े उद्योगों के विकास की मूल प्रवृत्तियों और उनके गुणात्मक परिवर्तनों के विषय में कुछ चर्चा करूंगा।

लौह और अलौह धातु-उद्योग की चर्चा मैं पहले करूंगा। १९६५ का लक्ष्य ६५०-७०० लाख टन तक कच्चा लोहा, ८६०-९१० लाख टन तक इस्पात और ६५०-७०० लाख टन तक वेल्लित इस्पात का उत्पादन करना है। अलौह और दुर्लभ धातुओं का उत्पादन तो कई गुना बढ़ जायेगा।

पिछले ३० वर्षों में व्यय हुई धनराशि से भी अधिक बड़ी धनराशि लौह और अलौह धातु-उद्यमों के निर्माण और विस्तार में ख़र्च होगी। लौह धातु उद्योगों में लगी पूंजी का ६७ प्रतिशत और अलौह उद्योग में लगी पूंजी का लगभग ६० प्रतिशत उन चालू उद्यमों के विस्तार अथवा पुनर्निर्माण में व्यय किया जायेगा जिन्हें कच्चे लोहे, इस्पात और वेल्लित इस्पात में निर्धारित वृद्धि की तीन-चौथाई से अधिक का उत्पादन करना होगा। अकेला मगनितोगोर्स्क का लोहे और इस्पात का कारख़ाना ही १९६५ तक वेल्लित इस्पात का उत्पादन प्रति वर्ष ५२ लाख टन से बढ़ाकर ८५ लाख टन तक कर लेगा।

धन का सदुपयोग करने का यही सबसे लाभदायक तरीक़ा है। उदाहरणार्थ करागन्दा लोहे और इस्पात के कारख़ाने के निर्माण में प्रति टन कच्चे लोहे के हिसाब से पूंजी-विनियोजन २,३४७ रूबल होगा जबकि मगनितोगोर्स्क कारख़ाने के विस्तार में यही व्यय होगा प्रति टन १,९४७ रूबल। नये अथवा पुनर्निर्मित लोहे और इस्पात के कारख़ानों में मशीनों की यूनिट-क्षमता में काफ़ी वृद्धि की जायेगी। २,००० और २,२८६ घन मीटर आयतनवाली, दुनिया की सबसे बड़ी पिघलाऊ भट्ठियों, ५०० टन से अधिक क्षमतावाली खुली भट्ठियों, ८० और १८० टन क्षमतावाली विद्युत् भट्ठियों, वार्षिक ३०-४० लाख टन क्षमतावाली

अविराम स्वचालित रोलिंग-मिलों तथा अन्य मशीनों के निर्माण की भी व्यवस्था की जायेगी।

आगामी सात वर्षों में नयी और अतिप्रभावकर प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं का व्यापक उपयोग किया जायेगा। उदाहरणार्थ, ५० से अधिक पिघलाऊ भट्ठियों और बहुत खुली और गर्मी देनेवाली भट्ठियों की व्यवस्था एक नया प्रौद्योगिक तरीक़ा अपनायेगी जिसमें प्राकृतिक गैस और आक्सीजन का इस्तेमाल किया जायेगा। निकिल, तांबे और सीसे-जस्ते के उद्योगों में आक्सीजन का व्यापक प्रयोग होगा। इससे पिघलाऊ भट्ठियों की उत्पादन-क्षमता ८-१० प्रतिशत तक और खुली भट्ठियों की २०-३० प्रतिशत तक बढ़ जायेगी। धातु-प्रक्रियाओं में वैकुअम का इस्तेमाल, वेल्लित इस्पात के तापोपचार और अन्य विधियों का इस्तेमाल करने से उत्पादन की क़िस्म सुधरेगी।

जिस द्रुतगति से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में प्रसार होगा उससे धातु उद्योग के गठन में परिवर्तन होंगे। पावर-इंजीनियरिंग और रसायन, तेल तथा गैस उद्योगों में विकास होने के साथ ही साथ इस्पात के पाइपों के उत्पादन में भी वृद्धि करने की ज़रूरत होगी। तदनुसार, जब आगामी सात वर्षों में वेल्लित इस्पात के उत्पादन में कुल ५३-६३ प्रतिशत की वृद्धि होगी तो पाइपों का उत्पादन १०० प्रतिशत से अधिक बढ़ जायेगा और इस्पात की चादरों के उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि होगी।

इंजीनियरिंग उद्योग का प्राविधिक स्तर बढ़ाने, स्वचालित यंत्रों की व्यवस्था में वृद्धि करने और विशेष इस्पातों और खोटों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विद्युत्-धातु-कर्म और लोहे की खोटों के उद्योगों तथा कई अलौह और दुर्लभ धातुओं के उत्पादन को–मुख्यतया कच्चे खनिजों के पूरे शोध से काफ़ी अधिक बढ़ाया जायेगा।

पिछले कुछ समय से अलुमिनियम का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। यह एक ऐसी धातु सिद्ध हो रही है जिसका उद्योग और निर्माण-कार्यों

में व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। इसी कारण, आगामी सात वर्षों में अलुमिनियम का उत्पादन २.८-३ गुना तक बढ़ाया जायेगा। इतनी वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास शक्ति के स्रोत भी हैं और कच्चा माल भी। तांबे का उत्पादन भी प्रायः दूना हो जायेगा।

धातु उद्योग के विकास का एक बहुत ही आवश्यक अंग है खानों के विकास की गति तेज़ करना। लौह-खनिज का उत्पादन कोई १०० प्रतिशत बढ़ाया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप हमारा देश दुनिया में सबसे अधिक लौह-खनिज का उत्पादन कर सकेगा। लौह-खनिज संकेन्द्रण के बड़े बड़े कारखानों का निर्माण कर तथा ड्रेसिंग और रोस्टिंग की विकसित प्रणालियां चालू कर क्रय-विक्रय योग्य खनिजों में लोहे का अंश बढ़ाया जायेगा। मुख्यतया खुली खुदाई प्रणाली से खानें खोदने की व्यवस्था कर—कज़ाख़स्तान और कुर्स्क मैगनेटिक अनोमली के क्षेत्र में भी—लौह-खनिज के नये ज़ख़ीरों का विकास किया जायेगा।

आगामी सात वर्षों में **रसायन-उद्योग** को विशेष महत्त्व दिया जायेगा। पार्टी की केन्द्रीय समिति के मई (१९५८) के पूर्णाधिवेशन ने भारी उद्योगों की इस मुख्य शाखा के तीव्र विकास का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया था। रसायन-उद्योग की उन्नति से देश की प्राकृतिक सम्पदा का सबसे प्रभावकर उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की प्रत्येक शाखा में और भी अधिक प्राविधिक प्रगति के लिए रसायन उद्योग का विकास अनिवार्य है। इंजीनियरिंग, निर्माण और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की अन्य शाखाओं में प्लास्टिक्स तथा अन्य संश्लिष्ट पदार्थों का व्यापक उपयोग किया जायेगा।

रसायन-उद्योग से उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए ऐसे ऐसे कच्चे मालों की व्यवस्था हो सकेगी जिनकी क़िस्म भी अच्छी होगी तथा जिन पर व्यय भी कम बैठेगा। इस उद्योग में प्रकार की दृष्टि से उत्तम ऐसे

ऐसे माल तैयार हो सकेंगे जिनके गुण प्राकृतिक माल से भी उच्च कोटि के होंगे, साथ ही उनपर श्रम-व्यय भी बहुत कम बैठेगा।

रासायनिक पदार्थों का कुल उत्पादन आगामी सात वर्षों में कोई तिगुना हो जायेगा। साथ ही, कृत्रिम रेशों का उत्पादन लगभग चौगुना और प्लास्टिक्स और राल का सात गुने से अधिक होगा।

मैं खनिज खादों के उत्पादन की विशेष चर्चा करना चाहता हूं। १९६५ में यह उत्पादन ३५० लाख टन हो जायेगा जबकि १९५८ में वह १२० लाख टन ही था। फ़स्लों की पैदावार बढ़ाने के महान लक्ष्य की पूर्त्ति के लिए खनिज खादों के उत्पादन में वृद्धि होनी ज़रूरी है।

रसायन उद्योग का पूर्णत: नये आधार पर विकास किया जायेगा और एतदर्थ सबसे सस्ते कच्चे माल (प्राकृतिक गैस तथा तेल साफ़ करनेवाले कारखानों से मिली हुई गैस) का प्रयोग किया जायेगा तथा आधुनिक प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं एवं उच्च क्षमतावाले उपकरणों से काम लिया जायेगा। फलत: रसायन फ़ैक्ट्रियों के निर्माण में होनेवाले खर्चों में तो बहुत कमी होगी ही, साथ ही लागत में भी कमी आयेगी।

ईंधन-उद्योग में हमने तेल और गैस के निस्सारण और उन्हें शुद्ध करने के कार्य को प्रमुखता दी है। १९६५ में तेल का उत्पादन बढ़कर २३-२४ करोड़ टन, अर्थात् दूने से भी अधिक, हो जायेगा और गैस का निस्सारण एवं उत्पादन कोई पांच गुना, अर्थात् प्रति वर्ष १५० अरब घन मीटर हो जायेगा। ईंधन के कुल उत्पादन में तेल और गैस का अनुपात ३१ प्रतिशत से बढ़कर ५१ प्रतिशत, और तदनुसार कोयले का ६० प्रतिशत से घटकर ४३ प्रतिशत हो जायेगा।

ईंधन-उद्योग में उपर्युक्त व्यवस्था हो जाने से आर्थिक दृष्टि से बड़ा लाभ होगा। उदाहरणार्थ, उराल की ईंधन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्त्ति की योजना में उज़्बेकिस्तान, कोमी स्वायत्त जनतंत्र और पोवोल्ज्ये क्षेत्रों से गैस की पाइपलाइनें बिछायी जाने की व्यवस्था है।

आगामी सात वर्षों की समाप्ति तक उराल में प्रति वर्ष २५-२७ अरब घन मीटर गैस की खपत होगी। नतीजा यह होगा कि उराल में दूरस्थ कोयला-क्षेत्रों से लाये जानेवाले पावर कोल की खपत आधी से भी कम रह जायेगी। गैस का इस्तेमाल करने से उराल उद्योग को १९६५ में लगभग १४० करोड़ रूबल की बचत होगी। एक अन्य उदाहरण भी लिया जा सकता है। सम्प्रति मास्को में प्रति वर्ष ४ अरब घन मीटर गैस और लगभग ६० लाख टन कोयले की खपत होती है। आगामी सात वर्षों के अन्त तक मास्को में गैस की सप्लाई बढ़कर प्रति वर्ष १३ अरब घन मीटर से ज्यादा हो जायेगी और कोयले की खपत केवल ७ लाख टन रह जायेगी जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि में ५ अरब रूबल की बचत होगी।

कोयले के स्थान पर प्राकृतिक गैस और तेल का इस्तेमाल होने से देश को सात वर्षों में १२५ अरब रूबलों से ज्यादा की बचत होगी अर्थात् देश को उतनी धनराशि बचेगी जितनी समस्त बिजलीघरों और विद्युत् तथा ताप ग्रिडों के निर्माण के लिए निर्दिष्ट की गयी है।

तेल और गैस उद्योग में ईंधन के नये नये ज़ख़ीरों का विकास करने, तेल और गैस की प्रमुख पाइपलाइनें बिछाने, तेल साफ़ करने और गैस-बेन्ज़ीन के कारख़ानों के निर्माण के संबंध में बहुत कुछ कार्य किया जायेगा।

तेल और गैस उद्योग का विकास करते समय हमें कोयला उद्योग को नज़रन्दाज़ न करना चाहिए। यद्यपि कोयला-उत्पादन में वृद्धि की गति पिछले सात वर्षों की अपेक्षा कहीं कम होगी, फिर भी उत्पादन २१-२३ प्रतिशत तक बढ़ जायेगा, ख़ासकर इसलिए कि दोनबास, कुज़बास और करागन्दा कोयला-क्षेत्रों में कोकिंग कोल और पूर्वी क्षेत्रों में सस्ता पावर कोल निकाला जायेगा।

कोयला-उद्योग में प्रमुख कार्य श्रम-उत्पादिता में वृद्धि करना और लागत को कम करना है। कोयला निकालने के लिए खुली खुदाई और जल-खुदाई की पद्धतियों के विकास और कोयला-खानों के, विशेषकर दोनवास में, पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में बिजलीकरण, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, समस्त प्राविधिक प्रगति और प्रतिव्यक्ति अधिकाधिक प्राविधिक सुविधाएं बढ़ाने का आधार है। हमारी पार्टी इस क्षेत्र के द्रुत विकास को सदा ही अपना लक्ष्य समझती रही है। महान लेनिन का कहना था कि सारे देश में बिजलीकरण हो। आज हम उनके उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पक्का क़दम उठा रहे हैं। आगामी सात वर्षों के अन्त में विद्युत् शक्ति का उत्पादन बढ़कर प्रति वर्ष ५००-५२० अरब किलोवाट-घंटे हो जायेगा। और बिजलीघरों की क्षमता दूनी से अधिक हो जायेगी। औद्योगिक उत्पादन में ८० प्रतिशत की वृद्धि होने से उद्योगों में होनेवाली विद्युत् शक्ति की खपत १२० प्रतिशत बढ़ जायेगी और हर औद्योगिक कर्मचारी को विद्युत् शक्ति के प्रायः दूने उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे।

कम अवधि में और कम से कम खर्च पर बिजलीकरण का कार्यक्रम पूरा करने के लिए हम विद्युत् शक्ति उद्योग को किस प्रकार विकसित करना चाहते हैं, यह एक प्रश्न है।

जब बिजलीघर बनता है उस समय शक्ति के साधनों का चुनाव उन प्राविधिक और आर्थिक गणनाओं के आधार पर होना चाहिए, जिनमें संबंधित क्षेत्र में यातायात और उत्पादन की दशाएं, निर्माण की लागत और अवधि, क्षमता की प्रत्येक इकाई पर पूंजी-विनियोजनों की बचत और बिजलीघर के संचालन में होनेवाली बचत का ध्यान रखा गया हो।

समय की बचत और सबसे प्रभावकर तरीक़े से मूल पूंजी-विनियोजनों का उपयोग करने के लिए सप्तवर्षीय योजना में प्राकृतिक गैस, मज़ूत

और सस्ते कोयले से चलनेवाले ताप-बिजलीघरों के निर्माण को प्रमुखता दी गयी है। यदि हम ताप-बिजलीघरों और पन-बिजलीघरों में लगी हुई पूंजी के विगतवर्षीय अनुपात को बनाये रखना चाहें तो हमें या तो उनकी निर्दिष्ट शक्ति-क्षमताओं में कमी करनी होगी या फिर २० अरब रूबल से अधिक की पूंजी और लगानी पड़ेगी।

ताप-बिजलीघरों को चालू करने के साथ ही साथ पन-बिजलीघरों के निर्माण की भी व्यवस्था की गयी है। ये बिजलीघर हैं— ३६,००,००० किलोवाट क्षमता का ब्रात्स्क; २५,३०,००० किलोवाट क्षमता का स्तालिनग्राद; ४२,००,००० किलोवाट क्षमता का क्रास्नोयार्स्क; ६,२५००० किलोवाट क्षमता का क्रेमेंचूग; ५,२५००० किलोवाट क्षमता का बुख़्तरमा; १०,००,००० किलोवाट क्षमता का वोतकिन्स्क आदि।

बड़े बड़े बिजलीघरों के निर्माण के साथ साथ विद्युत् ग्रिडों के विस्तार की भी आवश्यकता पड़ती है। देश के समस्त क्षेत्रों को निरन्तर बिजली देने और शक्ति-क्षमताओं का सुचारु रूप से प्रयोग करने के लिए सप्तवर्षीय योजना में बिजलीघरों को बड़े बड़े विद्युत्-प्रणालियों का स्वरूप देने की व्यवस्था है ताकि सोवियत संघ में एक संयुक्त विद्युत् प्रणाली की स्थापना हो सके। कई नाभिकीय बिजलीघर भी चालू किये जायेंगे जिनमें कई प्रकार के प्रबाधक लगाये जायेंगे।

मुख्य उद्योगों को विकसित करने की और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के बिजलीकरण की सम्भावनाओं की चर्चा करते समय हम **मशीन-उद्योग** का भी उल्लेख करेंगे जो पिछले वर्षों की भांति आगे भी बढ़ता ही रहेगा।

सप्तवर्षीय योजना के अधीन, मशीन-उद्योग की समस्त आधुनिक शाखाओं—मुख्यतया भारी मशीन-उद्योग, यथातथ उपकरण निर्माण और स्वचालित और विद्युत्कण यंत्रों के उत्पादन—में तेज़ी से विकास होगा।

नयी नयी मशीनों के निर्माण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में विज्ञान और इंजीनियरिंग की सफलताओं और खोजों – विशेष रूप से रेडियो एलेक्ट्रानिक्स, सेमी-कन्डक्टर्स, अल्ट्रा साउन्ड और रेडियो-ऐक्टिव आइसोटोपों – का पूरा पूरा उपयोग किया जायेगा।

लोहा और इस्पात उद्योग के लिए अधिक शक्तिशाली और अधिक क्षमतावाली ५० से अधिक रोलिंग-मिलें बनायी जायेंगी। इन मिलों में अविराम रोलिंग और स्वचालन के सिद्धान्तों का प्रयोग किया जायेगा। साथ ही भिन्न भिन्न प्रकार की नवीनतम रासायनिक साधनों का भी विकास किया जायेगा।

मशीन-उद्योग से अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए हमें सभी फ़ैक्ट्रियों के पुराने मशीन उपकरणों, फ़ोर्ज प्रेसों और फ़ाउन्ड्री की मशीनों को या तो आधुनिक रूप देना होगा या उनकी जगह नये उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी। मशीनें बनानेवाले कारख़ानों को नवीनतम प्रकार के विशेष और अग्रीगेट मशीनों, प्री-सेट प्रोग्राम कन्ट्रोल मशीनों, स्टाम्पिंग और चाकिंग दाब-यंत्रों, फ़ोर्जिंग मशीनों, आटोमेटिक फ़ोर्ज प्रेसों और आटोमेटिक एवं सेमी आटोमेटिक लाइनों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा।

देश के बिजलीकरण के मुख्य प्राविधिक आधार के रूप में, विद्युत् इंजीनियरिंग उद्योग के और भी अधिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें बिजली की मशीनों, केबिलों और बिजली के इनसुलेटिंग सामानों की क़िस्म सुधारनी चाहिए और उनका प्राविधिक स्तर ऊंचा उठाना चाहिए। साथ ही विद्युत् इंजीनियरिंग उद्योग की क्षमताओं को बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए।

जैसा कि रिपोर्ट की थीसिस में बताया गया था, **इमारती लकड़ी, काग़ज़ और काठ के उद्योग** को भी विकसित किया जायेगा।

भारी उद्योगों के अधिक विकास और खेतीबारी को समुन्नत बनाने के उपायों की सफलता के कारण हम **खाद्य-पदार्थों और उपभोक्ता-वस्तुओं** में काफ़ी वृद्धि कर सकेंगे।

अगले सात वर्षों में हल्के उद्योग के सकल उत्पादन में प्राय: ५० प्रतिशत की और खाद्य उद्योग के उत्पादन में लगभग ७० प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। अन्य चीज़ों के उत्पादन की वृद्धि इस प्रकार होगी—सूती कपड़ा ३३-३८ प्रतिशत, ऊनी कपड़ा—६५ प्रतिशत, रेशमी कपड़ा—७६ प्रतिशत, चमड़े के जूते—४५ प्रतिशत, मांस—११० प्रतिशत, मक्खन और घी—५८ प्रतिशत, दूध-पदार्थ—१२० प्रतिशत, शक्कर—७६-९० प्रतिशत और मछली—६० प्रतिशत।

हल्के उद्योगों और खाद्य उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने के साथ ही साथ उनकी क़िस्में सुधारनी और उनमें वृद्धि करनी चाहिए। अब इन कार्यों को प्रमुखता दी जायेगी। यह भी आवश्यक है कि उपभोक्ता वस्तुएं अच्छी क़िस्म की हों, देखने में अच्छी हों, खूबसूरती से पैक की गयी हों और अलग अलग वज़न की हों। अच्छी क़िस्म की उपभोक्ता वस्तुओं और खाद्य-पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के निमित्त निर्धारित किये गये लक्ष्यों की पूर्त्ति के लिए खाद्य उद्योगों और हल्के उद्योगों की १,६०० से भी अधिक फ़ैक्ट्रियां बनायी जायेंगी। इसके अतिरिक्त बहुत-सी वर्तमान फ़ैक्ट्रियों का भी पुनर्निर्माण किया जायेगा।

खेतीबारी के कच्चे माल के एक बड़े भाग का विधायन ग़ैर-सरकारी उद्यमों में होगा। एतदर्थ कोलख़ोज़ों, सोवख़ोज़ों और उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को नानबाइयों के कारख़ाने और ऐसी ऐसी फ़ैक्ट्रियां बनानी होंगी जिनमें सासेज और मांस के अध-पके सामान, मक्खन, पनीर, छेना तथा डिब्बे बन्द तरकारियों और फल, कलफ तथा अन्य खाद्य-पदार्थ तैयार किये जायेंगे। कोलख़ोज़ों के विक्रययोग्य उत्पादन और

उनकी आमदनियां बढ़ने के कारण कई कोलख़ोज़ों को अपने अपने साधन एक साथ मिलाकर अन्तर-कोलख़ोज़ के आधार पर और भी बड़ी बड़ी एवं बढ़िया साधन-सम्पन्न फ़ैक्ट्रियां बनाने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए जिनमें खाद्य-पदार्थों को डिब्बों में भरने की तथा डबलरोटी, सासेज आदि बनाने की व्यवस्था होगी।

देश के खाद्य-साधनों की वृद्धि का एक प्रमुख स्रोत है मछलियां। खुले समुद्रों और महासमुद्रों में मछली पकड़ने की व्यवस्था में विकास करने के साथ ही साथ देश के भीतर स्थित जलाशयों का भी क़ायदे से उपयोग किया जाना चाहिए। इन जलाशयों से प्रति वर्ष कम से कम ६०-८० लाख सेन्टनर तक मछलियां मिल सकती हैं।

शक्कर-उत्पादन का विशेष उल्लेख करना होगा। आपको याद होगा कि सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के जयन्ती-अधिवेशन में १९७२ तक शक्कर का वार्षिक उत्पादन ९०-१०० लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हमारी सम्भावनाओं की जांच-पड़ताल, तथा मीठी चुक़न्दर का उत्पादन बढ़ाने में कृषि-श्रमिकों द्वारा प्रदर्शित पहलक़दमी के फलस्वरूप केन्द्रीय समिति और सरकार ने इस लक्ष्य में परिवर्तन करने का निश्चय किया। अब १९६५ तक, अर्थात् निर्दिष्ट काल से ७ साल पहले, शक्कर का वार्षिक उत्पादन बढ़ाकर एक करोड़ टन तक कर दिया जायेगा। प्रतिव्यक्ति शक्कर का उत्पादन १९६५ में ४१-४४ किलोग्राम हो जायेगा जबकि इस समय वह २६ किलोग्राम है **(तालियां)**।

शक्कर के उत्पादन में योजनानुसार जो वृद्धि होगी उससे न सिर्फ़ जनता को ही अधिक शक्कर उपलब्ध होगी अपितु बजट की आय भी बढ़ेगी और साथ ही शराब की बिक्री कम हो जाने से होनेवाली हानि पूरी हो सकेगी। १९५७ की तुलना में पिछले साल जनता ने ११.३

करोड़ लीटर शराब कम ख़रीदी। अधिकाधिक सांस्कृतिक उत्थान और शैक्षणिक कार्यों के परिणामस्वरूप भविष्य में जनता और भी कम शराब ख़रीदेगी **(तालियां)**। अन्धाधुन्ध मदिरापान जैसे विगतकाल के दुर्व्यसनों के दूर हो जाने से जनता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, परिवार और भी सुखी होंगे और जनता का आचार-व्यवहार अधिक शिष्ट बनेगा। इससे राज्य और जनता दोनों को ही लाभ होगा। जनता मिठाइयों का अधिक इस्तेमाल करने लगेगी और शराब जैसे पेयों का कम **(हॉल में सजीवता; तालियां)**।

बड़े पैमाने पर हल्के उद्योग के विकास के साथ साथ सप्तवर्षीय योजना में इंजीनियरिंग के कारखानों, काष्ठोद्योग फ़ैक्ट्रियों तथा अन्य उद्योगों के उपभोक्ता-वस्तु-विभागों में घरेलू सामग्रियों, घरेलू श्रम की बचत करनेवाली मशीनों और उपकरणों का उत्पादन दूना किये जाने की योजना है।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में तीव्र गति से प्रगति होने के साथ ही साथ ढुलाई के साधनों में भी वृद्धि करनी होगी। १९६५ में **रेलों द्वारा ढुलाई** १९५८ की अपेक्षा ३९-४३ प्रतिशत अधिक होगी। यातायात के मूल साधनों, विशेष रूप से रेलवे, का प्राविधिक पुनर्निर्माण किया जायेगा और वाष्पचालित इंजनों के स्थान पर कम ख़र्चवाले बिजली और डीज़ेल के इंजनों से काम लिया जायेगा।

आगामी सात वर्षों के अन्त तक सभी ट्रंक लाइनें जिनकी कुल लम्बाई प्राय: १,००,००० किलोमीटर होगी, बिजली और डीज़ेल की सहायता से चलने लगेंगी। इन लाइनों की यातायात-क्षमता प्राय: दूनी हो जायेगी। सात वर्षों में बिजली और डीज़ेल के इंजनों के चालू हो जाने से लगभग ४० करोड़ टन कोयले की बचत हो सकेगी और संचालन-व्यय भी ४५ अरब रूबल कम होगा।

इसके अतिरिक्त, यातायात के अन्य साधनों का भी विकास किया जायेगा और समुद्र, नदी, वायु तथा मोटर यातायात और पाइपलाइनों

द्वारा ढुलाई में वृद्धि होगी। मोटर-सड़कों का निर्माण बढ़ाया जायेगा। राज्य की सभी मोटर-सड़कें मज़बूत सीमेंट-कांक्रीट की बनायी जायेंगी। कोलखोज़ों, सोवखोज़ों तथा उद्योगों, यातायात, निर्माण तथा अन्य उद्यमों और आर्थिक संगठनों को स्थानीय सड़कों के निर्माण में हाथ बटाना चाहिए।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और नगर तथा ग्राम की जनता के लिए उसकी ज़रूरत के समस्त संचार-साधनों की व्यवस्था की जायेगी। रेडियो-प्रसारण तथा केबिल की लाइनें बिछाने का काम भी अधिक द्रुतगति से किया जायेगा। रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण-केन्द्रों की संख्या भी काफ़ी बढ़ायी जायेगी।

साथियो, सप्तवर्षीय योजना के लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकते हैं जब नये टेक्नीक का व्यापक प्रयोग किया जाय, उत्पादन प्रक्रियाओं में **सर्वांगीण यंत्रीकरण और स्वचालन** की पूरी पूरी व्यवस्था की जाय और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की सभी शाखाओं में **विशेषीकरण और समन्वयन** के आधार पर काम हो।

सप्तवर्षीय योजना में, उद्योग की उत्पादन प्रक्रियाओं, कृषि, निर्माण, यातायात, लदाई और उतराई के कामों, तथा जनोपयोगी कार्यों में सर्वांगीण यंत्रीकरण का प्रबन्ध किये जाने के द्वारा कठोर शारीरिक श्रम दूर किया जायेगा। इस कार्य के लिए आवश्यक मशीनों के उत्पादन में निकट भविष्य में काफ़ी वृद्धि करने की ज़रूरत है।

सर्वांगीण यंत्रीकरण की व्यवस्था के साथ ही साथ अधिकाधिक स्वचालन की भी आवश्यकता होगी। इससे काम की स्थिति में सुधार होगा, काम हल्का होगा और श्रम-उत्पादिता में काफ़ी वृद्धि होगी। समाजवादी समाज में स्वचालन का महत्त्व आर्थिक ही नहीं अपितु सामाजिक भी है। इससे श्रम की प्रकृति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आता है, श्रमिकों

के सांस्कृतिक और प्राविधिक स्तर में वृद्धि होती है और ऐसी हालत पैदा होती है जिसमें दिमाग़ी और शारीरिक श्रम के बीच पाया जानेवाला अन्तर दूर हो सके। फिर मनुष्य का कार्य स्वचालित मशीनों और उपकरणों का नियंत्रण करना, उन्हें ठीक दशा में रखना और प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं का कार्यक्रम तैयार करना रह जाता है।

इस क्षेत्र में हमारे देश को कुछ सफलताएं मिल भी चुकी हैं। उदाहरणार्थ हमने इंजीनियरिंग और लोहे तथा इस्पात के कारख़ानों के कुछ विभागों तथा पन-बिजलीघरों में सर्वत्र स्वचालन की व्यवस्था की है। कतिपय रसायन प्रक्रियाओं में भी स्वचालन का प्रबन्ध किया गया है। किन्तु कहना यह चाहिए कि अभी स्वचालन का प्रयोग व्यापक रूप से नहीं होता। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगामी कुछ वर्षों में आधुनिक स्वचालन-यंत्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होगा ताकि भविष्य में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की सभी शाखाओं में स्वचालन की सर्वांगीण व्यवस्था हो सके। रसायन उद्योगों, तेल साफ़ करने और खाद्य-पदार्थों के कारख़ानों, बिजलीघरों, पिघलाऊ भट्ठियों, खुली भट्ठियों और रोलिंग-मिल के विभागों और इंजीनियरिंग की अलग अलग शाखाओं जैसे कुछ उद्योगों में सर्वांगीण स्वचालन की व्यवस्था तुरन्त होनी चाहिए।

उद्योगों और उद्यमों में समन्वयन और विशेषीकरण में वृद्धि करने की दृष्टि से सप्तवर्षीय योजना में एक ही क़िस्म की चीज़ों के उत्पादन को कम से कम कारखानों में केन्द्रित करने की व्यवस्था है। धातु के सामानों, पिघलाऊ भट्ठियों और इस्पात पिघालने की मशीनों तथा इंजीनियरिंग उद्योग के कास्टिंग, फ़ोर्जिंग, स्टाम्पिंग और अन्य अधबने सामानों के उत्पादन में विशेषीकरण की वर्तमान व्यवस्था में बड़े पैमाने पर और भी अधिक विकास किया जायेगा। इस प्रकार हम नये नये कारख़ानों का निर्माण किये बिना भी टर्बाइन, जनरेटर, स्टीम ब्वायलर, ट्रैक्टर और अन्य मशीनों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि कर लेंगे।

इन प्रमुख तालिकाओं से पता चलता है कि आगामी सात वर्षों में उद्योग और यातायात के क्षेत्र में कितना विकास होगा। साथियो, आप देख ही रहे हैं कि हमारे सामने बड़े बड़े कार्य हैं। सोवियत राज्य की औद्योगिक शक्ति को और भी अधिक मज़बूत बनाने और उद्योग को और भी ऊंचे प्राविधिक स्तर तक बढ़ाने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सृजनात्मक प्रेरणाशक्ति का परिचय देकर तथा समाजवादी प्रतियोगिता में और भी व्यापक पैमाने पर विकास कर साहसी मज़दूर वर्ग और वैज्ञानिक, टेक्नीशियन तथा इंजीनियर सप्तवर्षीय योजना में निर्दिष्ट लक्ष्यों तक न सिर्फ़ पहुंचेंगे ही अपितु उनसे भी आगे बढ़ जायेंगे (**देर तक तालियां**)।

समाजवादी कृषि का विकास

साथियो, समाजवादी कृषि के द्रुत विकास से कम्यूनिस्ट निर्माण और जनता के रहन-सहन को ऊपर उठाने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी।

जैसा कि केन्द्रीय समिति के दिसम्बर के पूर्णाधिवेशन के निश्चय में बताया गया था, आगामी सात वर्षों में कृषि क्षेत्र का मुख्य लक्ष्य यह है कि हम **जनता की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं, उद्योग की कच्चे माल संबंधी आवश्यकताओं और कृषि-उत्पादन के लिए राज्य की अन्य सभी आवश्यकताओं की निःशेष रूप से पूर्त्ति कर सकें।**

१९५९-१९६५ में, कृषि के सकल उत्पादन में ७० प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि ८ प्रतिशत होगी। यह उल्लेखनीय है कि पिछले सात वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरीका में कृषि-उत्पादन में वृद्धि की मध्यक वार्षिक गति २ प्रतिशत से भी कम थी।

१९६५ तक भिन्न भिन्न चीज़ों का उत्पादन इस प्रकार हो जायेगा —

अनाज	— १०-११ अरब पूड (१६.४-१८ करोड़ टन) तक। १९५८ में यही उत्पादन ८.५ अरब पूड था;
कच्ची कपास	— ५७-६१ लाख टन तक, अर्थात् १९५८ के उत्पादन की तुलना में ३०-३९ प्रतिशत अधिक;
मीठी चुक़न्दर	— ७६०-८४० लाख टन तक, अर्थात् १९५८ के उत्पादन की तुलना में ४०-५५ प्रतिशत अधिक;
तिलहन	— ५५ लाख टन तक, अर्थात् १९५८ की तुलना में १० प्रतिशत अधिक;
पटुए का रेशा	— ५८० हज़ार टन तक, अर्थात् १९५८ की तुलना में ३१ प्रतिशत अधिक;
आलू	— १४.७ करोड़ टन तक; १९५८ में यह उत्पादन ८.६ करोड़ टन था;
तरकारियां	— इतनी मात्रा में कि जनता की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जायं;
फल और बेरी	— कम से कम १०० प्रतिशत अधिक; अंगूर — १९५८ की तुलना में कम से कम ३०० प्रतिशत अधिक;
मांस (बूचड़ वज़न)	— कम से कम १६० लाख टन तक, अर्थात् १९५८ की तुलना में १०० प्रतिशत अधिक;
दूध	— १०-१०.५ करोड़ टन तक, अर्थात् १९५८ की तुलना में ७०-८० प्रतिशत अधिक;
ऊन	— लगभग ५४८ हज़ार टन तक, अर्थात् १९५८ की तुलना में ७० प्रतिशत अधिक;
अंडे	— ३७ अरब तक, अर्थात् १९५८ की तुलना में ६० प्रतिशत अधिक।

अगले कुछ वर्षों तक फ़स्लों में अन्नोत्पादन को ही अधिक से अधिक बढ़ाया जायेगा क्योंकि अन्न ही तो सारे कृषि-उत्पादन का आधार है। पिछले कुछ वर्षों में अन्नोत्पादन में मुख्यतया फ़स्ल-क्षेत्रों में विस्तार करके ही, वृद्धि की गयी थी। हम अब भी नयी नयी ज़मीनों का उद्धार करते रहेंगे किन्तु यह कार्य अभी तक जिस पैमाने पर किया जाता रहा है अब अपेक्षाकृत उससे छोटे पैमाने पर होगा और उससे अनाज के सकल उत्पादन में भी अधिक वृद्धि न होगी क्योंकि काफ़ी बड़े क्षेत्र में या तो उद्योगोपयोगी फ़स्लें बोयी जायेंगी या उन्हें परती छोड़ दिया जायेगा।

आज कोलखोज़ों और सोवखोज़ों के पास कुशल कर्मचारी और आधुनिक मशीनें हैं और वे सारे कार्य पूरी क्षमता के साथ और समय से कर सकते हैं, अधिकाधिक कार्बनिक और खनिज खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे क़िस्म के बीज वो सकते हैं। सारांश यह कि सारे देश में आगामी वर्षों में **औसतन ३-४ सेंटनेर फ़ी हेक्टेयर के हिसाब से अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए आवश्यक हर तरह की स्थिति मौजूद है।** इस प्रकार अनाज के सकल उत्पादन के जो लक्ष्य के आंकड़े निश्चित किये गये हैं उन्हें न सिर्फ़ पूरा किया जा सकता है, बल्कि उनसे भी आगे निकला जा सकता है।

पशुपालन के क्षेत्र में, आगामी सात वर्षों में मुख्य लक्ष्य होगा मांस, दूध, ऊन और अंडों का उत्पादन बढ़ाना। और यह कार्य किया जाना चाहिए कोलखोज़ों और सोवखोज़ों में सभी प्रकार के पशुधन तथा मुर्ग़-मुर्ग़ियों और खरगोशों की संख्या में काफ़ी वृद्धि करके तथा पशुओं का उत्पादन बढ़ाकर।

चारों के साधनों में पहले से भी अधिक मनोयोग के साथ वृद्धि करनी होगी और एतदर्थ, संबद्ध क्षेत्रों की विशेषताओं के अनुसार, मुख्यतया मक्का, आलू और मीठी चुक़न्दर की फ़स्लों और क्लोवर, आलफ़लफ़ा, मोठ-जई, मटर, लुपाइन आदि प्रोटीनवाले चारों का उत्पादन बढ़ाना होगा।

खाद्य तथा औद्योगिक और चारे की फ़स्लों के रूप में सोयाबीन बहुत ही उपयोगी अनाज है। हमें इसके उत्पादन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

दूध और मक्खन के सकल उत्पादन की दृष्टि से दुनिया में हमारा देश सर्वप्रथम है। आगामी कुछ वर्षों में, इन पदार्थों के प्रतिव्यक्ति-उत्पादन के क्षेत्र में भी हम संयुक्त राज्य अमेरीका से बढ़ जायेंगे। मांस का उत्पादन ढाई-तीन गुना तक बढ़ाने के लिए अपनी सारी क्षमताओं और सम्भावनाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने, सप्तवर्षीय योजना में निर्दिष्ट लक्ष्यों की अतिपूर्त्ति करने और पशुजन्य पदार्थों में प्रतिव्यक्ति-उत्पादन के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरीका के बराबर आ जाने के निमित्त देश के अग्रगामी कोलखोज़ों और सोवख़ोज़ों के आह्वान को कार्यान्वित करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा।

कृषि-उत्पादन में विकास की उक्त तीव्र गति का आधार अर्थ-व्यवस्था की समाजवादी पद्धति के महान लाभ और हमारे उन उद्योगों की ज़बरदस्त ताक़त है जो बड़े पैमाने की यंत्रीकृत कृषि के लिए आवश्यक समस्त प्राविधिक और सामग्री संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं।

आगामी सात वर्षों में हमें कृषि क्षेत्र में दस लाख से अधिक ट्रैक्टरों, लगभग ४ लाख अनाज-कम्बाइनों तथा दूसरी बहुत-सी मशीनों और ढेरों साज़-सामान की व्यवस्था करनी होगी। कोलख़ोज़ों और सोवख़ोज़ों को उपलब्ध विद्युत्-शक्ति की क्षमताएं प्रायः दूनी कर दी जायेंगी।

समस्त कोलख़ोज़ों को बिजली सपलाई करने का कार्य १९६५ तक पूरा हो जायेगा जबकि सोवख़ोज़ों में यह कार्य बहुत पहले ही हो चुकेगा। देहातों में कोई चार गुनी अधिक विद्युत्-शक्ति की खपत होगी जिससे कृषि-उत्पादन के व्यय में १९ अरब रूबल से भी अधिक की कमी हो जायेगी। इससे कोलख़ोज़ गांवों का सांस्कृतिक स्तर ऊंचा होने के साथ ही साथ जन जीवन भी उत्कृष्ट बनेगा।

कृषि के सबसे महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है—श्रम-उत्पादिता में वृद्धि करना और कृषि-उत्पादन की लागत में कमी करना। यह आवश्यक है कि सकल उत्पादन में वृद्धि की जायं और साथ ही साथ श्रम और उत्पादन पर होनेवाले खर्चे घटाये जायं।

आज कोलखोज़ सशक्त और प्राविधिक दृष्टि से सुसज्जित हैं तथा उनके कर्मचारी प्रशिक्षित हैं। ऐसी अवस्था में आगामी सात वर्षों में श्रम उत्पादिता बढ़ सकती है और उत्पादन-लागत घट सकती है।

हमारा मशीन-उद्योग कृषि को पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी मशीनें सप्लाई करता रहेगा। फलतः कम श्रम और कम खर्च से कोलखोज़ और सोवखोज़ अपने उत्पादन बढ़ा सकेंगे। एतदर्थ हमें ऐसी ऐसी मशीनों के निर्माण की गति बढ़ानी चाहिए जिनसे कपास, मीठी चुक़न्दर, आलू समेत हर तरह की तरकारियों और अन्य फ़स्लों की खेती सर्वांगीण रूप से यन्त्रीकृत हो जाय।

पशुपालन के क्षेत्र में श्रमसाध्य कार्य मशीनों से कराने में हम पिछड़े हुए हैं। हमें चाहिए कि यह पिछड़ापन दूर करें, यातायात सुविधाओं का काफ़ी विस्तार करें और शक्तिशाली ढुलाई-मशीनें, तेज़ चलनेवाले ट्रैक्टर तथा तरह तरह के ट्रैलर और स्वतः माल उतारनेवाली गाड़ियां बनायें। अब समय आ गया है जब हमें मिले-जुले चारों की राज्य और अन्तर-कोलखोज़ीय फ़ैक्ट्रियों का निर्माण करके इन चारों को पैदा करने की समस्या हल करनी चाहिए। हमें भूमि को कृषि-योग्य बनाने की अधिकाधिक मशीनों, लदाई और उतराई के कामों में मशीनों के अधिक प्रयोग और जीर्णक, चूना तथा अन्य स्थानीय खादों के संचय के लिए मशीनों का अधिकाधिक उत्पादन करना चाहिए।

इन कार्यों के साथ ही साथ, कोलखोज़ों और सोवखोज़ों की मौजूदा मशीनों और ट्रैक्टरों का अधिक कुशलता के साथ प्रयोग करना चाहिए, कोलखोज़ों और सोवखोज़ों की मांग की पूर्त्ति के लिए मशीनी पुर्ज़ों का

उत्पादन बढ़ाना चाहिए और मशीनों की मरम्मत की क़िस्म हर सम्भव तरीक़े से सुधारनी चाहिए।

साथियो, केन्द्रीय समिति के दिसम्बर के पूर्णाधिवेशन में कोलख़ोज़ों के चेयरमैनों, सोवख़ोज़ों के मैनेजरों, मेकैनिकों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों तथा पार्टी और सोवियतों की संस्थाओं के अधिकारियों ने कृषि समस्याओं पर जो विचार-विनिमय किया था उससे निश्चित रूप से पता चल गया था कि हर जनतंत्र, प्रदेश, क्षेत्र, हल्का, हर कोलखोज़ तथा सोवख़ोज़ कृषि-पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने में समर्थ है।

संघीय जनतंत्रों की कम्यूनिस्ट पार्टियों की केन्द्रीय समितियों, क्षेत्रीय तथा प्रदेशीय पार्टी समितियों के पूर्णाधिवेशनों और पार्टी और फ़ार्मिंग ऐक्टिव की मीटिंगों में केंद्रीय समिति के दिसम्बर के पूर्णाधिवेशन के प्रस्ताव पर व्यापक विचार-विनिमय हुआ था और उसके निश्चयों का अनुमोदन किया गया था। साथ ही गणनाओं और उपलब्ध क्षमताओं के ब्योरों के आधार पर कई चीज़ों का, और ख़ासकर पशुजन्य पदार्थों का, उत्पादन बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी ली गयी थी।

पूर्णाधिवेशन के निश्चयों पर होनेवाली बहसों के दौरान में कोलख़ोज़ के किसान, सोवख़ोज़ के मज़दूर और कृषि विशेषज्ञ ऐसी ऐसी सम्भावनाओं को प्रकाश में ला रहे हैं जिनसे यदि उनका बुद्धिमानी से उपयोग किया जाय तो, अनाज, मांस तथा अन्य पदार्थों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य – मात्रा और निश्चित अवधि की दृष्टि से – पूरे करने, बल्कि उनसे भी आगे बढ़ जाने में, मदद मिलेगी।

हमें अभी से अपनी सफलताओं के लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं। उदाहरणार्थ र्याज़ान प्रदेश के कोलख़ोज़ों और सोवख़ोज़ों ने अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ली है कि इस वर्ष में ही वे १९५८ की अपेक्षा ३.८ गुना मांस अधिक पैदा करेंगे। स्तवरोपोल क्षेत्र और रोस्तोव प्रदेश के कोलख़ोज़ों और सोवख़ोज़ों ने निश्चय किया है कि वे मांस का उत्पादन क्रमशः ढाई गुना और दुगुना कर दिखायेंगे। मास्को प्रदेश-भर में यह निश्चय किया

गया है कि प्रति १०० हेक्टेयर कृषिभूमि में मांस का उत्पादन ७० सेन्टनर तक हो जायेगा और १९५८ की अपेक्षा राज्य को दूना मांस उपलब्ध किया जायेगा। क्रास्नोदार क्षेत्र में प्रति १०० हेक्टेयर कृषिभूमि में ८४ सेन्टनर मांस का उत्पादन किया जायेगा और कोलखोज़ों तथा सोवखोज़ों में मांस में १५० प्रतिशत से ज़्यादा की वृद्धि की जायेगी।

आगामी कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर खेती की पैदावार बढ़ाने की दिशा में की जानेवाली कार्यवाहियों की रूप-रेखा उक्रइन, बेलोरूस, कज़ाखस्तान और अन्य जनतंत्रों की कम्यूनिस्ट पार्टियों के अधिवेशनों और प्रदेशीय एवं क्षेत्रीय पार्टी कान्फ्रेंसों द्वारा उस समय तैयार की गयी थी जब उन्होंने केन्द्रीय समिति के दिसम्बर के पूर्णाधिवेशन के निश्चयों और लक्ष्य के आंकड़ों पर विचार-विनिमय किया था। उक्रइन की कम्यूनिस्ट पार्टी के अधिवेशन ने पूरे उत्साह के साथ जनतंत्र के अग्रगामी कोलखोज़ों, सोवखोज़ों और हल्कों का उनके इस निश्चय पर हौसला बढ़ाया था कि वे आगामी पांच वर्षों में प्रति १०० हेक्टेयर कृषिभूमि में कम से कम १०० सेन्टनर मांस (बूचड़ वज़न में) का उत्पादन करेंगे और मांस के उत्पादन में सं० रा० अ० के बराबर आ जाने के संबंध में कुछ अग्रगामी कोलखोज़ों के आह्वान में अपना भी योग देंगे। बेलोरूस की कम्यूनिस्ट पार्टी के अधिवेशन ने यह निर्णय किया था कि इस वर्ष कोलखोज़ों और सोवखोज़ों में मांस का उत्पादन दूना किया जाय।

हमें विश्वास है कि ऐसा बीड़ा उठानेवाले लोग हिसाब लगाना और अपना वचन निभाना जानते हैं। पार्टी संगठनों का कर्त्तव्य है कि वे निश्चित लक्ष्यों के लिए काम करने के निमित्त जनता को संघटित करें।

मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि उत्पादन को कई गुना बढ़ाने की प्रतिज्ञाएं किसी भी दशा में हमारी समस्त क्षमताओं की द्योतक नहीं होतीं। कुछ अग्रगामी कोलखोज़ों और सोवखोज़ों ने मांस तथा अन्य कृषि-पदार्थों के उत्पादन में सं० रा० अ० के बराबर आ जाने का जो नारा बुलन्द किया है उसे कार्यरूप देने में प्रत्येक जनतंत्र, क्षेत्र, प्रदेश,

हल्का और कोलखोज़ तथा सोवखोज़ अपना जो भी योग देगा उसका प्रति १०० हेक्टेयर कृषिभूमि उत्पादन के रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

कृषि की समस्त शाखाओं में और भी अधिक प्रगति करने के लिए यह ज़रूरी है कि उपयुक्त कर्मचारियों – विशेष रूप से कोलखोज़ों के चेयरमैनों, सोवखोज़ों के मैनेजरों, ब्रिगेड-लीडरों और फ़ार्मों के व्यवस्थापकों – का, जो जनता को संघटित कर सकते हैं और उसका पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं, क़ायदे से निर्वाचन किया जाय और उन्हें उचित काम दिया जाय।

कोलखोज़ और सोवखोज़ तथा ब्रिगेड और फ़ार्म १९५९-१९६५ में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए सम्प्रति निश्चित योजनाएं बना रहे हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी का सदा से यह विश्वास रहा है कि आर्थिक योजनाएं तैयार करना जनता का रचनात्मक कार्य है। कोलखोज़ों और सोवखोज़ों को ऐसी ऐसी योजनाएं तैयार करने में पूरी पूरी सहायता दी जानी चाहिए, जिनमें सामाजिक अर्थ-व्यवस्था के अधिकाधिक विकास की, और कृषि-उत्पादन में वृद्धि की, समस्त क्षमताओं का ध्यान रखा गया हो।

हमें यह विश्वास है कि हमारे कोलखोज़ों के किसान, सोवखोज़ों के श्रमिक और विशेषज्ञ कृषि के निर्धारित लक्ष्यों को न सिर्फ़ पूरा ही करेंगे अपितु उनसे आगे भी बढ़ जायेंगे **(देर तक तालियां)।**

बुनियादी निर्माण-कार्य और उत्पादक शक्तियों का वितरण

साथियो, उद्यमों के नव-निर्माण और पुनर्निर्माण में मूल पूंजी-विनियोजन विस्तृत समाजवादी पुनरुत्पादन की तीव्र गति का आधार होता है। आगामी सात वर्षों में राज्य का मूल पूंजी-विनियोजन लगभग २० खरब रूबल का हो जायेगा। यदि हम इसमें अकेन्द्रित निधियों द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता से किये गये निर्माणों, कोलखोज़ों के मूल पूंजी-विनियोजनों और जनता द्वारा लगी धनराशि जोड़ दें तो कुल मूल

पूंजी-विनियोजन कोई ३० खरब रूबल का हो जायेगा। **इसके माने यह हैं कि सात वर्षों में लगभग उतनी ही पूंजी लगायी जायेगी जितनी कि पिछले समस्त सोवियत वर्षों में लगायी गयी थी (ज़ोर की तालियां)।**

उद्योगों में बुनियादी निर्माण-कार्य बड़ी तेज़ी से किये जायेंगे। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कुल मिलाकर मूल पूंजी-विनियोजनों में ८० प्रतिशत की वृद्धि होगी और उद्योगों में मूल पूंजी-विनियोजन, पिछले सात साल की तुलना में, प्रायः दूना हो जायेगा।

अलग अलग उद्योगों, निर्माण-उद्योगों और यातायात में लगनेवाला मूल पूंजी-विनियोजन निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा प्रदर्शित किया गया है (तुल्य मूल्यों में १०० करोड़ रूबलों में)

	१९५२-१९५८	१९५९-१९६५	१९५२-१९५८ के अनुसार प्रतिशत में वृद्धि
लोहा और इस्पात उद्योग	४०.८	१००	२४५
रसायन उद्योग	१९.९	१००-१०५	५०२-५२८
तेल और गैस उद्योग	७२.२	१७०-१७३	२३५-२४०
कोयला उद्योग	६१.२	७५-७८	१२२-१२७
बिजलीघर, विद्युत् और ताप ग्रिड	७५.१	१२५-१२९	१६६-१७२
मशीन उद्योग	६५.५	११८	१८०
इमारती लकड़ी, कागज़ और काठ के उद्योग	२५.३	५८-६०	२२९-२३७
हल्के उद्योग और खाद्य उद्योग	४०	८०-८५	२००-२१२
निर्माण उद्योग और निर्माण-सामग्री उद्योग	६१.५	११०-११२	१७९-१८२
यातायात और संचार	१०७.४	२०९-२१४	१९५-१९९
रेल यातायात	५९.३	११०-११५	१८५-१९४

राज्य और कोलखोज़ कृषि के क्षेत्र में जो मूल पूंजी लगायेंगे वह लगभग ५०० अरब रूबल हो जायेगी, अर्थात् पिछले सात वर्षों की तुलना में क़रीब दूनी।

योजना में मूल पुनर्निर्माण, वर्तमान स्थापनों के विस्तार और उनकी प्राविधिक पुनःसज्जा तथा साज-सामानों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की व्यवस्था है। इस व्यवस्था से, बहुत-सी दशाओं में, उत्पादन तेज़ होगा और नये नये कारख़ाने बनाने की तुलना में व्यय और सामग्री काफ़ी कम लगेगी।

पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक साधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए योजना में यह निश्चय किया गया है कि आगामी सात वर्षों में समस्त मूल पूंजी-विनियोजनों की ४० प्रतिशत से भी अधिक धनराशि इन्हीं क्षेत्रों में लगायी जायेगी।

सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करनेवाली सांस्कृतिक संस्थाओं और स्थापनों, तथा मकानों के निर्माण के लिए बहुत बड़ी धनराशि निर्दिष्ट की गयी है। आगामी सात वर्षों में मकानों और नागरिक सुविधाओं पर अकेले राज्य-निधि से ही ३७५-३८० अरब रूबल तक ख़र्च किये जायेंगे जबकि पिछले सात वर्षों में इस मद में २१४ अरब रूबल ख़र्च किये गये थे; स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सांस्कृतिक तथा चिकित्सा संबंधी स्थापनों पर ८० अरब रूबल से अधिक (पिछले सात वर्षों में यह धनराशि ४६ अरब थी) ख़र्च किये जायेंगे। छात्रावास-स्कूलों और शिशु-सदनों के निर्माण में बड़ी बड़ी धनराशियां ख़र्च की जायेंगी।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की समस्त शाखाओं में संयोजित बुनियादी विकास कार्यों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि निर्माण में औद्योगिक प्रणालियों का और भी अधिक व्यापक उपयोग किया जाये, ढांचा खड़ा करने के सारे कार्य निरन्तर मशीनों द्वारा किये जायें और भवन और दूसरे निर्माण, कारख़ानों में पहले से ढले हुए बड़े बड़े ब्लॉकों, हिस्सों और अन्य सामानों से बनाये जायें।

निर्माण-कार्यों को शीघ्र से शीघ्र औद्योगिक ढंग से सम्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर फट्टेदार परतें जमाने या स्थिर ढांचों में डालकर रीइनफ़ोर्स्ड कांक्रीट के पैनेल बनाये जायें। इन बड़े बड़े पैनेलों से खड़े किये गये मकान निश्चय ही बड़े लाभदायक होते हैं। अचल ढांचों में डालकर बनाये गये हिस्सों को जोड़-जाड़कर निर्मित किये गये बड़े बड़े पैनेलों वाले मकानों के निर्माण में काम आनेवाले ढांचे बनाने में ईंटों की दीवालों वाले मकानों की अपेक्षा प्रति १००० वर्ग मीटर फ़र्श-क्षेत्रफल में एक-तिहाई से कम श्रम-व्यय लगता है। निर्माण में श्रम-व्यय आधा कम हो जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि बड़े बड़े पैनेलों वाले मकानों में सीमेन्ट का ख़र्च ईंटों की दीवालों वाले मकानों के लिए आवश्यक सीमेन्ट के ख़र्च से अधिक नहीं होता जबकि धातु का व्यय अपेक्षाकृत कम पड़ता है। इन पैनेलों के मकान ईंटों के मकानों की तुलना में ५० प्रतिशत हल्के होते हैं।

बड़े बड़े पैनेलों से बने हुए मकान सस्ते भी होते हैं और प्राविधिक दृष्टि से अच्छे भी। साथ ही उत्पादन-साधनों की व्यवस्था के व्यय भी आधे हो जाते हैं। बड़े बड़े पैनेलों से बने मकानों के फ़ायदों का पूरा पूरा उपयोग तभी किया जा सकता है जब मकानों के हिस्से बड़े पैमाने पर कारख़ानों में तैयार किये जायें और निर्माण-स्थलों पर ये मकान सिलसिलेवार जोड़े जाते रहें। यही कारण है कि योजना में १९६५ में बड़े बड़े पैनेलों द्वारा गृह-निर्माण का वार्षिक परिमाण ढाई करोड़ वर्ग मीटर फ़र्श-क्षेत्रफल निर्दिष्ट किया गया है।

सम्प्रति निर्माण सामग्री-उद्योग साज-सामान संबंधी परीक्षण कर रहा है, औद्योगिक प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप दे रहा है और पतली दीवालों वाले पहले से ही सुदृढ़ किये गये पैनेल बनाने के लिए रोलिंग की भिन्न भिन्न प्रणालियों का परीक्षण कर रहा है। इन पैनेलों से औद्योगिक, [illegible] तथा अन्य निर्माण-कार्यों में, जहां बड़े बड़े अन्तर

और भार आवश्यक होते हैं, बड़े बड़े पैनेलवाले ढांचों का प्रयोग सम्भव हो सका है।

रीइनफ़ोर्स्ड कांक्रीट के सामानों के उत्पादन बढ़ाने के साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि पहले से ही सुदृढ़ किये गये और पतली दीवालों वाले संरचनात्मक भागों और हल्के कांक्रीट की बनी चीज़ों का व्यापक उपयोग किया जाये इसलिए कि इनके उपयोग से धन की काफ़ी बचत होती है। इन चीज़ों में धातुओं की खपत ४०-५० प्रतिशत कम होती है और इमारतों का भार भी हल्का रह जाता है। ऐसबेस्टस-सीमेन्ट की चीजों और हिस्सों का प्रयोग भी निर्माण की एक उन्नत पद्धति है।

बड़े पैमाने पर रीइनफ़ोर्स्ड कांक्रीट के उत्पादन और उससे बने निर्माणोपयोगी नये नये उपकरण, तथा भारी भारी सामानों को ऊपर उठाने की सुविधाएं उपलब्ध होने से छतों की डिज़ाइनों की समस्या एक नये ढंग से हल हो सकती है, अर्थात् इस प्रकार कि छतों के विशेष ऊपरी भागों के प्रयोग की वर्तमान पद्धति समाप्त कर दी जाये और छत के ऊपरी भाग को रीइनफ़ोर्स्ड कांक्रीटवाले भीतरी भाग के साथ जोड़ दिया जाये। व्यवहार में इस व्यवस्था का प्रयोग किया जा चुका है और छत के ऊपरी और भीतरी भागों को उपर्युक्त ढंग से जोड़कर कई मकान बनाये भी जा चुके हैं। इस क्षेत्र में छत-निर्माण की उन नयी नयी पद्धतियों का व्यापक रूप से प्रयोग होना चाहिए जिनमें धातु की बचत होने के साथ ही साथ मरम्मत भी नहीं करनी पड़ती। सम्भवतः हमें कोई ऐसा विशेष निर्णय भी अंगीकार करना होगा जिसमें उक्त व्यवस्था को कार्यान्वित करने की तिथियां नियत की जायें, ताकि अन्ततः दक़ियानूसी विचारों वाले लोग भी नये ढंग से कार्य करने के लिए मजबूर हों।

निर्माण-कार्यों को औद्योगिक ढंग से सम्पन्न करने के लिए सीमेन्ट के उत्पादन में अधिक वृद्धि करने और उसकी क़िस्म में सुधार करने की आवश्यकता है। आगामी सात वर्षों में सीमेन्ट के उत्पादन में ५ करोड़

टन की वृद्धि होगी। सं० रा० अ० में सम्प्रति सीमेन्ट के उत्पादन का प्राय: यही स्तर है। योजना में अन्य निर्माण-साधनों विशेषकर ताप इन्सुलेशन, प्लास्टिक्स और संश्लिष्ट रालों से बनी सामग्रियों और चीज़ों और सफ़ाई के साज़-सामानों के उत्पादन में वृद्धि करने की व्यवस्था है।

निर्माण-कार्य संबंधी सामानों और संरचनोपयोगी चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि निर्माण उद्योग और निर्माण-सामग्री उद्योग में विकास किया जाये। प्रत्येक निर्माण-स्थल पर निर्माण संबंधी प्राय: आदिकालीन जैसे उत्पादन-साधनों की व्यवस्था बन्द होनी चाहिए और जिस आर्थिक क्षेत्र अथवा स्थान पर निर्माण-कार्य हो रहे हों वहां जिलेवार निर्माण-उद्योग-स्थापनों की व्यवस्था करने की पद्धति काम में लायी जानी चाहिए जिससे कि वहां की सारी ज़रूरतें पूरी हो जायें।

निर्माण के छोटे छोटे संगठनों को मिलाकर बड़े बड़े संगठन बनाने और उनमें विशेषीकरण की व्यवस्था जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे निर्माण की गति बढ़ेगी और लागत में कमी आयेगी। लागत में कमी और निर्माण तथा ढांचे बिठाने के कार्यों की क़िस्म अभी तक बड़े महत्त्व की समस्याएं बनी हुई हैं। योजना में, १९५८ की तुलना में, आगामी सात वर्षों में कुल मिलाकर निर्माण की लागत में कम से कम ६ प्रतिशत और गृह-निर्माण की लागत में १४ प्रतिशत की कमी किये जाने की व्यवस्था है।

साथियो, निर्माण-स्थलों पर बेकार पैसा बरबाद करने की दूषित प्रणाली अब समाप्त होनी चाहिए। बड़े बड़े तथा शीघ्र पूरे होने के लिए निर्दिष्ट निर्माण-स्थलों में मूल पूंजी, सामग्री तथा श्रम के साधनों को केन्द्रित किया जाना चाहिए। जब तक पूरी पूरी तैयारी न कर ली जाये, डिज़ाइनें न तैयार हो जायें और निर्माण को शीघ्र समाप्त करने की अन्य परिस्थितियां तथा निर्माण की आवश्यक सुविधाएं न प्राप्त हो जायें, तब तक नये निर्माण-कार्य में हाथ न लगाना चाहिए। संयोजन एवं

अर्थ-व्यवस्था से संबद्ध हमारी संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में मूल पूंजी लगाते समय वे सावधानी बरतें और किफ़ायत का ध्यान रखें।

आगामी सात वर्षों में जिस अभूतपूर्व पैमाने पर निर्माण-कार्य होनेवाले हैं उनके लिए **उत्पादक शक्तियों के वितरण** पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

पार्टी की २० वीं कांग्रेस ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि विशाल परिमाण में उपलब्ध पूर्वी क्षेत्रों के कच्चे माल और शक्ति के साधनों का उपयोग देश की अर्थ-व्यवस्था में किया जाये। इस निश्चय को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। देश का लोहे और इस्पात का तीसरा केन्द्र साइबेरिया और कज़ाख़स्तान में बन रहा है और दुनिया के सबसे बड़े पन-बिजलीघर अंगारा और येनिसेई में। परती और अछूती ज़मीनों को कृषियोग्य बनाने के प्रयत्नों में जो सफलताएं मिली हैं उन्हें पुष्ट किया जा रहा है।

लक्ष्य के जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनसे पता चलता है कि इन समस्याओं को हल करने में हम बहुत आगे बढ़ जायेंगे। १९६५ में, कोयले के उत्पादन में पूर्वी क्षेत्रों का अनुपात ५० प्रतिशत, इस्पात में ४८ प्रतिशत, शुद्ध किये गये तांबे में ८८ प्रतिशत, अल्युमिनियम में ७१ प्रतिशत, सीमेन्ट में ४२ प्रतिशत, विद्युत्-शक्ति में ४६ प्रतिशत और काग़ज़ में ३२ प्रतिशत बढ़ेगा। जिन स्थानों पर पेड़ काटे जाते हैं वहां से लायी जानेवाली इमारती लकड़ी में भी ५२ प्रतिशत की वृद्धि होगी। रसायन, तेल शुद्ध करने और अलौह धातुओं के उद्योगों का भी विकास किया जा रहा है।

जिस विशाल पैमाने पर निर्माण के नये नये कार्य किये जायेंगे उनसे पूर्वी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। कुस्तनाई, पवलोदार-एकिबास्तुज़, अचिंस्क-क्रास्नोयार्स्क, ब्रात्स्क-ताइशेत आदि बड़े

बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण से सोवियत पूर्व की उत्पादक शक्तियों के विकास को काफ़ी बल मिलेगा।

पूर्व में एक नये अन्नोत्पादक केन्द्र का निर्माण हो जाने से कई जनतंत्रों और क्षेत्रों में कृषि का मौलिक पुनर्निर्माण आरम्भ होना और खेतों की फ़स्लों और पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि के लिए समृद्ध प्राकृतिक और आर्थिक साधनों का और भी अधिक उपयुक्त प्रयोग किया जाना सम्भव हो सका है।

उदाहरणार्थ, पहले हमें सारे देश में अनाज का संचय करना पड़ता था. लेकिन अब रूसी संघ के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों, बाल्टिक के जनतंत्रों, बेलोरूस के बहुत-से हल्कों और पोलेस्ये के उक्रइनी भाग में कुछ समय के लिए अन्न की ख़रीदारी बन्द करना सम्भव हो गया है। अब ये क्षेत्र दूध, बेकन और औद्योगिक फ़स्लों में विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये क्षेत्र इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए बड़े अनुकूल हैं। बेशक जब भविष्य में इन क्षेत्रों को अनाज की फ़स्लों के लिए आवश्यक मात्रा में खनिज खादें मिलने लगेंगी और जब उनके अन्नोत्पादन में वृद्धि हो जायेगी तो अन्य क्षेत्रों और जनतंत्रों की तुलना में, वहां अनाज सस्ता हो जायेगा। उस समय इन क्षेत्रों में भी अनाज ख़रीदना लाभदायक होगा।

अब हम इस स्थिति में हैं कि ट्रान्स-काकेशियाई और मध्य एशियाई जनतंत्रों में अनाज की ख़रीद कम कर सकते हैं। जैसे ही जैसे अन्य क्षेत्रों के अन्नोत्पादन में वृद्धि होती जायेगी वैसे ही वैसे हम उपर्युक्त जनतंत्रों में अनाज की ख़रीद बन्द करते जायेंगे ताकि वहां कपास, चाय, अंगूर और फलों – जिनमें सन्तरा, नींबू, नारंगी भी शामिल हैं – की बहुमूल्य फ़स्लों में तीव्र गति से विकास किया जा सके।

उक्रइन, उत्तरी काकेशिया और केन्द्रीय काली मिट्टीवाले क्षेत्र बहुत समय तक हमारे देश के मुख्य अन्न-भंडार रहे हैं। अब वहां अनाज की खेती कुछ कम कर दी गयी है, फलतः उन्हें अपने कोलखोज़ों और सोवखोज़ों

में पशुपालन में तथा औद्योगिक फ़स्लों, मुख्यतया मीठी चुक़न्दर, के उत्पादन में विशेषीकरण करने का अवसर मिला है।

हमें चाहिए कि हम अपने देश के पूर्वी क्षेत्रों की उत्पादक शक्तियों का सर्वाधिक विकास करने के साथ साथ सोवियत संघ के यूरोपीय भाग में उत्पादन-वृद्धि की सम्भावनाओं का भी पूर्णतम उपयोग करें। इस संबंध में चालू औद्योगिक स्थापनों की क्षमताओं के सदुपयोग और विस्तार, भूमि के सदुपयोग, रिज़र्वों से संचित साधनों का पूर्ण लाभ उठाने, क्षेत्रों के विशेषीकरण के विकास और आर्थिक संबंधों के अभिनवीकरण पर विशेष बल दिया जाता है।

आगामी सात वर्षों में सोवियत संघ के यूरोपीय भाग के कच्चे माल और विद्युत् शक्ति के साधनों को काफ़ी सुदृढ़ बनाया जायेगा। तेल और गैस के अति समृद्ध ज़ख़ीरों के कारण ईंधन की प्राप्ति का तो सन्तुलन ही बदल गया है तथा हज़ारों किलोमीटर दूर दूर तक भेजे जानेवाले कुज़बास और कराग़न्दा के कोयले की डेलीवरी रोकना सम्भव हो सका है।

बहुत-से क्षेत्रों में, मुख्यतया पोवोलज्ये में, एक सशक्त कार्बनिक संश्लेषण उद्योग की स्थापना की जायेगी जिसमें कच्चे माल के रूप में तेल और गैस का इस्तेमाल किया जायेगा। सोवियत संघ के यूरोपीय भाग के सभी मुख्य आर्थिक क्षेत्रों में तेल साफ़ करने के उद्योग पनप रहे हैं। कुर्स्क मैगनेटिक अनामली और क्रिवोई रोग लौह-खनिज क्षेत्र का व्यापक इस्तेमाल किये जाने से मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में लोहे और इस्पात का उद्योग काफ़ी बढ़ जायेगा। स्तालिनग्राद, क्रेमेनचुग तथा अन्य पन-बिजलीघरों के चालू हो जाने से वोल्गा, द्नेपर तथा अन्य नदियों के जलशक्ति-साधनों का और भी अधिक उपयोग किया जायेगा।

क्षेत्रवार कृषि-उत्पादन के विशेषीकरण को सुधारने, भरपूर खेती करने तथा समस्त फ़स्लों की पैदावार और पशुपालन की उत्पादिता में वृद्धि करने के द्वारा कृषि के प्राकृतिक और श्रम साधनों का पूर्णोपयोग

करने की भी व्यवस्था की गयी है। बड़े बड़े औद्योगिक केन्द्रों की आबादी को तरकारियां तथा गव्य पदार्थ आदि की सप्लाई करने के निमित्त बड़े बड़े उपनगरीय फ़ार्मों की स्थापना की जायेगी।

आगामी सात वर्षों में देश के विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनसे राष्ट्रीय आर्थिक संयोजन में सुधार अत्यावश्यक हो जाता है। हमारी योजना में जनतंत्रों और बड़े बड़े आर्थिक क्षेत्रों के और अधिक विशेषीकरण, और सुसम्बद्ध आर्थिक विकास, की व्यवस्था होनी चाहिए।

आर्थिक प्रशासन क्षेत्रों की स्थापना से स्वयं इन क्षेत्रों के भीतर और परस्पर क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंध सुदृढ़ हुए हैं और इससे देश की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। किन्तु सुसम्बद्ध अर्थ-व्यवस्था का यह ग़लत, संकुचित क्षेत्रीय अर्थ भी लगाया जाता है कि वह दीवारबंद अर्थ-व्यवस्था है। राज्य के हितों के विरुद्ध चालू की जानेवाली ऐसी प्रवृत्तियों का साहस के साथ प्रतिरोध करना आवश्यक है।

सोवियत संघ बहु-जातीय समाजवादी राज्य है जिसका आधार उन समान अधिकार प्राप्त जनताओं की पारस्परिक मित्रता है, जो एक ही आकांक्षा से बंधी हुई हैं—कम्यूनिस्ट निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना। **लेनिन की जातीय नीति सारी जनता को अपनी चतुर्दिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए बड़े बड़े अवसर प्रदान करती है। हमारी योजनाओं में इसी नीति की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है (तालियां)।** इस बात की पुष्टि एक बार फिर १९५९-१९६५ के राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लक्ष्य के आंकड़ों से होती है। इन आंकड़ों में समस्त सोवियत जनतंत्रों के विशाल आर्थिक विकास की व्यवस्था है। हर जनतंत्र पहले उन शाखाओं का विकास करेगा जिनके लिए वहां सबसे अनुकूल प्राकृतिक और आर्थिक परिस्थितियां उपलब्ध हैं।

रिपोर्ट की थीसिस में समस्त संघीय जनतंत्रों में आर्थिक विकास के मुख्य सूचनांक दिये गये हैं, जिनका इन जनतंत्रों की श्रमिक जनता ने पूरा पूरा समर्थन और अनुमोदन किया है।

सप्तवर्षीय योजना में एक ओर तो प्रत्येक जनतंत्र के साधनों के सबसे कुशल उपयोग की व्यवस्था है और दूसरी ओर अलग अलग जनतंत्रों और सम्पूर्ण सोवियत संघ के हितों का समुचित समन्वय होता है। योजना में अन्तर-जनतंत्रीय आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने और समाजवादी श्रम-वितरण को व्यापक बनाने की व्यवस्था है। समाजवादी जन-जातियों का साहचर्य बहु-जातीय समाजवादी राज्य की बढ़ती हुई शक्तियों और बल का स्रोत है। हमारी पार्टी ने जनता में सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना भरी है और उसने महान राष्ट्र होने की अंधराष्ट्रीयता और संकुचित इलाक़ापरस्ती, दोनों के विरुद्ध सदैव बड़ी निर्दयता से मोर्चा लिया है। लक्ष्य यह है, कि श्रमिक जनता में सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयता और सोवियत देशभक्ति की और भी अधिक भावना भरी जाये। कम्यूनिस्ट पार्टी जनता की पारस्परिक मित्रता को निरन्तर सुदृढ़ करते रहना अपना पवित्र कर्त्तव्य समझती है क्योंकि यही भावना सोवियत संघ के बल और अजेय शक्ति की आधार-शिला है (**देर तक तालियां**)।

* * *

साथियो, आगामी सात वर्षों में औद्योगिक, कृषि और यातायात की योजनाओं तथा निर्माण-योजना की पूर्त्ति तभी सम्भव है जब प्रविधि का स्तर काफ़ी ऊंचा हो और **सामाजिक श्रम-उत्पादिता** बढ़े – यह उत्पादिता विस्तृत समाजवादी पुनरुत्पादन और संचय का प्रमुख स्रोत और रहन-सहन के स्तरों की वृद्धि का आधार है।

सप्तवर्षीय अवधि में प्रति व्यक्ति श्रम-उत्पादिता में उद्योग में ४५-५० प्रतिशत, निर्माण में ६०-६५ प्रतिशत, रेलवे यातायात में ३४-३७ प्रतिशत और सोवख़ोज़ों में ६०-६५ प्रतिशत – वृद्धि होनी चाहिए। कोलख़ोज़ों में तो यह वृद्धि प्राय: दूनी होगी। कार्य-दिवस में कमी हो जाने के कारण घंटेवार उत्पादन और भी अधिक बढ़ जायेगा। १९६५ में उच्च श्रम-उत्पादिता औद्योगिक उत्पादन में तीन-चौथाई वृद्धि का कारण होगी।

सामाजिक उत्पादन में विस्तार होने के साथ सामग्री और श्रम में बचत का महत्त्व भी बढ़ जायेगा। इस समय हमें अपने समस्त आर्थिक संचयों को सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है। सात वर्षों में उद्योग, निर्माण, यातायात और सोवख़ोज़ों के उत्पादन-व्ययों में लगभग ८५० अरब रूबल की कमी की जानी चाहिए। पता है यह राशि कितनी होती है? सात वर्षों में राज्य द्वारा लगायी जानेवाली कुल मूल पूंजी की लगभग आधी।

संयोजित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समस्त आर्थिक क्षेत्रों के कार्यों में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है।

हमारे देश में, जहां भिन्न भिन्न उद्यमों में उनके निजी संचय विस्तृत पुनरुत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं, किफ़ायत की योजनाओं को बड़ा महत्त्व दिया गया है। पार्टी ने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि अर्थ-व्यवस्था को सबसे युक्तिसंगत तरीक़े से संचालित करने की आवश्यकता है। आज **जब उत्पादन-व्यय में एक प्रतिशत कमी करने से १२ अरब रूबल से अधिक की बचत होती है – सात वर्षों के अन्त में यह बचत २१ अरब रूबल वार्षिक होगी – तो उत्पादन-व्यय कम करने के प्रयासों और किफ़ायत बरतने का तो बहुत ही बड़ा महत्त्व है।**

अतएव यह आवश्यक है कि जन सम्पत्ति के संबंध में होनेवाली सभी प्रकार की दुर्व्यवस्थाओं, फ़िज़ूलख़र्ची और उपेक्षा के ख़िलाफ़ सख़्त क़दम उठाया जाये। हमें चाहिए कि हम औद्योगिक अधिष्ठापनों और निर्माण-स्थलों की गुणात्मक क्षमताएं बढ़ाने – विशेष रूप से लागत में कमी करने और उत्पादित वस्तुओं की क़िस्म सुधारने – के लिए मैनेजरों पर अधिक उत्तरदायित्व डालें। सरकारी सहायता के बिना किये जानेवाले कार्यों को उद्योग, निर्माण, यातायात और कृषि-क्षेत्रों में और भी अधिक सुदृढ़ रूप देना चाहिए।

सप्तवर्षीय योजना कुछ ऐसी बनायी गयी है कि उसे बिना अधिक खींचतान के कार्यान्वित किया जा सकता है। ऐसा किया क्यों गया था?

इसलिए कि यदि हमारी योजना खींचतानवाली हुई तो इस बात की सम्भावना बनी रहेगी कि उसके कुछ लक्ष्य पूरे ही न हों और अर्थ-व्यवस्था की कुछ शाखाओं को—कच्चे माल, सप्लाई और साज-सामान के रूप में—उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें न मिलें फलत: उनके कामों में रुकावट पड़ जाये। और इस सब का नतीजा यह होगा कि कारख़ानों और फ़ैक्ट्रियों में उनकी क्षमता से कम काम होगा, काम का समय ख़ाली जायेगा और इन बुराइयों के और भी जो परिणाम हो सकते हैं वे होंगे। अर्थशास्त्री ऐसी व्यवस्था को असन्तुलन कहते हैं।

सप्तवर्षीय योजना इस ढंग से बनायी जा रही है कि उसमें उपर्युक्त दोष न रहें। योजना में निर्दिष्ट लक्ष्यों से आगे निकल जाने से हमें अतिरिक्त रिज़र्व बनाने और अतिरिक्त संचय करने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार औद्योगिक अधिष्ठानों के लयबद्ध काम और साज-सामान के सदुपयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होंगी। परिणामत: उद्यमों में काम का समय ख़ाली न जायेगा, श्रम और साधनों का सदुपयोग होगा और क्षमता से कम कार्य करने का दोष दूर होगा। नतीजा यह होगा कि श्रम-उत्पादिता बढ़ेगी और श्रमिकों की कमाई अधिक स्थायी बनेगी।

इस प्रकार राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की सभी शाखाओं के सन्तुलित विकास की अच्छी परिस्थितियां पैदा होंगी। किन्तु यदि योजना में हेर-फेर की गुंजाइश हो और इस हेर-फेर को नज़रन्दाज़ कर दिया जाये तो फिर वह पूरी नहीं हो सकती। हमें सप्तवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करने और उनसे आगे बढ़ जाने के लिए श्रमिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों, वैज्ञानिकों, दफ़्तर के कर्मचारियों, कोलख़ोज़ के कृषकों और सोवख़ोज़ के श्रमिकों को संघटित करना होगा **(तालियां)**।

आज के युग में राष्ट्रीय आर्थिक योजना के निर्दिष्ट लक्ष्यों से एक या दो प्रतिशत आगे बढ़ जाने का क्या अर्थ है?

यह उल्लेखनीय है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (१९३२) में औद्योगिक उत्पादन में एक प्रतिशत वृद्धि के, इस समय के मूल्यों के अनुसार, माने थे ८० करोड़ रूबल, १९५९ में यह राशि ११ अरब रूबल से अधिक और १९६५ में, योजनानुसार, १९ अरब रूबल से अधिक होगी। यदि, उदाहरणार्थ, योजना में निश्चित औसत वार्षिक औद्योगिक वृद्धि (८.६ प्रतिशत) प्रति वर्ष केवल एक प्रतिशत बढ़ा दी जाये तो इसका अर्थ यह होगा कि १९६५ में उद्योग में १३० अरब रूबल से अधिक का उत्पादन और होने लगेगा, अर्थात् सात वर्षों में कुल अतिरिक्त उत्पादन ४४० अरब से भी अधिक का होगा। यदि औसत वार्षिक वृद्धि दो प्रतिशत बढ़ जाये तो १९६५ में अतिरिक्त उत्पादन २६५ अरब रूबल से भी अधिक, और सात वर्षों में ९०० अरब रूबल से भी अधिक का, हो जायेगा। हमें विश्वास है कि कृषि-उत्पादन के और उत्पादन और वितरण के व्ययों में कमी करने के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं हम उनसे आगे बढ़ जायेंगे।

परिणामतः राज्य के पास खरबों रूबलों की अतिरिक्त संचित धनराशि हो जायेगी। यह राशि जनता की भौतिक सुख-सुविधा के लिए सरकार के हाथों में रिज़र्व के रूप में होगी। योजना के लक्ष्यों से बढ़ जाने के फलस्वरूप हमें जितना धन प्राप्त होगा उससे हम मकान, छात्रावास-स्कूल और उपभोक्ता सामानों का उत्पादन करनेवाली फ़ैक्ट्रियों का निर्माण बढ़ा सकेंगे। इस प्रकार हम कृषि की मुख्य शाखाओं के तीव्र विकास में और भी धन लगा सकेंगे। साथ ही हमें समाजवादी भ्रातृ-देशों की सहायता करने का भी अधिक अवसर मिलेगा।

अपने देश के समाजवादी निर्माण के अनुभव, राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता और श्रम-उत्साह से हमारा यह विश्वास जमता है कि हमारी नयी योजना न सिर्फ़ पूरी ही होगी अपितु हम उसके लक्ष्यों से अधिक की प्राप्ति भी करेंगे **(ज़ोर की तालियां)**।

सोवियत जनता के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि

साथियो, सप्तवर्षीय योजना में अर्थ-व्यवस्था की चतुर्दिक शक्तिशाली प्रगति और विशेष रूप से भारी उद्योगों की वृद्धि के आधार पर **जनता के रहन-सहन के स्तर में निरन्तर वृद्धि करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।**

आज की परिस्थितियों में, जब हमारे देश में शक्तिशाली उद्योगों और बड़े पैमाने पर खेतीबारी की व्यवस्था हो चुकी है और उनमें अच्छी प्रगति हो रही है तो निकटतम भविष्य में सोवियत जनता के और भी आराम से रहने-सहने और उसकी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की और भी अधिक पूर्त्ति की गुंजाइश हो गयी है।

सप्तवर्षीय योजना में निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं:

—राष्ट्रीय आय में ठोस वृद्धि और इस आधार पर जनता की वास्तविक आय में उल्लेखनीय बढ़ती;

—पहले की अपेक्षा छोटा कार्य-दिवस और छोटा कार्य-सप्ताह;

—उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि और उनकी क़िस्मों में सुधार;

—बड़े पैमाने पर गृह-निर्माण;

—सार्वजनिक, सांस्कृतिक तथा अन्य नागरिक सेवाओं में काफ़ी अधिक वृद्धि।

समाजवादी समाज में राष्ट्रीय आय की वृद्धि जनता के कल्याण की असली नींव है।

सं० रा० अ० में यद्यपि पूंजीवादी वर्ग देश की जनसंख्या का दशमांश ही है फिर भी वह राष्ट्रीय आय का आधा हिस्सा हड़प ले जाता है। सोवियत संघ में श्रमिक जनता को, उसकी भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए राष्ट्रीय आय का कोई तीन-चौथाई हिस्सा

मिलता है। शेष राष्ट्रीय आय भी श्रमिक जनता की ही है। उसका उपयोग समाजवादी उत्पादन की वृद्धि तथा अन्य सामाजिक आवश्यकताओं के लिए किया जाता है।

१९६५ में सोवियत संघ की राष्ट्रीय आय, १९५८ की तुलना में, ६२-६५ प्रतिशत और, १९४० के युद्धपूर्व-स्तर की तुलना में, लगभग ६ गुनी बढ़ जायेगी। किसी भी पूंजीवादी देश में राष्ट्रीय आय में इतनी अधिक वृद्धि कभी नहीं हुई। बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय से आगामी सात वर्षों में जनता की उपभोग-क्षमता में ६०-६३ प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। जनता की आय भी काफ़ी बढ़ जायेगी।

श्रमिक को धन के रूप में मिलनेवाले पारिश्रमिकों, पेंशनों और आर्थिक सहायता की बढ़ती, तथा सार्वजनिक भोजनालयों में क़ीमतों में कमी आ जाने के फलस्वरूप, सात वर्षों के अन्त में फ़ैक्ट्री और कार्यालय के कर्मचारियों की प्रतिव्यक्ति वास्तविक आमदनियां ४० प्रतिशत बढ़ जायेंगी। हमारी योजना यह है कि कम वेतन पानेवालों का कम से कम वेतन २७०-३५० रूबल प्रतिमास से बढ़ाकर ५००-६०० रूबल प्रतिमास कर दिया जाये। कोलख़ोज़ के किसानों की वास्तविक आमदनियां भी—मुख्यतया कोलख़ोज़ों में सामाजिक उत्पादन में वृद्धि करने से—कम से कम ४० प्रतिशत बढ़ जायेंगी।

सम्प्रति सोवियत संघ में समस्त राष्ट्रीय आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए मुख्यतया समाजवादी स्थापनों की संचित निधियों से ही धन की सहायता दी जाती है। जैसे ही जैसे सप्तवर्षीय योजना में प्रगति होती जायेगी वैसे ही वैसे इन संचित निधियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जायेगी और अन्ततः यही निधियां समाजवादी पुनरुत्पादन में विस्तार, और रहन-सहन के स्तर में और भी अधिक वृद्धि का एकमात्र स्रोत हो जायेंगी।

इन परिस्थितियों में, जनता से लिये जानेवाले टैक्सों की आवश्यकता न रहेगी, उनके वर्ग-महत्त्व की दृष्टि से भी—जैसा कि विगत काल में

जब वे पूंजीपतियों की आमदनियों को सीमित करने के लिए होते थे—और राज्य बजट की आय की दृष्टि से भी, क्योंकि अब भी जनता जो टैक्स देती है वह बजट की आय का केवल ७.८ प्रतिशत अर्थात् एक नगण्य-सा भाग है।

उपर्युक्त कारणों से हम आगामी कुछ वर्षों में जनता को टैक्स देने से मुक्त कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इस बड़े कार्य के लिए आवश्यकता है सभी दृष्टि से अध्ययन करने की और पर्याप्त तैयारियां करने की, ताकि यह व्यवस्था, जनता और राज्य दोनों के हितों पर ध्यान रखते हुए, विवेकपूर्ण ढंग से चालू की जाये।

हमारे देश में पेंशन की व्यवस्था किसी भी पूंजीवादी देश से अच्छी है। सोवियत संघ में फ़ैक्ट्रियों और कार्यालयों के सभी कर्मचारियों को पेंशनें राज्य द्वारा दी जाती हैं। जिन पूंजीवादी देशों में पेंशनें दी जाती हैं वहां पेंशन के धन की व्यवस्था मुख्यतया श्रमिक ही करते हैं क्योंकि अधिकतर उन्हीं के वेतन से कटौतियां करके पेंशन-फ़ंड बनाये जाते हैं।

काम पाने की सामाजिक समस्याएं, नगरों में निरन्तर रहनेवाली बेकारी और देहातों में कृषक-वर्ग की सामूहिक अवनति आदि ऐसी बातें हैं जिनका हल पूंजीवादी व्यवस्था में असम्भव है। समाजवादी समाज में इन बुराइयों का नामोनिशान तक नहीं होता। सात वर्षों में, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में लगे हुए श्रमिकों तथा कर्मचारियों की संख्या में लगभग १ करोड़ २० लाख की वृद्धि और हो जायेगी और उस समय उनकी कुल संख्या ६६५ लाख हो जायेगी।

आप जानते हैं कि सप्तवर्षीय योजना में जनता की सुख-सुविधा के लिए किये जानेवाले अन्य उपायों के साथ साथ वेतनों में वृद्धि किये जाने की भी व्यवस्था है। प्रश्न यह है कि क्या हमें रहन-सहन का स्तर एकमात्र वेतन में वृद्धि और क़ीमतों में कमी करके ही उठाना चाहिए?

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जहां तक वेतन बढ़ाने और क़ीमतें

घटाने का सवाल है पार्टी और सरकार इस दिशा में निश्चित क़दम उठायेंगी। किन्तु यह तो केवल एक रास्ता है। वस्तुतः सोवियत जनता के भौतिक और सांस्कृतिक स्तर इसी बात से निर्दिष्ट नहीं होते कि वेतन के रूप में उन्हें क्या मिलता है या क़ीमतें घट जाने से उन्हें कितना लाभ होता है। यह कहना ग़लत होगा कि अगर आज आप ३० रूबल रोज़ कमाते हैं तो आप समाजवाद की व्यवस्था के अन्तर्गत रहते हैं और कल यदि पांच गुना अधिक कमाने लगें तो कम्यूनिस्ट व्यवस्था के अन्तर्गत आ जायेंगे।

समाजवाद के अधीन जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास मानव की अनेकानेक विविध आवश्यकताओं की पूर्त्ति की दिशा में किये जाते हैं। जनता के हितों की वृद्धि करने तथा सारे समाज और उसके हर सदस्य के लिए रहन-सहन की और भी अच्छी परिस्थितियां पैदा करने का हमारा एक वास्तविक साम्यवादी ढंग है। जन-हित के कार्यों के अन्तर्गत अच्छे अच्छे मकान, सार्वजनिक सेवाओं और भोजनालयों की सुव्यवस्था, अधिकाधिक शिशु-सदन, शिक्षा की अधिक समुन्नत पद्धति, मनोरंजन और छुट्टी की अधिक सुविधाएं, चिकित्सा की और भी अच्छी सेवाएं और अधिकाधिक सांस्कृतिक स्थापन आदि आते हैं।

सोवियत शासन के आरम्भिक वर्षो में जब हमारे देश में सार्वजनिक भोजनालय, किंडरगार्टेन और शिशु-गृहों की स्थापना हुई थी उस समय व्ला० इ० लेनिन ने "साम्यवाद की कोंपलों के आदर्श नमूने" कहकर उनका स्वागत किया था। उनका कहना था कि पार्टी और राज्य का कर्त्तव्य है कि वे इन कोंपलों की सावधानी से देख-रेख करें। उनके शब्द थे कि "सर्वहारा राज्य के शासन का सहारा पाकर साम्यवाद की ये कोंपलें मुरझायेंगी नहीं अपितु विकसित होंगी और पूर्ण साम्यवाद के रूप में पनप उठेंगी" (ग्रन्थ-संग्रह, खंड २९, पृष्ठ ३९७)। आज हमारे सामने थोड़ी-सी कोंपलें ही नहीं किन्तु कम्यूनिस्ट ढंग के भिन्न भिन्न संगठनों की एक

सम्पूर्ण प्रणाली है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनकी संख्या में वृद्धि करें और उनके कार्यों को और सुधारें।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज के साथ, भिन्न भिन्न संबंधों से, बंधा हुआ है। समाज से अलग रहना उसके लिए असम्भव है। साम्यवादी निर्माण-काल में मनुष्य के जीवन की यही सामाजिक प्रवृत्ति अधिक फलती-फूलती है, अधिक पनपती है। यही कारण है कि उसकी निजी आवश्यकताओं की पूर्त्ति समाज की भौतिक और सांस्कृतिक सुख-सुविधा में वृद्धि के साथ ही साथ होनी चाहिए। यह पूर्त्ति न सिर्फ़ बढ़े हुए वेतनों के माध्यम से ही अपितु सामाजिक निधियों से भी होनी चाहिए। इन निधियों का महत्त्व बराबर बढ़ना ही रहेगा।

जनता जिन जिन सामाजिक सेवाओं का उपयोग कर रही है उनपर राज्य के व्यय बराबर बढ़ते ही जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, सामाजिक बीमे के लाभों, आर्थिक सहायताओं, पेंशनों, छात्रों के वेतनों, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा-सेवाओं, छुट्टियों के वेतनों, बोर्डिंग-स्कूलों के रख-रखाव, किंडरगार्टनों, शिशु-गृहों, आरोग्य-सदनों, अवकाश-गृहों, वृद्ध-गृहों, आदि पर १९५८ में २१५ अरब रूबल से अधिक ख़र्च हुए थे। सप्तवर्षीय योजना में यह व्यवस्था है कि इस मद के ख़र्च बढ़ाकर ३६० अरब रूबल, अर्थात् प्रति कर्मचारी लगभग ३,८०० रूबल वार्षिक, कर दिये जायं। इसके अतिरिक्त घरों, स्कूलों, सांस्कृतिक एवं दैनिक आवश्यकताओं तथा चिकित्सा संबंधी स्थापनों के निर्माण पर भी राज्य प्रति वर्ष, प्रति कर्मचारी ८०० रूबल से ज्यादा ख़र्च करेगा।

साथियो, ये बड़ी बड़ी धनराशियां हैं। रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी धनराशियों की व्यवस्था अकेले समाजवादी राज्य में ही की जा सकती है। हमारे देश में बहुत-से विदेशी आते हैं जो प्रायः कम्यूनिस्ट नहीं फिर भी ईमानदार होते हैं।

जब वे यह देखते हैं कि हमारे देश में मनुष्य की भलाई के लिए क्या क्या किया जा रहा है तो चकित रह जाते हैं।

उदाहरणार्थ, हम रिहाइशी मकानों की महत्त्वपूर्ण समस्या पर विचार करें। मकान की समस्या मनुष्य के लिए सबसे गम्भीर सामाजिक समस्याओं में से है। अमेरिकी डिमाक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रकाशित 'आंकड़ा पुस्तक' में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में १ करोड़ ५० लाख लोग गन्दे झोंपड़ों में रहते हैं, १ करोड़ ३० लाख मकान (यानी सारे मकानों के एक-चौथाई) रहने के क़ाबिल नहीं हैं और ७० लाख शहरी मकान तो इतने टूटे-फूटे हैं कि वहां आदमियों का रहना ही असम्भव है। पूंजीवादी संसार में घरों की कमी और उनके ऊंचे ऊंचे किराये, जो परिवार के बजट का २५-३० प्रतिशत तक चूस लेते हैं, श्रमिक जनता के लिए तो जैसे निरंतर बने रहनेवाले अभिशाप हैं।

सोवियत संघ में घरों और रहन-सहन की स्थिति को सुधारने की दिशा में बहुत कुछ किया जा रहा है। मकान का किराया, मय जनोपयोगी सेवाओं के, पारिवारिक बजट का औसतन ४-५ प्रतिशत होता है। देहातों में मकान बनाने में कोलखोज़ और राज्य सहायता देते हैं। किसी भी पूंजीवादी देश में श्रमिक जनता को ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं हैं।

मकानों की कमी दूर करने और इस प्रकार आगामी १०-१२ वर्षों में रहने-बसने की समस्या हल करने के लिए पार्टी और सरकार ने १९५७ में जो लक्ष्य निर्धारित किये थे उनपर सफलतापूर्वक अमल किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में १२ करोड़ वर्ग मीटर फ़र्श-क्षेत्र के मकान बन चुके हैं और यह क्षेत्र-फल मूलतः निर्धारित क्षेत्र से १ करोड़ २० लाख वर्ग मीटर अधिक है। आगामी सात वर्षों में हमें ६५-६६ करोड़ वर्ग मीटर फ़र्श-क्षेत्र के मकान बनाने हैं। इनमें फ़्लैटों की संख्या १ करोड़ ५० लाख होगी, जो क्रान्ति के बाद से आज तक बने हुए मकानों की संख्या से भी अधिक है।

मकानों का वितरण इस आधार पर किया जाता है कि प्रत्येक परिवार को एक अलग फ़्लैट मिल सके। डिज़ाइनें तैयार करनेवाले संगठनों के कामों में सुधार करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका कार्य बढ़ती हुई मांगों की पूर्त्ति की तरफ़ ध्यान देना है। उन्हें कम ख़र्च पर बनाने लायक़ मकानों के नमूने तैयार कर उन्हें व्यवहार में लाना चाहिए। साथ ही उन्हें नगर-विकास योजनाएं तथा देहाती बस्तियों के नक़्शे इस बात को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए कि शहर व देहात की रहन-सहन की स्थिति सोवियत जनता की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी करे।

मनुष्य के लिए हमें घरों का ही सुप्रबन्ध नहीं करना है, बल्कि उसे यह भी सिखाना है कि वह समाज मे होनेवाले लाभों का सदुपयोग कैसे कर सकता है, क़ायदे मे कैसे रह सकता है और समाजवादी समाज के नियमों का पालन कैसे कर सकता है। ये काम आदमी सीखता है नयी कम्यूनिस्ट जीवन-प्रणाली की सफलता के लिए लम्बे अर्से तक अविचलित प्रयास करते रहने के फलस्वरूप।

सप्तवर्षीय योजना में जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा-सेवाओं के और भी अधिक सुधार की व्यवस्था है। पूंजीवादी देशों में कोई भी श्रमिक की, उसके स्वास्थ्य की और उसके जीवन की चिन्ता नहीं करता। वहां चिकित्सा-सेवाओं के लिए, चाहे वे मामूली हों या विशिष्ट, आदमी अपनी जेब से काफ़ी बड़ी रक़म ख़र्च करता है। जब हम फ़िनलैंड में थे तो एक मज़दूर ने हमें बताया कि जब उसे अपेंडिसाइटिस हुआ और उसे आपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गयी। उसके पास दो ही विकल्प रह गये थे—मर जाना या फिर ढेर-सा रुपया उगलना।

और अकेला यही उदाहरण तो है नहीं। 'यूनाइटेड स्टैट्स न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट' में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में

चिकित्सा-व्यय "सामान्य परिवार के लिए काफ़ी बड़ा बोझ" बन गया है। पत्रिका ने लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट के फोड़ों के शल्य उपचार पर १,२६४.५ डालर ख़र्च पड़ता है जिसके ब्योरे इस प्रकार हैं—२१ दिन तक अस्पताल में रहने का ख़र्च—३२५.५ डालर, आपरेशन की फ़ीस—५०० डालर, आपरेशन का कमरा इस्तेमाल करने की फ़ीस—७५ डालर, तीमारदारी के वार्ड में ठहरने का शुल्क—३ डालर, उपचार शुल्क—७८.६ डालर, आक्सीजन के लिए—२१.५ डालर, पट्टियों के लिए—५६.३ डालर, प्रयोगशाला की सेवाओं के लिए—९९ डालर, बेहोशी की दवा के लिए—५० डालर और एक्स-रे परीक्षण के लिए—५५ डालर।

सोवियत संघ में जनता को निःशुल्क चिकित्सा-सेवाएं उपलब्ध हैं। इन सेवाओं के अधीन अनगिनत अस्पताल और पोलीक्लिनिक हैं। अपने देश में जन-स्वास्थ्य सेवाओं के और अधिक सुधार पर आगामी सात वर्षों में राज्य को कोई ३६० अरब रूबल व्यय करने होंगे।

रहन-सहन के उच्च स्तर और स्वास्थ्य की समुन्नत सेवाओं के कारण हमारे देशवासियों की आयु में वृद्धि हो गयी है। पिछले कुछ वर्षों में सोवियत संघ में मृत्यु-संख्या का अनुपात दुनिया में सबसे कम था। यहां आबादी की वृद्धि भी अन्य बहुत-से देशों की तुलना में अधिक रही है। सोवियत संघ में सामान्य मृत्यु-संख्या, क्रान्ति से पहले के आंकड़ों की तुलना में, चौथाई और शिशु मृत्यु-संख्या षष्टमांश हो गयी है।

ये सब ऐसे तथ्य हैं जो स्वतः स्पष्ट हैं।

कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों का एक अंग कार्य-दिवस को घटाना भी रहा है। लक्ष्यांकों के मसविदे में यह व्यवस्था है कि १९६० में मज़दूरों और कर्मचारियों के लिए कार्य-दिवस सात घंटों का और कोयला और खनिज उद्योगों के प्रमुख विभागों में, ज़मीन के नीचे काम करनेवालों के लिए, कार्य-दिवस ६ घंटों का होगा। १९६२ में,

मज़दूरों और कर्मचारियों से सात घंटों के कार्य-दिवस सहित सप्ताह में ४० घंटे काम लिया जायेगा।

१९६४ से ज़मीन के नीचे काम करनेवाले तथा हानिकर श्रम-स्थितिवाले कामों में लगे हुए कर्मचारियों को क्रमिक रूप से सप्ताह में ३० घंटे और शेष को ३५ घंटे काम करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिली तो कार्य-दिवस काम की प्रकृति के अनुसार पांच या छः घंटों का होगा। चूंकि अधिकांश मज़दूर और कर्मचारी हफ़्ते में दो पूरे दिनों की छुट्टी चाहते हैं अतएव योजना यह है कि कार्य-सप्ताह पांच दिनों का हो और कार्य-दिवस छः या सात घंटों का।

हमारे देश में कार्य के छोटे दिन और छोटे सप्ताह, वेतन में किसी प्रकार की कटौती किये बिना ही लागू किये जायेंगे। इसके विपरीत वेतनों में काफ़ी वृद्धि भी होगी। **सोवियत संघ में कार्य-दिवस और कार्य-सप्ताह दुनिया में सबसे छोटे होंगे और साथ ही रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा होगा (ज़ोर की तालियां)।**

सोवियत संघ में खाद्य-पदार्थों का उत्पादन अधिक होने से उनकी खपत भी सारी जनता में अधिक होती है और उसे अधिक अच्छा भोजन भी मिलता है। पूंजीवादी देशों में जो औसत आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं उनसे उस अन्तर पर परदा पड़ता है जो रईस वर्ग और श्रमिक वर्ग के भोजन के स्तर और शासक देशों और उपनिवेशों की जनताओं के भोजन के स्तर में होता है।

उपभोक्ता-वस्तुओं के अधिक उत्पादन और जनता की ऊंची ऊंची आमदनियों का नतीजा यह होगा कि व्यापार में भी वृद्धि होगी। आगामी सात वर्षों में राज्य और सहकारी व्यापार संघों की फुटकर बिक्रियां लगभग ६२ प्रतिशत बढ़ जायेंगी। जनता में खाद्य-पदार्थों, कपड़ों, सिले कपड़ों, अण्डरवियरों और जूतों की बिक्री ज़्यादा बढ़ जायेगी। सात

वर्षों में ६० हजार दूकानें और ६४ हज़ार सार्वजनिक भोजनालय खोले जायेंगे।

साथियो, सार्वजनिक भोजनालयों के महत्त्व को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। भोजन तैयार करनेवाले बड़े बड़े उद्योगों, कारखानों और फ़ैक्ट्रियों के भोजनालय, कालेज और स्कूल की कैन्टीनों का अधिकाधिक विकास करना जरूरी है। इसके अलावा बड़े बड़े गृह समूहों में भी भोजनालयों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि श्रमिकों के परिवार, उनका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। हमारा लक्ष्य यह है कि सार्वजनिक भोजनालयों में क़ीमतें गिरायी जायं।

जनता के हित के लिए सिलाई, कपड़ों और जूतों की मरम्मत की दूकानों और मकानों, फ़र्नीचर तथा घरेलू और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की चीज़ों की मरम्मत के कारखानों की संख्या बढ़ाना भी आवश्यक है।

हमारे विदेशी शत्रु हमपर यह आरोप लगाते हैं कि सप्तवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है, जिसे पूरा करने के लिए जनता को 'क़ुरबानियां' देनी होंगी। निश्चय ही हमारी योजना में भारी उद्योगों के विकास के लिए विशाल पूंजी लगाने की व्यवस्था है। लेकिन दूसरा उपाय है भी क्या?

यथेष्ट मात्रा में उपभोक्ता-वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमें उत्पादन-साधनों की ज़रूरत है और ज़रूरत है धातु पैदा करने की, मशीनों को समुन्नत बनाने की और ऐसी ऐसी स्वचालित मशीनें स्थापित करने की, जिनसे आदमी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके। आलू जैसी मामूली चीज़ उगाने के लिए पुराने ज़माने तक के लकड़ी के हल में धातु का होना आवश्यक था। लेकिन हम तो कम्यूनिस्ट समाज की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपने मुख्य मुख्य कामों में मशीनों का उपयोग करें और आदमी उनपर सिर्फ़ नियंत्रण रखे। पुराने ज़माने में किसान घोड़ा ख़रीदने के लिए पेट काटकर पैसा जुटाता था। वह

अच्छी तरह जानता था कि अगर उसके पास घोड़ा हो जाय तो उसके खाने-पीने का इन्तज़ाम हो सकता है। बिना घोड़े के तो उसके भूखों मरने की नौबत आ सकती है। किन्तु आज युग ने करवट ली है। आज तो उद्योगों का विकास, उत्पादन-साधनों की वृद्धि—यही है हमारा सर्वशक्तिमान घोड़ा। अगर हमारे पास यह घोड़ा हो जाय तो फिर बाक़ी सब कुछ जुटा लेना बायें हाथ का खेल है **(तालियां)**।

पहले कुछ पंचवर्षीय योजना-कालों में सोवियत संघ दुनिया के पूंजीवादी देशों से घिरा हुआ अकेला समाजवादी देश था। उस समय उसे अपने अस्तित्व के लिए जी जान से लड़ना पड़ा था, युगों के पिछड़ेपन से पिंड छुड़ाने और एक शक्तिशाली समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का विकास करने के लिए जनता को एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ा था, क़ुरबानियां देनी पड़ी थीं। किन्तु उस समय भी पार्टी और राज्य ने जनता का जीवन-स्तर बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति-भर सब कुछ किया। आज हम विकास के एक दूसरे ही सोपान पर हैं। हमारे आगे अन्य सम्भावनाएं, अन्य शक्तियां हैं और हम जीवन-स्तर और भी ऊंचा उठाने के लिए सभी कुछ कर रहे हैं। इसी लिए जब तक कोई सत्य को विकृत नहीं करना चाहता हो तब तक 'क़ुरबानियों' की बातें करने का कोई कारण नहीं।

हमारी योजना के 'आलोचक' ऐसे किसी एक भी पूंजीवादी सरकार की मिसाल हमारे सामने रखें जो जनता की उपभोग-क्षमता इतने बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहती हो जितना हमारा देश चाहता है। वे एक भी ऐसे बूर्जुआ राज्य का नाम बतायें जो उतने ही, बल्कि बढ़े हुए, वेतन पर कार्य-दिवस के घंटों में कमी करने का विचार भी करता हो। पूंजीवादी देशों में इसके लिए मजदूर वर्ग, श्रमिक जनता को शोषकों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है। पूंजीवादी संसार में ऐसे राज्य तथा ऐसी सरकारें नहीं हैं और न हो ही सकती हैं जो श्रमिक जनता का इतना अधिक ध्यान रखती हों **(तालियां)**।

कम्यूनिस्ट पालन-पोषण और जन-शिक्षा। विज्ञान और संस्कृति का विकास।

साथियो, कम्यूनिज़्म में समाज के परिवर्तन के लिए केवल विकसित भौतिक और प्राविधिक आधार ही नहीं बल्कि समाज के सभी सदस्यों की अत्यंत सचेत प्रवृत्ति भी आवश्यक है। **करोड़ों की संख्यावाले समाज की प्रवृत्ति जितनी अधिक सचेत होगी, कम्यूनिस्ट निर्माण की योजनाएं उतनी ही अधिक सफलता के साथ कार्यान्वित की जायेंगी।** इसी लिए जनता की और विशेषकर नयी पीढ़ी की कम्यूनिस्ट शिक्षा से संबंधित प्रश्नों को असाधारण महत्त्व प्राप्त हो रहा है।

हमारी पार्टी और सरकार की सभी सैद्धान्तिक गतिविधियों का उद्देश्य है सोवियत जनता में नयी प्रवृत्तियां विकसित करना, उन्हें सामूहिकतावाद एवं उद्योगप्रियता, समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद एवं देशभक्ति – जोकि नये समाज के महान आचारनैतिक सिद्धान्त हैं – और मार्क्सवाद-लेनिनवाद की प्रवृत्ति में शिक्षित करना। कम्यूनिज़्म ही वह न्याय्यतम एवं पूर्णतम समाज है जिसमें स्वतंत्र मानव की सर्वोत्तम नैतिक प्रवृत्तियां पूर्णतया विकसित होंगी। इस कम्यूनिज़्म की प्राप्ति के लिए हमें आज ही भावी मानव का सुयोग्य पालन-पोषण करना होगा। सोवियत जनता में कम्यूनिस्ट आचारनीति को विकसित करना होगा। यह ऐसी आचारनीति है जो कम्यूनिज़्म के प्रति निष्ठा और उसके शत्रुओं के प्रति अक्षमा पर, सामाजिक कर्त्तव्य की भावना पर, समाज-कल्याण के लिए सक्रिय कार्यमग्नता पर, मानव-संबंधों के बुनियादी नियमों के स्वैच्छिक पालन पर, भ्रातृत्वपूर्ण परस्पर सहायता, ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा पर और सार्वजनिक सुव्यवस्था का उल्लंघन करनेवालों के प्रति अक्षमा पर आधारित हैं।

पूंजीवादी विचारधारा-प्रचारक एवं राजनीतिज्ञ और उनके अवसरवादी ख़ुशामदी कठपुतले यह सिद्ध करने की जीतोड़ कोशिश कर

रहे हैं कि कम्यूनिस्ट लोग नीति-नियमों को अस्वीकार करते हैं और समाजवाद तथा मानवता के नीति-नियमों की पटरी नहीं बैठती। दूसरी ओर वे अपने को बड़े घमंड के साथ नैतिक मूल्यों और मानवतावाद के, स्वतंत्रता और वैयक्तिक अधिकारों के समर्थक घोषित करते हैं।

लेकिन क्या उनके इन दावों का कोई आधार है? स्वयं जीवन ही इस प्रश्न का उत्तर देता है, दो संसारों की आचारनीति की तुलना भर से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

पूंजीवादी समाज की आचारनीति का सार है व्यक्तिवाद, स्वार्थपरायणता, लाभ की तृष्णा, शत्रुता और प्रतियोगिता। पूंजीवादी समाज का आधार है मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण जो आचारनीति को पैरों तले रौंद देता है। शोषक वर्गों की आचारनीति की विशेषता 'मनुष्य के लिए मनुष्य एक भेड़िया है' इस सूत्र में प्रकट होती है और यह कोई संयोग मात्र की बात नहीं है। लेकिन समाजवाद इससे भिन्न आचारनीति का समर्थन करता है। इस आचारनीति का सार है सहयोग एवं सामूहिकतावाद, मैत्री एवं पारस्परिक सहायता। यह जनता के आम कल्याण पर, समूह में मानवीय व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इस नीति के अनुसार मनुष्य मनुष्य में मित्रत्व एवं भ्रातृत्व का संबंध है, शत्रुत्व का नहीं।

कम्यूनिज़्म के समर्थक मानव-समाज को पूंजी के जुए से मुक्त करने और आम जन-कल्याण के महान आदर्श से प्रेरित हैं। उनका अपना उदाहरण और आचरण नैतिक शक्ति का आदर्श है। कम्यूनिस्टों ने न कभी कोशिशों में कमी आने दी और न अपनी जान ही की परवाह की। अपने महान आदर्शों की विजय के लिए उन्होंने जान क़ुर्बान की और घोर यंत्रणाएं सहीं। आज भी कई कम्यूनिस्ट अपनी मानवीय विचारधारा, जननिष्ठा और मुक्ति प्राप्ति के निःस्वार्थ संघर्ष के लिए पूंजीवादी देशों के क़ैदखानों और काल-कोठरियों में कष्ट भोग रहे हैं।

नवजीवन के निर्माण में करोड़ों लोगों के सक्रिय सहयोग से समाजवादी देशों में कम्यूनिज़्म के आदर्शों का प्रभाव सुस्पष्ट होता है। सोवियत नर-नारी समाज के हितों को अपने हितों से श्रेष्ठ मानते हैं, वह जानते हैं कि समाजवाद के अंतर्गत जनता की सुख-सुविधा सारे समाज द्वारा सुनिश्चित की जाती है। लेकिन सोवियत नर-नारियों की देशभक्ति एवं श्रमोत्साह को समझ लेना पूंजीवादी राजनीतिज्ञों की पहुंच से बाहर है।

उदाहरणार्थ, जनता की पहलक़दमी पर कार्यान्वित की गयी राजकीय ऋण संबंधी कार्रवाइयों को ही लीजिये। करोड़ों सोवियत नर-नारियों ने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया कि पुराने राजकीय ऋणों का भुगतान २०-२५ बरस के लिए स्थगित किया जाये। हमारी निगाह में तो इस उदाहरण से हमारी जनता के चरित्र की ऐसी नयी प्रवृत्तियां, ऐसे नैतिक गुण स्पष्ट होते हैं, जिनकी शोषक प्रणाली में कल्पना तक नहीं की जा सकती।

यह सर्वविश्रुत है कि पूंजीवादी प्रणाली में मनुष्य केवल स्वार्थरत रहता है, दूसरों से दूर रहता है और केवल अपने ही बल पर निर्भर करता है, क्योंकि निर्भर करने योग्य अन्य कोई होता ही नहीं। वह जानता है कि यदि उसे काम से हाथ धोना पड़े तो उसकी जीविका छिन जायेगी और उसे ग़रीबी और भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा।

समाजवाद के अंतर्गत स्थिति दूसरी है। यहां हर आदमी को अपने समाज और शासन का सहारा है। इसी के फलस्वरूप सोवियत नागरिक के मन में धनलोलुपता और निजी संपत्ति की तृष्णा अस्त हो रही हैं जबकि सामूहिकता और सार्वजनिक कल्याण की भावना उसके मन में अधिकाधिक ज़ोर पकड़ रही है। उदाहरणार्थ, हमारा देश अत्यंत समृद्ध प्राकृतिक स्रोतोंवाले कई नये क्षेत्रों को विकसित कर रहा है। साइबेरिया, कज़ाख़स्तान, उत्तरी प्रदेश, सुदूर पूर्व इत्यादि क्षेत्रों में

और कई मामलों में अत्यंत कठोर जलवायु वाले निर्जन इलाकों में बड़ी संख्या में नये कल-कारखानों, खानों, बिजलीघरों और अन्य उपक्रमों का निर्माण हो रहा है। इन उपक्रमों के निर्माण एवं संचालन के लिए भारी संख्या में कामगारों की आवश्यकता है। फिर ये कामगार आयेंगे कहां से?

पूंजीवादी देशों में हमेशा बेकारों की बड़ी फ़ौज होती है। ये लोग काम की खोज में दुनिया का कोना कोना छानते फिरते हैं। अपनी जीविका के लिए वे कैसा भी काम करने को तैयार होते हैं। सोवियत नर-नारी बेरोज़गारी के अभिशाप से पूर्णतया मुक्त हैं। हमारे देश में काम का अभाव नहीं है और न किसी को अपनी रोटी कमाने के लिए दूर दूर के स्थानों में मारे मारे फिरने की नौबत आती है। हां, सोवियत लोग नये नये स्थानों में जाते हैं अवश्य, किन्तु इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उनकी उदात्त देशभक्ति की भावना। राजधानियों और अन्य सांस्कृतिक केंद्रों में काम-काज पर लगे हुए शत शत सहस्र युवक-युवतियां पार्टी या सरकार की पुकार पर अपने घर-बार को छोड़कर नये, अज्ञात स्थानों के लिए रवाना होते हैं। वे जानते हैं कि शुरू शुरू में उन्हें ऐसी कई सुख-सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा जो उन्हें अपने घर पर उपलब्ध हैं। वे यह भी जानते हैं कि उन्हें तंबुओं में रहना पड़ेगा और कभी कभी ऐसा भी काम करना पड़ेगा जिसके वे अभ्यस्त नहीं हैं।

लगभग सभी सोवियत नागरिकों की भावनाएं एक महान आदर्श से अभिभूत हैं। यह आदर्श है—समाज के लिए उपयुक्त होना, जीवनावश्यक अच्छी वस्तुओं का अधिकाधिक उत्पादन करना। पूंजीवाद की तरह धन-तृष्णा नहीं बल्कि उपर्युक्त आदर्श ही सोवियत जनता के क्रिया-कलापों की प्रधान प्रेरक शक्ति है। अमेरिकन लेखक जैक लंडन ने 'स्वर्ण-लोभी' पूंजीवादी संसार के उन लोगों का बड़ा प्रभावशाली शब्द-चित्र खींचा है जो सोने के पीछे दुनिया के दूसरे छोर तक रेंगकर

चले जाने को तैयार होते हैं। प्रगतिशील सोवियत नर-नारी दूर दूर जाते हैं, लेकिन 'सोने की चिड़िया' के पीछे नहीं, और न ही खुद मालामाल होने के लिए, बल्कि नये कल-कारख़ाने क़ायम करने, अछूती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने, नये नगर बसाने, समाज के लिए, हमारे बच्चों के विकास एवं हमारे भविष्य निर्माण के लिए और कम्यूनिज़्म की विजय के लिए। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति और निजी हितों की पूंजीवादी धारणा वाले लोग सोवियत जनता की नयी नैतिक प्रवृत्तियों को समझ नहीं सकते और इसी लिए सोवियत जनता के देशभक्तिपूर्ण कार्यों को वे ऐसी बातों में उड़ाने के प्रयत्न करते हैं कि ये कार्य बल-प्रयोग के फल मात्र हैं।

इस प्रकार की बातों से और इनके प्रवर्तकों से सोवियत जनता का ख़ासा मनबहलाव होता है। समाज-कल्याण और मानव-कल्याण के लिए वीरतापूर्ण कार्य करनेवाले सोवियत नागरिक के उच्चतम नैतिक मूल्य इन टिप्पणीकारों की पहुंच से बाहर हैं **(ज़ोर की तालियां)**।

अपने सैद्धांतिक कार्य के संगठन में हम इस सिद्धान्त से आरम्भ करते हैं कि कम्यूनिस्ट आचारनीति का पालन कम्यूनिस्ट निर्माण के उद्देश्यों से संबद्ध होना चाहिए। वैज्ञानिक कम्यूनिज़्म का यह परम सत्य कि जनता की जीवन-स्थितियों और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में क्रांतिकारी व्यवहार का निर्णायक स्थान है, हमने केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि अनुभव से भी सीख लिया है। जीवन, सोवियत वास्तविकता की शिक्षा-दीक्षा की सर्वोत्तम पाठशाला है और अत्यंत कठोर अध्यापक भी। कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों का पुस्तकीय ज्ञान या जीवन से विच्छिन्न ज्ञान कौड़ी-मोल का है।

शिक्षा सबसे पहले जीवन, उत्पादन और समाज की व्यावहारिक गतिविधियों से संबद्ध होनी चाहिए। पार्टी जनता की श्रम-शिक्षा को, श्रम के प्रति सचेत साम्यवादी प्रवृत्ति के विकास को अपनी सभी शैक्षणिक

गतिविधियों की धुरी मानती है। हम चाहते हैं कि श्रम, अर्थात् सभी भौतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का स्रोत जनता की सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बन जाय।

पूंजीवाद के अवशेषों के विरुद्ध अपने संघर्ष में कम्यूनिस्ट दृष्टिकोण और व्यवहार के प्रतिमान जोर पकड़ रहे हैं। हमें आज भी अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो सामाजिक श्रम के प्रति उपेक्षा-भाव रखते हैं, मुनाफ़ाख़ोरी में लगे रहते हैं, अनुशासन को तोड़ते हैं और सार्वजनिक सुव्यवस्था को भंग करते हैं। हमें चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि पूंजीवाद के ये अवशेष अपने आप नष्ट हो जायेंगे; हमें निश्चयपूर्वक उनका सामना करना चाहिए और पूंजीवादी दृष्टिकोणों एवं प्रथाओं के प्रदर्शन के विरुद्ध, समाजविरोधी तत्त्वों के विरुद्ध, जनमत तैयार करना चाहिए।

पार्टी अपने समूचे शैक्षणिक कार्य में तरुण पीढ़ी की शिक्षा-दीक्षा को विशेष महत्त्व देती है। व्ला० इ० लेनिन ने कहा था कि "वर्तमान तरुण पीढ़ी के पालन-पोषण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के समूचे कार्य का लक्ष्य उसमें साम्यवादी आचारनीति का विकास होना चाहिए"।

अब तरुण पीढ़ी कम्यूनिज़्म का निर्माण करने लग गयी है और परिणामतः वह कम्यूनिस्ट समाज में जीवन-यापन और काम-काज करती रहेगी, अपने सभी व्यवहारों का प्रशासन स्वयं करेगी। सोवियत तरुण पीढ़ी की शिक्षा-दीक्षा का उद्देश्य यही महान कार्य होना चाहिए।

हमारी तरुण पीढ़ी को वह संघर्ष नहीं अनुभव करना पड़ा जो पुरानी पीढ़ी की क़िस्मत में बदा था। युवा लोगों को क्रांतिपूर्व-कालीन आतंक और कठिनाइयां मालूम नहीं हैं और श्रमिक जनता के शोषण की कल्पना उन्हें केवल पुस्तकों द्वारा मिल सकती है। अतः हमारी तरुण पीढ़ी के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि वह अपने देश का, श्रमिक जनता के मुक्ति-संघर्ष का इतिहास, कम्यूनिस्ट पार्टी का वीरतापूर्ण

इतिहास जान ले और यह महत्त्वपूर्ण है कि उसकी शिक्षा-दीक्षा का आधार हमारी पार्टी की, श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी परंपराएं बन जायें।

पूंजीवादी प्रभावों के कारण सोवियत तरुण पीढ़ी को जो हानि पहुंचती है उसपर कुछ लोग काफ़ी ध्यान नहीं देते। वे मानते हैं कि पूंजीवादी संसार तो हमसे काफ़ी दूर है और हमारी तरुण पीढ़ी उसकी पहुंच से बाहर है। लेकिन यह भ्रांत धारणा है। हमें पूंजीवादी प्रभाव की संभावना की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके विरुद्ध संघर्ष करना हमारा कर्त्तव्य है। सोवियत जनता में और विशेषकर तरुण पीढ़ी में विरोधी दृष्टिकोणों एवं प्रभावों के प्रवेश का डटकर सामना करना हमारा कर्त्तव्य है।

नयी पीढ़ी की कम्यूनिस्ट शिक्षा में स्कूल का विशेष स्थान है। सोवियत स्कूलों ने करोड़ों सुशिक्षित नागरिक, समाजवाद के निर्माता तैयार किये हैं, उत्कृष्ट इंजीनियर, प्रविधिविज्ञ, कृषि-विशेषज्ञ, अध्यापक, चिकित्सक और माध्यमिक या उच्च शिक्षा वाले अन्य विशेषज्ञ उपलब्ध कराने में स्कूलों ने ख़ासा हाथ बंटाया है। नयी पीढ़ी की शिक्षा-दीक्षा में स्कूल की यथार्थ भूमिका सर्वविदित है। लेकिन अपनी सारी सफलताओं के बावजूद सोवियत स्कूली प्रणाली अभी तक कम्यूनिस्ट निर्माण की सभी मांगें पूर्ण नहीं कर पाती; अभी भी उसमें गंभीर ख़ामियां हैं।

'स्कूल एवं जीवन में निकटतम संबंधों की स्थापना और जन-शिक्षा के अधिक विकास' पर कम्यूनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और सोवियत सरकार की संक्षिप्त रिपोर्ट को राष्ट्र-व्यापी विचार-विमर्श में आम समर्थन प्राप्त हुआ और सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत ने उसका अनुमोदन करके इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय स्वीकार किया।

जब हमने स्कूली प्रणाली के पुनःसंगठन का सवाल उठाया तो कुछ विदेशी 'भविष्यवक्ता' चिल्ला उठे कि "उनके पास श्रमिकों की

कमी है इसलिए वे किशोरों से काम लेना चाहते है"। ये भविष्यक्ता भले ही कांय कांय करते रहें। हमारी बात वे कभी समझें तब न? हम स्कूली प्रणाली का पुनःसंगठन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास श्रमिकों की कमी है बल्कि इसलिए कि हम शिक्षा-प्रणाली को और सुधारना चाहते हैं, स्कूल को जीवन के और निकट लाना चाहते हैं **(तालियां)**।

शिक्षा-प्रणाली का पुनःसंगठन शिक्षा एवं पालन-पोषण से संबंधित मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा के सिद्धान्तों से पूरी तरह मेल खाता है और स्कूली प्रणाली के प्रभावशाली पोलीटेकनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। पिछली शताब्दी के अंत में व्ला० इ० लेनिन ने नया आदमी अर्थात् नये समाज का निर्माता ढालने और शिक्षा को औद्योगिक उत्पादन से सम्बद्ध करने के मार्गों पर सोचते समय लिखा था—

"...नयी पीढ़ी में शिक्षा एवं उत्पादक कार्य के समन्वय के बिना आदर्श भावी समाज की कल्पना करना असंभव है। न बिना उत्पादक कार्य के शिक्षा-दीक्षा का और न बिना समानांतर शिक्षा-दीक्षा के उत्पादक कार्य का ही उतना विकास हो सकेगा जितना प्रविधि और वैज्ञानिक ज्ञान की वर्तमान स्थिति में अभिप्रेत है।" (लेनिन, ग्रंथ-संग्रह, खंड २, पृष्ठ ४४०)

स्कूल में विज्ञान के मूल सिद्धान्तों की पढ़ाई का मुख्य तत्त्व, नयी पीढ़ी को कम्यूनिस्ट आचारनीति के अनुसार शिक्षित करने का आधार, यही होना चाहिए कि स्कूल का जीवन, उत्पादन और कम्यूनिस्ट निर्माण के व्यवहार के साथ घनिष्ठ संबंध हो।

शिक्षा को उत्पादक कार्य के साथ संबद्ध करने से प्राप्त ज्ञान घटता नहीं बल्कि वह अधिक विस्तृत होता है। मैंने कई अवसरों पर ऐसे युवा कोलख़ोज़ किसानों और कामगारों से बातचीत की है जो संध्याकालीन इन्स्टीट्यूटों या टेकनिकल स्कूलों में पढ़ते हैं अथवा पत्र-

व्यवहार द्वारा अध्ययन करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र से टेकनिकल स्कूलों या इन्स्टीट्यूटों में आये हुए विद्यार्थियों से भी मैंने बातचीत की है। कैसे शानदार लोग हैं ये! अध्यवसायी, दृढ़ निश्चयी और ज्ञानार्जन के लिए उन्मुक्त। वे शिक्षा प्राप्त करते हैं अधिक अच्छी तरह से समाज-कल्याण-कार्य करने के लिए – अपना दहेज-मूल्य बढ़ाने के लिए नहीं और न ऐसे माता-पिता की मनःशांति के लिए ही जो सोचते हैं कि अपने बेटे या बेटी के पास डिप्लोमा का न होना एक 'ट्रेजिडी' है।

हमें बच्चों के पालन-पोषण के क्षेत्र में शासन एवं समाज की भूमिका और ऊपर उठानी है, शासन और समाज द्वारा परिवार के लिए अधिक सहायता उपलब्ध करानी है। इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए बड़ी संख्या में नये छात्रावास-स्कूल, शिशु-गृह और किंडरगार्टन बनाने की योजना है। १९६५ में छात्रावास-स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या २५,००,००० या इससे अधिक होगी। किंडरगार्टनों में दाखिल बच्चों की संख्या आगामी सात वर्षों में २२,८०,००० से बढ़कर ४२,००,००० होगी। भविष्य में हमारी यह योजना है कि सभी बच्चों को छात्रावास-स्कूलों में भर्ती होने का अवसर मिले। इससे समाज तरुण पीढ़ी की कम्युनिस्ट शिक्षा का कार्य आवश्यक मात्रा में सफलतापूर्वक कर सकेगा और लाखों अधिक स्त्रियां कम्यूनिज़्म के निर्माण में सक्रिय भाग ले सकेंगी **(तालियां)**।

ज़ारशाही ज़माने में नारी को अर्द्ध-दासता में घुल-घुलकर मरना पड़ता था और कई पूंजीवादी देशों में आज भी उसकी वही स्थिति है। लेकिन सोवियत शासन ने नारी को अर्द्ध-दासता से मुक्त कर दिया है। सोवियत नारी सभी सरकारी, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन-क्षेत्रों में एक सक्रिय शक्ति है और उसे समाजवादी समाज के नागरिक के नाते पुरुष के बराबर सभी अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन फिर भी कई स्त्रियों को घर के काम में और बच्चों की देखभाल में लगी रहना पड़ता है जिससे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भाग लेना उनके लिए कठिन होता है।

ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना आवश्यक है जिनमें सभी स्त्रियां अपने अधिकारों, ज्ञान और प्रतिभा का उत्पादक और समाजोपयोगी क्रिया-कलापों में अपनी क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। छात्रावास-स्कूलों, किंडरगार्टनों, शिशु-गृहों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक सुख-सुविधाओं की वृद्धि के द्वारा हम स्त्रियों के लिए ये स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं।

सप्तवर्षीय योजना में उच्च या माध्यमिक शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों के प्रशिक्षण में काफ़ी और विस्तार एवं सुधार का प्रबंध किया गया है। १९५९-१९६५ की अवधि में विश्वविद्यालयों और इन्स्टीट्यूटों से २३,००,००० विशेषज्ञ स्नातक होकर निकलेंगे जबकि पिछली सप्तवर्षीय अवधि में यह संख्या १७,००,००० थी। १९६५ में उच्च शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों की कुल संख्या ४५,००,००० से अधिक याने १९५८ की तुलना में ५० प्रतिशत अधिक होगी। भौतिक उत्पादन के क्षेत्र में लगे हुए विशेषज्ञों की संख्या विशेष तेज़ी से बढ़ेगी।

उच्च शिक्षा-प्रणाली के पुनःसंगठन से मुख्य बात है उसे जीवन के निकटतर लाना, विशेषज्ञों के व्यावहारिक, वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण का स्तर विशेष रूप से सुधारना और उन्हें कम्यूनिज़्म के सक्रिय निर्माताओं के नाते शिक्षित-दीक्षित करना।

माध्यमिक और उच्च शिक्षा-प्रणालियों के पुनःसंगठन के लिए कुछ और समय तथा प्रयत्न की आवश्यकता है। संघीय जनतंत्रों की सर्वोच्च सोवियतें अपनी जातीय परंपराओं एवं विशेषताओं के अनुरूप शिक्षा-प्रणालियों के संबंध में कानून स्वीकृत कर लेंगी।

साथियो, कम्यूनिज़्म का भौतिक और प्राविधिक आधार निर्मित करने के लिए वैज्ञानिक प्रगति और हमारे देश की उत्पादक शक्तियों के और सर्वांगीण विकास से संबंधित समस्याओं के सुलझाव में वैज्ञानिकों के सक्रिय

योगदान की आवश्यकता है। सप्तवर्षीय योजना ने हमारे वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक संस्थानों के सामने नये क्षितिज खोल दिये हैं। उन्हें ऊर्जा और ज्ञान के उपयोग का विस्तृत अवसर उपलब्ध है!

आगामी सात वर्षों में हमारे वैज्ञानिक किस विषय पर काम करेंगे? सबसे पहले वे ऊर्जा का व्यवहारतः असीम स्रोत प्राप्त करने के लिए नियंत्रित तापनाभिकीय प्रवाधों पर अधिकार प्राप्त करने पर, विद्युत उत्पादन एवं परिवहन में आणविक शक्ति के विस्तृत उपयोग से संबंधित समस्याओं पर, अर्थ-व्यवस्था नाभिकीय विखण्डन एवं रेडियो-आइसोटोपों से प्राप्त संश्लिष्ट पदार्थों के अधिक व्यवहार पर और उत्पादन प्रक्रियाओं के व्यापक यंत्रीकरण एवं स्वचालन और एतदर्थ नये प्राविधिक साधनों के विकास से संबंधित समस्याओं पर काम करेंगे जिसका आधार होगा भौतिकी, रेडियो विद्युत्कण विज्ञान और गणन प्रविधियों का व्यापक प्रयोग। जैसा कि थीसिस में दिखाया गया है रसायन, धातुविज्ञान, भूगर्भशास्त्र, कृषि तथा चिकित्सा की विविध शाखाओं और अन्य क्षेत्रों में काम करनेवाले वैज्ञानिकों को भी महान कार्य संपन्न करना है।

सामाजिक विज्ञानों की सभी शाखाओं को भी गंभीर मांगों की पूर्त्ति करनी है। समाजवाद से कम्यूनिज़्म में संक्रमण को शासित करनेवाले नियमों का गंभीर अध्ययन करना, आथिक और सांस्कृतिक विकास के अनुभव का परिशीलन करना और कम्यूनिस्ट विचार-प्रणाली में श्रमिक जनता को शिक्षित करने में सहायता देना हमारे अर्थशास्त्रियों, दार्शनिकों और इतिहासकारों का कर्त्तव्य है। सामाजिक विज्ञानों और विशेषकर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करनेवाले विद्वानों के आगे जीवन निर्मित नयी समस्याओं को रचनात्मक रीति से संकलित करने एवं उनके साहसपूर्ण सैद्धांतिक हल प्रस्तुत करने का महान कार्य खड़ा है। पूंजीवादी संसार में घटनेवाली प्रधान प्रक्रियाओं का सभी पहलुओं से विश्लेषण करना, पूंजीवादी विचारधारा का भंडाफोड़

कर देना और मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत की शुद्धता के लिए संघर्ष करना आवश्यक है।

हमें वैज्ञानिक संस्थाओं और व्यवहार के संबंध बराबर दृढ़तर करने हैं, विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों को अर्थ-व्यवस्था में व्यापकतर एवं शीघ्रतर रीति से लागू करना है, प्रायोगिक एवं रूपांकन-कार्य को दृढ़तापूर्वक अधिक गतिशील बनाना है।

कम्यूनिज़्म के निर्माण में केवल अपूर्व आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास की पूर्वकल्पना की जाती है सो बात नहीं; उससे मनुष्य की सभी रचनात्मक क्षमताओं एव प्रतिभाओं के पूर्णतम एवं सर्वांगीण विकास के लिए असाधारण अवसर उपलब्ध होता है।

साहित्य और कला का समाजवादी समाज की आध्यात्मिक संस्कृति की प्रगति एवं समृद्धि में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनसे कम्यूनिस्ट आदमी के निर्माण में सक्रिय सहायता मिलती है। हमारी कला के सामने जनता की अर्थात् कम्यूनिज़्म के निर्माताओं की वीरतापूर्ण कृतियों को चित्रित करने का महान कार्य है। इससे श्रेष्ठतर एवं उदात्ततर कोई और कार्य नहीं है। लेखकों, थियेटर, सिनेमा और संगीत क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं, मूर्तिकारों एवं चित्रकारों का कर्त्तव्य है कि वे अपने कार्य के आशय एवं कलात्मक स्तर को उच्चतर कर लें; श्रमिक जनता की कम्यूनिस्ट शिक्षा में, कम्यूनिस्ट आचारनीति के सिद्धांतों के प्रचार में, बहुजातीय समाजवादी संस्कृति के विकास में और अच्छी सौंदर्य-रुचि के संवर्द्धन में पार्टी और सरकार के उत्साहपूर्ण सहायक बने रहें।

सप्तवर्षीय योजना में सैद्धान्तिक कार्य के लिए और भी अनुकूल स्थितियों का प्रबंध है। प्रेस, रेडियो और टेलिविजन, सिनेमा और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थापनों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जानेवाला है। पत्र-पत्रिकाओं के प्रसार में और पुस्तकों के प्रकाशन में काफ़ी वृद्धि होगी।

सप्तवर्षीय अवधि में मुद्रण-उद्योग की क्षमता काफ़ी बढ़ायी जायेगी। रेडियो कार्यक्रमों और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थापनों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। खासकर ग्रामीण इलाक़ों में ये सुविधाएं बड़े पैमाने पर उपलब्ध करायी जायेंगी।

हमारे देश के सामने जो महान कार्य हैं उन्हें सफल बनाने में सारे सोवियत बुद्धिजीवी महान भूमिका खेलेंगे। श्रमिक वर्ग तथा कोलख़ोज़ किसानों के साथ वे कम्यूनिज़्म के निर्माण में प्रशंसनीय योग देंगे **(देर तक तालियां)**।

३

समाजवाद और पूंजीवाद के बीच आर्थिक प्रतियोगिता का निर्णायक दौर और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति

साथियो, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर सप्तवर्षीय योजना का सक्रिय प्रभाव पड़ेगा और वह मार्क्सवाद-लेनिनवाद के लिए नयी विजय होगी। योजना पूरी करने में हमारी सफलता से आकृष्ट होकर करोड़ों लोग नये सिरे से समाजवाद के अनुयायी बनेंगे, शान्ति की शक्तियां उससे सुदृढ़ होंगी, युद्ध की शक्तियां शिथिल पड़ेंगी। इस योजना की सफलता से न केवल हमारे देश में, बल्कि सारे संसार में भारी परिवर्तन होंगे। संसार आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की ओर निर्णयात्मक करवट लेगा।

समाजवाद और पूंजीवाद के बीच प्रतियोगिता मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में आरम्भ हो रही है। हमारा हित इसी में है कि हम ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़े अर्से में यह प्रतियोगिता जीत जायें।

सप्तवर्षीय योजना और सोवियत संघ का बुनियादी आर्थिक कर्त्तव्य

ऐतिहासिक दृष्टि से जितनी थोड़ी अवधि में सम्भव हो सके उतनी थोड़ी अवधि में आबादी के प्रति-व्यक्ति-उत्पादन में सबसे उन्नत पूंजीवादी देशों की बराबरी करना और उनसे आगे निकल जाना—यह है सोवियत संघ का बुनियादी आर्थिक कर्त्तव्य। सप्तवर्षीय योजना पूरी करने से हम इस कर्त्तव्य को पूरा करने की दिशा में निर्णायक क़दम बढ़ायेंगे।

पूंजीवाद के साथ हमारी प्रतियोगिता का पहला दौर, महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति के साथ आरम्भ हुआ। इसमें 'कौन किसे पछाड़ता है' वाला प्रश्न, जिसे व्ला० इ० लेनिन ने प्रतिपादित किया था, हमारे देश में समाजवाद के हक़ में तय हुआ। वह तो विश्व-इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण विजय थी। पूंजीवाद के मुक़ाबले में समाजवाद की निर्णायिक अनुकूल स्थिति उससे प्रकाश में आयी। उस शुरू शुरू के दौर में भी समाजवाद ने अन्तर्राष्ट्रीय अखाड़े में बड़ी बाज़ियां जीतीं। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, सोवियत संघ औद्योगिक उत्पादन में पश्चिमी यूरोप के सबसे उन्नत देशों को पीछे छोड़कर आगे निकल गया और संसार में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। १९५८ में, सोवियत संघ का औद्योगिक उत्पादन फ़्रांस, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी के कुल औद्योगिक उत्पादन से काफ़ी ज़्यादा था।

समाजवाद ने निर्णायक रूप से यह साबित कर दिया है कि आर्थिक विकास की गति में वह पूंजीवाद से कहीं बढ़कर है। पूंजीवाद के साथ आर्थिक प्रतियोगिता में अब हम एक नये दौर में क़दम रख रहे हैं। **आज हमारा कर्त्तव्य है विश्व-उत्पादन के क्षेत्र में पूंजीवादी प्रणाली के मुक़ाबले में समाजवादी प्रणाली का पलड़ा भारी करना, सामाजिक श्रम-उत्पादिता और आबादी के प्रति-व्यक्ति-उत्पादन में सबसे समुन्नत पूंजीवादी देशों से आगे बढ़ जाना और संसार का सबसे ऊंचा जीवन-स्तर प्राप्त करना।**

प्रतियोगिता के इस दौर में सोवियत संघ आर्थिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे बढ़ने का इरादा रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्पादन-स्तर वह सर्वोच्च शिखर है जिसतक पहुंचने में पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था समर्थ हुई है। हम सब जानते हैं कि इसमें अनुकूल ऐतिहासिक और प्राकृतिक परिस्थितियों का काफ़ी हाथ रहा है। अमेरिका के स्तर से ऊपर उठने का तात्पर्य है, पूंजीवाद की सर्वोच्च सिद्धि को पीछे छोड़ देना।

हमने अपने लिए यह कर्त्तव्य निर्धारित कर लिया है, इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारी शक्ति, हमारे साधन कितने बढ़ गये हैं। एक ज़माना था जब हमारा देश कई आर्थिक व सांस्कृतिक पहलुओं में अधिकांश पूंजीवादी देशों से कहीं पिछड़ा हुआ था; जब हम अमेरिका से अपनी तुलना करने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। आज हमारा स्तर कुछ और है, हमारी क्षमता और है, हमारी सम्भावनाएं और। लेनिन द्वारा प्रशस्त पथ का अनुगमन करनेवाले सोवियत जनों के महान श्रम और प्रयास ने हमारे पहले के पिछड़े हुए देश को इतना ऊंचा उठा दिया है कि अब हम सबसे शक्तिशाली पूंजीवादी देश से भी टक्कर लेने में समर्थ हो गये हैं (**देर तक तालियां**)।

जब समाजवाद की नींव ही रखी जा रही थी, तभी हमारी पार्टी साफ़ साफ़ यह जानती थी कि पूंजीवाद के साथ निर्णायक प्रतियोगिता का दौर अनिवार्य रूप से आयेगा और तब समाजवाद अपनी सभी सम्भावनाएं निदर्शित करेगा। अब हम यह कह सकते हैं कि यह दौर आ गया है। अपनी वर्तमान उत्पादक शक्तियों, सामाजिक श्रम की बढ़ी हुई उत्पादिता, आधुनिक प्रौद्योगिकी, सुयोजित समाजवादी अर्थ-व्यवस्था और जनता की सृजनात्मक शक्ति के बल पर शान्तिपूर्ण प्रयास से यह प्रतियोगिता जीतने में सोवियत संघ के सफल होने की पूर्ण सम्भावना है (**ज़ोर की तालियां**)।

संसार की दोनों प्रणालियों के आर्थिक विकास की तात्कालिक सम्भावनाएं क्या हैं?

अपना बुनियादी आर्थिक कर्त्तव्य पूरा करने में सोवियत संघ कितना समय लगायेगा, यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादन-स्तरों के प्रारम्भिक सम्बन्ध पर मुख्य रूप से निर्भर है। इस सिलसिले में क्या कहा जा सकता है?

—सोवियत औद्योगिक उत्पादन की मात्रा अमेरिका की उत्पादन-मात्रा की लगभग आधी है। सोवियत कृषि-उत्पादन अमेरिका से २० से २५ प्रतिशत तक कम है।

—आबादी के प्रति-व्यक्ति के हिसाब से अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन सोवियत संघ से दुगुने से ज़्यादा है और कृषि-उत्पादन क़रीब ४० प्रतिशत ज़्यादा।

कितनी जल्दी हम यह खाई पाटकर अमेरिका के बराबर हो सकते हैं और फिर इन मदों में अमेरिका से आगे बढ़ सकते हैं?

इस मामले में उत्पादन-वृद्धि की गति निर्णायक होती है। और गति में अनुकूल स्थिति तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली के हक़ में है। क्रान्ति के बाद से आज तक हमारे औद्योगिक उत्पादन की मध्यक वार्षिक वृद्धि की गति समुन्नत पूंजीवादी देशों की तुलना में तीन से पांच गुनी तक अधिक रही है।

सप्तवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन की मध्यक वार्षिक वृद्धि की गति ८.६ प्रतिशत निर्धारित की गयी है। हमें इस बात में लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि यह लक्ष्य पूरा तो होगा ही, बल्कि हम इससे आगे भी बढ़ जायेंगे। यह तो स्पष्ट है कि पूंजीवादी देश भी जहां के तहां रुके नहीं रहेंगे। अगले कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन अनुमानतः प्रतिवर्ष क़रीब दो प्रतिशत बढ़ेगा। यही हाल के वर्षों में अमेरिकी उद्योग के विकास की गति रही है।

एक और महत्त्वपूर्ण बात है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। आर्थिक विकास की गति काफ़ी धीमी होने के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका, सकल औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि में इधर काफ़ी लम्बे अर्से से सोवियत संघ से आगे रहा था। लेकिन अब वह ज़माना लद चुका। पिछले आठ बरसों में (इस्पात, कच्चा लोहा, लौह-खनिज, तेल, कोयला, सीमेंट, ऊनी कपड़े जैसे) बहुत-से आधारभूत मदों में सोवियत संघ की सकल उत्पादन-वृद्धि की मात्रा अमेरिका से आम तौर पर बढ़ गयी है।

इस प्रकार इस दृष्टि से भी हमारी प्रतियोगिता में गुणात्मक नया दौर शुरु हो गया है। उत्पादन की वार्षिक गति में और सकल उत्पादन की

वार्षिक वृद्धि में आज हमारा देश संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे है। हम न केवल चौगुनी रफ़्तार से आगे बढ़ रहे हैं बल्कि हर साल हमारे उत्पादन की मात्रा भी अमेरिका की तुलना में बढ़ती जा रही है। फलतः आज हमारे लिए अमेरिका की बराबरी करना ज्यादा आसान है **(तालियां)**।

सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक वृद्धि की गति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सप्तवर्षीय योजना पूरी करने के बाद सोवियत संघ कुछ आधारभूत मदों के सकल उत्पादन में अमेरिका से आगे बढ़ जायेगा और दूसरों में अमेरिका के वर्तमान उत्पादन-स्तर के निकट पहुंच जायेगा। उस समय तक प्रमुख कृषि-पदार्थों का सकल उत्पादन और प्रति-व्यक्ति-उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान स्तर से बढ़ जायेगा। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या बढ़ेगी और यह आशा की जा सकती है कि हमारे देश की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक बढ़ेगी। सम्भवतः सोवियत संघ की जनसंख्या अमेरिका से १५ से २० प्रतिशत तक अधिक होगी। इसलिए, अगर हम जनसंख्या के प्रति-व्यक्ति के हिसाब से सोचें तो औद्योगिक उत्पादन में अमेरिका की बराबरी करने और आगे बढ़ने में हमें सप्तवर्षीय योजना की पूर्ति के बाद और पांच साल लगेंगे। **फलतः उस समय तक – या उससे भी पहले – सकल उत्पादन की मात्रा में और जनसंख्या के प्रति-व्यक्ति-उत्पादन में सोवियत संघ संसार में पहला स्थान प्राप्त कर लेगा। अन्तर्राष्ट्रीय अखाड़े में पूंजीवाद के साथ शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता में यह समाजवाद की ऐसी विजय होगी जो विश्व-इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होगी (ज़ोर की तालियां)।**

पूंजीवादी अर्थशास्त्री यह दलील देते हैं कि एक सीमा तक पहुंचने के बाद सोवियत संघ के औद्योगिक विकास की गति में अनिवार्य रूप से 'अवरोध' शुरू होगा। ये अर्थशास्त्री पूंजीवादी आर्थिक मापदण्ड को समाजवाद पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात सही है कि पूंजीवाद उत्पादक

शक्तियों के विकास में अलंघ्य बाधाएं खड़ी करता है और इस कारण उसके औद्योगिक विकास की गति निश्चय ही धीमी पड़ने लगती है। इसके विपरीत समाजवाद तो उत्पादक शक्तियों के निरन्तर विकास के लिए हर अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है।

युद्धोत्तर काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे पूंजीवादी देशों में 'समृद्धि' की और पूंजीवादी विकास में 'संकट से मुक्त' युग के उदय की बड़ी चर्चा होती थी। लेकिन असल में युद्ध के बाद की पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है? क़रीब बारह साल के दौरान में अमेरिका में तीन बार उत्पादन में संकटपूर्ण मन्दी का दौर चल चुका है—१९४८-१९४९ में, १९५३-१९५४ में और खास तौर पर १९५७-१९५८ में।

अर्थ-व्यवस्था पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, यह बात आखिरी संकट से निदर्शित होती है। १९५७ में अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन मुख्यतः उससे पहले के वर्ष के समान ही था, जबकि १९५८ में वह १९५७ के आंकड़ों से ६.५ प्रतिशत घट गया। इस प्रकार, इस संकट ने अमेरिकी उद्योग को उसके १९५३ के स्तर तक पीछे धकेल दिया है।

कभी संकटपूर्ण मन्दी और कभी ज़बरदस्त तेज़ी का लगातार बारी बारी से होता रहना पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की अस्थिरता पर प्रकाश डालता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे पूंजीवादी देशों को अत्युत्पादन के संकटों से न तो शस्त्रों की होड़ कभी मुक्त कर पायेगी, न और कोई तरीक़ा ही। पूंजीवादी राज्य चाहे कुछ भी कर लें, संकटों के कारणों का वे कभी उन्मूलन नहीं कर पायेंगे। पूंजीवाद अपने ही में निहित विरोधाभासों के गलघोंट चंगुल से कभी छूट नहीं पायेगा। ये विरोधाभास आकार और परिधि में बराबर बढ़ते जाते हैं और नयी आर्थिक उथल-पुथल की आशंका खड़ी करते रहते हैं। इस बात के हर तरह के प्रमाण उपस्थित हैं कि विश्व समाजवादी प्रणाली और विश्व पूंजीवादी प्रणाली के शक्ति-

सन्तुलन में आमूल परिवर्तन आ जाने, उपनिवेश-प्रणाली के विघटित होने और पूंजीवादी देशों में सामाजिक वैर के तीव्र हो जाने के फलस्वरूप पूंजीवाद का आम संकट और गम्भीर हो जायेगा।

पूंजीवाद पर समाजवाद की विजय उत्पादन-वृद्धि पर बहुधा निर्भर करती है। लेकिन दूसरी प्रणाली के मुक़ाबले में किसी प्रणाली की अनुकूलताओं को ठीक से आंकने के लिए हमें मुख्यतया इस बात पर विचार करना चाहिए कि उत्पादन की इस वृद्धि से समाज को, मनुष्य को, क्या लाभ पहुंचता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में गोश्त और मक्खन बहुत पैदा होने से, जनसंख्या के प्रति-व्यक्ति के हिसाब से बहुत-से टेलिविज़न सेट और मोटरें तैयार होने से किसी बेकार नागरिक को क्या फ़ायदा है?

आख़िर पूंजीवादी देशों में जो कुछ दौलत पैदा की जाती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो शोषकों और उनके पिछलग्गुओं ही को मिलता है न! इसके विपरीत समाजवाद के अन्तर्गत प्रति-व्यक्ति-उत्पादन बढ़ने का मतलब श्रमिक जन की जीवन-स्थिति में सच्चा सुधार होता है। दूसरे शब्दों में जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो देश का एक एक व्यक्ति उससे लाभान्वित होता है, जबकि पूंजीवादी देशों में केवल धनी व्यक्ति को, पूंजीवाले व्यक्ति को उत्पादन-वृद्धि के सभी लाभ पहुंचते हैं। निपूंजिया व्यक्ति तो उत्पादन बढ़ने के बावजूद मुश्किल से जीविका चला पायेगा। इसी को वे पूंजीवादी प्रणाली में 'समान अवसर' कहते हैं—यानी एक तो तिजोरियां भरे और दूसरा भूखों मरे। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो पूंजीवाद के नियमों के अनुरूप ही है। उसमें तो यह साधारण और स्वाभाविक बात मानी जाती है।

उत्पादन तो बढ़े लेकिन अधिकांश जनता की उपभोग-क्षमता न बढ़े—इस प्रकार के विरोधाभास की समाजवाद में कल्पना तक नहीं की जा सकती। समाजवादी समाज में तो उत्पादन में विस्तार की योजना समाज के सभी सदस्यों की भौतिक सम्पत्ति बढ़ाने और उनकी आवश्यकताएं और पर्याप्त ढंग से पूरी करने के स्पष्ट उद्देश्य से बनायी जाती है।

इस बात पर ज़ोर देना होगा कि एक पूंजीवादी और एक समाजवादी देश में – मिसाल के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में – उत्पादन का स्तर एक-जैसा भले ही हो, उसके सामाजिक प्रभाव में ज़मीन-आसमान का अन्तर होता है। ठीक इसी बात में समाजवाद की श्रेष्ठता स्वयं प्रकट होती है, क्योंकि उसके अन्तर्गत उत्पादन नफ़ाख़ोरी की ख़ातिर नहीं बल्कि समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने की ख़ातिर होता है।

विश्व समाजवादी प्रणाली का और दृढ़ीकरण

साथियो, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, समूची विश्व समाजवादी प्रणाली और विश्व पूंजीवादी प्रणाली के बीच, आर्थिक प्रतियोगिता हो रही है।

समसामयिक पूंजीवाद की स्थिति केवल अत्युन्नत देशों द्वारा ही नहीं, बल्कि ऐसे देशों द्वारा भी व्यक्त होती है जिनका उत्पादन-स्तर अनुलनीय रूप से नीचा है। समूची पूंजीवादी प्रणाली का आम उत्पादन-स्तर संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादन-स्तर से कहीं कम है। आर्थिक विकास की गति में भिन्न भिन्न पूंजीवादी देशों के बीच बड़ी बड़ी खाइयां हैं जो बराबर चौड़ी होती जा रही हैं।

इसी समय विश्व समाजवादी प्रणाली के सभी देश द्रुत गति से आर्थिक व सांस्कृतिक प्रगति कर रहे हैं। **विकास की तीव्र गति समाजवाद का एक निरपेक्ष साधारण नियम है। समाजवादी शिविर के सभी देशों के अनुभव से अब इस नियम की पुष्टि हो गयी है।** १९५८ में समाजवादी देशों का औद्योगिक उत्पादन १९३७ की तुलना में पांच गुना था। १९५० से १९५८ तक चीनी जनवादी जनतन्त्र ने अपना औद्योगिक उत्पादन लगभग दस गुना बढ़ा लिया। युद्ध से पहले की तुलना में १९५८ में औद्योगिक उत्पादन पोलैंड में ४५० प्रतिशत से अधिक, चेकोस्लोवाकिया में २३०

प्रतिशत, जर्मन जनवादी जनतन्त्र में १५० प्रतिशत से ज्यादा, रूमानिया में लगभग ३०० प्रतिशत, हंगरी में ३०० प्रतिशत से ऊपर, बल्गारिया में क़रीब ८०० प्रतिशत और अल्बानिया में १,३०० प्रतिशत बढ़ा। कोरिया के जनवादी जनतन्त्र ने १९४९ की तुलना में अपना औद्योगिक उत्पादन ३.५ गुना बढ़ा लिया।

समाजवादी उद्योगीकरण के फलस्वरूप अधिकांश जनवादी जनतन्त्रों में उद्योग को प्रमुख स्थान प्राप्त है। पोलैंड, हंगरी, रूमानिया और बल्गारिया में भारी उद्योग का अच्छा विकास हुआ है और वे औद्योगिक व कृषि-प्रधान देश बन गये है। चीनी जनवादी जनतन्त्र कृषि-प्रधान देश से बदलकर औद्योगिक व कृषि-प्रधान देश का रूप धारण कर रहा है।

किसानों को सहकार में प्रवृत्त करने की समस्या समाजवादी विकास की आधारभूत समस्या है। यह समस्या सफलता से हल की जा रही है। चीनी जनवादी जनतन्त्र, बल्गारियाई जनवादी जनतन्त्र और कोरियाई जनवादी जनतन्त्र में सहकारी पद्धति में कृषि की व्यवस्था हो चुकी है। चेकोस्लोवाकिया और अल्बानिया में यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जर्मन जनवादी जनतन्त्र में लगभग आधी कृषियोग्य भूमि सहकारी समितियों और राजकीय फ़ार्मों के हाथ में है। दूसरे समाजवादी देशों में भी सहकारी कृषि-प्रणाली लागू की जा रही है।

कुछ जनवादी जनतन्त्र समाजवाद का निर्माण पूरा करने की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। वह समय निकट है जब सोवियत संघ की तरह वे भी कम्यूनिस्ट समाज का निर्माण करने लगेंगे। यह अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की बात है।

व्यवहार ने यह दिखा दिया है कि नये जीवन के निर्माण में वे ही कम्यूनिस्ट पार्टियां सफल हो सकती हैं जो मार्क्सवाद-लेनिनवाद से तथा समाजवादी विकास के आम निरपेक्ष नियमों से मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं

और जो क्रान्तिकारी सिद्धान्तों को सृजनात्मक ढंग से काम में लाती हैं और अपने देशों के राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक विशेषांशों को ध्यान में रखकर काम करती हैं। समाजवादी देशों की भ्रातृ-पार्टियां समाजवादी निर्माण के सिद्धान्त और व्यवहार को समृद्ध बनाती हैं और मार्क्सवाद-लेनिनवाद को और विकसित करने में हाथ बंटाती हैं।

यूरोप और एशिया के सभी समाजवादी देशों के अनुभव ने साबित कर दिया है कि समाजवादी तरीक़ों ही से सच्ची प्रगति हो सकती है।

समस्त विश्व समाजवादी प्रणाली, जनसंख्या के प्रति-व्यक्ति-उत्पादन में विश्व पूंजीवादी प्रणाली के बराबर तो हो ही चुकी है। समाजवादी देशों की आबादी विश्व-जनसंख्या की क़रीब एक-तिहाई है और वे विश्व औद्योगिक उत्पादन की एक-तिहाई से ज़्यादा, संसार के अनाज-उत्पादन का लगभग आधा और कपास-उत्पादन का ४३ प्रतिशत पैदा करते हैं। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि **सोवियत संघ द्वारा आर्थिक विकास की सप्तवर्षीय योजना पूरी करने और लक्ष्य से आगे बढ़ जाने के बाद तथा जनवादी जनतन्त्रों में आर्थिक विकास की गति तीव्र होने पर, विश्व समाजवादी प्रणाली संसार के कुल औद्योगिक उत्पादन में आधे से ज्यादा माल उत्पन्न करेगी (जोर की तालियां)**। भौतिक उत्पादन मानवीय प्रयास का निर्णायक क्षेत्र होता है। इसमें विश्व पूंजीवादी प्रणाली की तुलना में विश्व समाजवादी प्रणाली की श्रेष्ठता इससे सुनिश्चित हो जायेगी **(तालियां)**।

ज़रा इस बात पर विचार तो कीजिये, साथियो! समाजवादी देश संसार के कुल भूभाग के सिर्फ़ एक-चौथाई हिस्से में फैले हुए हैं। उनमें से अधिकांश अतीत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। फिर भी वह समय दूर नहीं जब वे संसार के औद्योगिक उत्पादन में आधे से ज्यादा माल पैदा करेंगे! क्या, यह इस बात का विशद प्रमाण नहीं है कि समाजवाद के रास्ते पर चलनेवाले देशों की संभावनाएं असीमित हैं?

जैसे कि सब जानते हैं समाजवादी क्रान्ति की पहली जीत हमारे देश में हुई। इसके बाद कई साल तक सभी देशों के पूंजीवादी और काउत्स्की से लेकर सुख़ानोव तक सोशल-डिमाक्रेटिक नेता भी यह पेशीनगोई किया करते थे कि हमारे आर्थिक पिछड़ेपन के कारण सोवियत सत्ता अनिवार्य रूप से भरभराकर ढह जायेगी और पूंजीवाद फिर से स्थापित होगा। लेकिन इन भविष्यवाणियों का आख़िर क्या नतीजा निकला? जो देश पहले औद्योगिक दृष्टि से अनुन्नत थे, समाजवाद के अन्तर्गत वे भी समुन्नत पूंजीवादी देशों के समकक्ष हो गये और अब विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी श्रमिक वर्ग द्वारा सत्ता ग्रहण की जाती है और समाजवादी प्रणाली स्थापित होती है, जनता को अपने देश की अर्थ-व्यवस्था का इतनी द्रुतगति से विकास करने का अवसर मिलता है जितनी कि पूंजीवाद के अन्तर्गत कभी संभव नहीं होती।

अनुभव बताता है कि समाजवादी देशों के लोग अपने आर्थिक विकास की गति तेज़ करने और जीवन-स्तर बढ़ाने के नये नये साधन खोज निकालते रहते हैं। हम भाईचारे की भावना से एक-दूसरे की सहायता करते, साथ देते हुए कंधा-ब-कंधा होकर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार हम सभी समाजवादी देशों का आर्थिक विकास क्रमश: समान स्तर पर लायेंगे।

पूंजीवाद के साथ प्रतियोगिता में अधिक से अधिक समय बचाने की समस्या का अकेले सोवियत संघ ही सामना नहीं कर रहा। उदाहरणत: आपको याद होगा कि चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी ने १९५७ में यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि अगले पन्द्रह वर्षों में चीन आधारभूत औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में ब्रिटेन से आगे बढ़ जायेगा। 'बड़ी छलांग' लगाने का जो जन-आन्दोलन उस देश में फैला है, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि चीन की जनता यह लक्ष्य बहुत ही कम अवधि में प्राप्त कर लेगी। चेकोस्लोवाकिया जनतन्त्र १९६५ तक अपना औद्योगिक उत्पादन १९५७

की तुलना में ९० – ९५ प्रतिशत तक बढ़ाने का इरादा रखता है। पोलैंड का जनवादी जनतन्त्र इसी अवधि में अपना औद्योगिक उत्पादन १९५८ की तुलना में ८० प्रतिशत बढ़ाना चाहता है। बल्गारिया के लोग अपनी पंचवर्षीय योजना तीन से चार साल तक में पूरी करना चाहते हैं।

समाजवादी शिविर के देशों के पास विश्व-उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त करने की सभी आवश्यक बातें मौजूद हैं।

आर्थिक विकास की गति तीव्रतर होने से विश्व समाजवादी प्रणाली अनुकूल स्थिति में है। समूचे समाजवादी शिविर में पिछले पांच वर्षों में (१९५४-१९५८) औद्योगिक उत्पादन की मध्यक वार्षिक वृद्धि ११ प्रतिशत हुई, जबकि विश्व पूंजीवादी देशों में वह ३ प्रतिशत से भी कम थी।

विश्व समाजवादी प्रणाली में सभी देश संयुक्त होकर अपने उत्पादक प्रयासों को सूत्रवद्ध करते हैं। इसके विपरीत पूंजीवादी देशों के आपस के सम्बन्धों में कभी न मिटनेवाले वैरभाव का बोलबाला होता है। चालू दौर में राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं को सूत्रबद्ध करने के द्वारा समाजवादी देशों के उत्पादक प्रयासों को एकत्र किया जाता है। श्रम का अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन, खासकर उसके उच्चतम स्वरूप – यानी, कार्य का विशेषीकरण और सहकरण – समाजवादी शिविर के आर्थिक विकास में बड़ा हाथ बंटायेंगे। समाजवादी शिविर में तथा प्रत्येक समाजवादी देश में उत्पादन का विस्तार करने के नये नये अवसर इससे और भी बढ़ जायेंगे। कोई भी अकेला देश अपने आप इतनी द्रुतगति से विकास नहीं कर सकता जितनी द्रुत-गति से वह समाजवादी देशों की प्रणाली के अन्तर्गत करता है।

समाजवादी देशों के आर्थिक विकास का एक विशिष्ट पहलू यह है कि ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों उनके आपसी सम्बन्ध सुदृढ़ होते जाते हैं और इस प्रकार विश्व समाजवादी प्रणाली में मेल और बढ़ता जाता है। लेकिन पूंजीवादी संसार में तो ठीक इसकी उलटी बात देखने में आती है। वहां तो किसी एक देश में उत्पादन बढ़ जाने से पूंजीवादी राज्यों का

आपसी वैर और उग्र हो जाता है, उनमें आपाधापी और बढ़ जाती है और झड़पें हो जाती हैं। प्रत्येक समाजवादी देश की वृद्धि और विकास समूची समाजवादी प्रणाली को मज़बूत बनाने में मदद देता है। हमारा बल, पूंजीवाद के साथ समाजवाद की शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता में होनेवाली हमारी जीतों की गारंटी, इसी में निहित है।

विश्व समाजवादी प्रणाली के देशों की एकता बढ़ाने की ख़ातिर, समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीयता और स्वतन्त्र जनताओं की भ्रातृत्वपूर्ण मैत्री के आधार पर उनमें सहयोग तथा आर्थिक व सांस्कृतिक सम्बन्ध और बढ़ाने की ख़ातिर काम करना सोवियत संघ अपना प्रमुख कर्त्तव्य मानता है **(देर तक तालियां)**।

* * *

साथियो, संसार का ध्यान हमारी सप्तवर्षीय योजना पर केन्द्रित है। हमारे मित्र और हमारे प्रतिपक्षी इस योजना की चर्चा और उसपर टिप्पणियां कर रहे हैं।

हमारे मित्र सोवियत संघ में कम्यूनिस्ट निर्माण के कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। हमारी योजना के मूल्यांकन में सभी कम्यूनिस्ट और कामगार पार्टियां एकमत हैं। सभी देशों की श्रमिक जनता और प्रगतिशील लोग शान्ति, जनतन्त्रवाद और समाजवाद की शक्तियों का बल और बढ़ाने में इस योजना को बड़े महत्त्व का मानते हैं।

जहां तक हमारे प्रतिपक्षियों से सम्बन्ध है, हमारे लक्ष्य के आंकड़ों ने उनमें खलबली मचा दी है। पूंजीवादी प्रचारक हमारी योजना के शान्तिपूर्ण ध्येयों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं और साधारण जनता के मन व हृदय पर उसके प्रभाव को घटाकर आंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूंजीवादी पत्रों को भी विवश होकर यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि सप्तवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य विराट हैं।

अंग्रेज़ी पत्रिका 'ईकोनामिस्ट' ने लिखा कि योजना की ऐसी छाप पड़ती है कि "दिमाग़ चकरा जाता है"।

हमारी योजना पर पूंजीवादी पत्र-पत्रिकाओं की टिप्पणियां पढ़कर यह बात बरबस याद हो आती है कि पहली पंचवर्षीय योजना पर उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की थीं। उस समय तो पूंजीवादी पत्रों ने पेशीनगोई की थी कि "बोल्शेविक परीक्षण" विफल होकर रहेगा। उन्होंने उसे "पागलपन" और "अफ़ीमची का सपना" कहा था।

लेकिन ज़माना बदल गया है। समाजवाद की सफलताओं ने संसार को हमारी योजनाओं की क़द्र करना सिखाया है। बहुत-से पूंजीवादी नेताओं, ठंडे दिमाग़ से सोचनेवाले अर्थशास्त्रियों और पत्र-पत्रिकाओं ने लाचार होकर हमारे कार्यक्रम की व्यावहारिकता मान ली है। अमेरिकी एकाधिकारवालों का मुखपत्र 'बिज़िनस वीक' कहता है कि "अपने समूचे औद्योगिक ध्येय प्राप्त करने में सोवियत संघ के सफल होने की काफ़ी सम्भावना है... अतीत में सोवियत लोग अपनी योजनाओं के लक्ष्य बड़ी हद तक पूरे करने में सफल हुए हैं।" जापानी एकाधिकारियों के पत्र 'सन्केई' ने बताया कि "प्रकाशित लक्ष्य के आंकड़ों की व्यावहारिकता पर शक करना, जैसे कि पूंजीवादी जगत के कुछ लोग अब भी कर रहे हैं, ग़लत होगा। सोवियत योजना क्रान्ति के बाद गुज़रे हुए चालीस वर्षों के अनुभव पर आधारित है, कम से कम इस कारण उसकी व्यावहारिकता असन्दिग्ध है।"

नये ज़माने—नये तराने। हम अधिकारपूर्वक कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत के सभी क्षेत्रों की मान्यता प्राप्त करने के द्वारा सप्तवर्षीय योजना को प्रारम्भिक सफलता प्राप्त हो चुकी है।

अमरीकी पत्र 'देस मोइन्स रेजिस्तर' पश्चिम के नेताओं को चेतावनी देता है कि सप्तवर्षीय योजना पर गम्भीर रूप से विचार करें, क्योंकि सोवियत संघ "बड़ी आर्थिक प्रगति करने की—संयुक्त राज्य अमेरिका से तेज़

रफ़्तार में आगे बढ़ने की—अपनी क्षमता साबित कर चुका है"। 'न्यूयार्क टाइम्स' का एक सम्पादक मानता है कि "सोवियत संघ तो अब जैसे हमारे पीठ-पीछे आ चुका है, यानी आर्थिक अर्थ में। उत्पादन-क्षमता में सोवियत लोग हमसे बस, दो ही छलांग पीछे हैं—सिर्फ़ दसेक साल पीछे हैं।" यह है ठंडे दिमाग़ का अनुमान। हम इससे सहमत होने को तैयार हैं।

हमारी नयी योजनाओं की व्यावहारिकता को मानने के साथ साथ पूंजीवादी नेता और पत्र-पत्रिकाएं यह चिन्ता भी व्यक्त करते हैं कि अगले सात वर्ष के लिए निर्धारित विराट लक्ष्य पूरे होने से कम्यूनिज़्म की विचारधारा का आकर्षण बेहद बढ़ जायेगा।

फ़्रांस का दक्षिणपन्थी पत्र 'ले आउरोर' लिखता है: "सोवियत संघ ने वे तिथियां निर्धारित कर दी हैं जब मार्क्सवादी क्रान्तिकारियों के चिरकाल के सपने साकार हो जायेंगे। सोवियत संघ तो ऐसे कारनामों पर उतर आया है जिनकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती।" अमरीकी पत्र 'वाल स्ट्रीट जर्नल' लिखता है कि कुछ देशों पर इस योजना का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि वे "कम्यूनिज़्म को अपनायेंगे"। लेकिन इसे रोकने के लिए "संयुक्त राज्य अमेरिका शायद ही कुछ कर सकेगा"। ख़ूब कहा! **(हॉल में सजीवता)।**

पश्चिम के लोग कहते हैं कि हमने "चुनौती" दे दी है। ख़ैर, अगर उन्हें यह शब्द पसन्द है, तो ठीक है, हम समझ लेंगे हमने चुनौती दी है। लेकिन यह है **हमारी अर्थ-व्यवस्थाओं के शान्तिपूर्ण विकास में और जनता का जीवन-स्तर ऊंचा करने में होड़ करने की चुनौती।** हमारे लोगों ने अक्तूबर क्रान्ति में विजयी होकर पूंजीवाद को चुनौती दी, लेकिन वह लड़ाई की चुनौती न थी। वह थी शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता की चुनौती। अगर हमारी जनता को अपने सामरिक उद्योग का विकास करना पड़ा तो वह केवल इसलिए कि सशस्त्र आक्रमण का खतरा हमारे

देश के ऊपर सदा मंडराता रहा और ऐसे आक्रमण को विफल करने के लिए हमारी जनता को तैयार रहना पड़ता था। शान्तिपूर्ण विकास और जीवन-स्तर बढ़ाना ही तब भी हमारा मुख्य लक्ष्य था और अब भी है **(देर तक तालियां)**।

हम औद्योगिक वस्तुएं, गोश्त, मक्खन, दूध, कपड़े, जूते और दूसरी उपभोक्ता-वस्तुएं उत्पन्न करने में होड़ करना चाहेंगे, बनिस्बत इसके कि शस्त्रों की होड़ में तथा अणुबम, उदजन बम व राकेट बनाने में प्रतियोगिता करें।

जनता स्वयं इस बात का निर्णय करे कि कौनसी प्रणाली उसकी आवश्यकताएं सबसे अच्छे ढंग से पूरी करती है। प्रत्येक प्रणाली के साथ उसके योग्य व्यवहार जनता स्वयं करे!

सोवियत संघ की शान्तिपूर्ण नीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

सप्तवर्षीय योजना सोवियत संघ की लेनिनवादी शान्तिपूर्ण नीति का नया निरूपण है। हमारे समय की प्रमुखतम समस्या – विश्व शान्ति को सुरक्षित रखने की समस्या – हल करने में इसकी पूर्ति बड़ा हाथ बंटायेगी।

इस योजना का महत्त्व सबसे पहले इस बात में है कि वह शान्ति की भावना से ओतप्रोत है। जो राज्य नये कल-कारखाने, बिजलीघर, खानें व दूसरे उद्यम निर्मित करने के विराट कार्यक्रम अपनाये हुए हो, जो रिहाइशी मकानों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए लगभग चार खरब रूबल निर्धारित करता हो और अपनी जनता का जीवन-स्तर काफ़ी मात्रा में बढ़ाने का बीड़ा उठाता हो, वह राज्य शान्ति चाहता है, न कि युद्ध।

दूसरी बात यह कि योजना पूरी होने पर सोवियत संघ की आर्थिक क्षमता इतनी बढ़ जायेगी कि सभी समाजवादी देशों की बढ़ी हुई आर्थिक

क्षमता के साथ मिलकर वह अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-सन्तुलन में शान्ति का पलड़ा निर्णायक रूप से भारी कर देगी। विश्व युद्ध रोकने व संसार में शान्ति सुरक्षित रखने की नयी, और भी अनुकूल स्थिति इस प्रकार उत्पन्न हो जायेगी।

पार्टी की २० वीं कांग्रेस ने निष्कर्ष निकाला था कि युद्ध अनिवार्य रूप से अवश्यम्भावी नहीं है। यह निष्कर्ष सही साबित हुआ है। आज तो इस निष्कर्ष को पुनः पुष्ट करने के अधिक कारण हमारे पास मौजूद हैं। अब तो ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो साम्राज्यवादी आक्रमणकारियों को सिर उठाने से रोक सकती हैं और अगर उन्होंने विश्वयुद्ध छेड़ा तो उन्हें हरा सकती हैं।

सोवियत संघ की तथा यूरोप व एशिया के सभी समाजवादी देशों की आर्थिक योजनाएं पूरी होने पर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में कौनसे नये तत्त्वों का उदय होगा? **तब तो वास्तव में इस बात की सम्भावना हो जायेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के निपटारे के एक साधन के रूप में युद्ध का उपयोग हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाये।**

सचमुच जब सोवियत संघ संसार का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बनेगा, जब चीनी जनवादी जनतन्त्र शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनेगा और सभी समाजवादी राष्ट्र मिलकर संसार के औद्योगिक उत्पादन का आधे से ज्यादा हिस्सा उत्पन्न करेंगे तब तो संसार की स्थिति तेजी से बदलेगी ही। समाजवादी शिविर के देशों की सफलताएं निःसन्देह संसार भर में शान्ति की शक्तियों का बल बढ़ाने में हाथ बंटायेंगी। तब तक स्थायी शान्ति के लिए काम करनेवाले देशों के साथ ऐसे नये देश निश्चय ही आ मिलेंगे जो औपनिवेशिक जुए को उतार फेंक चुके हों। यह विचार कि युद्ध नहीं होने देना चाहिए, लोगों के दिलो-दिमाग में गहरी जड़ जमायेगा। शक्तियों का यह नया सन्तुलन इतने विशद रूप से स्पष्ट होगा कि परले दर्जे के दकियानूस साम्राज्यवादी भी समाजवादी शिविर

के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की निष्फलता स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे। तब समाजवादी शिविर की ताक़त का सहारा पाकर शान्तिप्रिय राष्ट्र जंगख़ोर साम्राज्यवादी जत्थों को नया विश्वयुद्ध छेड़ने के मनसूबे छोड़ देने के लिए मजबूर कर सकेंगे।

इस प्रकार, समाजवाद की विश्वव्यापी विजय से पहले ही, संसार के कुछ हिस्सों में पूंजीवाद के मौजूद रहते हुए भी, समाज के जीवन से विश्वयुद्ध का उन्मूलन करने की सच्ची सम्भावना उपस्थित हो जायेगी।

कुछ लोग कह सकते हैं: लेकिन पूंजीवाद तो तब भी अस्तित्व में रहेगा, इसलिए ऐसे दु:साहसी तो होंगे ही जो युद्ध छेड़ सकते हैं। यह बात तो सच है, और हमें यह भूलनी नहीं चाहिए। जब तक पूंजीवाद मौजूद रहेगा, तब तक ऐसे लोग तो हर वक़्त हुआ करेंगे जो विवेक को ताक़ में रखकर व्यर्थ का बखेड़ा खड़ा करने पर उतारू होंगे। लेकिन ऐसा करने से वे लोग पूंजीवादी प्रणाली के अवश्यम्भावी विघटन को और नज़दीक ही लायेंगे, और कुछ नहीं। आक्रमण के किसी भी प्रयत्न को विफल कर दिया जायेगा और दु:साहसी लोगों को ठिकाने लगा दिया जायेगा। **(देर तक तालियां)।**

साथियो, जब हम अपनी योजनाओं पर विचार करते हैं, तब हमारे सामने ऐसी ही सम्भावनाएं उपस्थित होती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से सम्बन्धित विशिष्ट समस्याओं की चर्चा करने की मुझे अनुमति दीजिये। मैं सभी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का तो ज़िक्र नहीं करूंगा, केवल मुख्य मुख्य समस्याओं पर कुछ कहूंगा।

जर्मन समस्या का उचित हल शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यन्त महत्त्व का है। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में दो बार जर्मन साम्राज्यवाद ने विश्वयुद्ध छेड़े थे। आज, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और आक्रमणकारी उत्तरी अटलांटिक सन्धि के दूसरे साझेदार

देशों के एकाधिकारवादियों की सहायता से पश्चिमी जर्मनी को नाटो का नाभिकीय शस्त्रों और राकेटों का प्रमुख अड्डा बनाया जा रहा है। अब भी पश्चिमी जर्मनी उस आक्रमणकारी गुट्ट में प्रमुख पार्ट खेलने जा रहा है। ज़ाहिर है कि पश्चिम के कुछ राजनीतिज्ञ फिरेक बार जर्मन खतरे को पूरब की ओर चलाने की सोच रहे हैं। वे भूल गये कि जर्मनी का सैन्यवाद पश्चिम का भी रास्ता जानता है।

ऐसी स्थिति पक रही है जिसमें जर्मन सैन्यवाद तीसरी बार मानव-समाज को विश्वयुद्ध में झोंक दे। पश्चिमी जर्मनी के पुन:शस्त्रीकरण से होनेवाले खतरे की ओर जब हम ध्यान दिलाते हैं तो हमें बताया जाता है कि पश्चिमी जर्मनी को नाटो के ढांचे के अन्दर जकड़कर रखा गया है, इसलिए वह अब खतरनाक नहीं रहा। लेकिन यह बात सर्व देख सकते हैं कि सैन्यवाद और प्रतिशोधवाद फिर से जिला दिये गये हैं और उनसे शान्तिप्रिय राष्ट्रों को खतरा हो गया है।

जर्मन संघात्मक जनतन्त्र उन देशों में से है जिनके शासक 'शीत युद्ध' जारी रखने और तथाकथित 'बल-प्रदर्शन की स्थिति' वाली नीति का अनुसरण करने के समर्थक हैं। चान्सलर आदिनावर तो सबसे अधिक निष्ठा से इस नीति का अनुसरण कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने और 'शीत युद्ध' समाप्त करने के उद्देश्य से कोई भी समझौता करने के प्रमुख विरोधियों में वह एक हैं। प्रभावशाली पश्चिमी गुट्टों का समर्थन आदिनावर की नीति को प्राप्त है। जो देश संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मन संघात्मक जनतन्त्र से उधार लेने की आशा से या और किसी कारण से उनके आश्रित बने हुए हैं, वे भी इस नीति की हामी भरते हैं।

जर्मन सैन्यवाद से उत्पन्न खतरे की दृष्टि से शान्तिपूर्ण राष्ट्र, खासकर पश्चिमी जर्मनी के पड़ोसी राष्ट्र, सतर्कता के क़दम उठाने के लिए विवश हुए हैं।

इधर कई बरसों से सोवियत संघ पोट्सडाम समझौते के अनुरूप जर्मनी का शान्तिपूर्ण जनतान्त्रिक विकास सम्पन्न करने तथा सैन्यवाद को फिर से पनपने न देने का प्रयत्न करता आया है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी के शासक सोवियत संघ के सभी प्रयासों का हठपूर्वक प्रतिरोध करते आ रहे हैं।

जर्मन संघात्मक जनतन्त्र से होनेवाले बढ़ते हुए ख़तरे की दृष्टि से सोवियत संघ ने हाल में जर्मन समस्या पर कई नये प्रस्ताव रखे। हमने सुझाया कि जर्मनी में विदेशी सेनाओं की संख्या क्रमशः कम की जाय, या, और भी अच्छा हो कि उन्हें पूर्ण रूप से हटा दिया जाय। हम इस बात के हक़ में हैं कि सशस्त्र सेनाओं के लिए एक 'टक्कर-रोक-क्षेत्र' क़ायम किया जाय। ये सेनाएं एक-दूसरी से जितनी दूर अलग होंगी, टक्करें व झड़पें होने का ख़तरा उतना ही कम होगा। अगर नाटो के सभी देश अपनी फ़ौजें अपने देशों की सीमाओं के अन्दर हटा लें और दूसरे देशों में बने हुए अपने अड्डे ख़त्म कर दें तो सोवियत संघ अपनी फ़ौजें जर्मनी से ही नहीं, बल्कि पोलैंड व हंगरी से भी हटाने को तैयार है जहां कि वे वार्सा सन्धि के अन्तर्गत तैनात की गयी हैं।

सोवियत संघ यूरोप में एक 'अणुशस्त्र मुक्त क्षेत्र' क़ायम करने तथा उस क्षेत्र में साधारण शस्त्रों की भी संख्या कम करने की पोलैंड की योजना का समर्थन करता है।

पिछले नवम्बर में सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ़्रांस के सामने यह प्रस्ताव रखा कि बर्लिन की बची-खुची मुक़ाबिज़ हुकूमत ख़त्म कर दी जाय और पश्चिमी बर्लिन को निःसैनीकृत आज़ाद नगर बना दिया जाय। बर्लिन समस्या का यह हल यूरोप में शान्ति क़ायम रखने के लिए उपयुक्त है और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में यह सहायक होगा।

मूलतः जर्मन समस्या का हल तब होगा जब जर्मन शान्ति-सन्धि

सम्पन्न होगी। इस बात का औचित्य सिद्ध करने का कोई भी कारण नहीं कि युद्ध समाप्त हुए चौदह साल बीत जाने पर भी, आज तक जर्मनी के साथ उन देशों की कोई शान्ति-सन्धि नहीं हो पायी है जिनके विरुद्ध वह लड़ा था। इससे 'शीत युद्ध' चाहनेवालों को तो सचमुच फ़ायदा होता है। इस बात की आड़ लेकर पश्चिमी राष्ट्र यूरोप के बीचोंबीच अपनी फ़ौजें क़ायम रख पाते हैं, वहां आणविक अग्रिम मोर्चा बनाये रख पाते हैं और जर्मनी और उसके लोगों के साथ ऐसे घमंडी ढंग से खिलवाड़ कर पाते हैं जैसे वे शतरंज के मोहरे हों।

सोवियत संघ ने शान्ति-सन्धि का जो मसविदा पेश किया है उसमें जर्मन जनता के अधिकारों, उनकी सम्पूर्ण सार्वभौमिक सत्ता और शान्तिपूर्ण जनतान्त्रिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ यूरोप में शान्ति और सुरक्षा क़ायम रखने के लिए आवश्यक क़दमों का भी समावेश किया गया है। जर्मनी के साथ शान्ति-सन्धि होते ही यूरोप में तनाव कम होगा। उससे एक निर्भर-योग्य क़ानूनी आधार स्थापित होगा और पश्चिमी जर्मनी में प्रतिशोधवादी मनोवृत्ति का आसरा उखड़ जायेगा। ऐसी शान्ति-सन्धि जर्मन जनता को विदेशी अधिक्रमण से छुड़ायेगी और घरेलू और विदेशी नीति के सभी मामलों का स्वेच्छा से निपटारा करने में उसे समर्थ बनायेगी।

सोवियत संघ ऐसी शान्ति-सन्धि सम्पन्न कराने में अपनी ओर से कोई कोशिश उठा नहीं रखेगा। वह तो इसके लिए बराबर अथक प्रयास करेगा। शान्ति-सन्धि बर्लिन की समस्या शान्तिपूर्ण एवं जनतान्त्रिक आधार पर सुलझाने को भी सुनिश्चित करेगी। उससे पश्चिमी बर्लिन को आज़ाद शहर बनाने में और उसके मामलों में दख़लन्दाज़ी न होने की आवश्यक गारंटी दिलाने में मदद मिलेगी। ऐसी गारंटी की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को बुलाया जाये। हम इन सभी समस्याओं पर बातचीत करना चाहते हैं ताकि उनका कोई विवेकशील हल निकाला

जाये। हमारे प्रस्ताव इस उद्देश्य के अनुरूप ही हैं। यूरोप के मध्यवर्त्ती राष्ट्रों के बीच मनमुटाव के बहुत-से कारण दूर करने और शान्ति को सुदृढ़ करने में ये प्रस्ताव सहायक होंगे।

वर्त्तमान अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के कारण, खासकर दोनों जर्मन राज्यों के आपसी सम्बन्ध में तनाव के कारण जर्मनी के एकीकरण में अड़चन पड़ी हुई है। शान्ति-सन्धि सम्पन्न होना जर्मनी के एकीकरण की ओर बड़ा क़दम साबित होगा।

यह बात समझी जानी चाहिए कि जर्मनी का एकीकरण जर्मन जनता का काम है—केवल जर्मन जनता का। आज जर्मनी के दो सार्वभौम राज्य हैं। विश्वयुद्ध भड़काये बिना इनमें से किसी एक को भी ख़त्म करना साध्य नहीं। इसलिए जर्मनी का एकीकरण जर्मन जनवादी जनतन्त्र और जर्मन संघात्मक जनतन्त्र के बीच वार्ता के द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है। और कोई रास्ता नहीं **(तालियां)**।

सभी विवेकशील लोग अनुभव करते हैं कि जर्मन जनवादी जनतन्त्र में जर्मन जनता जो समाजवादी लाभ प्राप्त कर चुकी है उन्हें ख़त्म करने के द्वारा जर्मनी का शान्तिपूर्ण एकीकरण सम्भव नहीं हो सकता। आदिनावर द्वारा प्रस्तुत शर्त्तों पर जर्मनी का एकीकरण करने से यूरोप की जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी, क्योंकि उसका अर्थ होगा सारे जर्मनी में सैन्यवाद, प्रतिशोधवाद और प्रतिक्रिया का फैलना। न हम यह आशा कर सकते हैं कि जर्मन संघात्मक जनतन्त्र में मौजूद सरकार को ख़त्म करके जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है।

जर्मनी के एकीकरण के सम्बन्ध में जर्मनों पर शर्तें थोपना ग़लत होगा। यह मसला तो जर्मनों को खुद ही निपटाना चाहिए। यही कारण है कि हम जर्मनी के जनवादी दलों के इस नारे का समर्थन करते हैं: "जर्मनो! एक मेज़ के गिर्द बैठो!"

पश्चिम के प्रचारक सोवियत संघ पर यह आरोप लगाते हैं कि

स्वतन्त्र चुनावों द्वारा जर्मनी के एकीकरण का वह विरोध कर रहा है। स्वतन्त्र चुनावों का तो हमने कभी विरोध नहीं किया न अब करते हैं। लेकिन हां, इस मसले का भी निपटारा ख़ुद जर्मनों को करना चाहिए। हम चाहते हैं जर्मनी के एकीकरण से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का निपटारा दोनों जर्मन राज्यों के बीच वार्ता के द्वारा किया जाये, न कि विदेशी राष्ट्रों के दबाव से, जर्मन जनता के घरेलू मामलों में विदेशियों की दख़लन्दाज़ी से और जर्मन जनवादी जनतन्त्र को निगल जाने से, जैसा कि आदिनावर चाहते हैं।

दोनों जर्मन राज्यों के एक होने में हाथ बंटाने की ख़ातिर हम जर्मन जनवादी जनतन्त्र के इस उचित प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि जर्मन जनवादी जनतन्त्र और जर्मन संघात्मक जनतन्त्र के बीच स्थायी सम्बन्ध स्थापित करने और अखिल जर्मन संस्थाओं का निर्माण करने की ओर पहले क़दम के रूप में दोनों राज्यों का संसंघ स्थापित किया जाये। अगर किसी और तरीक़े से दोनों जर्मन राज्य एकीकरण की समस्या हल कर सकते हों तो हम उसमें सहयोग देने को तैयार हैं।

इस प्रसंग में हमें चान्सलर आदिनावर का फिर से ज़िक्र करना होगा। वह शान्तिपूर्ण और जनतान्त्रिक आधार पर जर्मनी के एकीकरण के ख़्याल से डरते हैं। उनका रवैया बिल्कुल समझ में नहीं आता। न वह विवेक के अनुरूप है, न जर्मन जनता के हित के ही अनुकूल है। आदिनावर क्रिस्चियन-डिमाक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। उनकी पार्टी ईसाई धार्मिक सिद्धान्तों की रट लगाती रहती है, इसलिए ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आदिनावर उन्हीं सिद्धान्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करते होंगे। **(हॉल में हंसी)**। लेकिन यह 'ईसाई' महोदय एक हाथ में तो सलीब लिये हुए हैं, और दूसरे हाथ के लिए अणुबम चाहते हैं। इतना ही नहीं, वह तो सलीब से बढ़कर अणुबम पर भरोसा रखते हैं, हालांकि ऐसा करना ईसाई दर्शन और जर्मन जनता के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है।

श्री आदिनावर वयोवृद्ध हैं, अनुभववृद्ध भी। उन्हें यह क्यों नज़र नहीं आता कि नाभिकीय शस्त्र केवल उनके साथियों के पास ही नहीं, बल्कि सोवियत संघ के पास भी हैं? यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये शस्त्र असंख्य मानव-प्राणों की बलि ले सकते हैं। और चूंकि पश्चिमी जर्मनी को आणविक अड्डा बनाया जा रहा है, इसलिए युद्ध छिड़ने पर उसी की जनता को सबसे पहले बलिपशु बनना होगा।

अगर श्री आदिनावर सचमुच भक्त हैं तो उन्हें चाहिए कि ईसाई धार्मिक नियमों का पालन करते, परलोक की चिन्ता करते और अपनी 'आत्मा के उद्धार' का विचार करते **(ज़ोर की हंसी)**। लेकिन उनके कारनामों को देखते हुए यह आशा बिल्कुल नहीं बंधती कि उनकी आत्मा कभी स्वर्ग जायेगी **(हॉल में सजीवता)**। धर्मग्रन्थों के अनुसार तो ऐसी कारस्तानियां इनसान को नरक पहुंचाती हैं **(ज़ोर की हंसी)**।

संसार के एक और भाग—सुदूर पूर्व—में चीनी जनवादी जनतन्त्र तथा दूसरे शान्तिप्रिय राज्यों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की आक्रमणकारी नीति तनाव का मुख्य कारण बनी हुई है। कुछ समय पहले संसार ने चिन्ता के साथ देखा कि किस तरह अमेरिका की आक्रमणकारी चालों ने सशस्त्र युद्ध का भयानक अग्निकांड मचाने का ख़तरा पैदा कर दिया था। चीनी जनवादी जनतन्त्र और दूसरी शान्तिप्रिय शक्तियों के दृढ़तापूर्ण रुख़ का शुक्र है कि यह ख़तरा किसी तरह टल गया।

प्रशान्त सागरीय क्षेत्र अमेरिका के नाभिकीय शस्त्रों का प्रमुख परीक्षण-स्थान बन गया है।

इन सब बातों के कारण उस भूभाग में युद्ध, ख़ासकर आणविक युद्ध, न होने देने के लिए सक्रिय क़दम उठाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। दूसरे इलाक़ों के मुक़ाबले में वहां शान्ति की सम्भावना अधिक प्रबल मालूम पड़ती है, क्योंकि सोवियत संघ, चीनी जनवादी जनतन्त्र,

कोरियाई जनवादी जनतन्त्र और वियतनामी जनवादी जनतन्त्र के साथ साथ भारत, इन्दोनेशिया, बर्मा और उस इलाक़े के दूसरे देश शान्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। आणविक शस्त्रों और नाभिकीय परीक्षणों का निषेध करने के लिए इन देशों की संयुक्त कार्रवाई, प्रशान्त सागरीय प्रदेश में शान्ति क़ायम रखने में संभवतः बड़ी हद तक हाथ बंटाये। इस दिशा में उनकी पहलक़दमी का जापान व प्रशान्त सागरीय प्रदेश के अन्य देशों के लोग भी शायद समर्थन करें। **पूर्वी एशिया में और समूचे प्रशान्त सागरीय प्रदेश में शान्ति का क्षेत्र, मुख्यतया अणुशस्त्र-मुक्त क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है, और स्थापित होना चाहिए।**

निकट और मध्यपूर्व की घटनाओं से प्रगतिशील लोग खुश हो सकते हैं। अरब जनता और एशिया व अफ़्रीका के जिन लोगों ने औपनिवेशिक जुए को उतार फेंका है, उनके राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन का हम स्वागत करते हैं। उस प्रदेश के कई देशों से विदेशी साम्राज्यवादियों की फ़ौजों का खदेड़ा जाना अरब जनता की और शान्ति की शक्तियों की बड़ी विजय है। लेकिन हमें यह नहीं समझना चाहिए कि उत्तेजना की आशंका वहां बिल्कुल न रही, क्योंकि उपनिवेशों से खदेड़े गये उपनिवेशवादी कभी दिल से हार नहीं मानेंगे। पश्चिमी राष्ट्र, ख़ास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, कुछ अरब राज्यों को दूसरे अरब राज्यों के ख़िलाफ़ उकसाकर भड़का रहे हैं, ईराक़ और दूसरे देशों में कुचक्र रच रहे हैं। वे कमज़ोर नुक़्तों की खोज में लगे रहते हैं ताकि आज़ाद जनताओं में, मुख्यतया अरब राष्ट्रों की जनताओं में, फूट डाल सकें।

जब लोग औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की ख़ातिर लड़ते हैं, तब तो सभी देशभक्त शक्तियां संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे पर संगठित होती हैं।

साम्राज्यवादी चंगुल से छूटने के लिए मिस्री और दूसरी अरब जनताओं ने जब संघर्ष किया, तब यही बात हुई। मिस्र से उपनिवेश-

वादियों को मार भगाने और स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण करने की खातिर सभी राष्ट्रीय शक्तियां कंधा-ब-कंधा होकर लड़ीं। सभी प्रगतिशील लोगों ने मिस्र की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का स्वागत किया। ईराक़ में साम्राज्यवादियों के पिट्ठू बने हुए प्रतिक्रियावादी गुट्ट का उन्मूलन हुआ और आज़ाद जनतन्त्र स्थापित हुआ। सोवियत जनता और दूसरे समाजवादी देशों की जनता ने अरब जनों के न्यायसंगत संघर्ष का समर्थन किया। संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासर और ईराक़ जनतन्त्र सरकार के प्रधान अब्दुल क़रीम कासिम जैसे स्वतन्त्रता-आन्दोलन के प्रमुख नेताओं को सोवियत जनों का हार्दिक सम्मान प्राप्त है।

उपनिवेशवादियों के खदेड़े जाने और सभी राष्ट्रीय कर्त्तव्यों के मुख्यतः पूरे होने के बाद लोग मूलभूत सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढ़ते हैं। यह बात मुख्य रूप से कृषि और किसान-समस्या और पूंजी व श्रम के संघर्ष की समस्याओं पर सर्वोपरि लागू होती है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन के अन्तर्गत सामाजिक प्रक्रियाएं उठ खड़ी होती हैं। इनके कारण अपने अपने राज्य के भावी विकास के बारे में अनिवार्य रूप से मतभेद पैदा होते हैं।

हमारा देश, दूसरे समाजवादी देशों की ही तरह, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन का सदा साथ देता रहा है और रहेगा। सोवियत संघ दूसरे देशों के घरेलू मामलों में कभी दखल नहीं देता, न दखल देने का इरादा ही रखता है। लेकिन कुछ देशों में कम्यूनिज़्म के विरोध के झूठे बहाने की आड़ में प्रगतिशील लोगों के विरुद्ध जो मुहिम चलायी जा रही है, उसे देखते हुए हम मौन नहीं रह सकते। हाल में संयुक्त अरब गणराज्य में कम्यूनिज़्म के विचारों के विरुद्ध वक्तव्य निकले और कम्यूनिस्टों पर आरोप लगाये गये, इसलिए, मैं एक कम्यूनिस्ट के नाते हमारी कम्यूनिस्ट पार्टी की इस कांग्रेस में यह घोषणा करना आवश्यक

समझता हूं कि कम्यूनिस्टों पर साम्राज्यवाद के विरुद्ध होनेवाले संघर्ष में राष्ट्रीय प्रयास को शिथिल और विभाजित करने में हाथ बंटाने का आरोप लगाना ग़लत है। सचाई तो इससे बिल्कुल भिन्न है। उपनिवेशवादियों के विरुद्ध संघर्ष में कम्यूनिस्टों से अधिक अटल इरादा और निष्ठा रखनेवाले और कोई नहीं **(देर तक जोर की तालियां)**। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में कम्यूनिज़्म की शक्तियों से बढ़कर अटल इरादा रखनेवाली और कोई शक्ति नहीं। साम्राज्यवादी तत्त्व कम्यूनिस्ट आन्दोलन के विरुद्ध अपना संघर्ष तीव्र कर रहे हैं तो यह कोई संयोग की बात नहीं।

कम्यूनिस्टों और दूसरी प्रगतिशील पार्टियों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ना प्रतिक्रियाशील काम है। कम्यूनिस्ट विरोधी नीति से राष्ट्रीय शक्तियों में एका नहीं होता। उससे तो उनमें फूट पड़ती है और फलतः साम्राज्यवाद के ख़तरे से राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का प्रयास शिथिल पड़ता है। कम्यूनिस्टों पर यह आरोप लगाना ग़लत है कि वे अरब जनता के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। कम्यूनिज़्म और यहूदी राज्यवाद को एक-जैसा मानना भी बचकाना बात है। यह स्मरण रहे कि कम्यूनिस्ट, इज़राइल के कम्यूनिस्ट भी, यहूदी राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं।

हर बात में 'कम्यूनिस्ट कुचक्र' की कल्पना करना बुद्धिमत्ता नहीं। सामाजिक विकास की समस्याओं को अधिक सोच-विचार कर आंकना चाहिए। सामाजिक विकास के निरपेक्ष नियम होते हैं। वे यह दिखाते हैं कि राष्ट्रों के अन्दर भिन्न भिन्न हितोंवाले वर्ग होते हैं। औपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवादी चंगुल से छुटकारा मिलने पर श्रमिक काम के समय में कमी और वेतन में वृद्धि की मांग करते हैं। किसान ज़्यादा ज़मीन की और अपने श्रम का फल भोगने के अवसर की मांग करते हैं। श्रमिक और किसान दोनों ही राजनीतिक अधिकार चाहते हैं। इसके विपरीत, पूंजीपति ज़्यादा नफ़ा कमाना चाहते हैं और भूस्वामी ज़मीन को अपने ही क़ब्ज़े में रखना चाहते हैं। प्रगतिशील लोग चाहते हैं कि उनके देश

की सामाजिक प्रगति हो। वे उसकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को सुदृढ़ बनाना और उसे साम्राज्यवादी षड्यन्त्रों से बचाना चाहते हैं। देश के भीतर की प्रतिक्रियाशील शक्तियां इन सब बातों का प्रतिरोध करती हैं और अक्सर बाहर से साम्राज्यवादी उन्हें उकसाते हैं।

साम्राज्यवादी जुए से छूटे हुए देशों में ये जो प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, वे किसी पार्टी की इच्छा और कामना से तो नहीं होतीं। वे शुरू होती हैं इसलिए कि अलग अलग वर्ग मौजूद होते हैं और उनके हित भिन्न भिन्न होते हैं। हम कम्यूनिस्ट और सभी प्रगतिशील लोग स्वभावतः उन लोगों से सहानुभूति रखते हैं जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं **(देर तक तालियां)**।

हम इस बात से इन्कार नहीं करते कि विचारधारा के क्षेत्र में हमारे और संयुक्त अरब गणराज्य के कुछ नेताओं के मत भिन्न भिन्न हैं। लेकिन साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने में, उपनिवेशवाद के जुए से छूटे हुए देशों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतन्त्रता को सुदृढ़ बनाने में और युद्ध के ख़तरे के विरुद्ध संघर्ष करने में हमारे रुख उनके रुख़ों से मिलते हैं। हमारे विचारधारात्मक दृष्टिकोणों में जो अन्तर है उससे हमारे देशों के बीच मैत्री-सम्बन्ध बढ़ने में तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे मिले-जुले संघर्ष में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए **(तालियां)**।

निकट और मध्यपूर्व में घूमने-फिरनेवाले साम्राज्यवादी एजेंट कुछ लोगों के मन में कम्यूनिज्म का भय बिठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से वे अपना प्रभाव बढ़ाने और स्थानीय प्रतिक्रियावादियों का साथ देने की आशा करते हैं। इस कारण वहां के लोगों को साम्राज्यवादी चालों से सतर्क रहना चाहिए।

जो देश राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुके हैं उन्हें समाजवादी देशों और सभी प्रगतिशील तत्त्वों की सहायता की आवश्यकता है और भविष्य में भी आवश्यकता होगी। सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी

देश उनके साथ घनिष्ठतर मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वे उन देशों की सहायता कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे।

साम्राज्यवादी राष्ट्र अनुन्नत देशों के साथ अपने आर्थिक सम्बन्धों से लाभ उठाकर इन देशों को डराते-धमकाते व लूटते-खसोटते हैं। वे इन देशों पर फ़ौजी व राजनीतिक शर्त्तें थोपते हैं। इसके विपरीत, हमारा देश सभी राज्यों के साथ सम्पूर्ण समानता और सहयोग के आधार पर, किसी प्रकार की फ़ौजी या राजनीतिक शर्त्त लगायें बिना, सम्बन्ध स्थापित करता है। हम दान देते नहीं फिरते। सोवियत संघ न्यायोचित व्यापारिक आधार पर सहायता देता है। समाजवादी देश अनुन्नत देशों को राष्ट्रीय उद्योग स्थापित करने में मदद देते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसी उपभोक्ता-वस्तुएं उनके गले मढ़ने की कोशिश करता है जिनकी स्वदेश में कोई मांग नहीं होती। सप्तवर्षीय योजना के फलस्वरूप औद्योगिक दृष्टि से अविकसित देशों के साथ सोवियत संघ के आर्थिक सहयोग की नयी सम्भावनाएं उपस्थित हो गयी हैं।

अपनी आज़ादी और स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रों के संघर्ष में अब एक नया दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन सभी औपनिवेशिक एवं पराधीन देशों में फैल रहा है। दक्षिणी अमेरिका के लोगों ने अमेरिका के साम्राज्यवादी दमन का विरोध तीव्र कर दिया है। एशिया और अफ़्रीका के लोगों में भावनात्मक उथल-पुथल मची हुई है। जो लोग राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुके हैं, वे अपने भाग्य का खुद ही निर्णय करना चाहते हैं। अब उन्हें शान्ति की पहले से भी अधिक आवश्यकता है। बड़े राष्ट्रों को चाहिए कि अरब राष्ट्रों व अफ़्रीकी राष्ट्रों की सार्वभौमिकता की क़द्र करने, विवादास्पद मामलों के निपटारे में बल-प्रयोग छोड़ देने और उन देशों के अन्दरूनी मामलों में दखलन्दाज़ी न करने का हार्दिक आश्वासन दें। ऐसे बारूदखानों के स्थान पर जहां छिछोरे सूरमे आग से खेला करते हैं, हमें ऐसा प्रदेश स्थापित करना चाहिए जहां शान्ति हो स्वतन्त्र राष्ट्रीय विकास हो।

भिन्न भिन्न प्रदेशों में स्थिति सुधारने के लिए जो क़दम उठाये जायें उनके साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को समूचे रूप से सुधारने का भी प्रयत्न होना चाहिए।

निःशस्त्रीकरण के मसले पर उत्पन्न गत्यवरोध को दूर करना आज का प्रमुखतम कर्त्तव्य है। शस्त्रों की होड़ धड़ाधड़ चल रही है, दिन पर दिन अधिक धनराशि और साधन उसपर स्वाहा हो रहे हैं। शस्त्रों के निर्माण के लिए धन एकत्र करने की ख़ातिर पूंजीवादी सरकारें अपने बजटों का अधिकांश हिस्सा सैनीकरण में लगा रही हैं और श्रमिक जनता को लूटने-खसोटने की नीति अपना रही हैं। "तन का कपड़ा भले ही जाये, तलवार हाथ में ज़रूर आये" वाले सिद्धान्त पर वे अमल कर रही हैं **(हॉल में सजीवता)।**

अणु एवं उदजन शस्त्रों के परीक्षणों पर रोक लगाना ख़ास तौर से ज़रूरी है। अब तो सभी यह मान चुके हैं कि पृथ्वी के किसी भी कोने में होनेवाले आणविक विस्फोटों का भी पता लगाया जा सकता है। ऐसे में इस मामले का निपटारा करने में अब भी विलम्ब करने का कोई कारण नहीं रहा। इन परीक्षणों के कारण संसार का वायुमण्डल हानिकारक विकिरण से कलंकित हो उठता है, इस कारण सभी देशों के लोग ये परीक्षण बन्द करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग पूरी की जानी चाहिए।

हम इस सिद्धान्त पर चल रहे हैं कि भिन्न भिन्न सामाजिक प्रणालियोंवाले राज्यों के बीच का सम्बन्ध शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के आधार पर पनपना चाहिए। हमारे और पूंजीवादी देशों के शासकों के विचार भिन्न हैं, विश्व-दृष्टिकोण भिन्न हैं। हम अपने विचार कभी नहीं बदलेंगे। हम इस भ्रम में भी नहीं हैं कि हमारे वर्ग-प्रतिपक्षी अपने विचार बदलेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मतभेद को लेकर हम एक-दूसरे से लड़ने पर आमादा हो जायें। प्रत्येक देश के लोग स्वयं ही अपने भाग्य का

निर्णय करते हैं और विकास का मार्ग चुनते हैं। सोवियत संघ किसी के ऊपर अपना मार्ग थोपने का इरादा नहीं रखता। हम व्ला० इ० लेनिन के इस सिद्धान्त को पथप्रदर्शक मानकर चलते हैं कि क्रान्तियों का निर्यात नहीं हो सकता।

क्या भिन्न भिन्न सामाजिक प्रणालियोंवाले राज्यों के नेताओं के लिए यह निश्चय करना और अविलम्ब यह निश्चय करना अच्छा न होगा कि चूंकि हम सब एक ही ग्रह के निवासी हैं, वह भी वर्त्तमान इंजीनियरिंग के मानदण्ड के अनुसार कोई ख़ास बड़ा नहीं, इसलिए यह उचित है कि हम जियें और जीने दें, दूसरे की ओर अणु और उदजन शस्त्रों के रूप में हर वक़्त मुक्के का इशारा न करते रहें? हमें अपने विवादों का निपटारा शान्तिपूर्ण वार्ता द्वारा करना सीखना चाहिए।

अब यह समझने का समय आ गया है कि सोवियत संघ और समाजवादी शिविर को धमकी देने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। संसार की स्थिति में सामरिक महत्त्व के जो आमूल परिवर्तन हुए हैं उन्हें मानने का भी समय आ गया है।

सोवियत विज्ञान और प्रविधि ने अन्तरिक्ष में मनुष्य का पथ आलोकित कर दिया है और आज सभी उनकी सफलताओं को मानते हैं। ये सिद्धियां सोवियत संघ की, विश्व समाजवादी प्रणाली की, साधन-सम्पन्नता की द्योतक हैं। यह तो स्पष्ट है कि अगर सोवियत संघ अन्तरिक्ष में लाखों किलोमीटर दूर राकेट चला सकता है तो वह पृथ्वी के किसी नुकते पर अचूक निशाना बांधकर शक्तिशाली राकेट मार सकता है **(तालियां)।**

लेकिन इन तथ्यों से हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वे पश्चिम के कुछ तबक़ों के निष्कर्षों से भिन्न होते हैं। पश्चिम के ये तबक़े तो विज्ञान और प्रविधि की प्रत्येक सिद्धि का मूल्य मुख्य रूप से उसकी सामरिक क्षमता की दृष्टि से आंकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला अणुबम तैयार

होने के बाद अमेरिका के नीति-निर्माता विश्व-आधिपत्य का दावा करने में क्षण भर भी न चूके।

सोवियत संघ का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम सोवियत विज्ञान और प्रविधि की ऐतिहासिक सिद्धियों को फ़ौजी नीति का समर्थन करने के लिए या दूसरे देशों से अपनी इच्छा मनवाने के लिए काम में नहीं लाते। हम तो विश्व शान्ति के संघर्ष में अपने प्रयास दुगुने उत्साह से जारी रखने में उनसे काम लेते हैं। आज राकेट इंजीनियरिंग में हमारी स्थिति अनुकूल होने पर भी हम संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ़्रांस से फिर एक बार कहते हैं: आइये, हम अणु, उदजन और राकेट-शस्त्रों के परीक्षण, निर्माण और उपयोग का सदा के लिए निषेध करें; इन नाशकारी शस्त्रों के सभी संचय नष्ट करें, मानव प्रतिभा के इस सर्वोच्च आविष्कार को हम शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, सब की भलाई के लिए, काम में लायें। इस सम्बन्ध में किसी उपयुक्त समझौते पर किसी भी वक़्त दस्तख़त करने को हमारी सरकार तैयार है **(देर तक तालियां)।**

बड़े राष्ट्रों के अनुसरण करने योग्य एक ही विवेकशील नीति है। वह यह कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का शान्तिपूर्ण ढंग से निपटारा कर लें और आम निःशस्त्रीकरण शुरू कर दें।

साल भर से पहले सोवियत सरकार ने सुझाव रखा था कि पूर्व और पश्चिम के सरकारी प्रधानों की बैठक की जाये। तब से इस सिलसिले में कोई प्रगति नहीं हुई है और इसका दोष पश्चिमी राष्ट्रों पर है। शान्ति व सुरक्षा चाहनेवाले सभी लोगों की आशा इसी बैठक पर केन्द्रित है, इसलिए हम ऐसी बैठक बुलाने के लिए कोशिश जारी रखना संसार के सभी देशों के लोगों के प्रति अपना कर्त्तव्य मानते हैं।

शान्ति क़ायम रखने में दो बड़े राष्ट्रों–सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका–की विशेष ज़िम्मेदारी की ओर हमें बार बार ध्यान दिलाना

पड़ा। जहां तक सोवियत संघ से सम्बन्ध है, उसने संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने सम्बन्ध ठीक करने की हार्दिक इच्छा बार बार व्यक्त की है और अपने शब्दों को कार्यों से पुष्ट किया है। सोवियत संघ ने पचास साल की अनाक्रमण-सन्धि का प्रस्ताव रखा। उसने सुझाया कि दोनों देशों में व्यापारिक लेनदेन बढ़ायी जाये, सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ें वग़ैरह। लेकिन हर बार हमारा सुझाव आंख मूंदकर ठुकरा दिया गया या छिपे तौर पर उसका विरोध किया गया।

हमारे दोनों देशों का एक दूसरे के प्रदेश पर कभी किसी प्रकार का दावा न रहा है। हमारी दोनों जनताओं में टक्कर की कोई गुंजाइश नहीं। फिर भी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बन्ध इधर एक अर्से से बिगड़े हुए हैं।

हम जानते हैं कि अमेरिका के बहुत-से राजनीतिज्ञों, पूंजीपतियों, कांग्रेस-सदस्यों और समाचारपत्र-प्रकाशकों का हित हमारे सम्बन्ध बिगड़े रहने में निहित है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है जो सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण, अच्छे पड़ोसी के सम्बन्ध क़ायम करना चाहते हैं। अमेरिका में अ० इ० मिकोयान का जो स्वागत हुआ, वह इस बात का प्रमाण है। उनकी यात्रा के समय अमेरिका की जनता ने सोवियत संघ की जनता के प्रति मैत्री का भाव व्यक्त किया। जिन अमेरिकियों से उन्होंने बातचीत की, उनमें से अधिकांश ने सोवियत संघ की जनता के साथ खुले तौर पर हार्दिक सहानुभूति व्यक्त की। इन लोगों ने कहा कि वे सोवियत संघ के साथ मैत्री व शान्तिपूर्ण सहयोग चाहते हैं। इस तरह के विचार व्यक्त करनेवालों में भिन्न भिन्न धार्मिक व राजनीतिक विचारों के लोग थे, समाज में उनकी हैसियतें भी भिन्न भिन्न थीं। उनमें वैज्ञानिक थे, सांस्कृतिक कार्यकर्त्ता थे, कारोबारी थे और साधारण जन भी। यह स्पष्ट है कि अमेरिका के अधिकांश लोग वहां के प्रतिगामी पूंजीवादी समाचारपत्रों में छपनेवाले सोवियत-विरोधी

प्रचार पर अब विश्वास नहीं करते। साथी मिकोयान की यात्रा के समय कुछ तत्त्वों ने उत्तेजना भड़काने के कार्य आयोजित करने की कोशिशें कीं, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि ये तत्त्व अमेरिकी जनता के उद्गारों-विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।

अमेरिका के जो लोग 'शीत युद्ध' खत्म करना चाहते हैं और सभी देशों में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहयोग का समर्थन करते हैं, उनके प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। अमेरिकी जनता की औद्योगिक प्रतिभा और कार्य-दक्षता तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। हमारे देश में अमेरिकी जनता के प्रति गहरी सहानुभूति विद्यमान है।

लेकिन हा, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के रास्ते में कितनी ही बाधाएं हैं। इस पथ का अनुगमन करते हुए दोनों पक्षों को एक-दूसरे को समझने की हार्दिक इच्छा दिखानी चाहिए और बड़ा ही संयम, या यों कहिये, बड़ी सहिष्णुता बरतनी चाहिए **(तालियां)**।

व्यापक रूप से **विश्व-व्यापार का विस्तार** अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में और आपसी विश्वास सुदृढ़ करने में शायद बड़ा सहायक हो सकता है।

वर्तमान रुकावटों के बावजूद सोवियत संघ और यूरोप व अमेरिका के पूंजीवादी देशों के बीच व्यापार, १९५० की तुलना में १९५८ में, लगभग तिगुना हुआ है। हम स्वीडन के साथ अच्छा कारोबार चला रहे हैं। फ़्रांस और इटली के साथ लम्बे अर्से के व्यापार-समझौते सम्पन्न हुए हैं। दूसरे देशों के साथ भी हमारा व्यापार बढ़ रहा है।

१९५९-१९६५ के लिए शान्तिपूर्ण विकास का सोवियत आर्थिक कार्यक्रम सभी देशों के साथ सोवियत वैदेशिक व्यापार बढ़ाने की अच्छी सम्भावनाएं प्रस्तुत करता है। हम इस व्यापार की मात्रा कम से कम दुगुनी कर सकते हैं।

पूंजीवादी देशों के सामने हम शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखते हैं और हमारा यह प्रस्ताव सप्तवर्षीय योजना-काल से भी आगे के

लिए है। हम तो एक दीर्घकालीन विकास-योजना तैयार कर रहे हैं जो पन्द्रह वर्ष की होगी। सिद्धान्त-रूप से यह योजना भी शान्तिपूर्ण विकास और शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर बनी है।

सभी राष्ट्र यह देख सकते हैं कि **हमारी योजनाएं शान्तिपूर्ण निर्माण की योजनाएं होती हैं। हम सभी लोगों को शान्ति रखने और सुदृढ़ करने की खातिर कठिनतर श्रम करने के लिए आह्वान करते हैं। अपनी ओर से हम सारे संसार में शान्ति को सुनिश्चित रखने के लिए वशभर हर तरह का प्रयास करेंगे (देर तक ज़ोर की तालियां)।**

सोवियत संघ में कम्यूनिस्ट निर्माण और अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग-आन्दोलन

साथियो, हमारी सप्तवर्षीय योजना अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक व कम्यूनिस्ट आन्दोलन के लिए, सभी जनवादी शक्तियों के लिए, प्रतिक्रियावाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनके संघर्ष में शक्तिशाली नैतिक सहायता प्रस्तुत करती है। कम्यूनिज़्म के निर्माण में नयी प्रगति करने के द्वारा सोवियत जनता अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग के प्रति अपना अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य निभायेगी।

इस समय ८३ देशों में कम्यूनिस्ट और कामगार पार्टियां हैं। उनकी कुल सदस्य संख्या ३३० लाख से ऊपर है। यह मार्क्सवाद-लेनिनवाद की बड़ी भारी विजय है, श्रमिक वर्ग के लिए बड़ा लाभ है (**देर तक तालियां**)।

सभी प्रकार के प्रतिक्रियावादियों ने कम्यूनिज़्म के विरुद्ध बीसियों मुहिमें चला रखी हैं। लेकिन कम्यूनिस्ट आन्दोलन को कोई कुचल नहीं सकता, क्योंकि वह सर्वहारा वर्ग-संघर्ष का, सभी श्रमिक लोगों के संघर्ष का शिशु है और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता है। पूंजीवादी देशों

की कई कम्यूनिस्ट पार्टियां इस समय बड़ी कठिनाइयों से गुज़र रही हैं। प्रतिक्रिया ने उनके विरुद्ध एक नया दीवानावार हल्ला बोल दिया है। हमें विश्वास है कि यह हमला भी आख़िर पस्त होकर रहेगा और हमारी भ्रातृ-पार्टियां इस आग में तपकर पहले से कहीं ताक़त के साथ इस्पात बन निकलेंगी (**देर तक तालियां**)।

श्रमिक वर्ग और कम्यूनिस्ट आन्दोलन के विरुद्ध आक्रमण करते समय अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सामाजिक धांधलेबाज़ी से काम लेती है और तथाकथित 'स्वतन्त्र संसार' के बारे में झूठी कहानियां सुनाकर आम जनता को फुसलाती है। साम्राज्यवादी विचारधारा के प्रचारक जन-विरोधी पूंजीवादी प्रणाली को ऊपरी सजधज से आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमुख पूंजीवादी नेता यह कहने से कभी नहीं चूकते कि पश्चिम के पूंजीवादी देश 'स्वतन्त्र देश' हैं और पूंजीवादी संसार 'स्वतन्त्र संसार' है।

वेशक पूंजीवादी देशों में आज़ादी तो है, लेकिन किसे? कामगारों को तो हरगिज़ नहीं। उन्हें तो किसी भी शर्त्त पर पूंजीवादियों के अधीन नौकरी स्वीकार करनी पड़ती है—इस आफ़त से बचने के लिए कि कहीं उन्हें ऐसे लोगों की विशाल सेना में शरीक न होना पड़े जो काम से 'आज़ाद' होते हैं। क्या किसानों को आज़ादी है? नहीं, क्योंकि उनके सामने तो यह खतरा हर वक़्त बना रहता है कि कहीं बर्बादी के कारण उन्हें अपने खेतों से 'आज़ाद' न होना पड़े। बुद्धिजीवियों को भी आज़ादी नहीं, क्योंकि उनका सृजनात्मक प्रयास पैसे के लिए रुपये के थैलों के आश्रित रहने की विवशता के कारण तथा तरह तरह के वफ़ादारी-कमीशनों के 'आत्मिक पथप्रदर्शन' के कारण कुंठित रहता है। पूंजीवादी देशों में तो आज़ादी केवल उन लोगों को मिली हुई है जिनके पास पूंजी है और फलतः जिनके हाथ में ताक़त है।

'स्वतन्त्र संसार' के राजनीतिज्ञ और विचारधारा-प्रचारक धार्मिक नीति के सिद्धान्त बघारना पसन्द करते हैं। लेकिन ईसा के बारे में धार्मिक

ग्रन्थों में लिखित वर्णनों से उन्हें जानना चाहिए कि जब ईसा ने मन्दिर में व्यापारियों और महाजनों को सौदेबाज़ी करते देखा तो उन्हें कोड़ा मारकर भगा दिया **(हॉल में सजीवता)**। अगर ये लोग धार्मिक सिद्धान्तों को मानते हैं तो फिर उन्होंने अपने द्वारा शासित समाज को धनियों का स्वर्ग और ग़रीबों का नरक क्यों बना रखा है? ईसाई धर्म की एक दृष्टान्त-कथा में कहा गया है कि सुई के छेद से ऊंट का निकल जाना उससे कहीं आसान है जितना कि धनी व्यक्ति का स्वर्ग जाना! इसके बावजूद पूंजीवादी संसार का यह हाल है। दर असल 'स्वतन्त्र संसार' है डालर का राज्य, नफ़ा कमाने और मनमानी नफ़ाख़ोरी का राज्य, मुट्ठीभर एकाधिकारियों की तिजोरियां भरने के लिए करोड़ों जनों का निर्मम शोषण करने का राज्य।

एक ज़माना था जब सामन्तवाद के विरुद्ध अपने संघर्ष में बूर्जुआ क्रान्तिकारियों ने स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारे के आकर्षक नारे बुलन्द किये थे। लेकिन बूर्जुआओं ने मुख्य रूप से भूस्वामियों को एक ओर हटाकर पूंजीपतियों के लिए रास्ता हमवार करने के ही इरादे से ये नारे लगाये थे। अपनी सत्ता की जड़ जमाने के बाद बूर्जुआ क्रमशः ये नारे भूलते गये।

आज भी साम्राज्यवादी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारे के नारे तो ख़ूब लगाते हैं, लेकिन असल में वे अक्सर खुली तानाशाही से काम लेते हैं। आज तो पूंजीवादी देशों में प्रतिक्रिया और फ़ासिज़्म के उभरने के मनहूस आसार नज़र आ रहे हैं। यही प्रतिक्रियाशील रास्ता पश्चिमी जर्मनी ने अपनाया है। वहां पर कम्यूनिस्ट पार्टी पर रोक लग गयी है, जनवादी उत्पीड़ित हो रहे हैं और फ़ासिस्ट व प्रतिशोधवादी संगटनों को खुली छूट मिली हुई है। फ़्रांस में खुली तानाशाही की ओर रुझान साफ़ रोशनी में आया है। वहां तो जनवादी अधिकारों और जनता द्वारा प्राप्त लाभों को रौंदा जा रहा है। फ़्रांस जैसे देश में,

जो अपनी जनवादी परम्पराओं के लिए प्रसिद्ध है, प्रतिक्रिया का यह बोलबाला जनतन्त्रवाद और प्रगति के सभी प्रेमियों के मन में चिन्ता पैदा कर रहा है। पाकिस्तान और थाइलैंड में सैनिकों का बलात् सत्ताग्रहण यह दिखाता है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त देशों के जनवादी लाभों पर धावा बोलने की तैयारियां हो रही हैं। दूसरे कुछ पूंजीवादी देशों में भी प्रतिक्रिया की शक्तियां सिर उठा रही हैं।

इस तरह हम बहुत-से पूंजीवादी देशों में पायी जानेवाली एक नपी-तुली आम प्रवृत्ति का सामना कर रहे हैं, न कि अलग अलग तथ्यों का।

प्रतिक्रियावादी उसी पुराने जन-विरोधी हथियार से काम ले रहे हैं—वे जनतन्त्रवादी प्रणाली को हटाकर उसकी जगह 'लाठीमार' सरकारें क़ायम कर रहे हैं। लेकिन जैसे इटली और जर्मनी में फ़ासिस्ट तानाशाहियां क़ायम होते समय स्पष्ट था, खुली तानाशाही की ओर एकाधिकारी बूर्जुआओं की यह प्रवृत्ति ताक़त का निशान नहीं, बल्कि कमज़ोरी का निशान है। फिर भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि असीमित तानाशाही के अन्दर प्रतिक्रिया को इस बात का बेहतर मौक़ा मिलता है कि वह आतंक और दमन का राज बरपा करे, सब प्रतिपक्षियों को दबाये, अपने मक़सद साधने के लिए जनता में ग़लत विचार फैलाये, उग्र राष्ट्रीयता की महामारी से जनता का मन विषाक्त करे, और बेरोकटोक फ़ौजी जुआख़ोरी कर सके। इस कारण लोगों को ख़ूब चौकस रहना चाहिए। प्रतिक्रियावादी आक्रमण और नये उभरते फ़ासिज़्म के ख़तरे का सामना कर उन्हें पछाड़ने के लिए लोगों को सदा-सर्वदा तैयार रहना चाहिए।

फ़ासिज़्म का नाम लेने पर करोड़ों लोगों को प्रायः हिटलर और मुसोलिनी के नाम याद आते हैं। लेकिन हमें यह बात असम्भव नहीं समझनी चाहिए कि फ़ासिज़्म जिन रूपों में राष्ट्रों की निगाह में पतित हो चुका है, उनके अलावा भी दूसरे रूपों में जी उठ सकता है।

आज शक्तिशाली समाजवादी शिविर विद्यमान है, प्रतिक्रिया के विरुद्ध लोहा लेने में श्रमिक वर्ग-आन्दोलन बहुत अनुभव प्राप्त कर चुका है और श्रमिक वर्ग पहले से कहीं सुसंगठित हैं। इस कारण फ़ासिज़्म का बढ़ाव रोकना जनता के लिए अधिक सुगम है। जनता के विशाल तबक़े, सभी जनतन्त्रवादी, सच्चे राष्ट्रवादी तत्त्व एक साथ संगठित होकर फ़ासिज़्म का प्रतिरोध कर सकते हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। ऐसा करते हुए यह ज़रूरी है कि तबकापरस्ती का लेशमात्र भी न रहे, वरना प्रतिक्रिया और फ़ासिज़्म के विरुद्ध जनता का सांझा मोर्चा क़ायम करने में अड़चन पेश आ सकती है। जनतन्त्रवादी तत्त्वों की सबसे ऊपर श्रमिक वर्ग की एकता ही फ़ासिस्ट ख़तरे को रोकने का सबसे निर्भर-योग्य अवरोध है।

श्रमिक वर्ग की एकता में ख़लल डालनेवाला आख़िर कौन है? ये हैं, साम्राज्यवादी प्रतिगामी और श्रमिक वर्ग-आन्दोलन में घुसे हुए गाइ मोले और स्पाक जैसे उनके भाड़े के टट्टू – कम्यूनिस्ट-विरोधी विचारोंवाले सोशल-डिमाक्रेटिक नेता। कम्यूनिस्ट-विरोध के इन सब नेताओं के तो हम नाम तक जानते हैं, इसलिए श्रमिक वर्ग के संयुक्त कार्य की चर्चा करते वक़्त उन्हें गिनती में ही नहीं लेते। सोशल-डिमाक्रेटिक पार्टियों के अधिकांश साधारण सदस्य शान्ति और सामाजिक प्रगति के हामी हैं, हालांकि इनकी प्राप्ति कैसे हो, इस सम्बन्ध में उनका विचार हमारे विचार से, यानी कम्यूनिस्ट विचार से भिन्न है। सच बात तो यह है कि प्रतिक्रिया और फ़ासिज़्म के विरुद्ध संघर्ष ही वह मोर्चा है जहां कम्यूनिस्ट और सोशल-डिमाक्रेट एक-जैसा नारा लगा सकते हैं। अब वक़्त आ गया है कि श्रमिक आन्दोलन की सभी प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि, कम्यूनिस्ट-विरोधी मसखरों को दूध की मक्खियों की तरह निकालकर अलग कर दें और एक मेज़ के इर्द-गिर्द बैठकर, श्रमिक वर्ग के हितों और शान्ति की रक्षा की ख़ातिर श्रमिक वर्ग की संयुक्त कार्रवाई का सर्वसम्मत कार्यक्रम तैयार करें।

भावी प्रगति की ख़ातिर यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि कम्यूनिस्ट और कामगार पार्टियां विचारधारा और संगठन की दृष्टि से अपनी मोर्चाबन्दी मज़बूत कर लें, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आधार पर उसे और पक्का कर लें और अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृ-पार्टियों के साथ अपने सम्बन्ध और सुदृढ़ बना लें।

नवम्बर, १९५७ में कम्यूनिस्ट और कामगार पार्टियों के प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन हुआ, उसने यह दिखा दिया कि भ्रातृ-पार्टियां अपने विचारों में एकमत हैं। सम्मेलन की घोषणा को सभी कम्यूनिस्ट व कामगार पार्टियों ने सर्वसम्मति से स्वीकारा और वह विश्व कम्यूनिस्ट आन्दोलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एकता का घोषणापत्र बन गयी है। घोषणा में संशोधनवाद को प्रधान ख़तरा बताकर उसकी निन्दा की गयी। साथ ही, लकीरपन्थी और तबकापरस्ती की भी निन्दा की गयी। घोषणा में जो निष्कर्ष निकाले गये थे, जीवन ने उन्हें सही साबित कर दिया है। फ़िलहाल हम इन निष्कर्षों से ही पथप्रदर्शन पाते हैं।

नवम्बर-सम्मेलनों के बाद प्रत्येक कम्यूनिस्ट पार्टी में और दृढ़ीकरण हुआ है। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन की भी ताक़त बढ़ गयी है। मार्क्सवादी-लेनिनवादी मार्ग से किसी भ्रातृ-पार्टी को भ्रष्ट करने में संशोधनवादी विफल रहे। गये-बीते इने-गिने अवसरवादी और ऐसे व्यक्ति जो वर्ग-शत्रु के आघात से तिलमिलाकर रास्ते से भटक गये, बस ये ही थे जो संशोधनवादियों के पीछे हो लिये। कम्यूनिस्ट आन्दोलन के स्वच्छ जल को कलंकित करनेवाली यह मैल संघर्ष की आंच लगने पर झाग बनकर ऊपर उभर आयी और अलग छंट गयी।

संशोधनवादियों के तर्क जीवन द्वारा, श्रमिक वर्ग के व्यावहारिक संघर्ष द्वारा, सामाजिक विकास की सारी प्रक्रिया द्वारा झुठला दिये गये। पूंजीवाद के स्वभाव में परिवर्तन, संकट-मुक्त पूंजीवादी प्रणाली का विकास,

पूंजीवाद की समाजवाद में शान्तिपूर्ण परिणति आदि आदि संशोधनवादी सिद्धान्त भरभराकर ढह गये और मिट्टी में मिल गये।

अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन ने यूगोस्लाविया के संशोधनवादियों के विचारों और नीतियों का खण्डन किया है। यूगोस्लाविया की कम्यूनिस्ट लीग के नेता कहते हैं कि उन्होंने नवम्बर-सम्मेलन की घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था, इसीलिए मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों ने उनके विरुद्ध विचारधारात्मक आन्दोलन चालू कर दिया है। लेकिन यह कथन सर्वथा असत्य है। दर असल यूगोस्लाव नेताओं ने ही उक्त घोषणा के विरुद्ध अपना संशोधनवादी कार्यक्रम प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन की मार्क्सवादी-लेनिनवादी नीतियों की आलोचना की थी। मैं आपसे पूछता हूं, मार्क्सवादी सचमुच इन तथ्यों की उपेक्षा कर सकते थे? हरगिज़ नहीं। यही कारण है कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद को माननेवाली सभी पार्टियों ने यूगोस्लाविया की कम्यूनिस्ट लीग के कार्यक्रम की सिद्धान्ततः आलोचना की।

यूगोस्लाविया के नेताओं के विचारों के बारे में हमारी स्थिति स्पष्ट है। हम बिना लुकाव-छिपाव के बार बार अपनी स्थिति पर प्रकाश डाल चुके हैं, जबकि यूगोस्लाव नेता सचाई को तोड़ते-मरोड़ते और टालते रहते हैं।

वे मार्क्सवादी-लेनिनवादियों से अपने मतभेद का सारांश छिपाना चाहते हैं। और वह सारांश यह है कि यूगोस्लाव संशोधनवादी अन्तर्राष्ट्रीय वर्ग-ऐक्य की आवश्यकता से इन्कार करते हैं और उन्होंने श्रमिक वर्ग के रुख त्याग दिये हैं। वे दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार में दो गुट्ट—दो सैन्य-शिविर हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि समाजवादी शिविर, जिसमें यूरोप व एशिया के समाजवादी देश शामिल हैं, कोई सैन्य-शिविर तो नहीं है, बल्कि वह तो शान्ति और बेहतर जीवन की ख़ातिर, समाजवाद और कम्यूनिज़्म की ख़ातिर, संघर्ष करनेवाले समान हैसियतवाले राष्ट्रों का परिवार है **(ज़ोर की तालियां)**। दूसरा है साम्राज्यवादी

शिविर, जो दमन व हिंसा की अपनी प्रणाली को हर क़ीमत पर क़ायम रखने पर तुला हुआ है और युद्ध का ख़तरा पैदा कर रहा है। इन शिविरों को हमने तो नहीं बनाया। सामाजिक विकास के दौरान में वे अपने आप बने हैं।

यूगोस्लाव नेता यह दावा करते हैं कि वे सभी गुटों के बाहर हैं, सभी शिविरों से परे हैं। परन्तु सचाई यह है कि वे बल्कान गुट में हैं जिसके सदस्य हैं यूगोस्लाविया, तुर्की और यूनान। स्मरण रहे, तुर्की और यूनान आक्रमणकारी नाटो गुट के सदस्य हैं। तुर्की तो बग्दाद सन्धि का भी सदस्य है। जब हम कहते हैं कि यूगोस्लाविया की कम्यूनिस्ट लीग के नेता दो कुर्सियों पर एक साथ बैठे हैं तो वे हमारी बात का बुरा मानते हैं। वे आग्रहपूर्वक कहते हैं कि हम तो अपनी यूगोस्लाव कुर्सी पर ही बैठे हैं। लेकिन जाने क्यों यह यूगोस्लाव कुर्सी अमेरिकी एकाधिकारियों के कंधों पर टिकी है! यूगोस्लाविया की कम्यूनिस्ट लीग के नेता 'किसी गुट में न होने' की, तटस्थता की, जिस स्थिति का गुण गाते नहीं थकते, हूबहू उसी में अमेरिकी एकाधिकारों की बू साफ़ आ रही है—उन एकाधिकारों की, जो 'यूगोस्लाव समाजवाद' को चुग्गा खिलाते रहते हैं। वर्ग-संघर्ष के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जब बूर्जुआ ने अपने वर्ग-शत्रु की आर्थिक या नैतिक सहायता की हो, समाजवाद के निर्माण में मदद दी हो।

किसी देश के प्रशासन को परखने की कसौटी यह होती है कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में तथा जनता की संस्कृति एवं खुशहाली को बढ़ाने में उसने क्या प्रगति की है। हम सोवियत कम्यूनिस्ट समझते हैं कि महान लेनिन द्वारा प्रशस्त समाजवाद का हमारा पथ ही सही मार्ग है। इस पथ पर चलकर सोवियत संघ ने बहुत-सी जीतें हासिल की हैं, जिनसे दुनिया दंग रह गयी है। सभी जनवादी जनतन्त्रों ने अक्तूबर क्रान्ति से आलोकित पथ का, लेनिन के पथ का अनुगमन किया है और उन्होंने भी उल्लेखनीय प्रगति की है।

तो सबसे कम फल किसने पाये हैं? उसी पार्टी ने, उसी देश ने, जिसके नेता अपने तथाकथित यूगोस्लाव मार्ग को एकमात्र सही मार्ग कहकर आसमान पर चढ़ाते हैं। लोग उसे इस प्रकार देखते हैं: सर्वोत्तम मार्ग तो वह है जो कम से कम समय में अच्छे से अच्छे आर्थिक और राजनीतिक परिणामों तक पहुंचाये। और अगर हम समाजवादी देशों के जीवन-स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो, जैसे कि आर्थिक प्रकाशनों से पता चलता है, हम पायेंगे कि यूगोस्लाविया में जीवन-स्तर अपेक्षाकृत बहुत ही मन्द गति से बढ़ता है। यूगोस्लाविया के व्यावहारिक तथ्य ही यूगोस्लाव संशोधनवादियों के सैद्धान्तिक 'आविष्कारों' को झुठलाते हैं।

अगर यूगोस्लाविया अपने विकास में पिछड़ा हुआ है, अगर वह समाजवाद के पथ पर सीधे क़दम नहीं बढ़ा रहा, बल्कि ऐंड़ा-बैंड़ा सरक रहा है, तो इसकी सारी ज़िम्मेदारी यूगोस्लाविया की कम्यूनिस्ट लीग के नेताओं के संशोधनवादी, मार्क्सवाद-विरोधी रुख़ पर है। समाजवाद के निर्माण में पार्टी के रोल के बारे में इन नेताओं का अपना निराला विचार है। यूगोस्लाव संशोधनवादी, पार्टी के रोल को गौण समझते हैं। बल्कि वे तो लेनिन की इस शिक्षा को वस्तुतः ठुकराते हैं कि समाजवाद के संघर्ष में पार्टी ही पथप्रदर्शक शक्ति होनी चाहिए।

मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियां यूगोस्लाविया की घटनाओं को चिन्ता के साथ देख रही हैं। यूगोस्लाविया की भ्रातृ-जनता ने बड़ी बड़ी क़ुर्बानियां देकर सोवियत संघ की सहायता से अपने को जर्मन व इतालवी फ़ौजों के क़ब्ज़े से आज़ाद किया, अपने देश के बूर्जुआ शासन को ख़त्म किया और समाजवाद का मार्ग अपनाया है। फिर भी, यूगोस्लाव नेताओं की नीति के कारण, जिसका उद्देश्य यूगोस्लाविया को समाजवादी शिविर और अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन के विपक्ष में खड़ा करने का है, यूगोस्लाव जनता को अपने समाजवादी लाभों से हाथ धोना पड़ सकता है।

यूगोस्लाविया की भ्रातृ-जनता के लिए और यूगोस्लाव कम्यूनिस्टों—

भूमिगत और पार्टीज़ान संघर्ष के उन वीरों – के लिए हमारे मन में घनिष्ठतम मैत्री की भावनाएं हैं। विदेश नीति के कुछ प्रश्नों में हमारे विचार एक-जैसे हैं। हम यूगोस्लाविया के साथ परस्पर लाभदायक व्यापारिक आदान-प्रदान जारी रखेंगे। साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष से सम्बन्धित सभी प्रश्नों में तथा शान्ति के लिए हम यूगोस्लाविया को सहयोग देने का प्रयास करेंगे, जहां तक इन बातों में हमारे रुख़ एक-से होंगे।

लेकिन पार्टी के क्षेत्र में स्थिति कैसी होगी? यह तो यूगोस्लाविया की कम्यूनिस्ट लीग पर निर्भर होगा। उसके नेताओं ने अपने को अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन से अलगा लिया है। इसलिए मार्क्सवादी-लेनिनवादी आधार पर कम्यूनिस्ट पार्टियों के साथ समझौता करने की ओर पहल करना यूगोस्लाविया की कम्यूनिस्ट लीग का काम है। इसी में यूगोस्लाव जनता का भी हित है।

कम्यूनिस्ट आन्दोलन ने संशोधनवाद की रीढ़ तोड़ दी है। फिर भी संशोधनवाद अभी मरा नहीं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि साम्राज्यवादी संशोधनवादियों की सहायता करने और साथ देने की हर तरह से कोशिश करेंगे।

लकीरपन्थी और तबक़ापरस्ती भी मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त के विकास और उसकी सृजनात्मक क्रियान्विति में बाधा डालते हैं और उनके कारण आम जनता के साथ कम्यूनिस्ट पार्टियों का सम्पर्क छूट जाता है। इसलिए इनके भी विरुद्ध जूझना आवश्यक है। आम जनता के साथ सम्पर्क सुदृढ़ करने, आम जनता की वाणी पर सबसे अधिक ध्यान देने और जनता का नेतृत्व करने का लेनिन का आदेश हम सभी कम्यूनिस्टों के लिए शिरोधार्य है।

अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन के ढांचे के अन्दर की भ्रातृ-पार्टियों के सम्बन्धों के बारे में हमने हमेशा लेनिन के रुख़ का अनुसरण किया है। लेनिन ने हमें सिखाया कि ये सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग-आन्दोलन

के राष्ट्रीय दस्तों की समानता और स्वतन्त्रता के आधार पर, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों के आधार पर, स्थापित होने चाहिए। सभी पार्टियों को समान अधिकार प्राप्त है, ठीक इसी कारण वे विश्वास और स्वेच्छापूर्ण सहयोग के सम्बन्ध निभाती हैं और स्वेच्छा से, समझ-बूझकर, एक विराट श्रमिक-सेना के दस्तों की हैसियत से संयुक्त कार्रवाई का प्रयास करती हैं।

सभी कम्यूनिस्ट पार्टियां स्वतन्त्र हैं। वे अपने अपने देश की ठोस परिस्थितियों के अनुरूप अपनी नीति स्वयं निर्धारित करती हैं। उन्होंने अपने काम में सफलताएं प्राप्त की हैं, अपना प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ा रही हैं, अपने अनुयायियों की संख्या में वृद्धि कर रही हैं और जनता के सभी तबक़ों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही हैं।

साम्राज्यवादी विचारधारा-प्रचारक और उनके इशारे पर चलनेवाले संशोधनवादी, कम्यूनिस्ट पार्टियों के बढ़ते हुए प्रभाव को घटाने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। वे ये मनगढ़न्त क़िस्से फैला रहे हैं कि कम्यूनिस्ट आन्दोलन "मास्को में निर्मित" होता है और कम्यूनिस्ट व कामगार पार्टियां सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की आश्रित हैं। यूगोस्लाव संशोधनवादी इस मामले में ख़ास लगन से जुटे हुए हैं और यह आरोप लगाते हैं कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की 'सरपंच' बनना चाहती है। यहां तक कि उन्होंने अपने कार्यक्रम में 'सरपंचवाद' पर एक थीसिस जोड़ दी। उनका कहना यह है कि हमारी पार्टी दूसरे देशों के अन्दरूनी मामलों में दख़लन्दाज़ी करती है और दूसरी कम्यूनिस्ट पार्टियों का नियन्त्रण करना चाहती है। इस मिथ्यारोप के लिए प्रतिक्रियावादी लोग यूगोस्लाविया के संशोधनवादियों का बड़ा आभार मान रहे हैं।

जो कोई भी कम्यूनिस्ट आन्दोलन को जानता हो, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावादियों और संशोधनवादियों के मनगढ़न्त क़िस्सों की धज्जियां उड़ाने में उसे ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी।

यह समझना तो उपहासास्पद है कि श्रमिक वर्ग की कोई राजनीतिक पार्टी, जिसकी सदस्य-संख्या अक्सर लाखों में और कभी कभी दसों लाखों में होती है, किसी देश में बाहर से संगठित की जा सकती है। मिसाल के तौर पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि २०,००,००० सदस्योंवाली इतालवी कम्यूनिस्ट पार्टी, ५,००,००० सदस्योंवाली फ़्रांसीसी कम्यूनिस्ट पार्टी, १५,००,००० सदस्योंवाली हिन्देशियाई कम्यूनिस्ट पार्टी, क़रीब ३,००,००० सदस्योंवाली भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी और दूसरी भ्रातृ-पार्टियां 'मास्को द्वारा स्थापित' की गयी हैं और उनके सदस्य 'विदेशी एजेंट' हैं।

सभी देशों में कम्यूनिस्ट पार्टियां किसी 'केन्द्र' द्वारा स्थापित की जाने के कारण अस्तित्व में नहीं आयी हैं। उस तरह का चमत्कार तो सम्भव ही नहीं। समाज-विकास का इतिहास बताता है कि श्रमिक वर्ग के उदय और वृद्धि के साथ साथ मार्क्सवादी पार्टियां अस्तित्व में आती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कम्यूनिस्ट आन्दोलन का उदय निरपेक्ष आवश्यकता के रूप में हुआ; कि प्रत्येक देश में श्रमिक वर्ग की जीवन-स्थिति ने ही उसे जन्म दिया। सभी पूंजीवादी देशों में वर्ग मौजूद हैं, फलतः उनके हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाली राजनीतिक पार्टियां भी उन देशों में हैं। कम्यूनिस्ट पार्टियां श्रमिक वर्ग की राजनीतिक पार्टियां हैं और जब तक श्रमिक वर्ग रहेगा, तब तक कम्यूनिस्ट पार्टियां भी रहेंगी **(ज़ोर की तालियां)**। यह समझना भी बुद्धूपना है कि कम्यूनिस्ट पार्टियों के लाखों-करोड़ों लोगों को बाहर से यह आदेश दिया जा सकता है कि उन्हें आज क्या सोचना चाहिए और कल क्या करना चाहिए।

कुछ लोग कहते हैं कि कम्यूनिस्ट और कामगार पार्टियों की मास्को पर 'आश्रितता' इस आशय के वक्तव्यों से पुष्ट हो जाती है कि सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन की अग्रणी है। इसके प्रमाण-स्वरूप वे मास्को सम्मेलन की घोषणा की सुज्ञात शर्त्त का

हवाला देते हैं जिसमें कहा गया है कि "समाजवादी राज्यों के शिविर का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा है"।

सोवियत संघ के और दूसरे सभी देशों के कम्यूनिस्ट समझते हैं कि इन शब्दों में हमारे देश और हमारे श्रमिक वर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी है। हमारे श्रमिक वर्ग ने महान लेनिन के नेतृत्व में संगठित कम्यूनिस्ट पार्टी की रहनुमाई में, सबसे पहले समाजवादी क्रान्ति की और सबसे पहले सत्ता हाथ में ली **(देर तक तालियां)**। इन चालीस वर्षों में हमने संघर्ष और विजय के कठिन मार्ग पर लम्बा रास्ता तय किया है और एक शक्तिशाली राज्य निर्मित किया है जो सभी समाजवादी देशों के लिए और विश्व कम्यूनिस्ट आन्दोलन के लिए गढ़-सा बना हुआ है **(ज़ोर की तालियां)**।

सोवियत संघ और सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी के ऐतिहासिक रोल को इस तरह मान्यता देने के लिए हम कम्यू-पार्टियों का हार्दिक आभार प्रदर्शित करते हैं **(देर तक ज़ोर की तालियां)**।

लेकिन यह बात ज़ोर देकर कहनी चाहिए कि कम्यूनिस्ट आन्दोलन और समाजवादी शिविर में सभी कम्यूनिस्ट व कामगार पार्टियों और समाजवादी देशों को हमेशा पूरी समानता और स्वतंत्रता प्राप्त रही है। सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी किसी दूसरी पार्टी का नेतृत्व नहीं करती; सोवियत संघ किसी दूसरे देश का नेतृत्व नहीं करता। कम्यूनिस्ट आन्दोलन में न कोई 'सरपरस्त' पार्टी है और न कोई 'मातहत' पार्टी ही। सभी कम्यूनिस्ट व कामगार पार्टियां समान और स्वतन्त्र हैं। कम्यूनिस्ट आन्दोलन के भविष्य, उसकी विफलताओं और सफलताओं के लिए ज़िम्मेदारी उन सभी पर होती है **(तालियां)**। प्रत्येक कम्यूनिस्ट व कामगार पार्टी श्रमिक वर्ग के प्रति, अपने देश के श्रमिक लोगों के प्रति तथा अन्तर्राष्ट्रीय कामगार व कम्यूनिस्ट आन्दोलन के प्रति, उत्तरदायी होती है। श्रमिक वर्ग के हितों के लिए, समाजवाद के लिए, अपने संघर्ष में

कम्यूनिस्ट पार्टियां मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सार्वभौम सिद्धान्तों के साथ अपने देशों की ठोस ऐतिहासिक व राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर काम करती हैं। श्रमिक वर्ग से, अपने देश की जनता से, संबद्ध मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी ही संघर्ष की ठोस परिस्थितियां समझ पाती है; अकेले वही पार्टी इन परिस्थितियों के अनुरूप तथा अपने देश के श्रमिक वर्ग-आन्दोलन की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक कार्य-पद्धति निर्धारित कर सकती है।

और यथार्थ यही है। सभी कम्यूनिस्ट व कामगार पार्टियां सम्पूर्ण स्वतन्त्रता और सर्वहारा-अन्तर्राष्ट्रीयता के आधार पर, स्वेच्छापूर्ण सहयोग और पारस्परिक सहायता के आधार पर, अस्तित्व में आती और संघर्ष करती हैं। भ्रातृ-पार्टियों के आपसी सम्बन्धों की प्रकृति को हमारी पार्टी इसी रूप में समझती है **(तालियां)।**

जहां तक सोवियत संघ से सम्बन्ध है, उसका रोल दूसरे देशों का नेतृत्व करने में नहीं, बल्कि मानवजाति के लिए सबसे पहले समाजवाद का मार्ग आलोकित करने में, विश्व समाजवादी प्रणाली का सबसे शक्तिशाली देश होने में और कम्यूनिज़्म के व्यापक निर्माण के काल में सबसे पहले क़दम रखने में है **(ज़ोर की तालियां)।**

सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी लेनिन द्वारा सर्वहारा-अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना में संगठित की गयी। हम सोवियत कम्यूनिस्टों ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद का पार ही नहीं पा लिया है बल्कि सब तरह के शत्रुओं से उसकी रक्षा भी की है। सोवियत जनता ने इस शिक्षा को पथप्रदर्शक मानकर कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, कठोर संघर्ष करके समाजवाद का निर्माण किया है और अब कम्यूनिज़्म की ओर विश्वास के साथ क़दम बढ़ा रहे हैं **(तालियां)।**

हमने मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन की महती अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का हमेशा वफ़ादारी के साथ अनुसरण किया है और सदा करते रहेंगे। आलंकारिक

भाषा में कहा जाय तो हमारी कम्यूनिस्ट पार्टी अपने को विश्व कम्यूनिस्ट आन्दोलन का एक अग्रिम दस्ता मानती है, वह दस्ता जो कम्यूनिज़्म के शिखर पर सबसे पहले क़ब्ज़ा करने को है। कम्यूनिज़्म की ओर बढ़ते हुए हमें न हिमस्राव रोक पायेगा न पहाड़ का धसकना रोक सकेगा। कम्यूनिज़्म की ओर जानेवाले पथ से हमें कोई डिगा नहीं सकेगा **(ज़ोर की तालियां)।**

हमारा हमेशा यह विचार रहा और अब भी है कि किसी को अपने राष्ट्रीय 'क्षेत्र' में घुसकर बैठ नहीं जाना चाहिए, घोंघे की तरह सीप के अन्दर धंसा नहीं रहना चाहिए। हम समझते हैं कि समाजवादी शिविर की ताक़त को हर तरह से बढ़ाते रहना चाहिए और मास्को घोषणा में सभी भ्रातृ-पार्टियों द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन को और सुगठित करना चाहिए। हमारी श्रेणियों की दृढ़ता और बल की चिन्ता करना प्रत्येक कम्यूनिस्ट व कामगार-पार्टी का सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। **श्रमिक वर्ग के सभी दस्तों की अन्तर्राष्ट्रीय दृढ़ एकता के बिना उसके राष्ट्रीय ध्येय में सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती (देर तक तालियां)।**

श्रमिक जनता को आज़ाद करने और संसार-व्यापी शान्ति के लिए संघर्ष करने के महान सांझे उद्देश्य से प्रेरित होकर हम सब एक हुए हैं। हम सब की एक चिन्ता है—राष्ट्रों के कल्याण की, उनकी समृद्धि और सुरक्षा की, उनके सुखी भविष्य की चिन्ता। ये सब बातें केवल समाजवादी तरीक़े से पूरी हो सकती हैं। मार्क्सवाद-लेनिनवाद की महान शिक्षा से और उसे कार्यरूप देने के संघर्ष से हम एक हुए हैं। मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा की शुद्धता की हम सदैव रक्षा करेंगे। अवसरवादियों के विरुद्ध, सभी प्रकार के संशोधनवादियों के विरुद्ध हम लोहा लेंगे और श्रमिक वर्ग के प्रति सदा वफ़ादार रहेंगे। हमारी समझ में विश्व कम्यूनिस्ट व कामगार-आन्दोलन के प्रति हमारा अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य यही है **(देर तक ज़ोर की तालियां)।**

•

४

कम्यूनिस्ट निर्माण का नया चरण और मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत की कुछ समस्याएं

साथियो, अब हमारे देश ने अपने विकास के एक नये ऐतिहासिक काल-खंड में प्रवेश किया है और इसके फलस्वरूप समाजवाद से साम्यवाद में संक्रमण से संबंधित मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत की समस्याओं को विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ है।

पहली बात है **कम्यूनिस्ट समाज की दो अवस्थाओं** का प्रश्न और समाजवाद के कम्यूनिज़्म में संक्रमण पर लागू होनेवाले नियम।

वैज्ञानिक कम्यूनिज़्म के संस्थापकों अर्थात् मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन ने सूचित किया था कि पूंजीवादी और ज़मींदारी प्रभुत्व का तख़्ता उलट जाने के बाद समाज दो चरणों से होकर गुज़रेगा। पहला चरण होगा समाजवाद और दूसरा उच्चतर चरण होगा वर्गहीन कम्यूनिस्ट समाज।

कम्यूनिज़्म की दो अवस्थाओं वाला यह मार्क्सवादी-लेनिनवादी भविष्य-कथन समाजवादी समाज के विकास से प्रमाणित हो चुका है। सोवियत जनता ने समाजवादी समाज का निर्माण कर दिया है और अब ऐसे नये काल-खंड में प्रवेश किया है जहां समाजवाद कम्यूनिज़्म में विकसित होता है।

मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत और समाजवादी समाज के निर्माण में प्राप्त किये गये व्यावहारिक अनुभव के बल पर हम कम्यूनिज़्म के प्रति

अपने भावी पदन्यास के स्वरूप के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

पहले, समाजवादी अवस्था से उच्चतर अवस्था में संक्रमण एक नियमबद्ध ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसका न उल्लंघन किया जा सकता है और जिसे न टाला ही जा सकता है। मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों का अंतिम लक्ष्य है कम्यूनिस्ट समाज का निर्माण। किन्तु समाज समाजवादी अवस्था से गुज़रे बिना पूंजीवाद से छलांग मारकर सीधे कम्यूनिज्म में परिणत नहीं हो सकता। लेनिन ने लिखा है कि "पूंजीवाद से मानव समाज सीधे समाजवाद में याने उत्पादन साधनों के समाजवादी स्वामित्व और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये गये काम के अनुसार पदार्थों के वितरण की अवस्था में ही परिणत हो सकता है। लेकिन हमारी पार्टी बहुत आगे को देखती है: समाजवाद की परिणति क्रमशः और अनिवार्यतः कम्यूनिज्म में होनी चाहिए जिसकी पताका पर यह आदर्श वाक्य अंकित है: 'हर एक से उसकी क्षमतानुसार, हर एक को उसकी आवश्यकतानुसार'"। (लेनिन, ग्रंथ-संग्रह: खंड २८, पृष्ठ ३२)

हां, कुछ साथी संभवतः सुझाव देंगे कि कम्यूनिज्म के सिद्धांत लागू करने के काम की चाल हम तेज़ कर दें। लेकिन जब हमारे पास भौतिक मूल्यों की समृद्धता नहीं और जब लोग कम्यूनिस्ट तरीक़े से जीने और काम करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं उस समय याने आवश्यक आर्थिक स्थितियों के अभाव में आवश्यकतानुसार वितरण के सिद्धांत को असमय अपना लेने से कम्यूनिज्म के निर्माण को हानि ही पहुंचेगी। यह ध्यान में रखना चाहिए कि उत्पादन के वर्तमान स्तर पर सभी के लिए अच्छी जीवनावश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं और हम अभी तक जनता की सभी आवश्यकताओं की सम्यक् पूर्ति नहीं कर सकते हैं। यह 'समानतावादी कम्यूनिज्म' बस, हमारे संचित साधनों को चट कर जायेगा, व्यापक पुनरुत्पादन असंभव कर देगा और अर्थ-व्यवस्था के सफल विस्तार का मार्ग रोक डालेगा।

हमें कम्यूनिज़्म में प्रणालीबद्ध संक्रमण के लिए आवश्यक भौतिक और आत्मिक परिस्थितियां पैदा करके क्रमशः आगे क़दम बढ़ाना चाहिए।

दूसरे, साम्यवादी और समाजवादी अवस्थाओं के सभी भेदों के बावजूद ऐसी कोई दीवार नहीं है जो सामाजिक विकास की इन दो अवस्थाओं को विभक्त कर दे। समाजवाद से उसके सीधे विकास के रूप में कम्यूनिज़्म अंकुरित होता है। यह मानना ग़लत और भ्रांतिमूलक होगा कि कम्यूनिज़्म किसी तरह यकायक प्रादुर्भूत होगा। श्रमिक और औद्योगिक संगठनों के कम्यूनिस्ट तरीक़े और सार्वजनिक भोजनालयों, छात्रावास-स्कूलों, किंडरगार्टनों और शिशु-गृहों जैसे जनता की आवश्यकताएं पूरी करनेवाले सामाजिक तरीक़े बढ़ते पैमाने पर तरक़्क़ी कर रहे हैं। हमारे समाज में कम्यूनिज़्म के कई बोधगम्य और दृश्य पहलू उपलब्ध हैं और वे बराबर विकसित होते रहेंगे।

कम्यूनिज़्म में हमारे प्रवेश की कोई निश्चित तिथि नहीं है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी निश्चित समय पर एक दरवाज़ा बंद करके घोषित कर दें कि "समाजवाद का निर्माण पूरा हो चुका है" और दूसरा दरवाज़ा खोलकर बता दें कि "अब हमने कम्यूनिज़्म में प्रवेश किया है।" समाजवाद से साम्यवाद में संक्रमण एक सतत विकास है। वस्तुतः हम कम्यूनिस्ट समाज में प्रवेश करने का दरवाज़ा खोल भी रहे हैं, क्योंकि इस समय हम जिस कार्य में लगे हुए हैं वह है कम्यूनिज़्म का निर्माण। हमारे देश ने व्यापक कम्यूनिस्ट निर्माण के ऐसे काल-खंड में प्रवेश किया है जहां कम्यूनिज़्म के लिए आवश्यक सभी भौतिक एवं आत्मिक स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं। कम्यूनिस्ट निर्माण का कार्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपनी सारी जनता की आवश्यकताएं पूरी करनेवाली हर चीज़ समृद्ध मात्रा में पैदा कर लेंगे, जब हमारे सभी देशवासी अपनी क्षमता के अनुसार काम करना सीख लेंगे ताकि समाज की संपत्ति संग्रहीत हो और बढ़ती रहे।

तीसरे, कम्यूनिज़्म में क्रमशः संक्रमण को किसी गति की संकल्पना नहीं मानना चाहिए। उल्टे यह ऐसा काल-खंड है जिसमें आधुनिक उद्योग का शीघ्र विकास, बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत कृषि और सभी आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में तेज़ तरक़्क़ी हो रही है। इन सभी कार्यों में कम्यूनिस्ट समाज के करोड़ों निर्माता सक्रिय एवं सचेत योग दे रहे हैं। समाजवाद के साम्यवाद में विकास की यह नियमानुसार प्रक्रिया समाजवाद के काल-खंड में प्राप्त किये गये भौतिक उत्पादन के उच्च स्तर के आधार पर अधिक गतिशील की जा सकेगी। हमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए और न ही जल्दी जल्दी ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिनके लिए समय अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। जल्दबाज़ी से बिगाड़ पैदा होगा और हमारे कार्य को हानि पहुंचेगी। लेकिन साथ साथ हमें उपलब्ध स्थिति में देर तक रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे गतिहीनता आ जायेगी।

क्या वह समय बहुत दूर है जब हम सभी सोवियत नागरिकों की सभी महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएं संपूर्णतया पूरी कर सकेंगे? सामाजिक उत्पादन बढ़ाने और सांस्कृतिक प्रतिमानों को ऊंचा उठाने की हमारी विशाल क्षमताओं को ध्यान में लें तो वैसे यह समय उतना दूर नहीं लगता। लेकिन यह स्थिति किसी एक कृति के द्वारा एकदम नहीं प्राप्त की जा सकेगी। भौतिक उत्पादन की जो स्थितियां हम उपलब्ध कर लेंगे उन्हीं के अनुपात में उपर्युक्त स्थिति क्रमशः और सुसंगत रीति से उत्पन्न होगी।

आवश्यक और तर्कसंगत सीमाओं में सभी सोवियत नागरिकों की अन्न, वस्त्र और आवास विषयक आवश्यकताओं की संपूर्णतया पूर्ति करने में शायद बहुत देर नहीं लगेगी। स्कूली बच्चों के लिए समाज के ख़र्चे पर निःशुल्क जलपान और भोजन का प्रबंध करने, किंडरगार्टनों, शिशु-गृहों और छात्रावास-स्कूलों में सब बच्चों के लिए काफ़ी स्थान उपलब्ध करने इत्यादि सुविधाओं के संगठन में उतना अधिक समय नहीं लगता। प्रौढ़ जनसंख्या के बारे में यह ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य की साधारण

आवश्यकताएं असीम नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकता से अधिक रोटी या अन्य खाद्य-पदार्थ नहीं खा सकता और वस्त्र एवं आवास के बारे में भी निश्चित सीमाएं हैं। बेशक जब हम जनता की आवश्यकताओं की पूर्त्ति की बात करते हैं तब हमारे मन में किसी की सनक या विलासी जीवन के दावे नहीं होते, बल्कि वह स्वास्थ्यकर उपभोग होता है जो सुसंस्कृत व्यक्ति की साधारण आवश्यकताओं के अनुरूप है।

जनता में अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करने की प्रवृत्ति दृढ़मूल होने में काफ़ी समय लगेगा। तब तक समाज को काम के समय के संबंध में कुछ नियम ज़रूर अपनाने होंगे ताकि हर समर्थ व्यक्ति समाज के लिए आवश्यक मूल्यों के उत्पादन में एक निश्चित मात्रा में अपना श्रम लगा दे।

आज देश का मूलभूत व्यावहारिक कार्य है **कम्यूनिस्ट समाज के लिए भौतिक तथा प्राविधिक आधार तैयार करना और समाजवादी उत्पादक शक्तियों का अधिक बलशाली विस्तार सुनिश्चित कर लेना।**

आज हमारे आर्थिक विकास में यह कार्य मुख्य क्यों है? इसका उत्तर यह है कि समाजवादी उत्पादन का वर्तमान स्तर अभी तक हमें वह सामर्थ्य नहीं देता जिससे हम अपनी जनता की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी भौतिक और सांस्कृतिक मूल्य समृद्ध मात्रा में उत्पन्न कर सकें। लेकिन इसके बिना कम्यूनिज़्म असंभव है। फलतः सबसे पहला काम है उत्पादक शक्तियों को अधिक विकसित करना और भौतिक मूल्यों के उत्पादन की गति बढ़ाना। कम्यूनिज़्म तभी संभव है जब हम प्रधान पूंजीवादी देशों के उत्पादन-स्तर से आगे निकल जायें और श्रम-उत्पादिता का स्तर पूंजीवाद में उपलब्ध स्तर से ऊपर उठा सकें।

कम्यूनिज़्म के भौतिक एवं प्राविधिक आधार के निर्माण में प्रथमतः और मुख्यतः ये बातें निहित हैं: अत्यंत विकसित आधुनिक उद्योग, संपूर्ण विद्युतीकरण,

उद्योग एवं कृषि की प्रत्येक शाखा में वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति, सभी उत्पादन-प्रक्रियाओं का व्यापक यंत्रीकरण एवं स्वचालन, नये ऊर्जा-स्रोतों एवं हमारे समृद्ध प्राकृतिक साधन-स्रोतों का अधिकतम उपयोग, नयी संश्लिष्ट एवं अन्य वस्तुओं का उत्पादन, जनता का उच्च सांस्कृतिक एवं प्राविधिक स्तर, उत्पादन के संगठन में अधिक सुधार और उच्चतर श्रम-उत्पादिता।

आर्थिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर होने के साथ कम्यूनिस्ट निर्माण कार्य की पूर्णता सूचित होगी ऐसा विश्वास करने में निरा भोलापन प्रकट होगा। नहीं, यह हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं होगा बल्कि यह पूंजीवाद के साथ वाली होड़ में एक निर्णायक अवस्था मात्र होगी।

हम अमेरिका के साथ होड़ लगा रहे हैं लेकिन हम अमेरिका को आर्थिक विकास का प्रतिमान नहीं मानते क्योंकि यद्यपि अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था अत्यंत विकसित है तथापि वहां दोषपूर्ण पूंजीवादी उत्पादन एवं वितरण-प्रणाली का ही प्रभुत्व है। अमेरिका में हर प्रकार के माल की समृद्धि है लेकिन साथ साथ वहां लाखों की संख्या में बेरोज़गार और अपर्याप्त आय वाले लाखों लोग हैं जो अपनी अत्यंत प्राथमिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते। कम्यूनिस्ट इन हालतों की नकल नहीं उतारना चाहते। उल्टे हम इस अन्याय को समाप्त कर देना चाहते हैं। अमेरिका के उत्पादन-स्तर को हम अपनी आर्थिक प्रगति को नापने का मापदंड मानते हैं तो केवल पूंजीवाद के प्रमुख शक्ति-केंद्र के साथ हमारे देश की तुलना करने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वाली इस आर्थिक होड़ में हमारी जीत का मतलब यही होगा कि हमने कम्यूनिस्ट निर्माण की प्रारंभिक अवस्था पूर्ण कर ली। इस अवस्था में प्राप्त किया गया आर्थिक स्तर हमारे सफ़र की आख़िरी मंज़िल नहीं होगी बल्कि यह बीच का एक स्टेशन मात्र होगा जहां हम पूंजीवादी संसार के अत्यंत विकसित देश के

बराबर हो जायेंगे, उसे पछाड़ देंगे और आगे निकल जायेंगे (ज़ोर की तालियां)।

हमारी उत्पादक-शक्तियों के विस्तार के साथ साथ समाज के सभी सदस्यों के भ्रातृत्वपूर्ण सहयोग, मैत्री और परस्पर सहायता पर आधारित समाजवादी उत्पादन-संबंधों का स्तर भी ऊंचा उठेगा। हमारे देश में सामाजिक श्रम को मनुष्य-मनुष्य के नये समाजवादी संबंधों की अभिव्यक्ति का और उत्कृष्ट नैतिक मानचिह्न का रूप प्राप्त हो चुका है।

और जैसे जैसे समाजवादी उत्पादन का नये भौतिक एवं प्राविधिक आधार पर विस्तार होगा और शिक्षण उत्पादक श्रम के घनिष्ठतर संपर्क में आयेगा वैसे वैसे मानसिक और शारीरिक श्रम के प्रधान भेद क्रमशः लोप हो जायेंगे। हमारी जनता का सर्वांगीण विकास श्रम को मनुष्य की प्रधान आवश्यकता में परिवर्तित कर देगा। काम के घंटों में प्रस्तावित घटाव और काम की स्थितियों में अधिक सुधार के फलस्वरूप यह कार्य सुगम होगा। जब उत्पादन की हर शाखा स्वचालित होगी और जब मनुष्य यंत्र का स्वामी बन जायेगा उस समय आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में उसे कम श्रम तथा समय लगाना पड़ेगा। फ़िलहाल कभी कभी कष्टकर और थकानेवाला श्रम सुविकसित स्वस्थ व्यक्ति के लिए आनंद और सुख का स्रोत बन जायेगा।

आगामी सप्तवर्षीय अवधि में कम्यूनिज़्म के भौतिक और प्राविधिक आधार के निर्माण पर बल देते समय हम हर बात में मार्क्सवाद-लेनिनवाद और सोवियत संघ तथा अन्य सभी समाजवादी देशों के अनुभव से श्रीगणेश करते हैं।

सामाजिक विकास हमारे आगे वैज्ञानिक कम्यूनिज़्म की एक और प्रधान समस्या खड़ी कर देता है। यह है **समाज द्वारा उत्पादित भौतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का उसके सभी सदस्यों में वितरण।** मार्क्सवाद-लेनिनवाद हमें सिखाता है कि सामाजिक विकास में वितरण निर्णायक नहीं अपितु एक

गौण पहलू हैं और उनका स्वरूप एवं सिद्धांत उत्पादन की पद्धति एवं मात्रा पर निर्भर करते हैं।

समाजवाद के अंतर्गत वितरण का मूलतः आधारभूत सिद्धांत होता है 'हर एक से उसकी क्षमतानुसार, हर एक को उसके श्रमानुसार'। इसका अर्थ यह है कि भौतिक और सांस्कृतिक पदार्थ का सबसे बड़ा हिस्सा समाज के हर सदस्य द्वारा सामाजिक उत्पादन में लगाये जानेवाले श्रम के अंश के अनुसार वितरित किया जाता है।

हमें निश्चय ही ध्यान में रखना चाहिए कि समाजवाद के अंतर्गत भी भौतिक और सांस्कृतिक पदार्थ का काफ़ी और वृद्धिशील अंश लगाये गये श्रम की मात्रा या गुण को देखे बिना यानी निःशुल्क वितरित किया जाता है। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य-सेवा, पेंशन, बड़े परिवारों के लिए अनुदान, क्लब-घर, पुस्तकालय इत्यादि पर समाज विशाल धन-राशि ख़र्च करता है।

निम्नलिखित तथ्यों से सूचना मिलती है कि हमारी जनता के जीवन-स्तर के सुधार में सरकारी और कोलख़ोज़ी ख़र्च का क्या स्थान है। सामाजिक उत्पादन में कोई १० करोड़ कामगार, कार्यालय-कर्मचारी और कोलख़ोज़-किसान लगे हुए हैं। लगभग २ करोड़ पेंशनरों का भरण-पोषण सरकार, कोलख़ोज़ों और सार्वजनिक संगठनों द्वारा किया जाता है। किंडरगार्टनों, शिशु-गृहों और बाल-गृहों में ५० लाख बच्चों का प्रबंध है; उच्च तथा विशेष माध्यमिक एवं श्रम-संचय विभाग के व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूलों में ३३,००,००० विद्यार्थियों को सरकार की ओर से वृत्ति एवं छात्रावासों में निवास की सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास-स्कूलों के छात्रों का पूरा ख़र्च सरकार उठाती है। हमारे तरुण पायोनियर शिविर, ग्रीष्म-कालीन स्कूली मैदान और पर्यटक शिविर प्रतिवर्ष ५३,००,००० बच्चों को स्थान देते हैं। हर वर्ष ३० लाख से भी अधिक औद्योगिक एवं कार्यालय-कर्मचारी और कोलख़ोज़ी किसान

उपचार या विश्राम के लिए आरोग्यालयों या आरामघरों में रहते हैं और उनका खर्च सामाजिक बीमा निधि और कोलख़ोज़ों द्वारा उठाया जाता है। इसके अलावा लगभग ७० लाख अविवाहित माताओं और अधिक बच्चों वाली माताओं को सरकारी अनुदान मिलते हैं।

भविष्य में इस प्रकार का सरकारी ख़र्च बढ़ता ही जायेगा क्योंकि जैसे जैसे हम कम्यूनिज़्म की ओर अग्रसर होंगे वैसे वैसे समाज अपने हर सदस्य को जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के लिए अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध करा देगा।

फ़िलहाल सामाजिक उत्पादन से हर नागरिक को मिलनेवाले अंश का मापदंड है उसका श्रम जो कि मात्रा और गुण की दृष्टि से नापा जाता है। लेनिन ने बतलाया था कि "जब तक हम कम्यूनिज़्म की 'उच्चतर' अवस्था तक नहीं पहुंचते, समाजवादियों की मांग है कि श्रम और उपभोग की मात्राओं पर समाज और **सरकार** का **अत्यंत कठोर** नियंत्रण हो" (लेनिन, ग्रंथ-संग्रह; खंड २५, पृष्ठ ४४१)।

हमारे देश को 'युद्धकालीन कम्यूनिज़्म' के काल-खंड से गुज़रना पड़ा। उस समय हमें अस्थायी उपाय के रूप में काम के अनुसार वितरण का सिद्धांत त्याग कर 'खानेवालों' की संख्या के अनुसार वितरण का सिद्धांत अपनाना पड़ा। इसका कारण समृद्धि नहीं बल्कि खाद्यान्न और उपभोग्य माल का तीव्र अभाव था। खाद्यान्न वितरण में अत्यंत कठोर अनुशासन के द्वारा सरकार सार्वत्रिक अकाल को रोक सकी और लाल सेना तथा नगरवासी जनता को ज़रा-सा भी क्यों न हो लेकिन नियमित रूप से राशन पहुंचा सकी। कभी कभी तो इस राशन की मात्रा रोज़ाना एक पौंड का आठवां हिस्सा भर होती थी।

लेकिन इस वितरण प्रणाली को सामान्य प्रणाली नहीं माना जा सकता था। देश ने आर्थिक पुनःसंस्थापन एवं विकास का कार्य हाथ में लिया ही था कि उपर्युक्त प्रणाली के दोष स्पष्ट दृष्टिगोचर हुए। लेनिन

ने साफ़ साफ़ बता दिया था कि कामगार को अपने काम के परिणामों में दिलचस्पी दिलानेवाली भौतिक प्रेरणा के बिना देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने या समाजवादी अर्थ-व्यवस्था निर्माण करने और करोड़ों लोगों को कम्यूनिज़्म की ओर अग्रसर करने का सवाल ही नहीं उठता।

शांतिपूर्ण निर्माण का कार्य आरंभ होते ही औद्योगिक, दफ़्तरी और अन्य कर्मचारियों को पैसे के रूप में वेतन दिया जाने लगा। इसका आधारभूत सिद्धांत था काम के अनुसार वितरण और कोलखोज़ प्रणाली की विजय के परिणामस्वरूप यह सिद्धांत ग्रामीण क्षेत्रों में भी दृढ़तापूर्वक स्थापित किया गया।

कुछ वैज्ञानिक कार्यकर्त्ता अपने लेखों और भाषणों में यह दोषारोपण करते हैं कि काम के अनुसार वितरण से समाजवादी समाज पर पूंजीवादी नियम का प्रयोग सूचित होता है। वे पूछते हैं कि क्या वह समय नहीं आया जब इस सिद्धांत को छोड़कर हम समाज के सभी श्रमिक सदस्यों में सामाजिक उत्पादन के समान वितरण का सिद्धांत अपना लें? हम इससे सहमत नहीं हैं।

यह सही है कि मार्क्स और लेनिन ने समाजवाद के अंतर्गत 'पूंजीवादी नियम' के अवशेष की अनिवार्यता के बारे में बतला दिया था। लेकिन उनका अभिप्राय विधान संबंधी स्वरूप से था जो पुराने समाज से चला आता है और कम्यूनिज़्म के अंतर्गत लोप हो जाता है।

समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांतानुसार समाजवादी वितरण का अर्थ यह है कि एक ही क़ानूनी मापदंड विभिन्न लोगों पर लगाया जाता है। यह एकरूप और समान मापदंड है श्रम। समाजवाद में वर्ग विषयक असमानता का कोई स्थान नहीं, वहां असमानता रहती है केवल वितरित सामाजिक उत्पादन के अंश के बारे में। चूंकि विभिन्न लोगों के पास विभिन्न कौशल, प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं और उनके परिवारों के आकार भी विभिन्न होते हैं इसलिए यह बिल्कुल

स्वाभाविक है कि समान काम के लिए समान वेतन के बावजूद उनकी आय असमान होती है। लेकिन कम्यूनिस्ट समाज की पहली अवस्था में यह अनिवार्य है।

क़ानूनी तरीक़ों द्वारा सामाजिक संबंध अभिव्यक्त होते हैं और हमें इन तरीक़ों और सामाजिक संबंधों के तत्त्व में गड़बड़ घोटाला नहीं करना चाहिए। पूंजीवादी क़ानून उत्पादन साधनों का व्यक्तिगत निजी स्वामित्व स्वीकार करता है जबकि समाजवाद इन्हें सार्वजनिक संपत्ति मानता है। यह बात पूंजीवादी क़ानून से स्पष्टतया भिन्न है। समाजवाद के अंतर्गत सभी लोग उत्पादन साधनों से समान संबंध रखते हैं और उन्हें अपने काम के अनुसार वेतन दिया जाता है। समाजवाद में समाज के सभी समर्थ सदस्यों पर लागू सिद्धांत यह है: जो काम नहीं करता, वह खायेगा भी नहीं।

पूंजीवाद के अंतर्गत वितरण परिणामतः काम पर नहीं बल्कि मूलतः पूंजी पर आधारित होता है और मूल्य, लाभ तथा लगान के नियमों से नियंत्रित। इसी कारण सबसे बड़ी आय ज़्यादा काम करनेवालों की नहीं बल्कि ज़्यादा पूंजीवालों की होती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि पूंजीवाद और समाजवाद के अंतर्गत उत्पादित मूल्यों के वितरण का मार्ग मूलतः भिन्न है।

काम के अनुसार वितरण का समाजवादी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि समाजवादी अवस्था में समान वितरण असंभव है। वर्तमान स्थितियों में काम के अनुसार वितरण यही एकमात्र तर्कसंगत और न्याय्य सिद्धांत है। हम इस तथ्य की अवज्ञा नहीं कर सकते कि समतलता का परिणाम होगा वितरण की अन्याय्य पद्धति: अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामगारों को समान अंश मिलेगा और इससे कामचोर लोग फ़ायदा उठायेंगे। अधिक अच्छा काम करने, श्रम-उत्पादिता बढ़ाने और ज़्यादा माल पैदा करने की लोगों की भौतिक प्रेरणा शिथिल

पड़ जायेगी। समतलता का अर्थ कम्यूनिज़्म में प्रवेश नहीं बल्कि कम्यूनिज़्म की बदनामी ही होगा।

काम के अनुसार वितरण से उत्पादन के परिणामों में रुचि लेने के लिए भौतिक प्रेरणा मिलती है। इससे श्रम-उत्पादिता, उच्चतर कौशल और प्राविधिक प्रगति के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इससे एक महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक कार्य भी संपन्न होता है। वह यह कि लोग समाजवादी अनुशासन से परिचित हो जाते हैं और श्रम सार्वत्रिक एवं आवश्यक बन जाता है। समाजवाद श्रमिक के उत्साह का संवर्द्धन करता है; नैतिक प्रेरणाओं को अधिकाधिक महत्त्व प्राप्त होता जाता है। भौतिक प्रेरणाओं की बदौलत, उच्चतर सजगता के फलस्वरूप और अभ्यास के परिणाम में श्रम समाजवादी समाज के करोड़ों लोगों की दृढ़मूल आवश्यकता बन जाता है।

समाज के सदस्यों में सामाजिक पदार्थ का नियंत्रित वितरण केवल कम्यूनिज़्म के अंतर्गत ही समाप्त हो सकेगा जब उत्पादक शक्तियों के विस्तार की वह अवस्था होगी जिसमें सभी आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओं की समृद्धि होगी और जब लोग भौतिक मूल्यों के अपने अंश का विचार न करते हुए स्वेच्छापूर्वक अपनी पूरी क्षमता के साथ इस ख़्याल से काम करेंगे कि यह आम कल्याण के लिए आवश्यक है।

अवश्य ही कम्यूनिस्ट समाज में उत्पादन की विविध शाखाओं में श्रम का योजनाबद्ध एवं संगठित बंटवारा होगा और विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के ख़ास पहलुओं के अनुसार काम के समय का सामाजिक नियंत्रण भी होगा। यंत्र उद्योग में एक ऐसी लय पैदा हुई है जिसके लिए काम की अनुरूप व्यवस्था आवश्यक है।

कम्यूनिस्ट समाज के बारे में एक गंवार धारणा यह है कि यह मनुष्य प्राणियों का एक ढीला-ढाला, असंगठित और अराजकतापूर्ण जमाव मात्र है। नहीं, यह सही नहीं है। असल में यह श्रमिक जनों का

सुसंगठित और सुसमन्वित समाज होगा। यंत्र के समुचित संचालन के लिए प्रत्येक कामगार को अपना श्रम सम्बंधी कार्य और सामाजिक कर्त्तव्य निर्धारित समय में और निश्चित प्रणाली के अनुसार पूर्ण करना होगा। व्यापक मात्रा में यंत्रीकृत एवं स्वचालित भावी उद्योग में काम के ज्यादा घंटों की ज़रूरत नहीं होगी। अध्ययन, कला, साहित्य, खेल-कूद इत्यादि के लिए काफ़ी समय उपलब्ध होगा।

समाजवादी संपत्ति के कोलख़ोज़ी और सार्वजनिक स्वरूपों को कैसे विकसित किया जाये और उन्हें एक दूसरे के निकटतर कैसे लाया जाये इस सवाल का कम्यूनिस्ट निर्माण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टि से काफ़ी महत्त्वपूर्ण स्थान है।

यह पूर्णतया स्पष्ट है कि भविष्य में संपत्ति के कोलख़ोज़-सहकारी और राजकीय स्वरूपों का एक अविभाज्य कम्यूनिस्ट संपत्ति में विलीनीकरण होगा। यहां पूछा जा सकता है कि फिर क्यों हम उनके विलीनीकरण का आग्रह नहीं करते और क्यों ऐसा सोचते हैं कि वर्तमान अवस्था में हमें कोलख़ोज़-सहकारी संपत्ति को राजकीय संपत्ति के साथ साथ विकसित करना चाहिए?

बात यह है कि संपत्ति के स्वरूप इच्छानुसार नहीं बदले जा सकते। वे आर्थिक नियमों के अनुसार विकसित होते हैं और उत्पादक शक्तियों की प्रकृति एवं स्तर पर निर्भर करते हैं। कोलख़ोज़ प्रणाली कृषि क्षेत्र की उत्पादक शक्तियों के वर्तमान स्तर एवं विकास विषयक आवश्यकताओं के पूर्णतया अनुरूप है। इस प्रणाली में आधुनिक कृषि यंत्रों का अत्यंत प्रभावशाली उपयोग हो सकता है जो कि छोटे छोटे किसानों की टुकड़ियल खेती में असंभव है। अब चूंकि कोलख़ोज़ों को शक्तिशाली आधुनिक मशीनरी सीधे सपलाई की जा रही है इसलिए उनका उत्पादन अधिक शीघ्रता से बढ़ रहा है।

कृषि की कई शाखाएं निकट अतीत में पिछड़ गयीं इसका कारण यह नहीं था कि कोलखोज़ प्रणाली उत्पादक शक्तियों के विस्तार में बाधा डाल रही थी बल्कि यह कि उसकी क्षमताओं और सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा था। कृषि क्षेत्र की गत पांच वर्षों की उपलब्धियां इस बात का निर्णायक प्रमाण हैं कि उत्पादन संबंधों की कोलखोज़ प्रणाली की क्षमताओं का समाप्त होना दूर ही रहा, वह कृषि-क्षेत्र की उत्पादक शक्तियां बढ़ाने में सहायक हो रही है और भविष्य में काफ़ी समय तक बराबर सहायक होती रहेगी।

उत्पादक शक्तियों के सतत विकास का रुझान यह होगा कि कोलखोज़ उत्पादन के समाजीकरण की मात्रा बढ़े, कोलखोज़-सहकारी संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति के निकटतर आये और क्रमशः इन दोनों के बीच की विभाजन-रेखा लोप हो जाये। निम्नलिखित विशेष प्रक्रियाओं से यह स्पष्ट होता है:

पहले, कोलखोज़ों की उस अविभाज्य निधि की सतत वृद्धि जो कि कोलखोज़ उत्पादन के बराबर विस्तार का आर्थिक आधार है, और कोलखोज़-सहकारी एवं सार्वजनिक संपत्ति में क्रमशः निकटतर संबंधों की स्थापना।

दूसरे, कोलखोज़ों के उत्पादन में कृषि की अधिकाधिक शाखाओं का संमिलन। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जायेगा वैसे वैसे कोलखोज़ अपने सदस्यों की केवल रोटी संबंधी नहीं बल्कि मांस, दूध, मक्खन, आलू और अन्य साग-सब्ज़ियों और फलों से संबंधित आवश्यकताएं भी अधिक अच्छी तरह पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। यह सब कम उपजवाली निजी खेतीबारी से नहीं बल्कि कोलखोज़ों से प्राप्त होगा जिनका उत्पादन-स्तर अनगिनत मात्रा में ऊंचा होता है।

तीसरे, कोलखोज़ कोलखोज़ के बीच उत्पादन संबंध और सहकार के विविध प्रकार। इन्हें अधिक विस्तृत रूप से लागू किया जा रहा है

और यह निश्चित है कि भविष्य में और भी वड़े पैमाने पर इनका विकास होगा। बिजलीघरों, सिंचाई नहरों और खाद्य-पदार्थों के कारख़ानों का संयुक्त निर्माण, निर्माण-सामग्रियों का उत्पादन और सड़कों का निर्माण—इन सब के लिए कई कोलख़ोज़ों के प्रयत्नों के अधिक प्रणालीबद्ध समन्वय की आवश्यकता है।

चौथे, कृषि के विद्युतीकरण, यंत्रीकरण और स्वचालन के परिणामस्वरूप कोलख़ोज़ उत्पादन साधनों और सरकारी तथा सार्वजनिक साधनों का समन्वय और एक अर्थ में विलीनीकरण भी होगा। कृषि-क्षेत्र का श्रम क्रमशः एक प्रकार का औद्योगिक श्रम बन जायेगा।

कोलख़ोज़-सहकारी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति के स्वरूपों का विलीनीकरण ऐतिहासिक रूप से अनिवार्य है। यह कोलख़ोज़-सहकारी संपत्ति को घटाकर नहीं बल्कि समाजवादी शासन की सहायता और समर्थन से उसका समाजीकरण का स्तर ऊंचा उठाने के ज़रिये संपन्न होगा।

कोलख़ोज़-सहकारी संपत्ति का राजकीय संपत्ति के साथ एक अविभाज्य सार्वजनिक संपत्ति के रूप में विलीनीकरण कोई सीधा-सादा संगठनात्मक और आर्थिक उपाय नहीं बल्कि शहर और देहात के प्रधान भेदों की खाई पाटने की महत्त्वपूर्ण समस्या का हल है।

आगामी सात वर्षों में कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हासिल करने का और इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की सांस्कृतिक एवं कल्याणकारी सुविधाओं में महान सुधार करने का हमारा इरादा है। कोलख़ोज़ देहातों को नवीनतम म्युनिसिपल और सांस्कृतिक सुविधाओं से संपन्न आधुनिक नगर-तुल्य बस्तियों में परिवर्तित करना पार्टी का भावी लक्ष्य होगा।

आर्थिक विकास की समस्याओं के साथ साथ हमारे सामने **कम्यूनिज़्म के व्यापक निर्माण की अवधि में समाज, राज्य और प्रशासन के राजनीतिक संगठन की समस्याएं** भी उठ खड़ी हुई हैं।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद हमें सिखाता है कि कम्यूनिज्म के अंतर्गत राज्य झरता जायेगा, सरकारी प्रशासन के कर्त्तव्यों का राजनीतिक स्वरूप समाप्त हो जायेगा और ये कर्त्तव्य सीधे जनता के प्रशासनाधीन होंगे। लेकिन हमें इस प्रक्रिया के प्रति भोला दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि राज्य का झर जाना शरद् के पतझड़ के समान होगा जब सारे वृक्ष ठूंठ भर रह जाते हैं।

अगर हम इस सवाल को द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से देखें तो राज्य के झर जाने का मतलब होगा समाजवादी राज्य का कम्यूनिस्ट सार्वजनिक आत्मप्रशासन में विकास; क्योंकि कम्यूनिज्म के अंतर्गत भी कुछ ऐसे सार्वजनिक कर्त्तव्य रहेंगे जो आज राज्य द्वारा पूर्ण किये जाते हैं। लेकिन उनका स्वरूप और उनके कार्यान्वय की पद्धतियां आज से भिन्न होंगी।

समाजवादी राज्य के विकास की मुख्य प्रवृत्ति है सभी राष्ट्रीय मामलों की व्यवस्था में जनता के विशालतम भागों को स्थान दिलाकर और आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की देखभाल में सभी नागरिकों को प्रविष्ट करके लोकतंत्र को अधिकतम बढ़ावा देना।

सामाजिक जनवादी विचारक और संशोधनवादी बराबर समाजवादी लोकतंत्र की निंदा एवं मानहानि करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जैसा कि वे समझते हैं, 'लोकतंत्रीकरण' में समाजवाद के अंतर्गत श्रमिक वर्ग और उसकी पार्टी की प्रमुख भूमिका के त्याग और पूंजीवादी लोकतंत्र के स्वरूपों की ओर पुनरागमन ध्वनित है। उनके दृष्टिकोण के अनुसार इनके बिना न लोकतंत्र संभव है और न समाजवाद ही। उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ है शब्दाडंबरपूर्ण संसदीय भाषण करने, विभिन्न पार्टियों के राजनीतिक मेल बनाने और 'मुक्त निर्वाचनों' का प्रदर्शन करने का अवसर। वस्तुतः ये मुक्त निर्वाचन पूंजी की सर्वशक्तिमत्ता के आवरण और जनता के वास्तविक मताधिकार के हरण के अलावा और कुछ नहीं हैं। हमारे लिए लोकतंत्र का अर्थ है वास्तविक जनशासन।

इसमें जनता की गतिविधियों और पहलक़दमी के लिए अर्थात् जनता के स्वशासन के लिए अधिकतम अवसर सन्निहित हैं (**तालियां**)।

यह स्पष्ट हो चुका है कि हमारी सरकारी संगठनों के अनेक कर्त्तव्य क्रमशः सार्वजनिक संगठनों के हाथों में चले जायेंगे। हमारी सांस्कृतिक सेवाओं के कुछ पहलुओं का ही उदाहरण लीजिये। यह बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि वे सरकारी संगठनों के अधीन रहें। सार्वजनिक संगठन उतनी ही सफलता के साथ उनका संचालन कर सकते हैं।

अनुभव यह भी बतलाता है कि स्वास्थ्य-केंद्रों और हमारी स्वास्थ्य-सेवाओं में सुधार आवश्यक है। स्पष्टतया हम ऐसी स्थिति को पहुंच रहे हैं जब शहर की अधिकाधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवाएं ट्रेड-यूनियनों के मातहत आनी चाहिए और देहाती इलाक़ों में फ़िलहाल सीधे स्थानीय सोवियतों के मातहत।

आज तक खेलकूद आंदोलन पर 'व्यायाम और खेलकूद समिति' नामक सरकारी संगठन की निगरानी रहती थी। अब हमने एक अधिक तर्कसंगत व्यवस्था ढूंढ ली है जिसके अंतर्गत खेलकूद आंदोलन में रुचि रखनेवाली सार्वजनिक संस्थाओं का निर्णायक स्थान होगा। अब 'ऐच्छिक खेलकूद संस्था संघ' नामक सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक संगठन क़ायम होगा।

इसी प्रकार सार्वजनिक सुव्यवस्था और समाजवादी मानवीय संबंधों के नियमों से संबंधित सवाल भी अधिकाधिक मात्रा में ग़ैरसरकारी संगठनों के अधिकार क्षेत्र में आने चाहिए। आज सोवियत संघ में राजनीतिक अपराधों के लिए लोगों के विरुद्ध मुक़दमा चलाये जाने के कोई मामले नहीं हैं। यह निःसन्देह एक महान उपलब्धि है। यह हमारी जनता की अतुलनीय राजनीतिक एकता और कम्यूनिस्ट पार्टी तथा सोवियत सरकार के लिए ठोस समर्थन का प्रमाण है (**देर तक तालियां**)।

लेकिन आज भी कुछ ऐसे मामले हैं जब सार्वजनिक सुव्यवस्था का भंग होता है और इनका निश्चयपूर्वक सामना करना आवश्यक है। क्या सोवियत जनता समाजवादी क़ानून और सुव्यवस्था को तोड़नेवाले इन लोगों का मुक़ाबला नहीं कर सकेगी? हां, ज़रूर कर सकेगी। हमारे सार्वजनिक संगठन इसके लिए सुसज्जित हैं। उनकी क्षमताएं और साधन मिलिशिया (पुलिस), न्यायालय और अभियोजन अधिकारियों की क्षमताओं और साधनों से किसी तरह कम नहीं हैं।

हम ऐसी स्थिति को पहुंच रहे हैं जब सार्वजनिक सुव्यवस्था एवं संरक्षा के कर्त्तव्यों का पालन मिलिशिया और न्यायालय जैसे सरकारी संगठनों के साथ साथ सार्वजनिक संगठन भी करेंगे। यह प्रक्रिया अब कार्यान्वित हो रही है। हमने मिलिशिया की संख्या बहुत ही कम कर डाली है और राज्य संरक्षा संस्थाओं का व्यय भी काफ़ी घटा दिया है।

समाजवादी समाज सार्वजनिक सुव्यवस्था के पालनार्थ जनता-मिलिशिया, मित्र पंचायत जैसे ऐच्छिक संगठनों की स्थापना करता है। सार्वजनिक कर्त्तव्यों के पालन में ये संगठन नयी पद्धतियां लागू करेंगे और नये तरीक़ों का अनुसरण करेंगे। अपनी अपनी बस्तियों में सार्वजनिक सुरक्षा क़ायम रखना और यह देखना कि सभी नागरिकों के अधिकारों एवं हितों का समुचित आदर एवं संरक्षण हो रहा है यही स्वयंसेवक जनता-मिलिशिया की टुकड़ियों का कर्त्तव्य होगा।

समय आ चुका है कि मित्र पंचायतों की ओर अधिक ध्यान दिया जाये। इनका काम मुख्यतया अपराध निरोधक होना चाहिए—इन्हें हर प्रकार के बुरे चाल-चलन की रोकथाम करनी चाहिए। और इन्हें अपना कार्य केवल कारखानों या खेतों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि हमारी नीति-संहिता के उल्लंघन के विरुद्ध, स्वीकृत प्रतिमानों की अवज्ञा करनेवाले समुदाय-सदस्यों के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

मित्र पंचायतों के सक्रिय संचालन और सार्वजनिक सुव्यवस्था संगठन में समाज के सदस्यों के निर्वाचन से नियमोल्लंघन करनेवालों का सामना करना अधिक आसान होगा। नियमोल्लंघन करनेवाला व्यक्ति क़ानून को तोड़ने या दंडनीय अपराध करने के बाद नहीं बल्कि तभी पकड़ा जा सकेगा जब वह सार्वजनिक व्यवहार के प्रतिमानों से इस तरह विचलित होगा जिसका परिणाम समाज-विरोधी अपराध हो सके। ऐसे लोगों पर जनमत का समय पर प्रभाव पड़ेगा और इसके फलस्वरूप क़ानून तोड़ने की उनकी प्रवृत्ति रोकी जा सकेगी। आवश्यकता ऐसे उपायों की है जो समाज-विरोधी कृत्यों को रोक देंगे और अंततः उन्हें पूर्णतया असंभव बना देंगे। यहां मुख्य बात है अपराध-निरोध अर्थात् शिक्षा-कार्य।

यह सही है कि तभी भी न्यायालयों, मिलिशिया और अभियोजन अधिकारियों के अधीन कुछ निश्चित कर्त्तव्य रहेंगे। समाजवादी व्यवहार के प्रतिमानों के पालन से बराबर इन्कार करनेवाले और समझाने-बुझाने से न सुधरनेवाले लोगों पर सुधारक प्रभाव डालने की दृष्टि से इन्हें काम करना चाहिए।

कुछ सरकारी कर्त्तव्यों को सार्वजनिक संगठनों के हाथ सौंप देने में ग़ैरवाजिब जल्दी नहीं करनी चाहिए। कुछ मामलों में यह हस्तांतरण अधिक दृढ़तापूर्वक किया जायेगा जबकि कुछ दूसरे मामलों में हम प्राथमिक और अन्वेषणात्मक क़दम उठायेंगे ताकि सार्वजनिक सुव्यवस्था के रक्षण में स्वयं जनता को प्रशिक्षित किया जा सके।

यह तर्कसंगत है कि फ़िलहाल सरकारी संगठनों द्वारा किये जानेवाले कुछ कार्य सार्वजनिक संस्थाओं को सौंप देने से यह अभिप्राय नहीं कि कम्युनिज़्म के निर्माण में समाजवादी राज्य की भूमिका कमज़ोर हो जाये। फ़िलहाल सरकारी संगठनों द्वारा पालन किये जानेवाले कुछ कर्त्तव्यों का भार सार्वजनिक संगठनों द्वारा स्वीकार किया जायेगा इस तथ्य के परिणाम में समाजवादी समाज का राजनीतिक आधार

विशालतर और दृढ़तर हो जायेगा और इससे समाजवादी लोकतंत्र के अधिक विकास में सहायता मिलेगी।

सोवियत प्रणाली अटूट बुनियाद पर खड़ी है यह बात केवल हम, कम्यूनिस्ट और आम सोवियत जनता ही नहीं बल्कि वे लोग भी मानते हैं जो यहां यह देखने के लिए आते हैं कि सोवियत प्रणाली टूटी तो नहीं जा रही है और अपना-सा मुंह लेकर वापस जाते हैं क्योंकि उन्हें यहां जो दिखाई देता है वह उनकी पसंद का नहीं होता। वे अभी भी आशा करते हैं कि आगे किसी समय सोवियत राज्य कमज़ोर हो जायेगा; लेकिन हमारे देश के सामने जो भविष्य है वह और भी उज्ज्वल है (**ज़ोर की तालियां**)।

भविष्य में सोवियत संघ अपनी अर्थ-व्यवस्था के, हमारी प्रणाली के भौतिक आधार के, विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में होगा। लेनिन का कथन है कि "पूंजीवादी प्रणाली में अर्थ-व्यवस्था मालिक लोग चलाते हैं, सरकारी संगठन नहीं। हमारे देश में आर्थिक विकास हम सब का साधारण कार्य है। हमारे लिए यह राजनीति की सबसे अधिक रोचक शाखा है" (लेनिन, ग्रंथ-संग्रह, खंड ३२, पृष्ठ ४०६-०७)।

शांति की रक्षा और साम्राज्यवादी शक्तियों के सशस्त्र आक्रमण के भय से देश की प्रतिरक्षा के संबंध में समाजवादी राज्य के कर्त्तव्य विशेष महत्त्वपूर्ण और विशाल हैं। जब तक पश्चिमी शक्तियां अपने आक्रमणकारी सैनिक गुट्ट बनाये रखती हैं तब तक हमारे लिए अपनी पराक्रमी सशस्त्र सेनाओं को बलिष्ठतर और प्रवीणतर बना लेना अनिवार्य है। ये सेनाएं हमारी जनता की महान सिद्धियों और प्रभावशाली शांतिपूर्ण श्रम का संरक्षण करती हैं (**देर तक ज़ोर की तालियां**)। हमें उन राज्य संरक्षा सेवाओं को भी मज़बूत बनाना चाहिए जिनका कर्त्तव्य मुख्यतया उन साम्राज्यवादी एजेंटों का मुक़ाबला करना है जो चोरी

चोरी हमारे देश में भेजे जाते हैं। हमें उन दूसरे संगठनों को भी मज़बूत बनाना चाहिए जिनका काम है हमारे साम्राज्यवादी शत्रुओं की उत्तेजक कार्रवाइयों और योजनाओं को परास्त कर देना। समाजवादी देशों के विरुद्ध विध्वंसकारी योजनाओं पर ये साम्राज्यवादी शत्रु अपार धन लगा रहे हैं। फिर इस हालत में कैसे हम उन संगठनों को बंद कर सकते हैं जिनका मुख्य कार्य समाजवादी राज्य को सुरक्षित रखना है? वह तो बड़ी घातक भूल होगी।

सोवियत राज्य के दृढ़ीकरण पर इतना अधिक ध्यान देने के लिए यूगोस्लाव संशोधनवादी हमारी पार्टी की आलोचना करते हैं। वे दोष लगाते हैं कि यह मार्क्सवाद-लेनिनवाद के इस कथन से मेल नहीं खाता कि राज्य झर जायेगा।

जैसा कि मैं बता चुका हूं, अब हमारे यहां राजनीतिक कारणों से किसी को भी जेल में नहीं रखा जा रहा है। अच्छा होगा यदि बलप्रयोगी (सरकारी) संगठनों के झर जाने के बारे में तर्कान्वेषण की अभिलाषा रखनेवाले यूगोस्लाव नेता उन सभी कम्यूनिस्टों को रिहा कर दें जो यूगोस्लाविया की कम्यूनिस्ट लीग के नये कार्यक्रम से सहमत न होने और समाजवाद के निर्माण एवं पार्टी की भूमिका के बारे में भिन्न मत धारण करने के कारण इस समय जेल काट रहे हैं (**हॉल में सजीवता। देर तक जोर की तालियां**)।

लेनिनवाद हमें सिखाता है कि राज्य तभी झर जायेगा जब कम्यूनिज़्म की पूरी विजय होगी। वर्तमान स्थितियों में समाजवादी राज्य को दुर्बल कर देने का अर्थ हमारे शत्रुओं की सहायता करना होगा। साम्राज्यवादी हमें इस समय कुचल नहीं सकते, लेकिन संशोधनवादी हमें परिणामतः यह बता रहे हैं कि हम देश की प्रतिरक्षा को सुनिश्चित रखनेवाले राजकीय संगठनों को निःशस्त्र कर दें, समाप्त कर दें और अपने को अपने शत्रुओं की दया-अनुकंपा पर छोड़ दें।

इस समय राज्य को सौंपे गये हमारे समाजवादी देश की प्रतिरक्षा के कार्य से तभी छुट्टी ली जा सकेगी जब सोवियत संघ या उसके मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध साम्राज्यवादी आक्रमण का भय पूर्णतया नष्ट हो जायेगा।

अब चूंकि समाजवाद का निर्माण एक देश तक सीमित नहीं रहा है और एक विश्वव्यापी समाजवादी प्रणाली स्थापित हो चुकी है इसलिए **समाजवाद और साम्यवाद की विजय के लिए चल रहे संघर्ष में नयी सैद्धांतिक समस्याएं** उत्पन्न हुई हैं।

क्या समाजवाद एक देश में अलग से निर्मित किया जा सकता है और क्या उसकी विजय पूर्ण और अंतिम हो सकती है? अभी कुछ समय पहले कम्यूनिस्ट आंदोलन में यह प्रश्न उठाया जाता था और उसपर चर्चा की जाती थी।

जब सोवियत जनतंत्र समाजवाद का निर्माण अभी शुरू ही कर रहा था और जब कई लोगों को देश का भावी मार्ग भविष्य के कोहरे में छिपा हुआ लग रहा था, लेनिन ने लोगों के सामने एक स्पष्ट और उत्साहदायी चित्र प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास "...वह सब कुछ है जो संपूर्ण समाजवादी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है" (लेनिन, ग्रंथ-संग्रह, खंड ३३, पृष्ठ ४२८)। लेनिन के मार्गदर्शन के अविचल अनुसरण से और कम्यूनिस्ट पार्टी से प्रेरणा पाकर सोवियत जनता, पूंजीवादी सैनिक आक्रमण के सतत भय के बावजूद समाजवादी समाज के निर्माण के लिए बराबर कार्यरत रही, समाजवाद की विवरण-रहित राह पर अग्रसर होती रही और संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली (**देर तक तालियां**)।

किन्तु यह अभी तक अंतिम विजय नहीं थी क्योंकि मार्क्सवादियों के अनुसार अंतिम विजय का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर प्राप्त विजय। समाजवाद के निर्माण के बाद हमारा देश एक लंबे अर्से तक दुनिया का

एकमात्र समाजवादी राज्य रहा और पूंजीवादी शत्रुओं से घिरा रहा। वह अपने को सशस्त्र हस्तक्षेप से, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के कारण पूंजीवाद की बलपूर्वक पुनःस्थापना के भय से पूर्णतया सुरक्षित नहीं मान सका क्योंकि उस समय समाजवादी भूमि को जो पूंजीवादी राज्य घेरे हुए थे वे आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से बहुत ही अधिक शक्तिशाली थे।

विश्व स्थिति में तब से मौलिक परिवर्तन हो चुके हैं। अब सोवियत संघ पूंजीवादी राज्यों के घेरे में नहीं है। विश्व में आज दो सामाजिक प्रणालियां हैं: पूंजीवाद जो कि अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है और समाजवाद जो कि एक सशक्त और विकासशील प्रणाली है जिसे सभी देशों के श्रमिकों का समर्थन प्राप्त है **(तालियां)**।

हर अन्य समाजवादी देश की तरह सोवियत संघ के पास भी साम्राज्यवादी आक्रमण की संभावना के विरुद्ध कोई गारंटी नहीं है। लेकिन संसार में आज वास्तविक शक्तियों का संतुलन ऐसा है कि हम किसी भी शत्रु के कैसे भी हमले को पीछे खदेड़ सकेंगे **(ज़ोर की तालियां)**।

आज दुनिया में ऐसी कोई ताक़त मौजूद नहीं है जो हमारे देश में पूंजीवाद को फिर से क़ायम कर सके या समाजवादी पड़ाव को कुचल सके। सोवियत संघ में पूंजीवादी पुनःस्थापना की संभावनाओं के दिन लद चुके। और इसका अर्थ यह है कि **समाजवाद की विजय संपूर्ण ही नहीं बल्कि अंतिम भी है (देर तक ज़ोर की तालियां)।**

अतः यह कहा जा सकता है कि किसी अकेले देश में समाजवाद के निर्माण और उसकी संपूर्ण एवं अंतिम विजय का प्रश्न समाज के ऐतिहासिक विकास-क्रम ने हल कर दिया है।

सोवियत संघ में समाजवाद की विजय और विश्व समाजवादी प्रणाली के संगठन से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग-आंदोलन की शक्तियां बेहद मज़बूत होती हैं और उसके सामने नये क्षितिज खुल जाते हैं। व्लादीमिर इल्यीच लेनिन ने अपनी अंतिम रचना में जो तेजस्वी वैज्ञानिक

भविष्यवाणी की थी वह अब सच निकल रही है। उन्होंने कहा था: "अंतिम विश्लेषण में संघर्ष का परिणाम इस तथ्य से निश्चित होगा कि विश्व की जनसंख्या में रूस, भारत, चीन आदि देशों की विशाल बहुसंख्या है। और ठीक यह बहुसंख्या ही पिछले कुछ वर्षों में मुक्ति संघर्ष में असाधारण शीघ्रता के साथ आकृष्ट हुई है, अतः इस संबंध में संदेह की ज़रा भी गुंजाइश नहीं कि विश्वव्यापी संघर्ष का अंतिम परिणाम क्या होगा। इस अर्थ में समाजवाद की अंतिम विजय पूर्णतया और निस्संदेह सुनिश्चित है।" (लेनिन, ग्रंथ-संग्रह, खंड ३३, पृष्ठ ४५८) **(ज़ोर की तालियां)**।

समाजवादी देश साम्यवाद की ओर अपनी प्रगति किस प्रकार जारी रखेंगे? क्या हम ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जब समाजवादी देशों में से कोई एक कम्यूनिज़्म को अपना लेता है और उत्पादन एवं वितरण के कम्यूनिस्ट सिद्धांत लागू कर देता है जब कि दूसरे देश समाजवादी निर्माण की प्राथमिक अवस्थाओं में कहीं पीछे घिसटते रहे हैं?

अर्थ-व्यवस्था की समाजवादी प्रणाली के विकास को शासित करनेवाले नियमों पर ध्यान देने से स्पष्ट होगा कि उपर्युक्त स्थिति का उत्पन्न होना असंभवप्राय है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यह अनुमान करना ज़्यादा सही होगा कि समाजवाद में सन्निहित क्षमताओं के सफल प्रयोग से सभी समाजवादी देश लगभग एक साथ कम्यूनिस्ट समाज की उच्चतर अवस्था में संक्रमण करेंगे। हम इस तथ्य से आगे बढ़ते हैं कि अर्थ-व्यवस्था की समाजवादी प्रणाली विकास के ऐसे नये नियमों के अधीन है जो मानव समाज के लिए अतीत में अज्ञात थे। उदाहरणार्थ, साम्राज्यवाद के अंतर्गत चलनेवाला नियम है विभिन्न देशों का विषम आर्थिक और राजनीतिक विकास। उस प्रणाली के अंतर्गत विकास का क्रम ऐसा होता है जिसमें कुछ देश दूसरे देशों के उत्पीड़न और शोषण के सहारे ख़ुद

आगे बढ़ सकते हैं। पिछड़े देशों को पराधीनता एवं दासता में रखने के लिए वे अपनी विशेषाधिकार-संपन्न स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

समाजवाद के अंतर्गत चलनेवाला आर्थिक नियम है संतुलित, सानुपात विकास जिसका परिणाम यह होता है कि अतीत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश खोये हुए समय की जल्दी जल्दी भरपाई कर पाते हैं और अन्य समाजवादी देशों के अनुभव, सहयोग और परस्पर सहायता के सहारे अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर ऊंचा उठा लेते हैं। इस प्रकार सभी समाजवादी देशों की आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का स्तर समान रहता है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्व समाजवादी प्रणाली की अधिक वृद्धि और सबलता के फलस्वरूप सभी समाजवादी देश अधिकाधिक सफलता के साथ विकसित होंगे। कम्यूनिज़्म की पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में उनके संक्रमण के लिए आवश्यक स्थितियां अधिकाधिक शीघ्रता से उत्पन्न की जायेंगी।

हमें केवल स्मरण कर लेना चाहिए कि व्यवहार ने कितने प्रभावशाली ढंग से लेनिन का यह कथन प्रमाणित कर दिया है कि अतीत के कुछ पिछड़े देश प्रगत समाजवादी राज्यों के सहारे विकास की कुछ अवस्थाओं को लांघ सकते हैं और बिना पूंजीवादी अवस्था से गुज़रे हुए कम्यूनिज़्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हर कोई कज़ाख़स्तान और मध्य एशिया की जनता की महान समाजवादी सिद्धियां देख सकता है। समाजवादी क्रांति के समय ये लोग या तो पूंजीवादी अवस्था तक पहुंचे ही न थे या अभी अभी उस अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। उन्हें पूंजीवादी विकास की पूरी यंत्रणापूर्ण अवस्था से नहीं गुज़रना पड़ा। उस अवस्था को टालकर वे अधिक प्रगत समाजवादी राष्ट्रों और विशेषकर रूसी समाजवादी राष्ट्र से प्राप्त समर्थन और सहायता के सहारे

समाजवादी परिवर्तन लागू कर सके। मंगोलिया के लोकतंत्रात्मक जनतंत्र का यहां अलग से उल्लेख करना चाहिए। पूंजीवादी अवस्था को टालकर इसने समाजवादी राह पर कभी से दृढ़तापूर्वक क़दम बढ़ाया है और आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रभावोत्पादक प्रगति कर ली है।

कम्यूनिज़्म की दिशा में मानव-जाति की प्रगति की संभावनाओं का सर्वेक्षण करते समय हमें विभिन्न देशों की अत्यधिक विविधतापूर्ण ऐतिहासिक स्थितियां ध्यान में रखनी चाहिए। इससे कम्यूनिज़्म की ओर मानव-जाति की प्रगति के साधारण नियम लागू करने की विशिष्ट पद्धतियां, आदर्श और स्वरूप अनिवार्यतः उत्पन्न होंगे। लेकिन यहां बल इस बात पर देना चाहिए कि कम्यूनिज़्म की ओर सभी देशों की प्रगति में प्रधान एवं निर्णायक पहलू उन सब के लिए लागू साधारण नियम हैं न कि उनके विशिष्ट रूप। मार्क्सवाद-लेनिनवाद के लिए वैज्ञानिक कम्यूनिज़्म के सिद्धांत प्रत्येक देश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उसकी वास्तविक स्थितियों पर लागू करने की क्षमता आवश्यक है।

यूगोस्लाव नेता बड़े ज़ोर-शोर से यह आरोप लगाते रहे हैं कि कम्यूनिस्ट पार्टियां इसलिए उनका विरोध कर रही हैं कि वे अपने देश के विशिष्ट पहलुओं को समाजवाद के निर्माण का आरंभ बिंदु मानते हैं और अन्य समाजवादी देशों के उदाहरण एवं अनुभव का अनुकरण नहीं करते। यह स्पष्टतया सत्य का विकृत रूप है। मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियां स्वीकार करती हैं कि हर देश के समाजवादी विकास के अपने विशिष्ट पहलू होते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम समाजवाद की ओर दूसरे ही किसी मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं जो मार्क्सवाद-लेनिनवाद द्वारा निर्दिष्ट किये गये साधारण मार्ग के समानांतर चलता हो। विचार करने की बात है उस परिस्थिति और अवधि के विशिष्ट पहलू जब कोई देश समाजवाद की दिशा में अग्रसर

होता है। उदाहरणार्थ, समाजवादी निर्माण के दौरान सोवियत संघ में अतीत में की गयी कुछ कार्रवाइयां अन्य देशों में यांत्रिक रीति से जैसी की तैसी नहीं लागू की जा सकतीं। सभी समाजवादी देश समाजवाद का निर्माण कर रहे हैं लेकिन उनके मार्ग एक सांचे के ढले नहीं हैं।

चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी समाजवादी निर्माण के कई मौलिक स्वरूपों का प्रयोग कर रही है। लेकिन उससे हमारा कोई मतभेद नहीं है और न हो सकता है।

यूगोस्लाव संशोधनवादी अब चीनी जनवादी जनतंत्र को अपनी अग्निवर्षा का लक्ष्य बनाकर सोवियत संघ और चीन की कम्यूनिस्ट पार्टियों के तथाकथित मतभेदों के बारे में अपने तरह तरह के आविष्कारों की बौछार कर रहे हैं। हां, कोरी इच्छा के बारे में एक पुरानी रूसी कहावत है कि 'भूखा आदमी हमेशा रोटी की ही सोचता है'। संशोधनवादी हमारी पार्टियों के बीच मतभेद खोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी यह भ्रांतिपूर्ण आशाएं भंग होकर ही रहेंगी **(देर तक जोर की तालियां)**। हम चीन की भ्रातृ पार्टी से संपूर्णतया सहमत हैं यद्यपि कई मामलों में समाजवादी निर्माण की उनकी पद्धतियां हमारी अपनी पद्धतियों से भिन्न हैं। लेकिन हम जानते हैं कि चीन में ऐतिहासिक विकास, जनसंख्या की विशालता, उत्पादन-स्तर और जातीय संस्कृति के अपने विशिष्ट पहलू हैं। इन विशिष्ट पहलुओं की उपेक्षा करना और एक देश के लिए उचित किंतु दूसरे के लिए अनुचित बात की केवल नक़ल उतारना ग़लत होगा।

चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी से हमारा कोई मतभेद नहीं है इसका कारण यह है कि हम दोनों का वही वर्ग-विषयक दृष्टिकोण है और समस्याओं को हम इसी दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी पूरी तरह मार्क्सवादी-लेनिनवादी वर्ग विचार पर आधारित है। वह

साम्राज्यवादियों और शोषकों के विरुद्ध संघर्ष कर रही है और समाजवादी ढंग से जीवन का नवनिर्माण करने के लिए प्रयत्नशील है। वह अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा एकता के सिद्धांतों का पालन करती है और मार्क्सवाद-लेनिनवाद का अनुसरण।

श्रमिक वर्ग की मुक्तता के लिए, समाजवाद के निर्माण के लिए पूंजीवाद-विरोधी संघर्ष में वर्ग-एकता को बनाये रखना और दृढ़तर बनाना यही मुख्य बात है। और इस विषय में कम्यूनिस्टों के बीच कोई मतभेद या परस्पर-विरोधी धारणाएं नहीं हैं, और न हो भी सकती हैं। यही मुख्य बात है जिसके बारे में संशोधनवादियों से हमारा मतभेद है (**ज़ोर की तालियां**)।

समाजवादी निर्माण की पद्धतियों और व्यवहार का प्रश्न हर देश का अपना घरेलू मामला है। कामगार परिषदों के संगठन या यूगोस्लाविया के अंतर्गत मामलों से संबंधित अन्य किसी बात के बारे में यूगोस्लाव नेताओं से हमारा कोई मतभेद नहीं है। समाजवादी देशों की कम्यूनिस्ट और कामगार पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये जाते समय उपर्युक्त बातों के संबंध में न कोई मतभेद थे और न परस्पर-विरोधी धारणाएं ही।

यूगोस्लाव संशोधनवादियों से हम कह सकते है कि जहां छिद्र नहीं है वहां उन्हें न ढूंढिये। ऐसा लगता है कि आप लोग इस बात पर ज़ोर देकर कि मतभेद केवल सोवियत संघ और यूगोस्लाविया के बीच ही नहीं बल्कि सोवियत संघ और चीनी जनवादी जनतंत्र के बीच भी है, अपने आपको प्रोत्साहित करना और यूगोस्लाव जनता को धोखा देना चाहते हैं। लेकिन इससे काम नहीं निकलेगा। आपको ऐसे कोई मतभेद नहीं मिलेंगे (**तालियां**)। सोवियत संघ और चीन की कम्यूनिस्ट पार्टियां इन दो

महान समाजवादी देशों की मैत्री को दृढ़तर बनाने के लिए हर प्रयत्न कर रही हैं (**देर तक जोर की तालियां**)।

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग-आन्दोलन के लिए और कम्यूनिज़्म की विजय के लिए मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारों का वही महत्त्व है जो धरती पर वनस्पतियों और प्राणियों के लिए सूर्यप्रकाश एवं उष्णता का। जिस प्रकार प्रगति और स्वरूप दर्शन की विविधता की दृष्टि से स्वयं जीवन असीम है उसी प्रकार नये अनुभवों एवं नये प्रस्तावों द्वारा अपने विकास एवं समृद्धि की दृष्टि से मार्क्सवाद-लेनिनवाद भी असीम है।

५

कम्यूनिस्ट पार्टी — कम्यूनिज्म की विजय के लिए संघर्ष में सोवियत जनता की अग्रणी और संगठनात्मक शक्ति

साथियो, सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की २० वीं कांग्रेस के बाद की अवधि में हमारी पार्टी का निरंतर विकास होता रहा है, इसकी एकता सुदृढ़ होती रही है और इसे सोवियत जनता का और भी सबल समर्थन प्राप्त होता रहा है। २० वीं कांग्रेस के ऐतिहासिक निर्णयों को कार्यान्वित करने में पार्टी ने जनसाधारण के साथ और भी घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किया और राजनीतिक नेतृत्व एवं संगठन-कार्य संबंधी नये अनुभव प्राप्त किये।

इस अवधि में पार्टी ने घरेलू एवं विदेशी नीति में कई महत्वपूर्ण उपाय कार्यान्वित किये, जिनसे सोवियत संघ की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, जनता की सुख-सुविधा बढ़ी और विश्व के समाजवादी शिविर एवं विश्वशांति को बल मिला **(तालियां)**।

कम्यूनिस्ट निर्माण की सारी समस्याओं को रचनात्मक ढंग से सुलझाने, हर विशेष स्थिति में ऐतिहासिक विकास की पूरी शृंखला में मुख्य और निर्णयात्मक कड़ी ढूंढ़ निकालने, आगे की संभावनाओं को परखने, जनता को क्रियाशील करने, हमारी प्रगति में जो भी घिसी-पिटी या रूढ़िगत बात बाधक बनकर आये उसे निर्भय एवं निर्णयात्मक ढंग से उखाड़ फेंकने आदि की आवश्यकता के सम्बन्ध में लेनिन ने जो

सीखें दी थीं, उनका पालन पार्टी ने निरन्तर दृढ़ता के साथ किया है। पार्टी को जो जीतें मिली हैं और मिल रही हैं, उनका कारण यह है कि वह मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारों में सम्पूर्ण आस्था रखती आयी है और जनता के साथ दृढ़ एकता में आबद्ध रही है **(तालियां)**।

अपने पूर्णाधिवेशनों में पार्टी की केन्द्रीय समिति ने कम्यूनिस्ट निर्माण की प्रमुख समस्याओं की क्रमबद्ध रीति से जांच की। पार्टी की केन्द्रीय समिति उद्योग और निर्माण के प्रबन्ध के पुन:संगठन, मशीन-ट्रैक्टर स्टेशनों के पुन:संगठन और सामूहिक कृषि-प्रणाली के उत्तरोत्तर विकास, स्कूल और जीवन के बीच घनिष्ठ संपर्क और जनशिक्षा के पुन:संगठन जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रव्यापी वाद-विवाद की व्यवस्था की। जनता से परामर्श लेकर, उसकी सामूहिक बुद्धि और समृद्ध अनुभव के आधार पर, पार्टी उन अति महत्त्वपूर्ण उपायों को बनाती और कार्यान्वित करती है जिनसे हमारी प्रगति की रफ़्तार और तेज़ हो जाती है।

२० वीं कांग्रेस के निर्णयों का पालन करते हुए पार्टी ने पार्टी-जीवन के लेनिनवादी मानदंडों और पार्टी के सामूहिक नेतृत्व के सिद्धान्तों को पुन:स्थापित और प्रसारित करने, पार्टी के सदस्यों और समस्त सोवियत जनों की रचनात्मक क्रियाशीलता को हर तरह से बढ़ाने का काम जारी रखा। केन्द्रीय समिति को अपने समस्त क्रिया-कलाप में लेनिनवादी सिद्धान्तों के इस प्रमुख सूत्र से मार्ग-प्रदर्शन मिलता है कि केवल सिद्धान्तवाली नीति ही सही नीति है। पार्टी की आम नीति में मलेन्कोव, कगानोविच, मोलोतोव, बुल्गानिन और शेपीलोव की पार्टी विरोधी दलबंदी ने अड़चनें डालनी शुरू कीं। इस दल ने गुटबन्दी और फूटपरस्ती के निन्दनीय तरीक़े अपनाकर पार्टी की एकता को कमज़ोर करने, २० वीं कांग्रेस के निर्णयों की कार्यान्विति में बाधा डालने तथा पार्टी और देश को लेनिनवादी मार्ग से भटकाने के प्रयास किये।

जीवन, जनता और पार्टी से नाता तोड़कर इस पार्टी विरोधी दलबन्दी ने सोवियत समाज के विकास को नौकरशाही नज़र से देखा। २० वीं कांग्रेस के निर्णयों के अनुसार पार्टी द्वारा लागू किये जानेवाले सारे महत्त्वपूर्ण उपायों का उन व्यक्तियों ने विरोध किया। जिन उपायों के अवलंबन से हम उद्योग, कृषि और जन-कल्याण के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर चुके हैं, उन्हीं का उन्होंने विरोध किया। विदेशी नीति में उन्होंने उन उपायों का विरोध किया जिनका सहारा लेकर हम अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम और विश्वशांति को सुदृढ़ कर सके है।

पार्टी और समस्त सोवियत जनता ने एकमत से सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के जूनवाले पूर्णाधिवेशन के निर्णयों का अनुमोदन किया। उस पूर्णाधिवेशन में इस पार्टी विरोधी दलबन्दी का परदाफ़ाश और सैद्धान्तिक विनाश हो गया। अब हर कोई यह समझ गया है कि पार्टी और इसकी केन्द्रीय समिति ने गुटबन्दी और फूटपरस्ती के निंदनीय तरीक़े अपनानेवाली इस दलबन्दी के प्रति कड़ा रुख अपनाकर कितना अच्छा किया। इस पार्टी विरोधी दलबन्दी की जड़ें उखाड़कर पार्टी ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी झंडे के नीचे केन्द्रीय समिति के चारों ओर अपनी एकता और भी सुदृढ़ कर ली (**देर तक ज़ोर की तालियां**)।

सोवियत जनता लेनिनवादी पार्टी को अपनी जांची-परखी नेत्री और शिक्षिका समझती है तथा इसके दूरदर्शी मार्ग-प्रदर्शन में कम्यूनिज़्म की नयी विजयों की गारंटी अनुभव करती है।

कम्यूनिस्ट पार्टी में जनता के अगाध विश्वास का ज्वलन्त प्रमाण सदस्यों की बढ़ती हुई संख्या है। कामगार वर्ग, सामूहिक किसान वर्ग और सोवियत बुद्धिजीवियों के सर्वोत्तम स्त्री-पुरुष पार्टी में दाख़िल होते है। फ़िलहाल पार्टी में ८२,३९,००० से अधिक सदस्य और उप-सदस्य हैं, अर्थात् २० वीं कांग्रेस के समय जो संख्या थी, उसमें १०,२३,००० की और वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में कामगारों और सामूहिक

किसानों का एक बड़ा रेला आया है और अब नये सदस्यों में उनकी संख्या लगभग दो तिहाई है।

पार्टी पहले से अधिक सशक्त, लेनिनवादी केन्द्रीय समिति के चारों ओर एकताबद्ध तथा कम्यूनिस्ट समाज की स्थापना के लिए बहुमुखी कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित करने में अधिक सक्षम होकर अपनी २१ वीं कांग्रेस आरम्भ कर रही है (**देर तक तालियां**)।

सप्तवर्षीय योजना की पूर्त्ति के प्रयास में हमारी समस्त शक्तियों को जुटाने की, पार्टी के संगठनात्मक और शैक्षणिक कार्यों में और भी ऊंचे स्तर लाने की आवश्यकता है। यह योजना हमारी प्रगति के लिए एक नये और युगान्तरकारी ध्येय का प्रतिनिधित्व करती है। और इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हमें अपनी शक्तियों को लामबन्द करके उनको ठीक से तरतीब देना और अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि हम आगे एक लम्बा कूच बोल सकें।

हमारी कांग्रेस आगामी सात वर्षों के लिए कम्यूनिस्ट निर्माण की वृहत् योजना बना रही है। पार्टी प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित कर रही है और इतिहास की इस अवधि में आम कार्य-नीति निश्चित कर रही है। योजना स्वीकृत हो जाने के बाद हर जनतन्त्र, प्रदेश, क्षेत्र और हलक़े को, हर मिल, कारख़ाने, निर्माण-परियोजना, कोलखोज़ और सोवखोज़ तथा अनुसंधान-केन्द्र को—आलंकारिक शब्दों का प्रयोग करें तो—उन सीमाओं का ठीक ठीक निर्धारण करना है जिनतक अपने कार्य-क्षेत्र में काम करते हुए उन्हें पहुंचना होगा ताकि वे सप्तवर्षीय योजना की सफल पूर्त्ति तथा अतिपूर्त्ति में अधिक से अधिक हाथ बंटायें। इन ठोस उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए पार्टी-संगठनों के समस्त संगठनात्मक और सैद्धान्तिक कार्यों को अब सक्रिय करना होगा।

अब हमें ख़ासकर अपने समस्त क्रिया-कलाप में ठोस दृढ़ता और उद्देश्य की एकाग्रता तथा इस बात के पूर्ण ज्ञान की ज़रूरत है कि हमें

क्या करना है और उसे कैसे करना है। ग्राम चर्चा और ग्राम अपील से कोई लाभ होने को नहीं।

जनसाधारण को यह समझाते हुए कि कम्यूनिज़्म के संघर्ष का क्या अर्थ है, पार्टी उनके सामने ठोस उद्देश्य रखती है और उनकी पूर्त्ति के लिए हर समुदाय के, समस्त जनता के प्रयासों का संगठन और निर्देशन करती है।

सप्तवर्षीय योजना की सफलता का निर्णय सीधे कारखानों, कोलखोज़ों और सोवखोज़ों, वैज्ञानिक संस्थाओं और अनुसंधान-केन्द्रों में किया जायेगा। इसलिए स्थानीय पार्टी-संस्थाओं और प्रारंभिक पार्टी-संगठनों को पहले से बहुत बड़ा रोल अदा करना होगा। यह उनका कर्त्तव्य होगा कि वे हर कारखाने, कोलखोज़ और कार्यालय में रचनात्मक प्रयास और उत्साह का वातावरण तैयार करें।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि उपलब्ध भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाये। हर कर्मी के दिमाग़ में यह बात लानी होगी कि प्रतिव्यक्ति उत्पादन में अग्रणी पूंजीवादी देशों से आगे हम तभी निकल सकते हैं, जब हम उनके उद्योग और कृषि के श्रम-उत्पादिता-स्तर से आगे बढ़ जायें। फ़िलहाल, अमेरिका में उद्योग का श्रम-उत्पादिता-स्तर हमसे लगभग दो-ढाई गुना ऊंचा है और कृषि का श्रम-उत्पादिता-स्तर लगभग तिगुना ऊंचा। हम इस स्थिति में हैं कि अमेरिका के श्रम-उत्पादिता-स्तर की बराबरी कर लें और निकट भविष्य में उसे मात भी दे दें। पार्टी-संगठनों को वे सारे प्रयत्न करने हैं जिनसे इस उद्देश्य की पूर्त्ति में मदद मिले।

इसमें संदेह नहीं कि हमारे कामगार, सामूहिक किसान और बुद्धिजीवी, जो अपने लिए, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपना रचनात्मक उत्साह और पहलक़दमी दिखा देंगे जो शोषक समाज में रहनेवाले अमेरिकन कामगारों व किसानों के श्रम-उत्पादिता-स्तर से आगे

निकलने के लिए आवश्यक है। हमारे देश में विज्ञान और इंजीनियरिंग की नवीनतम सिद्धियों के दक्षतापूर्ण उपयोग से और व्यापक यन्त्रीकरण और स्वचालन के आधुनिक साधनों के प्रयोग से, जो औद्योगिक और कृषि-कार्य को सरल बना देंगे, श्रम-उत्पादिता-स्तर और ऊंचा उठाया जायेगा। और इस संबंध में महत्त्व की बात यह है कि हमारी जनता में कम्यूनिस्ट चेतना की निरंतर वृद्धि होती जा रही है (**तालियां**)।

यह बात उद्योग, कृषि और निर्माण संबंधी समस्त संस्थाओं के कर्मी-समुदायों और हर कामगार और सामूहिक किसान के दिमाग में स्पष्ट हो जानी चाहिए। कम लागत पर अच्छी क़िस्म के अधिक उत्पादन के लिए उद्योग और कृषि में हर कर्मी को श्रम के प्रगतिशील तरीक़ों का प्रयोग करना होगा ताकि वह अपनी मशीन, यन्त्र, ट्रैक्टर और कम्बाइन से अधिक से अधिक लाभ उठा सके।

हमारे संगठनात्मक और सैद्धान्तिक शिक्षा के कार्यों में इसी प्रकार समान रूप से ठोस दृढ़ता और उद्देश्य की एकाग्रता अत्यावश्यक है। हमारी कम्यूनिस्ट निर्माण-योजनाओं की कार्यान्विति के सिलसिले में पार्टी-संगठनों, प्रचारकों और वक्ताओं को सरलता और स्पष्टता से यह समझाना है कि कम्यूनिज़्म का अर्थ क्या है और इससे जनता को कितना बड़ा लाभ हो सकता है। कम्यूनिज़्म की हर अभिव्यंजना को अधिक से अधिक समर्थन और प्रोत्साहन देना है।

मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त, जो हमारी विचारधारा का आधार है, मानव-जीवन से अविच्छिन्न रूप से आवद्ध है। कम्यूनिज़्म के उच्च आदर्श जनता के कार्य से अलग नहीं किये जा सकते क्योंकि वह समाज के समस्त भौतिक मूल्यों का उत्पादन करती है।

कम्यूनिस्ट समाज ही मेहनतकश जनता का चिरवांछित स्वप्न रहा है। लेकिन उस स्वप्न को साकार बनाने में हमें जीवन से दूर भागना नहीं होगा क्योंकि हम इस तथ्य की ओर से आंखें नहीं मूंद सकते कि

कम्यूनिज़्म के निर्माण के लिए मुख्य बात है भौतिक मूल्यों का उत्पादन, जो जनता के जीवन को और सुन्दर, और सुखकर बनाते हैं। कम्युनिस्ट आदर्श वैसे ही समाज में यथार्थ रूप धारण कर सकते है जिसके सदस्य भौतिक और सांस्कृतिक लाभों का प्रचुर मात्रा मे उपभोग करने हों। यही कारण है कि हम जब कम्यूनिज़्म-निर्माण की वृहत् योजनाओं पर विचार-विमर्श करते हैं तो पहले धातु, मशीनरी, तेल, बिजली, अनाज, मांस, मक्खन, वस्त्र, जूतों के अधिकतम उत्पादन और रिहाइशी मकानों के और अधिक निर्माण के महत्त्व पर ज़ोर देते है।

हमारी कम्यूनिस्ट विचारधारा का महत्त्व इस बात में निहित है कि वह मानव के जीवन और कार्य तथा सामाजिक विकास से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है।

साथियो, हमारी पार्टी और सरकारी अधिकारियों को सप्तवर्षीय योजना की पूर्त्ति के लिए अति महत्त्वपूर्ण रोल अदा करना है। सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की २०वीं कांग्रेस के बाद नये अधिकारियों को प्रशिक्षित और नियोजित करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। उद्योग और निर्माण के प्रबन्ध के पुनःसंगठन के फलस्वरूप भूतपूर्व मंत्रालयों और केन्द्रीय विभागों के बहुत-से प्रमुख अधिकारी आर्थिक परिषदों, कारखानों और निर्माण-परियोजनाओं में काम करने के लिए आर्थिक प्रदेशों में चले गये हैं। लाखों सुदक्ष टेकनिशियन और अनुभवी संगठक कृषि-क्षेत्र में काम करने लगे हैं।

लेकिन अधिकारियों के प्रशिक्षण और वितरण के संबंध में अभी भी बहुत कुछ करना है। हमें उत्तरदायी पदों पर वैसे व्यक्तियों को बिठाना है जो उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों, जिनमें पहलकदमी हो, नवीनता की ओर झुकाव हो और जो काम उन्हें सौंपना हो उसका उन्हें पूर्ण ज्ञान हो। हां, वे ऐसे व्यक्ति हों जो लोक-कल्याण के लिए अपनी सारी शक्ति और ज्ञान लगा दें और क्रान्तिकारी जोश, बोल्शेविक

लगन और सिद्धान्त के प्रति ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें। हमारे समस्त अधिकारियों को यह ध्यान में रखना है कि वे अपने काम के लिए पार्टी और जनता के सामने उत्तरदायी हैं।

हमारी पार्टी ऐसे अधिकारियों से संपन्न है। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में अनुभवी व्यक्तियों के साथ साथ, जो अपनी योग्यता का सिक्का जमा चुके हैं, ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हमारे प्रतिभाशील युवक समुदाय का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं। उक्त दोनों प्रकार के व्यक्तियों को महत्त्वपूर्ण पदों पर भेजा जा सकता है। लेकिन यह भी सही है कि हमारे महत्त्वपूर्ण पदों पर—जिनमें ज़िला, नगर, प्रादेशिक और क्षेत्रीय पार्टी-समितियों के सेक्रेटरियों और संघीय जनतन्त्रों की केन्द्रीय समितियों के सेक्रेटरियों के पद भी शामिल हैं—युवकों की संख्या अभी भी अपर्याप्त है।

हमें युवक अधिकारियों को आगे लाने में साहस से काम लेने की ज़रूरत है और युवक और वृद्ध के बीच कोई रेखा नहीं खींचनी है। प्रत्यक्ष है कि हमें 'वृद्ध' और 'युवक' के बारे में अपनी धारणाओं की व्याख्या में संशोधन करना है। अक्सर ३५ या ४० वर्ष का व्यक्ति किसी उत्तरदायी कार्य के लिए अपरिपक्व समझा जाता है। यह ग़लत धारणा है। इस उम्र के व्यक्ति जोश और उत्साह से भरे रहते हैं। हमारा बढ़ता हुआ अधिकारी समुदाय पूर्ण ज्ञान और पर्याप्त अनुभव से संपन्न है। इन लोगों को मौक़ा देना चाहिए कि व्यावहारिक कार्य में अपनी योग्यता दिखाकर वे यह सिद्ध कर सकें कि वे अपने कर्त्तव्यों का सफलतापूर्वक पालन कर सकते हैं। युवक अधिकारियों और वृद्ध अधिकारियों के संयोग से निश्चय ही और भी अच्छे परिणाम निकलेंगे।

कुछ पार्टी-संस्थाएं सुदक्ष और सुशिक्षित व्यक्तियों का हमेशा उचित रूप से मूल्यांकन नहीं कर पातीं और उन्हें ऊपर लाने में हिचकिचाती हैं। यह कोई असाधारण बात नहीं कि उत्तरदायी पदों

पर लम्बे अरसे तक ऐसे ही व्यक्ति बने रहते हैं जिनमें अपर्याप्त योग्यता रहती है और प्रगति और विकास से जिनका संबंध टूट गया-सा होता है और जो अपने कर्त्तव्य का पालन उचित रूप से नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति कार्यमुक्त किये जाने के बदले एक काम से दूसरे काम पर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजे जाते रहते हैं। यह एक बहुत बड़ा अवरोध है जो नयी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ने देता।

इस प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि पिछड़े हुए कारखानों, कोलखोज़ों, सोवखोज़ों और ज़िलों में सुयोग्य और सक्षम अधिकारी रखे जायें, क्योंकि अग्रणी कारखानों, कोलखोज़ों और सोवखोज़ों के साथ साथ कुछ ऐसे भी कारखाने और फ़ार्म हैं जो लम्बे अरसे से बहुत पिछड़े रहे हैं और ज़रा भी प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण अधिकतर यही है कि उनके अधिकारियों को पर्याप्त अनुभव और योग्यता नहीं है, अर्थशास्त्र और उत्पादन का अच्छा ज्ञान नहीं है और इसलिए वे ठीक से नेतृत्व नहीं कर पाते। यदि अल्पावधि में ही हम इन पिछड़े कारखानों और फ़ार्मों को योग्य और अनुभवी अधिकारियों, संगठकों और विशेषज्ञों से संपन्न कर दें तो उद्योग और कृषि को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। इस समस्या को लगन और धैर्य के साथ सुलझाना है।

उन व्यक्तियों की ओर भी ध्यान देना है जिन्होंने लम्बे अरसे तक सक्रिय और लाभप्रद कार्य किये हैं, लेकिन अब अधिक उम्र या अन्य कारणों से अपने कार्यों में आवश्यक उत्साह और पहलक़दमी दिखाने में असमर्थ हैं। ये नेक साथी हैं और पार्टी के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा है, अतः वे पार्टी और जनता के सम्मान और आभार के अधिकारी हैं। उनके विस्तृत अनुभवों का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाना चाहिए जो उनकी शारीरिक योग्यता और अन्य योग्यताओं के अनुरूप हों। और यदि वे दूसरा काम करना या पेंशन पर अवकाशग्रहण करना चाहते हों

तो उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनके लिए अच्छी स्थितियां पैदा करें।

पिछले कुछ वर्षों में पार्टी-संगठनों ने वहुधा उत्तरदायी व्यक्तियों को स्थानीय स्तर पर स्थायी कार्य करने के लिए भेजा है। पार्टी की अपील पर ऐसे हज़ारों व्यक्तियों ने सोवखोज़ों और कोलखोज़ों के निर्देशक पद स्वीकार किये हैं और अल्पावधि में ही कृषि-उत्पादन बढ़ाने में अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। अनुभवी आर्थिक प्रबन्धकों को कारखानों और निर्माण-परियोजनाओं में भेजने के भी अच्छे परिणाम निकले हैं। अतः इस परिपाटी को जारी रखना है।

सामने उपस्थित कार्यों की दृष्टि से हमें उन कर्मचारियों के सुयोजित प्रशिक्षण की समस्या का भी विवेचन कर उसका उचित समाधान खोजना है, जिन्हें विभिन्न आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यों में लगाना है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात, जिसपर हमें ध्यान देना है, यह है कि देश के उन इलाक़ों के लिए सुदक्ष और सुयोग्य कर्मचारियों की व्यवस्था करनी है, जहां आगामी कुछ वर्षों में प्राकृतिक स्रोतों का विकास होनेवाला है और नये औद्योगिक केन्द्र बनाये जानेवाले हैं।

जिस तरह हज़ारों विशेषज्ञों और अनुभवी अधिकारियों ने उत्साह के साथ देश के पूर्वी हिस्सों में अछूती ज़मीन पर खेती-बारी करने के काम में हाथ बंटाया, उसी तरह इन समृद्ध क्षेत्रों में, जिनका अब विकास किया जा रहा है, काम करने के लिए उद्योग, विद्युत् इंजीनियरिंग, यातायात, निर्माण, कृषि, विज्ञान और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों में व्यापक आन्दोलन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हमें कई प्रमुख वैज्ञानिकों – अकादमीशियन मिख़ाइल अलेक्सेयेविच लावरेंत्येव, सेर्गेई अलेक्सेयेविच ख्रीस्तीआनोविच और सेर्गेई ल्वोविच सोबोलेव – के दृष्टान्तों की सराहना और स्वागत करना है जिन्होंने सोवियत पूर्व में नये वैज्ञानिक केन्द्रों का

संगठन करने का सुझाव दिया है और वहां स्थायी रूप से कार्य करना शुरू किया है।

कम्यूनिस्ट पार्टी अपने अधिकारियों और समस्त पार्टी-सदस्यों को यह शिक्षा देती है कि वे आलोचना और आत्म-आलोचना के ज़रिये, पार्टी के सिद्धान्तों में निष्ठा रखते हुए, कमज़ोरियों के सामने न झुकते हुए, जनता और कम्युनिज़्म के हित में अपनी निःस्वार्थ सेवाओं से प्रेरित होकर अपने कर्त्तव्यों का ठीक-ठीक पालन करें।

इस देश या अन्य समाजवादी देशों में समाजवाद और कम्यूनिज़्म की विजय के लिए संघर्ष में प्राप्त समस्त अनुभव लेनिनवादी सिद्धान्तों के इस प्रमुख सूत्र को प्रमाणित करते हैं कि कम्यूनिस्ट समाज के निर्माण के क्रम में पार्टी की भूमिका में कमी नहीं, जैसा कि आजकल के संशोधन-वादियों का मत है, बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धि ही होनी चाहिए।

सामाजिक संगठन का उच्चतम स्वरूप, जनता का विश्वसनीय हरावल दस्ता – कम्यूनिस्ट पार्टी – श्रमिक जनता के अन्य सारे सामाजिक संगठनों का नेतृत्व करती है।

साथियो, अब जबकि हमारा देश अपने विकास के एक नये और महत्त्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहा है, वह समय आ गया है कि हम सोवियत संघ के संविधान में कुछ नये संशोधन और परिवर्द्धन करें। संविधान बने बीस वर्ष गुज़र गये और ये वर्ष युगान्तरकारी और अति महत्त्वपूर्ण घटनाओं से भरे रहे हैं। समाजवाद एक देश में सीमित न रहकर एक सशक्त विश्वप्रणाली बन चुका है। सोवियत संघ के राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं। कम्यूनिस्ट समाज का निर्माण ही पार्टी और जनता का सर्वोपरि और व्यावहारिक लक्ष्य बन चुका है। देश के जीवन और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, उन्हें सोवियत संघ के संविधान – देश के मूलभूत क़ानून – में समाविष्ट करना ही होगा।

विकास की वर्त्तमान अवस्था में श्रमिक जनता के प्रतिनिधियों की सोवियतों को और भी महत्त्वपूर्ण रोल अदा करना होगा। वे राजकीय सत्ता के अंग हैं जिनका कार्य जनता के क्रिया-कलाप, समाजवादी लोकतंत्र के उत्तरोत्तर विकास, कामगार वर्ग और किसान वर्ग के बीच और भी दृढ़ एकता और सोवियत राष्ट्रों की और घनिष्ठ मैत्री पर आधारित है। सोवियतों के क्रिया-कलाप में सुधार लाने के लिए, जनता के साथ उनका संपर्क और सुदृढ़ करने के लिए, सोवियत लोकतंत्र का और प्रसार करने के लिए, लोगों को सोवियतों के व्यावहारिक कार्य में और संलग्न करने के लिए संघीय जनतंत्रों की सर्वोच्च सोवियतें यह आवश्यक समझती हैं कि मार्च के आगामी निर्वाचनों में स्थानीय सोवियतों की सदस्य-संख्या में लगभग ३,५०,००० की वृद्धि की जाय।

सोवियतें अधिक दक्षतापूर्वक काम कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि वे नौकरशाही के सारे तत्त्वों का समूल नाश करें और जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्त्ति की ओर और ध्यान दें।

सप्तवर्षीय योजना की सफल पूर्त्ति के लिए लोगों को क्रियाशील करने में ट्रेड-यूनियनों के कंधों पर भी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी आ जायेगी, जिनके सदस्यों की संख्या ५ करोड़ से अधिक है। सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की २०वीं कांग्रेस के बाद से पार्टी-संगठनों ने ट्रेड-यूनियनों का पहले से अच्छा नेतृत्व किया है और पहले से अधिक मदद भी की है। ट्रेड-यूनियनों के क्रिया-कलाप काफ़ी बढ़ गये हैं – वे उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं, श्रम-उत्पादिता-स्तर ऊंचा करने, श्रम और जीवन-यापन की आम स्थितियां सुधारने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं और अर्थ-व्यवस्था के प्रशासन में हिस्सा बंटाने के लिए जनसाधारण को सक्रिय कर रहे हैं।

पूंजीवाद से कम्यूनिज़्म की ओर संक्रान्ति-काल में ट्रेड-यूनियनों के कार्य की चर्चा करते हुए व्ला. इ. लेनिन ने कहा था कि ट्रेड-यूनियन "...एक शैक्षणिक संस्था है, एक ऐसा संगठन, जो जनसाधारण को संगठित

और प्रशिक्षित करता है, अर्थात् प्रशासन का, प्रबन्ध का और कम्यूनिज़्म का स्कूल है।" (ग्रन्थ-संग्रह, खंड ३२, पृष्ठ २)। अतः यह स्पष्ट है कि ट्रेड-यूनियन को 'कम्यूनिज़्म का स्कूल' कहकर लेनिन ने उसे कितना बड़ा महत्त्व दिया था।

लेनिन के शब्दों से प्रेरित होकर ट्रेड-यूनियनों को चाहिए कि वे कामगार वर्ग और समस्त श्रमिक जनता के क्रिया-कलाप को हर क्षेत्र में राजकीय योजनाओं की सफल पूर्त्ति की ओर और टेकनिकल प्रगति की ओर अग्रसारित और प्रोत्साहित करें। ट्रेड-यूनियनों को चाहिए कि वे समाजवादी होड़ को प्रोत्साहित करें, उत्पादन में वृद्धि करनेवालों, आविष्कार करनेवालों और अग्रणी कर्मियों को समर्थन और बढ़ावा दें तथा उनके तरीक़ों को लोकप्रिय बनायें।

ट्रेड-यूनियन के ज़िम्मे अब बड़े बड़े काम हैं, जैसे—कारखानों में श्रमरक्षा, आवास-गृह-निर्माण-योजना की पूर्त्ति, आवास-गृहों के उचित वितरण, खाद्य-आपूर्त्ति, चिकित्सा और सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्त्ति पर लोक-नियंत्रण का संगठन, इत्यादि। ट्रेड-यूनियनों को चाहिए कि वे शैक्षिक संस्थाओं के कार्य में सुधार करें, कम्यूनिस्ट चेतना का निरंतर विकास करें और जनता के सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठायें।

पार्टी-संगठनों का कर्त्तव्य है कि वे ट्रेड-यूनियनों को उनके विविध और महत्त्वपूर्ण कार्यों में हर संभव समर्थन और सहयोग दें। इसमें सन्देह नहीं कि सप्तवर्षीय योजना की सफल पूर्त्ति में ट्रेड-यूनियन बहुत महत्त्वपूर्ण योग देंगे (**तालियां**)।

साथियो, लेनिन कोम्सोमोल संगठन (तरुण कम्यूनिस्ट लीग), जिसमें १८० लाख युवक और युवतियां हैं, कम्यूनिज़्म के लिए संघर्ष में पार्टी का विश्वसनीय सहायक है। हमारे कोम्सोमोल संगठन ने २०वीं कांग्रेस के निर्णयों के अनुसार आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए युवक समुदाय को प्रेरित किया है।

हमारे युवक समुदाय ने अछूती ज़मीन में खेती-बारी करने, कृषि-उत्पादन की वृद्धि करने और उद्योग का विस्तार करने में बहुत बड़ा योग दिया है। आगामी कुछ वर्षों के अन्दर वृहत् निर्माण-परियोजनाओं के लिए १० लाख स्वयंसेवकों को भर्ती करने का जो बीड़ा कोम्सोमोल संगठन ने उठाया है, वह वस्तुतः प्रशंसनीय और समर्थनीय है। हमारे युवकों और युवतियों द्वारा पेश किये गये बहुत-से दृष्टान्त यह प्रमाणित करते हैं कि कम्यूनिस्ट चेतना का निरंतर विकास हो रहा है और देश के हित के लिए वे अपनी सारी शक्ति लगा देने को तैयार हैं। अपने गौरवपूर्ण कार्यों से कोम्सोमोल संगठन समस्त जनता की श्रद्धा और स्नेह प्राप्त कर चुका है **(देर तक तालियां)**।

हमारी पार्टी ने आगामी सात वर्षों के लिए कम्यूनिस्ट निर्माण का जो उत्साहवर्द्धक कार्यक्रम बनाया है, वह युवक समुदाय को अपनी रचनात्मक पहलक़दमी और सक्रियता दिखलाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

इस कांग्रेस के पूर्ववर्त्ती महीनों में कोम्सोमोल संगठन ने एक नया देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन – कम्यूनिस्ट श्रम-ब्रिगेडों के लिए आन्दोलन – चलाया है।

पार्टी को विश्वास है कि लेनिन कोम्सोमोल संगठन, हमारा सोवियत युवक समुदाय सप्तवर्षीय योजना की पूर्त्ति में अगली पांतों में दिखाई पड़ेगा।

समाजवाद के निर्माण में सोवियत जनों न श्रम-वीरता के चमत्कार दिखाये हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि सप्तवर्षीय योजना श्रम-उत्साह की एक नयी लहर दौड़ायेगी और समाजवादी होड़ के नये स्वरूप को जन्म देगी ताकि हमारे देश में कम्यूनिज़्म-निर्माण के कार्यक्रम नियत समय से पहले ही पूरे कर लिये जायें।

* * *

साथियो, हम लोग एक महत्त्वपूर्ण युग में रह रहे हैं। यह ऐसा समय है जबकि कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सोवियत जनता की लगन और रचनात्मक श्रम के जरिये मानव के सबसे प्रिय स्वप्न साकार किये जा रहे हैं। कई पीढ़ियों ने एक उज्ज्वल भविष्य का, एक ऐसे समाज का सपना देखा जिसमें अमीर और ग़रीब का फ़र्क़ न हो और जिसमें मेहनतकश जनता का शोषण न किया जाता हो। वह सपना था–कम्यूनिज़्म।

एक शताब्दी से अधिक हुआ कि कामगार वर्ग के महान नेताओं और शिक्षकों–मार्क्स और एंगेल्स–ने श्रमिक जनता को वैज्ञानिक कम्यूनिज़्म का क्रान्तिकारी सिद्धान्त रूपी अस्त्र दिया। अमर लेनिन ने इतिहास की नयी परिस्थितियों में उस सिद्धान्त को रचनात्मक रूप से विकसित और समृद्ध किया। उन्होंने हमारी कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसके नेतृत्व में हमारे देश के कामगार वर्ग और मेहनतकश जनता ने महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति को सफल बनाया, समाजवाद का निर्माण किया और वे अब सफलतापूर्वक कम्यूनिस्ट समाज का निर्माण कर रहे हैं।

हम सारे व्यवधानों और अवरोधों को पार करते हुए दृढ़ क़दमों से विश्वास के साथ लेनिन के मार्ग पर अग्रसर होते जा रहे हैं। जिस तरह सुदक्ष और अनुभवी पर्वतारोहियों का दल नये और दुर्गम शिखरों पर पहुंचने के लिए दूसरों के लिए पथ प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ता जाता है, उसी तरह हमारी पार्टी–सोवियत संघ के कामगार वर्ग और श्रमिक जनता का अग्रदल–हमारे देश की जनता को कम्यूनिज़्म के ज्योतिर्मय शिखरों की ओर ले जा रही है **(ज़ोर की तालियां)**।

यह सप्तवर्षीय अवधि, जिसमें हम अब प्रवेश कर चुके हैं, एक नयी और महत्त्वपूर्ण अवधि है। इसे इतिहास में हमारे पथ पर की निर्णयात्मक शिखर कहा जा सकता है। कम्यूनिस्ट पार्टी और हमारी

समस्त जनता को पूर्ण विश्वास है कि हम इस शिखर को लांघकर ही रहेंगे। और तब हम एक विस्तृत समतल भूमि पर पहुंच जायेंगे जहां से नये मार्ग खुलेंगे और जहां से निरंतर आगे बढ़ते जाना सुगम हो जायेगा। हमारे सामने जो लक्ष्य है, वह स्पष्ट और महान है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें ठीक से कार्य करना है, परिश्रम करना है। इससे हमें प्रतिष्ठा, संतोष और सुख की प्राप्ति होनेवाली है **(तालियां)**।

सोवियत जन समाजवादी शिविर के लोगों के साथ घनिष्ठ एकता बनाये हुए आगे बढ़ रहे हैं। समाजवाद और कम्यूनिज़्म की विजय-पताका के नीचे यूरोप और एशिया के समाजवादी देशों में लगभग १०० करोड़ जनता अर्थात् एक तिहाई मानव-जाति एकत्र है। समाजवाद अडिग और शक्तिशाली है और इसकी शक्ति दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। भविष्य की बागडोर इसके हाथ में है **(देर तक तालियां)**।

हम मार्क्सवादी-लेनिनवादी झंडे के नीचे विश्वास के साथ प्रगति करते जा रहे हैं और एक सर्वोत्तम, सर्वोचित समाज – कम्यूनिस्ट समाज – का निर्माण कर रहे हैं **(ज़ोर की तालियां)**।

कम्यूनिज़्म का निर्माण करनेवाली महान सोवियत जनता ज़िन्दाबाद! **(देर तक ज़ोर की तालियां)**।

सोवियत जनता की सबल और विश्वसनीय नेत्री, कम्यूनिस्ट विजयों की प्रेरक शक्ति – कम्यूनिस्ट पार्टी ज़िन्दाबाद! **(देर तक ज़ोर की तालियां)**।

सबल समाजवादी देशों की बिरादराना दोस्ती ज़िन्दाबाद! **(देर तक ज़ोर की तालियां)**।

सभी देशों की कम्यूनिस्ट और कामगार पार्टियों की मार्क्सवादी-लेनिनवादी एकता ज़िन्दाबाद! **(देर तक ज़ोर की तालियां)**।

विश्वशांति ज़िन्दाबाद! **(देर तक ज़ोर की तालियां, सभी सभासदों द्वारा खड़े होकर अभिनन्दन)**।

सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की २१ वीं कांग्रेस में ५ फ़रवरी १९५९ को साथी नि० से० ख़ुश्चेव का उपसंहार-भाषण

साथियो, हमारी कांग्रेस अपना काम समाप्त कर रही है। कांग्रेस की तैयारी के समय और स्वयं कांग्रेस में १९५९-१९६५ के लिए सोवियत संघ के आर्थिक विकास सम्बन्धी लक्ष्यांकों पर हुए विवाद से यह प्रकट हुआ कि हमारी समस्त पार्टी, सोवियत संघ की सारी जनता सर्वसम्मति से सप्तवर्षीय योजना का समर्थन करती है और उसे कार्यान्वित करने का बीड़ा उठा चुकी है **(जोर की तालियां)**।

कांग्रेस में कुल ८६ साथी बोले। सभी संघीय जनतन्त्रों, बहुत-से स्वायत्त जनतन्त्रों, क्षेत्रों और प्रदेशों के पार्टी-संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योग व कृषि के अग्रिम श्रेणी के हमारे शानदार कार्यकर्त्ता, विज्ञान, इंजीनियरिंग और संस्कृति के कार्यकर्त्ता इनमें थे।

सभी वक्ताओं ने कांग्रेस में विचारार्थ प्रस्तुत किये गये लक्ष्य के आंकड़ों का पूर्ण रूप से समर्थन किया। वे सप्तवर्षीय योजना को हमारे देश में कम्यूनिज़्म के निर्माण के वर्त्तमान दौर में पार्टी की लेनिनवादी आम-कार्यपद्धति की अभिव्यक्ति मानते हैं।

हमारी कांग्रेस की कार्यवाही से हमारी पार्टी की चट्टान जैसी दृढ़ता और एकता पर तथा पार्टी-संगठनों व सभी कम्यूनिस्टों की बड़ी गतिविधियों पर विशद प्रकाश पड़ता है। सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की २१ वीं कांग्रेस को हर दृष्टि से कम्यूनिज़्म के निर्माताओं की कांग्रेस कहा जा सकता है। यह विकास के एक नये ऐतिहासिक कालखण्ड में—कम्यूनिस्ट समाज के व्यापक निर्माण के कालखण्ड में—हमारे देश के पदार्पण का प्रतीक है **(तालियां)**। कांग्रेस ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारों की महती सृजन-शक्ति तथा कम्यूनिज़्मरूपी तेजोमय भवन का निर्माण करनेवाले जनसाधारण के व्यवहार के साथ इन विचारों के जीवन्त, अटूट सम्बन्ध निदर्शित कर दिये।

कांग्रेस में जो लोग बोले, उन्होंने बहुत-से ठोस और अत्यन्त मूल्यवान सुझाव पेश किये। इन सुझावों को कार्यरूप देने से हम योजना की सफल पूर्त्ति और अतिपूर्त्ति के लिए उद्योग व कृषि की क्षमता के अजस्र स्रोतों को अधिक पूर्णता से काम में ला सकते हैं।

कांग्रेस के प्रतिनिधियों के भाषण सुनते सुनते मुझे व्लादीमिर इल्यीच लेनिन के वे शब्द याद हो आये जो उन्होंने पहली आर्थिक योजना पर—रूस के बिजलीकरण की योजना पर—विचार करने के लिए आयोजित अखिल रूसी सोवियतों की कांग्रेस में कहे थे। लेनिन ने कहा था: "मैं समझता हूं कि हम एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मोड़ पर यहां एकत्र हुए हैं। यह ऐसा मोड़ है जो सोवियत सत्ता की महान सफलताओं के आरम्भ को हर तरह से प्रमाणित करता है। अब तो अखिल रूसी कांग्रेसों के मंच पर केवल राजनयिक और प्रशासक ही नहीं, बल्कि इंजीनियर और कृपिविज्ञ भी खड़े होंगे। यह एक सबसे सुखमय युग का आरम्भ है... आर्थिक विकास के दौर में सचमुच क़दम बढ़ाने के लिए यह परिपाटी सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस में शुरू की जानी चाहिए और ऊपर से नीचे तक सभी सोवियतों और संगठनों में, सभी

समाचारपत्रों में, प्रचार व आन्दोलन सम्बन्धी सभी कार्यालयों में, सभी संस्थाओं में यह परिपाटी लागू की जानी चाहिए... कांग्रेसों और कान्फ्रेंसों को कभी न खत्म होनेवाले बहस-मुबाहिसे की बैठकें न बनाइये, बल्कि उन्हें ऐसी सभाएं बनाइये जिनमें हम सही ढंग से अर्थ-व्यवस्था का विकास करना सीख सकें।" (ग्रन्थ-संग्रह, खंड ३१, पृष्ठ ४८१–४८२)

महान लेनिन ने जो सुझाया, हमारी पार्टी उसीपर अमल कर रही है। हमारी कांग्रेस का काम कामकाजी भावना से ओतप्रोत है, कम्यूनिस्ट निर्माण की आवश्यक समस्याओं के प्रति ठोस सृजनात्मक दृष्टिकोण उसमें पाया जाता है। और देखिये, कांग्रेस के काम पर इसका कैसा फलदायी प्रभाव पड़ा है, करोड़ों कामगारों, कोल्खोज किसानों और बुद्धिजीवियों के क्रिया-कलाप में, उनके समूचे व्यावहारिक प्रयास में वृद्धि को किस तरह उपयोगी ढंग से यह प्रोत्साहित कर रहा है!

आर्थिक विकास में हम विशद अनुभव संचित कर चुके हैं। देश की अर्थ-व्यवस्था के संचालन सम्बन्धी मूलभूत समस्याओं को हल करने पर हमारे पार्टी-संगठनों ने गम्भीर ध्यान दिया और काफी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सप्तवर्षीय योजना के बड़े भारी लक्ष्यों को पूरा करने में नीचे से लेकर ऊपर तक के हमारे सभी पार्टी-संगठनों को, सोवियत समाज के कामगारों की प्रत्येक संस्था को चाहिए कि हमारे सभी कार्यो के कामकाजी व ठोस स्वरूप और उद्देश्यपूर्णता के बारे में लेनिन की हिदायतों को पथप्रदर्शक मानें **(तालियां)।**

पार्टी, सरकारी, आर्थिक, ट्रेड-यूनियन व कोम्सोमोल कार्यकर्त्ताओं के, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों व कृषिविज्ञों के भाषण, उद्योग और कृषि के अग्रिम श्रेणी के कार्यकर्त्ताओं की मार्के की तक़रीरें हमने बड़े ध्यान से सुनीं। ये सब हमारे देश के सामने उपस्थित ठोस और महत्त्वपूर्ण कार्यो पर बोले।

दोनबास के विख्यात खनिक निकोलाई याकोव्लेविच मामाई, मास्को टायर-फ़ैक्टरी की फ़िटर अलेक्सानद्रा मिख़ाइलोव्ना रिबाकोवा, लेनिनग्राद 'अडमिरालटी' जहाज़-निर्माणशाला के जहाज़-निर्माता व्लादीमिर इवानोविच गोर्बूनोव, 'क्रास्नोये सोर्मोवो' कारख़ाने के इस्पात-निर्माता निकोलाई इवानोविच अनीश्चेन्कोव, मिन्स्क मोटर-कारख़ाने के कामगार द्मीत्री इवानोविच बराश्किन आदि आदि कांग्रेस के मंच से बोले। क्या ही दिलचस्प और उद्देश्यपूर्ण भाषण थे उनके! इन भाषणों में वक्ताओं की विषय सम्बन्धी गहरी जानकारी और अपने ही कारख़ाने या खान में नहीं, बल्कि देश भर में उत्पादन के विकास के प्रति आत्मीयतापूर्ण आस्था छलक पड़ती थी।

या फिर येव्गेनिया अलेक्सेयेव्ना दोलिन्यूक, अलेक्सान्द्र वसीलियेविच गितालोव, पेलागेया निकान्द्रोव्ना क़ोवाल्योवा, सेर्गेई कुज़्मीच बोइको, येव्गेनिया इवानोव्ना अन्द्रेयेवा, तेरेन्ती सेम्योनोविच माल्त्सेव और दूसरे साथियों जैसे कृषि के अग्रिम श्रेणी के शानदार कार्यकर्त्ताओं के भाषणों को लीजिए। वे अपने कोलख़ोज़ों के काम के बारे में बोले और असन्दिग्ध रूप से साबित कर दिया कि कुशल प्रबन्ध से क्या क्या सफलताएं पायी जा सकती हैं और हमारे कोलख़ोज़ों-सोवख़ोज़ों में कैसी बड़ी क्षमताएं भरी पड़ी हैं।

अकादमीशियन ईगोर वसीलियेविच कुर्चातोव, अकादमीशियन मिख़ाईल अलेक्सेयेविच लाव्रेन्त्येव, सोवियत संघ की विज्ञान-अकादमी के अध्यक्ष अलेक्सान्द्र निकोलायेविच नेस्मेयानोव, कज़ाख जनतन्त्र की विज्ञान-अकादमी के अध्यक्ष कानीश इमन्तायेविच सत्पायेव जैसे हमारे प्रमुख वैज्ञानिकों, सुप्रसिद्ध कवि अलेक्सान्द्र त्रीफ़ोनोविच त्वार्दोव्स्की और हमारे गरिमामय सृजनात्मक बुद्धिजीवियों के दूसरे प्रतिनिधियों ने इस ऊंचे मंच से जो भाषण दिये उन्हें हमने सुना।

यह महत्त्व की बात है कि अपने भाषणों में सप्तवर्षीय योजना की

समस्याओं की चर्चा करते समय पार्टी व सरकार के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं ने औद्योगिक व कृषि उत्पादन की गहरी जानकारी का परिचय दिया और जनसाधारण के समृद्ध अनुभव के आधार पर आवश्यक कार्यों को निपटाने में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया।

उद्योग व कृषि के अग्रिम श्रेणी के कार्यकर्त्ताओं, बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधियों, पार्टी व सरकारी कार्यकर्त्ताओं–कांग्रेस में बोलनेवाले सभी साथियों–ने असन्दिग्ध रूप से साबित किया कि सप्तवर्षीय योजना के लक्ष्य पूरे तो होंगे ही, बल्कि उनसे आगे भी पहुंचा जा सकता है **(देर तक तालियां)।**

जीवन के घनिष्ठ सम्पर्क में रहनेवाले, जनसाधारण के बीच काम करनेवाले लोगों के सशक्त एवं विश्वास से भरे स्वर कांग्रेस के मंच पर से गूंज उठे तो सुनकर चित्त आह्लाद और प्रसन्नता से फूल उठा। ये उन लोगों के स्वर थे जो करोड़ों जनों के उद्गारों, विचारों व भावनाओं को जानते और मुखरित करते हैं। ये भाषण सोवियत जनों के उमगते उछाह को व्यक्त करते हैं–उन जनों के, जो सप्तवर्षीय योजना के बड़े भारी लक्ष्य पूरे करने में जुट पड़े हैं। इतना ही नहीं, इन सबसे यह प्रकट होता है कि हमारे अधिकारी कितने ऊंचे स्तर पर पहुंचे हैं, सोवियत जन किस विशाल परिमाण पर सोचते हैं और वे अपने प्रत्यक्ष कार्य को ही नहीं बल्कि देश के जीवन को कितनी अच्छी तरह जानते हैं।

जैसे मैं कह चुका हूं, आगामी सात वर्षों में सोवियत संघ के आर्थिक विकास के लक्ष्यांकों सम्बन्धी रिपोर्ट पर विवाद के दौरान में कितने ही अत्यन्त मूल्यवान सुझाव पेश किये गये। कांग्रेस में दिये गये भाषणों में जो कामनाएं व्यक्त की गयीं और जो सुझाव प्रस्तुत किये गये, पार्टी की केन्द्रीय समिति और सोवियत संघ की मन्त्रि-परिषद उनपर ध्यान देंगी। साथ ही, लक्ष्य के आंकड़ों पर विवाद के समय

जनता की ओर से बड़ी संख्या में जो ठोस सुझाव रखे गये, उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का और उन्हें कार्यरूप देने के लिए व्यावहारिक क़दम उठाने का काम राज्य संयोजन समिति तथा जनतन्त्रीय व दूसरी स्थानीय संस्थाओं को सौंपना आवश्यक है।

कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधियों ने अपने भाषणों में शराबख़ोरी की निन्दा की और इस ऐब के विरुद्ध संघर्ष तीव्र करने का और नाजायज़ ढंग से स्पिरिट बनाने के विरुद्ध क़दम उठाने का सुझाव दिया। नाजायज़ ढंग से स्पिरिट बनानेवाले लोग चीनी, अनाज व अन्य पदार्थ ज़ाया करते और नफ़ाख़ोरी करते तो हैं ही, साथ ही वे कमज़ोर दिलवाले लोगों को शराबख़ोर बनाते हैं, उनके शरीरों में ज़हर मिलाते हैं, क्योंकि नाजायज़ तरीक़े से बनी स्पिरिटों में बड़ी मात्रा में फ्यूज़ल आइल होता है।

शराबख़ोरी के और नाजायज़ ढंग से स्पिरिट बनाने के ख़िलाफ़ संघर्ष तीव्र करने के सुझावों को मैं सही मानता हूं। कांग्रेस ने ऐसे सुझाव देनेवाले साथियों का समर्थन किया है **(तालियां)।**

अगर संघीय जनतन्त्रों की कम्यूनिस्ट पार्टियों की केन्द्रीय समितियां और मन्त्रि-परिषदें इस प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देतीं और मादक पेयों के दुरुपयोग के विरुद्ध तथा नाजायज़ ढंग से स्पिरिट बनानेवाले उन 'कीमियागरों' के ख़िलाफ़, जो जनता के स्वास्थ्य को गम्भीर हानि पहुंचाते हैं और समाज को बिगाड़ते हूं, ठोस क़दम सुझातीं तो अच्छा होता **(हॉल में सजीवता)।**

मैं समझता हूं कि जनतन्त्रों में इस सम्बन्ध में विधेयक तैयार किये जाने चाहिए और जनता के विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किये जाने चाहिए। इन विधेयकों पर चर्चा हो चुकने के बाद ऐसे क़ानून पास होने चाहिए जिनमें मादक पेयों का दुरुपयोग करनेवालों और सामाजिक नियमों को भंग करनेवालों के विरुद्ध और खासकर नाजायज़ ढंग से स्पिरिट

बनानेवालों के विरुद्ध सख़्त क़दम उठाने की व्यवस्था है। हमें विश्वास है कि प्रत्येक जनतन्त्र के लोग शराबख़ोरी और नाजायज़ ढंग से स्पिरिट बनाने के विरुद्ध संघर्ष तीव्र करने के उपायों का समर्थन करेंगे। **(तालियां)**।

साथियो, इन दिनों सारे देश का ध्यान कांग्रेस के काम पर केन्द्रित है। स्थान स्थान पर कारख़ानों व निर्माणस्थलों में, कोलख़ोज़ों व सोवख़ोज़ों में और वैज्ञानिक संस्थाओं में सभाएं व बैठकें हुईं जिनमें कांग्रेस की गतिविधि पर विस्तृत चर्चाएं की गयीं। २१ वीं कांग्रेस के नाम हज़ारों चिट्ठियां व तार मिले हैं जिनमें केवल अभिनन्दन-सन्देश ही नहीं, बल्कि २१ वीं कांग्रेस के उपलक्ष्य में ठोस कार्य किये जाने की ख़बरें भी दी गयी हैं। 'प्राव्दा' ने उन श्रमिक समूहों की सूची प्रकाशित की है जिन्होंने पार्टी की २१ वीं कांग्रेस को अभिनन्दन-सन्देश भेजे हैं और सप्तवर्षीय योजना के लक्ष्य नियत समय से पहले पूरे करने की प्रतिज्ञा की है।

जिन समूहों और साथियों ने २१ वीं पार्टी-कांग्रेस के नाम अभिनन्दन-सन्देश भेजे हैं, कांग्रेस की ओर से उनके प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शित करने और हमारे देश के हितार्थ उनके काम में और सफलताओं की कामना करने की मुझे इजाज़त दीजिये **(ज़ोर की तालियां)**।

हमें विश्वास है कि सप्तवर्षीय योजना की पूर्त्ति और अतिपूर्त्ति के लिए देशव्यापी समाजवादी अनुकरण का जो आन्दोलन शुरू हुआ है वह और भी व्यापक परिमाण में फैलेगा और श्रम की नयी असाधारण विजयों से शोभित होगा।

ज़रा देखिये तो, सूरज का उजाला फिरेक बार खिल उठा। यह उजाला तो शुरू से आख़िरी दिन तक हमारी कांग्रेस के साथ ही रहा है **(ज़ोर की तालियां)**।

साथियो, विदेशों की ७२ कम्यूनिस्ट व कामगार पार्टियों के प्रतिनिधिमण्डल हमारी कांग्रेस में उपस्थित हैं। जिन भ्रातृ-पार्टियों के

प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का अभिनन्दन न कर सके, उन्होंने मैत्रीपूर्ण सन्देश भेजे हैं।

मार्क्सवादी-लेनिनवादी भ्रातृ-पार्टियों के अभिनन्दन-सन्देशों व स्वागत-भाषणों में उनके देशों के कम्यूनिस्टों, श्रमिक वर्ग और करोड़ों मेहनतकश लोगों की ओर से हमारी पार्टी, सोवियत संघ की सभी जनताओं के प्रति हार्दिक मैत्री और एकता के उद्गार व्यक्त हुए। हमारी पार्टी के प्रति, हमारे देश के प्रति समाजवादी देशों की जनताओं, संसार भर के आम श्रमिक जनों और शान्ति, लोकतन्त्र एवं प्रगति के संघर्षकारियों का बड़ा भरोसा और हार्दिक स्नेह इन सन्देशों में हृदयस्पर्शी शब्दों में मुखरित हुए **(तालियां)**।

चीन, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनवादी जनतन्त्र, बल्गारिया, रूमानिया, हंगरी, कोरियाई जनवादी जनतन्त्र, वियतनाम के जनवादी जनतन्त्र, अल्बानिया और मंगोलियाई जनता के जनतन्त्र की भ्रातृ-पार्टियों के प्रतिनिधिमण्डलों ने हमें यह ख़ुशख़बरी सुनायी कि कम्यूनिस्ट व कामगार पार्टियों के नेतृत्व में समाजवादी निर्माण में उनके देशों की जनताओं ने कैसी उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं **(तालियां)**।

पूंजीवादी देशों से आये हुए भ्रातृ-पार्टियों के साथियों ने हमें बताया कि श्रमिक वर्ग के हित में, शान्ति और जनताओं की सुरक्षा की ख़ातिर, सभी लोगों की सुख-सुविधा के लिए इन देशों के कम्यूनिस्ट कैसा वीरतापूर्ण संघर्ष कर रहे हैं **(तालियां)**।

पार्टी-कांग्रेसों के अवसरों पर एक दूसरे के यहां प्रतिनिधिमण्डल भेजने की परम्परा कम्यूनिस्ट पार्टियों में चल पड़ी है। इससे भ्रातृ-पार्टियों के दृढ़ ऐक्य, आपसी सहायता तथा सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना बढ़िया ढंग से व्यक्त होती है। हम यह परम्परा जारी रखेंगे **(तालियां)**।

भ्रातृ-पार्टियों से प्राप्त अभिनन्दन-सन्देश तथा हमारी कांग्रेस के प्रतिनिधियों और मास्को की मेहनतकश जनता से इन पार्टियों के प्रतिनिधियों की मुलाक़ातें मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों के सिलसिले में अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन की एकता, बल और दृढ़ता की द्योतक थीं **(देर तक तालियां)।**

सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी और जनता की हर प्रकार की सफलता की कामना करते हुए भ्रातृ-पार्टियों ने हमारा जो अभिनन्दन किया, उसके लिए हमारी पार्टी-कांग्रेस एवं सोवियत जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करने की अनुमति दीजिए **(देर तक ज़ोर की तालियां। सब खड़े हो जाते हैं)।**

अपनी तरफ़ से हम यह हार्दिक कामना करते हैं कि शान्ति और समाजवाद की ख़ातिर संघर्ष में सभी भ्रातृ-कम्यूनिस्ट व कामगार पार्टियों को सफलता मिले **(तालियां)।**

विदेशों के जिन सार्वजनिक संगठनों, ट्रेड-यूनियनों और श्रमिक जनता ने हमारी पार्टी-कांग्रेस के नाम अभिनन्दन-सन्देश भेजा, उनके भी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की मुझे आज्ञा दीजिये **(तालियां)।**

प्यारे मेहमानो, भ्रातृ-कम्यूनिस्ट व कामगार पार्टियों के प्रतिनिधियो! आप लोग संसार के कोने-कोने से आकर हमारी कांग्रेस में उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी पार्टियों के सदस्यों और अपने देशों के श्रमिक जनों को सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की २१ वीं कांग्रेस का यह आश्वासन पहुंचायें कि सोवियत संघ के कम्यूनिस्ट और सभी जनताएं साथीपन, मैत्री और दृढ़ एकता की उन भावनाओं का बड़ा मान करती हैं जो आपने हमारी कांग्रेस का अभिनन्दन करते हुए व्यक्त की थीं **(ज़ोर की तालियां)।**

संसार भर के श्रमिक जनों और जनवादी शक्तियों के साथ मैत्री और सर्वहारा दृढ़ एकता के सम्बन्ध बराबर सुदृढ़ करना, शक्तिशाली

समाजवादी शिविर की ताक़त बढ़ाना और राष्ट्रों में शान्ति की ख़ातिर अथक प्रयास करना हमारी पार्टी और सोवियत जनता अपना अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य समझती हैं **(देर तक तालियां)।**

कम्यूनिस्ट पार्टी और सोवियत जनता नयी सप्तवर्षीय योजना की सफल पूर्त्ति और अतिपूर्त्ति को अपना प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य मानती हैं।

आप विश्वास करें, प्यारे साथियो, कि सोवियत संघ के सभी कम्यूनिस्ट और सभी श्रमिक जन इस ऐतिहासिक कर्त्तव्य को सम्मानपूर्वक पूरा करने में अपनी सारी ताक़त लगाने में आनाकानी नहीं करेंगे! **(ज़ोर की तालियां)।**

साथियो, २१ वीं कांग्रेस शान्तिपूर्ण निर्माण की शानदार योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस की कार्यवाही कम्यूनिस्ट निर्माण-योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा शान्ति और भिन्न भिन्न सामाजिक प्रणालियोंवाले देशों का शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व क़ायम रखने के लिए वशभर प्रयास करने के पार्टी और समूची सोवियत जनता के संकल्प को प्रतिबिम्बित करती है। हमारी कांग्रेस का प्रधान विशेषांश वही है। शीत युद्ध के पक्षपोषक भी—यदि निष्पक्षता से घटनाओं का मूल्यांकन करें तो—पायेंगे कि हमारी कांग्रेस जो योजना स्वीकार कर रही है उसका उद्देश्य शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित करना और संसार भर में शान्ति को सुदृढ़ करना है **(ज़ोर की तालियां)।**

साथी प्रतिनिधियो, आपको एक ख़ुशख़बरी सुनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है: भारत सरकार द्वारा सोवियत सरकार की सहायता से बनाये जा रहे भिलई लोहा व इस्पात कारख़ाने के निर्माण में काम करनेवाले सोवियत इंजीनियरों ने एक बड़ी औद्योगिक जीत की सूचना दी है। उन्होंने बताया है कि उक्त कारख़ाने में १ फ़रवरी को पहले-पहल कोक तैयार हुआ और ३ फ़रवरी को पहले-पहल कच्चा लोहा बनाया गया **(ज़ोर**

की तालियां)। लोहे व इस्पात का यह बड़ा कारख़ाना सोवियत डिज़ाइनों के अनुरूप हमारे विशेपज्ञों की देखरेख में बन रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि सोवियत संघ की सहायता से बन रहे इन कारख़ाने के अलावा भारत में दो और कारख़ाने निर्मित हो रहे हैं—एक ब्रिटेन की मदद से और दूसरा पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। भिलईवाले कारख़ाने का निर्माण ब्रिटिश व पश्चिमी जर्मन फ़र्मों की सहायता से बननेवाले कारख़ानों के साल डेढ़ साल बाद शुरू हुआ। फिर भी हमारे साथियों ने भारतीय विशेपज्ञों और कामगारों के साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से मिलकर काम करके काफ़ी कठिनाइयों पर क़ाबू पा लिया और अंग्रेज़ों और जर्मनों से काफ़ी पहले एक भारी आधुनिक लोहा व इस्पात कारख़ाने का पहला हिस्सा बनाकर तैयार करने तथा कोक और कच्चा लोहा बनाने में सफल हो गये **(तालियां)**।

इस कारख़ाने में पहले-पहल तैयार हुआ कच्चा लोहा सोवियत संघ और भारत की जनताओं के बीच उत्तरोत्तर सुदृढ़ होती हुई मैत्री का प्रतीक बने! **(ज़ोर की तालियां)**।

सोवियत-भारत मैत्री के और पनपने में, शान्ति के लिए, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों की विजय के लिए हमारे संयुक्त संघर्ष में रोड़ा अटकाने की कोशिश करनेवाले साम्राज्यवादियों की साज़िशें इस पिघलाऊ भट्ठी की आग में जलें! **(देर तक तालियां)**।

इस पिघलाऊ भट्ठी की उष्णता हमारी दोनों महान और शान्तिप्रेमी जनताओं की मैत्री को सुखद बनाये **(ज़ोर की तालियां)**।

हमारी मैत्री उतनी ही मज़बूत हो, जितनी कि इस कारख़ाने में पिघालकर तैयार की जानेवाली धातु—इस कारख़ाने में, जो सोवियत संघ और भारत की सरकारों और जनताओं के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप निर्मित हुआ है **(ज़ोर की तालियां)**।

यह महान औद्योगिक विजय भारत के उद्योगीकरण तथा उसकी

आर्थिक स्वतन्त्रता को सबल बनाने के काम में बड़े भारी महत्त्व की है। इस अवसर पर हम भारत की जनता और भारत सरकार को, जिसके अगुआ प्रधानमन्त्री श्री नेहरू हैं, बधाइयां देते हैं **(देर तक तालियां)**।

हमें यह जानकर प्रसन्नता होती है कि उक्त लोहा व इस्पात कारख़ाने के पहले हिस्से के चालू होने के अवसर पर भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद उपस्थित थे और उन्होंने सोवियत-भारत मैत्री सुदृढ़ बनने की हार्दिक कामना व्यक्त की **(देर तक तालियां)**।

हम हृदय की तह से उन सोवियत विशेषज्ञों और कामगारों को बधाइयां देते हैं जिन्होंने भारतीय विशेषज्ञों और कामगारों से मिलकर ऐसी असाधारण सफलताएं प्राप्त कीं और भारत व सोवियत संघ की जनताओं की भ्रातृत्वपूर्ण मैत्री बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योग दिया **(देर तक तालियां)**।

हम इस औद्योगिक विजय को लेनिनवादी सही शान्ति-नीति का ज्वलन्त प्रमाण मानते हैं। हम इसे अपनी आज़ादी और स्वतन्त्रता को सुदृढ़ बनाना चाहनेवाली जनताओं के साथ सोवियत संघ के निःस्वार्थ आर्थिक सहयोग का एक उदाहरण मानते हैं **(ज़ोर की तालियां)**।

सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की २१ वीं कांग्रेस के कार्य की सभी देशों में बड़ी ही दिलचस्पी के साथ चर्चा हो रही है। कहना होगा कि बहुत-से पूंजीवादी देशों की अधिकांश पत्र-पत्रिकाएं कांग्रेस की कार्यवाही के संवाद निष्पक्ष रूप से छाप रही हैं। यह अनुकूल बात है, क्योंकि पत्रों में निष्पक्ष संवादों के छपने से तनाव बढ़ता नहीं, बल्कि घटता है और महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मसलों को शान्ति के हक़ में शीघ्रता से निपटाने के लिए आवश्यक परिस्थिति बनती है।

हमें यह देखकर सन्तोष होता है कि हमारी योजना की शान्तिपूर्ण अभिलाषाओं को अधिकांश देशों में ठीक से समझा गया है। हम घोषणा

कर चुके हैं कि हम लेनिनवादी शान्तिपूर्ण विदेशी नीति का अविचलित रूप से अनुसरण करेंगे जिसका उद्देश्य शान्ति और जनताओं की सुरक्षा क़ायम रखना और सुदृढ़ बनाना है।

लेकिन पश्चिम में अब भी ऐसे कुछ नेता हैं जो हमारी शान्ति-नीति का विकृत चित्र प्रस्तुत करते हैं और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों का विरोध करते हैं।

इस सिलसिले में मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं वर्त्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों की चर्चा करूं और हमारा यह अडिग विश्वास व्यक्त करूं कि शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों का दृढ़ता से पालन होना चाहिए।

शान्ति का, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रश्न प्रमुखतम प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक देश के लोग, चाहे उसकी सामाजिक प्रणाली कुछ भी हो, सुख से जीना चाहते हैं, शान्ति से काम करना और जीवन की उत्कृष्टतर स्थितियां पैदा करना चाहते हैं।

हमारा दृष्टिकोण यह है कि लोगों को शान्ति से रहना चाहिए, चाहे उनके देशों की सामाजिक प्रणाली कैसी भी हो, और राज्यों के बीच उठनेवाले मसलों का निपटारा शान्ति से होना चाहिए, न कि युद्ध से।

अब तो दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। वे देश हैं, जो विश्व समाजवादी प्रणाली के अंग हैं, और वे देश, जो विश्व साम्राज्यवादी प्रणाली के अंग हैं। लेकिन साथ ही ऐसे भी देश हैं जो समाजवादी तो नहीं हैं, फिर भी उन्हें साम्राज्यवादी प्रणाली के भी नहीं माना जा सकता। आज़ादी के संघर्ष के फलस्वरूप इन देशों ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त की है। अब वे विकास के पूंजीवादी दौर से किनारा करते हुए अपने अलग रास्ते पर चलना चाहते हैं ताकि औपनिवेशिक दमन से पिंड छुड़ाने के बाद वे उससे भिन्न सिद्धान्तों के आधार पर समाज का निर्माण शुरू कर सकें।

इन देशों के बहुत-से नेता कहते हैं कि वे समाजवाद का निर्माण करना चाहते हैं। यह बात सच है कि 'कम्यूनिज़्म' शब्द का उच्चारण करने में उन्हें दिक़्क़त होती है और यह भी हमेशा साफ़ समझ में नहीं आता कि समाजवाद से आख़िर उनका मतलब क्या है। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि समाजवादी देशों के साथ उनका रवैया अच्छा है, वे उन्हें शत्रु नहीं समझते और न यह समझते हैं कि समाजवादी देश साम्राज्यवाद से रहित, औपनिवेशिक दमन से मुक्त नया जीवन निर्मित करने के उनके प्रयत्न के विरोधी हैं। इस कारण समाजवादी देशों और इन देशों के बीच अच्छे, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुए हैं और साधारण आर्थिक सम्बन्ध उनमें बढ़ रहे हैं। शान्ति और जनताओं की सुरक्षा की ख़ातिर, अणु व उद्‌जन-शस्त्रों के निषेध की ख़ातिर, साम्राज्यवादियों की उपनिवेशवादी नीति के विरुद्ध संघर्ष में हम साथ साथ मोर्चा ले रहे हैं।

अगर हम विश्व समाजवादी प्रणाली के देशों को और साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विरुद्ध साहसपूर्ण संघर्ष करनेवाले देशों को मिलाकर देखें तो पायेंगे कि इन शान्तिप्रिय देशों का ही पलड़ा भारी है, न कि साम्राज्यवादी देशों का। प्रदेश के विस्तार में, जनसंख्या में और प्राकृतिक सम्पत्ति में इन शान्तिप्रिय देशों के आगे साम्राज्यवादी देश कहीं नहीं टिकते।

संसार में शक्तियों के वर्तमान गठजोड़ का विवेचन करने से निकलनेवाले प्रमुख निष्कर्षों में एक यह है कि अधिकांश औपनिवेशिक और अर्द्ध-औपनिवेशिक देश, जो हाल तक साम्राज्यवाद के लिए रसद और कुमक पहुंचाने के अड्डे होते थे, अब ऐसे न रहे। लम्बे अरसे के संघर्ष के परिणामस्वरूप ये देश शान्ति की सक्रिय शक्तियां बन गये हैं। वे अब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध, आज़ादी व राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की ख़ातिर जूझ रहे हैं और भिन्न भिन्न

सामाजिक प्रणालियोंवाले राज्यों के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का समर्थन कर रहे हैं।

साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पूंजीवादी देशों के श्रमिक जन—श्रमिक वर्ग, मेहनतकश किसानों और बुद्धिजीवियों का अधिकांश हिस्सा—शान्ति बनाये रखने और अपना जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर प्रयास कर रहे हैं। वे समाजवादी देशों की शान्तिपूर्ण नीति का समर्थन करते है। पूंजीवादी देशों में कम्यूनिस्ट पार्टियों के अलावा समाजवादी और कामगार पार्टियां हैं जो कामगारों और किसानों के एक हिस्से की अगुआई कर रही हैं। यद्यपि इन पार्टियों के राजनीतिक और विचारधारात्मक दृष्टिकोण मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों के दृष्टिकोणों से भिन्न होते हैं, तो भी उनके अधिकांश सदस्य शान्ति का समर्थन करते हैं। इन प्रश्नों में हमारे प्रयास सम्मिलित भी हो सकते हैं। फलतः पूंजीवादी देशों में साम्राज्यवादियों को आम श्रमिक जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, क्योंकि श्रमिक जनता का तो आधारभूत हित शान्ति क़ायम रखने और सुदृढ़ करने में है।

सोवियत संघ लगातार शान्तिपूर्ण विदेशी नीति का अडिग रूप से अनुसरण करता आया है और आगे भी करता रहेगा। संसार भर में शान्ति क़ायम रखने की समस्या हमारे समय की सबसे प्रमुख समस्या है। इस समस्या के हल पर सप्तवर्षीय योजना की पूर्ति का भारी प्रभाव पड़ेगा।

उत्पादक शक्तियों और देश की आर्थिक क्षमता के विकास तथा जनता की भौतिक एवं सांस्कृतिक सुख-सुविधा की वृद्धि जैसे शान्तिपूर्ण क्षेत्रों में हम पूंजीवादी देशों से प्रतियोगिता करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता के दौरान में प्रत्येक प्रणाली अपनी आर्थिक और आत्मिक शक्तियों का प्रदर्शन करे। अगर कारोबारी ज़बान

में कहा जाय, जो, ज़ाहिर है, पूंजीवादी संसार के प्रतिनिधियों के लिए अधिक सुबोध होगी, तो हम अपने अपने 'माल' खोलकर रखें–समाजवादी संसार अपने और पूंजीवादी संसार अपने। फिर प्रत्येक प्रणाली यह दिखाए कि कहां का कार्य-दिवस कितना लम्बा है, श्रमिक जन को कितने भौतिक और आत्मिक लाभ मिलते हैं, उसकी रिहाइश का क्या इन्तज़ाम है, उसके शिक्षा पाने की कितनी सम्भावना है, राजकाज में, देश के राजनीतिक जीवन में वह क्या हिस्सा लेता है और सब प्रकार की भौतिक एवं सांस्कृतिक सम्पत्तियों का स्वामी कौन है–वह, जो मेहनत करता है, या वह, जो मेहनत नहीं करता, लेकिन जिसके पास पूंजी है।

हम समझते हैं कि जो सामाजिक प्रणाली जनता को अधिक भौतिक सम्पत्ति प्रदान करती हो, जिस प्रणाली में जनता को आत्मिक विकास के असीमित अवसर प्राप्त होते हों, वही प्रणाली प्रगतिशील है, वही भविष्य की प्रणाली है **(देर तक तालियां)**।

अच्छा, तो इसका निर्णायक कौन होगा? कौन फ़ैसला करेगा कि अमुक सामाजिक प्रणाली श्रेष्ठतर और अधिक प्रगतिशील है? स्वभावतः हमें यह तो मान्य नहीं होगा कि पूंजीवादी दुनिया के विचारधारा-प्रचारक इसके निर्णायक हों। और हम यह भी आशा नहीं करते कि बूर्जुआ विचारधारा-प्रचारकों को हमारा निर्णायक बनना मान्य होगा। यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि इस मामले में दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जायेंगे। लेकिन आखिर निर्णायक होगा कौन? निर्णायक होंगे जनसाधारण। वे ही सदा यह निर्णय करते हैं कि कौनसी प्रणाली श्रेष्ठतर है। हमें विश्वास है कि जनसाधारण सही चुनाव करेंगे, और वे अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध छेड़े बिना, उद्जन और अणु-बमों के बिना, यह चुनाव करेंगे **(ज़ोर की तालियां)**।

पूंजीवादी दुनिया में तो होड़ाहोड़ी का बोलबाला होता है। जब दो व्यापारियों में एक गाहक को लेकर होड़ चलती है और गाहक आख़िर उसका माल लेने पर राज़ी हो जाता है जो बेहतर माल सस्ते दामों बेचने को तैयार हो, तो दूसरा व्यापारी मर तो नहीं जाता, उसकी जान तो नहीं ली जाती, उसका शारीरिक विनाश तो नहीं किया जाता।

पूंजीवादी देशों से हम कहते हैं: आइये, हम इस तरीक़े पर अमल करें, इसे तो आप समझते हैं **(हॉल में सजीवता)**। दोनों प्रणालियोंवाले देशों के बीच के सम्बन्ध को शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता कहना आपको मंज़ूर नहीं। आप तो उसे प्रतिद्वन्द्विता कहना ज्यादा पसन्द करते हैं। तो ठीक है, चलिये, हमने आपकी यह बात मान ली। लेकिन चाहे हम इसे 'प्रतियोगिता कहें, चाहे प्रतिद्वन्द्विता, दोनों सूरतों में हमारा सुझाव यह है कि इसका निपटारा हो तोपों की दनदनाहट के बिना, नाभिकीय शस्त्रों के प्रयोग के बिना, जनता का सर्वनाश करनेवाले रासायनिक, रोगाणविक और दूसरे साधनों का इस्तेमाल किये बिना, युद्ध के बिना, मानव-समाज की चिरसंचित निधियों को मिट्टी में मिलाये बिना **(देर तक तालियां)**।

हम जनता को कोई ऐसी सामाजिक प्रणाली चुनने का मौक़ा दें जो उसके हितों के अनुकूल हो। बूर्जुआ नेता अक्सर पूंजीवादी प्रणाली की तारीफ़ के पुल बांधते हैं। लेकिन समाजवादी देशों से शान्तिपूर्ण आर्थिक प्रतियोगिता के लिए वे तैयार नहीं होते। वे जनता को अपनी पसन्द की सामाजिक प्रणाली चुनने का मौक़ा ही नही देना चाहते। इससे साबित होता है कि वे अपने ही देश की जनता पर विश्वास नहीं करते, जनता से डरते हैं, अपनी ही जनता का उन्हें भरोसा नहीं।

संयुक्त राज्य अमेरिका की कारोबारी दुनिया के कुछ प्रतिनिधियों ने यह इच्छा प्रकट की है कि हमें अपने भाषणों में 'संघर्ष' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो सिर्फ़ 'प्रतियोगिता' या

'प्रतिद्वन्द्विता' शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। सम्बन्ध बिगड़ने न देने की ग़रज़ से हम 'प्रतियोगिता' या 'प्रतिद्वन्द्विता' तक कहना मान लेते हैं। इस तरह हम छूट देने को और ऐसे शब्द इस्तेमाल करने को तैयार हैं हमारे प्रतिपक्षियों के कान जिनके आदी हैं।

लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि बात महज़ लफ़्ज़ों की नहीं, शब्दावली की नहीं। मिसाल के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर, उपराष्ट्रपति निक्सन, विदेश-सचिव डलेस, सेनेटर हम्फ़्री आदि के नवीनतम भाषण लीजिये। इन तक़रीरों में वे चौकसी की अपील करते हैं और शक का इशारा करते हैं। ऐसा भान होता है कि वे जंगख़ोरी की अपनी पुरानी शब्दावली की ओर रुजू हो रहे हैं, ऐसे वक्तव्यों की ओर, जैसा कि २७ जनवरीवाले अपने पत्रकार-सम्मेलन में श्री डलेस ने देना उचित समझा। उन्होंने बिना किसी कारण के यह बताया कि सोवियत संघ शीत युद्ध जारी रखने का इरादा रखता मालूम पड़ता है; सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साधारण व्यापार बढ़ाने का सुझाव रखते समय सोवियत संघ सचमुच पूंजीवादी देशों के विरुद्ध शीत युद्ध में अपने और 'विश्व कम्यूनिज़्म' के शस्त्रों पर सान धरने की सोच रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अ० इ० मिकोयान का अच्छा स्वागत होने के कारण हाल में हमारे दोनों देशों के सम्बन्धों में जो सुधार होने लगा था, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ लोग इस तरह उसे मिटाना चाहते हैं। वे तो शीत युद्ध की बुझती आग को भड़काना और हमारे देशों के बीच तनावपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं।

और फिर, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख जनरलों की तो बातें सुनते ही बनती हैं! लगता है वे श्रम-विभाजन के सिद्धान्त पर अमल कर रहे हैं और बम्वारों, उद्‌जन व अणु-बमों के नाम ले लेकर चिल्ला रहे हैं। साथ साथ वे यह भी कह रहे हैं कि सोवियत संघ के ख़ास

ख़ास नुक़्तों को बर्बाद करने में उन्हें कितने घंटे या दिन लगेंगे, तबाहकुन वार करने में कितनी देर लगेगी, वग़ैरह। सारी बात का निचोड़ यह कि सर्वाधिक चिन्तनशून्य और बेहद जंगख़ोर अमेरिकी जनरल सचमुच के युद्ध की, जनता के उन्मूलन की, भौतिक निधियों के विध्वंस की तैयारियों की चर्चा कर रहे हैं।

ऐसा करते हुए अमेरिकी जनरल और राजनयिक अक्सर कहते हैं कि सामरिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ की अपेक्षा अधिक अनुकूल स्थिति में है, क्योंकि यूरोप व एशिया के देशों के प्रदेशों में उसके फ़ौजी अड्डों की शृंखला मौजूद है जिनसे फ़ायदा उठाकर हमारे देश पर वार किया जा सकता है, जबकि, वे कहते हैं, सोवियत संघ के पास अब भी थोड़े ही अन्तर्महाद्वीपीय राकेट मौजूद हैं। इस कारण वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सचमुच कोई भारी ख़तरा नहीं है। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिरक्षा-सचिव मैकएलराय ने हाल में बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ की सीमाओं के पास स्थित अपने मित्र-देशों के प्रदेशों से फ़ौजी कार्रवाइयां चलायेगा, जबकि सोवियत संघ को तो केवल उन्हीं राकेटों का भरोसा करना पड़ेगा जिन्हें वह अपने ही प्रदेश से चला सकता है।

यह अनुमान किया जा सकता है कि ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी, तुर्की, यूनान, इटली और दूसरे देशों के लोग, जहां अमेरिका के फ़ौजी अड्डे क़ायम हैं, इस बात पर विचार करने लगे हैं कि ऐसी सम्भावना का उनके लिए क्या परिणाम निकलेगा।

जब ग़लत अनुमानों के आधार पर सामरिक योजनाएं बनायी जाती हैं तब उनके कारण ऐसी भूलें हो सकती हैं जिनका शान्ति के ध्येय के लिए विनाशकारी परिणाम निकले। अगर कोई राज्य समझता है कि किसी निर्दिष्ट क्षण में उसके प्रतिपक्षी के पास ऐसे शस्त्र का अभाव है

जिससे उसके प्रदेश पर वार किया जा सकता है, तो ऐसे अनुकूल क्षण का लाभ उठाकर युद्ध छेड़ देने का लोभ उसके मन में उठ सकता है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के कोई राजनयिक कहीं यह समझ बैठें कि आज उनका प्रदेश आक्रमण के परे है, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उनके लिए युद्ध छेड़ने का ऐन मौक़ा आ गया है—ऐसा युद्ध, जिसकी क़ीमत अंग्रेज़ों, फ़्रांसीसियों, इतालवियों, जर्मनों, तुर्कों और दूसरे मित्र-जनों के ख़ून व जानों से अदा की जा सकती है, जिनके इलाक़े युद्ध छिड़ते ही मध्यम और स्वल्प दूरी के राकेटों के हमले से मरघट बन जायेंगे। इन अफ़ीमची 'समरनीतिज्ञों' की राय में संयुक्त राज्य अमेरिका अपने को बर्बादी से बचाये रख सकेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता अपने मित्रों की बलि चढ़ाने में जो तत्परता दिखा रहे हैं, अपने संकुचित स्वार्थों की ख़ातिर मानव-समाज के भाग्य के प्रति जो तिरस्कार-भाव दरसा रहे हैं, वह तो कोरी बनियाई मनोवृत्ति है, मौत के उन व्यापारियों की नीति है, जो नफ़ा कमाने की धुन में खुद अपने बाप तक को बेचने के लिए तैयार होते हैं, मित्रों की तो बिसात ही क्या?

कहना न होगा कि यह नीति हमारी जनता के, हमारे सोवियत राज्य के, श्रमिक वर्ग के, मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों का अनुसरण करनेवाले लोगों के स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है। हम तो युद्ध न होने देने, नाभिकीय शस्त्रों का निषेध और उनके परीक्षण बन्द करने, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस और अन्य पश्चिमी देशों से सभी आधारभूत मसलों पर परस्पर-मान्य समझौते ढूंढ़ने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं। हम विश्व शान्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य मात्र का बड़ा मान करते हैं, चाहे उसकी जाति, नस्ल और धर्म कुछ भी क्यों न हो।

हम तो इस मत के हैं कि दूसरों की मुसीबतों और तकलीफ़ों की नींव पर किसी की खुशहाली का महल खड़ा करना दण्डय अपराध है। हम समझते हैं कि एक राष्ट्र की जनता को, चाहे वह दूर हो, चाहे निकट, बड़ी विपदा पहुंचाकर दूसरों की सुख-सुविधा की व्यवस्था करने की कामना करना, खासकर बिना किसी उचित कारण के, सर्वथा वर्ज्य है।

अगर अमेरिका के राजनीतिज्ञ और जनरल अपने निजी स्वार्थ का विचार छोड़कर समस्त मानव-समाज के हितों के विचार से प्रेरित हों तो वह न केवल अमेरिका की जनता के लिए, बल्कि संसार भर की जनता के लिए लाभकर होगा।

मेरे ख़्याल में अब समय आ गया है कि अमेरिका के फ़ौजी साहिब बेवकूफ़ों की बहिश्त से निकलकर अक़्लमन्दों की दुनिया में आयें। वे ये मन के लड्डू खाना छोड़ दें कि फ़ौजी भिड़न्त होने की सूरत में संयुक्त राज्य अमेरिका का इलाक़ा हमलों से अछूता रहेगा। वे दिन कभी के गुज़र गये। इधर एक मुद्दत से सचाई इसकी बिल्कुल उलटी है। अब भी अमेरिकी इलाक़े को हमले से परे समझना अमेरिकी जनरलों का पकाया खयाली पुलाव है, और कुछ नहीं। सच्ची बात तो यह है कि सोवियत संघ के पास आज ऐसे साधन मौजूद हैं जिनके सहारे वह दुनिया के पर्दे के किसी भी नुक़ते पर हमलावर पर तबाहकुन वार कर सकता है **(ज़ोर की तालियां)**। आख़िर जब हम कहते हैं कि हमने अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों का लगातार निर्माण चालू कर दिया है, तो यह कोरी लफ़्फ़ाज़ी तो नहीं है। न हम यह बात किसीको धमकाने के लिए कह रहे हैं। हम तो वर्त्तमान परिस्थिति में स्पष्टता लाने के लिए यह कह रहे हैं **(हॉल में सजीवता। देर तक तालियां)**।

सोवियत संघ की शान्ति की इच्छा का सबसे असन्दिग्ध प्रमाण, अगर किसीको चाहिए, तो उसके लिए हमारी सप्तवर्षीय योजना मौजूद

है। हमें शान्ति की आवश्यकता है और हम उसकी खातिर लगातार दृढ़ता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। पृथ्वी के सभी जन शान्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यही कारण है कि संसार भर में सोवियत संघ की शान्तिपूर्ण विदेशी नीति को इतना हार्दिक सम्मान और समर्थन प्राप्त है **(तालियां)।**

साथियो, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के सम्बन्धों में सुधार अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। कुछ ही समय पहले सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के बीच तीखे सन्देशों का आदान-प्रदान हुआ। इसका कारण यह था कि ये सन्देश बहुत ही तीखे अन्तर्राष्ट्रीय मसलों के सम्बन्ध में थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ चालों ने शान्तिप्रेमी जनताओं में आशंका पैदा कर दी थी। ऐसे में हम इस सम्बन्ध में अपना रवैया बताये बिना न रह सके।

अब तो ये बातें गुज़र चुकी हैं। हमें तो आगे देखना है। अपनी ओर से सोवियत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय तनाव दूर करने और सभी देशों से सम्बन्ध सुधारने का भरसक प्रयास कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और दूसरे नेताओं ने अ० इ० मिकोयान से अपनी बातचीतों के दौरान में कहा था कि वे शान्ति चाहते हैं। अगर यह सच है तो वे शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता मानेंगे और सोवियत संघ व दूसरे समाजवादी देशों के साथ अपने सम्बन्धों का आधार इसी को बनायेंगे।

व्यापारिक व सांस्कृतिक सम्बन्धों के विस्तार तथा राजनयिकों एवं सार्वजनिक नेताओं के व्यक्तिगत सम्पर्क से आपसी सौमनस्य सुधरने और राज्यों के बीच मैत्री सम्बन्ध क़ायम होने में बड़ी मदद मिल सकती है।

१९५५ की गर्मियों में जेनेवा में हुई चार राष्ट्रों के राजनयिकों की वार्ता की संसार भर में जो अनुकूल प्रतिक्रिया हुई, उसकी स्मृति आज

तक हमारे मन में ताज़ी है। शान्ति के मित्रों ने अनुभव किया कि यह वार्ता अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण क़दम है।

जेनेवा में श्री आइज़नहावर से हमारी जो मुलाक़ातें और वार्ताएं हुई उनके फलस्वरूप उनके बारे में हमारे मन में सुखद स्मृतियां संचित हुईं। मैंने तो यह राय बना ली कि जनरल होने के बावजूद श्री आइज़नहावर उन फ़ौजियों में नहीं हैं जो विवादास्पद मसलों के निपटारे में केवल तोपों का आसरा लेते हैं और शस्त्रों के बूते पर सभी समस्याओं का समाधान करना पसन्द करते हैं। श्री आइज़नहावर ने बार बार कहा कि उनका उद्देश्य युद्ध को रोकना है। हम इस बात की बड़ी क़द्र करते हैं और आशा करते हैं कि श्री आइज़नहावर के वक्तव्यों के अनुरूप ठोस कार्य भी किये जायेंगे।

साथी मिकोयान की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा से यह आशा पैदा हुई कि हमारे दोनों देशों के सम्बन्धों में 'रुखाई' और कम होगी, संपर्क बढ़ेंगे, आदान-प्रदान अधिक होंगे। प्रसंगवश यह बता दूं कि साथी मिकोयान ने अपनी छुट्टी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा में बितायी थी। लेकिन अब वह यह इशारा कर रहे हैं कि आख़िर सोवियत संघ में ही कहीं विश्राम करने का उन्हें मौक़ा दिया जाना चाहिए **(हॉल में सजीवता। तालियां)।**

हमारे सम्बन्धों में जो कठोर बर्फ़ीली ठंड छायी हुई थी, साथी मिकोयान की यात्रा से वह ज़रा कम हुई। शून्य से नीचे के शीतमान से ठंड उत्तरोत्तर घटती गयी और मौसम में गरमाहट उस सीमा की ओर बढ़ी जो साधारण अस्तित्व क़ायम रखने के लिए अत्यावश्यक होती है। मालूम पड़ता है, कुछ राजनीतिज्ञों को यह अच्छा न लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के जनमत पर साथी मिकोयान की यात्रा का जो अनुकूल प्रभाव पड़ा, ये राजनीतिज्ञ उसका प्रतिकार करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस तरह के सम्पर्क बढ़ाने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका में तो बातें उलटी ही दिशा में मोड़ी जा रही हैं। २८ जनवरी को हुए पत्रकार-सम्मेलन में एक संवाददाता ने श्री आइज़नहावर से पूछा कि मिकोयान की ही तरह ख्रुश्चेव की अमेरिकी यात्रा की कोई सम्भावना है? इसके जवाब में राष्ट्रपति ने कहा कि इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा: "श्री मिकोयान की तरह... अनौपचारिक रूप से यात्रा करना... असम्भव होगा!" इसका तात्पर्य यह हुआ कि साथी मिकोयान के लिए अलग मापदण्ड इस्तेमाल किया जाता है और मेरे लिए अलग **(हॉल में सजीवता)।**

निश्चय ही यह अप्रत्याशित तर्क है। यह तो क़रीब क़रीब भेदभाव है **(हॉल में हंसी)।** एक आदमी तो सभी को समान रूप से प्राप्त अधिकारों का उपभोग करे, लेकिन दूसरे को उससे वंचित किया जाय।

मैं चाहता हूं कि मेरा आशय ठीक से समझा जाय। ऐसी यात्रा पर जाने के लिए वीज़ा की अर्ज़ी देने का मेरा क़तई इरादा नहीं। यहां तो काम के मारे सिर उठाने की फ़ुर्सत नहीं। इसके अलावा, मेरे पास इतने न्योते आते हैं कि उन सब का खुद ही इस्तेमाल करने के लिए शायद ही समय निकाल पाता हूं। इसलिए बात यह नहीं कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका जाना चाहता हूं। बात तो बिल्कुल ही दूसरी है—यानी मनुष्य के अधिकारों की **(हॉल में सजीवता। तालियां)।** मेरी समझ में नहीं आता, कौनसी ऐसी बात है जिससे राष्ट्रपति आइज़नहावर मुझे उस अधिकार से वंचित कर रहे हैं, जो उन दूसरों को दिया जाता है जिन्हें उस देश जाने की अनुमति मिलती है **(हॉल में हंसी)।**

जहां तक सोवियत जनता से सम्बन्ध है, इन बातों में हमारा दृष्टिकोण ही भिन्न है। हम तो खुश होते हैं जब दूसरे देशों से लोग हमारे यहां आते हैं, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों, चाहे पर्यटक।

हाल के वर्षों में यह शानदार परिपाटी चल पड़ी है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल, संसद-सदस्य और पर्यटक सोवियत संघ की यात्रा कर रहे हैं और सोवियत लोग संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे हैं। इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हमारे लोग अमेरिकनों का खूब स्वागत-सत्कार करते हैं और अमेरिकी जनता हमारे लोगों के साथ बड़ी दोस्ती से पेश आती है। साथी मिकोयान की अमेरिका-यात्रा के समय तो यह दोस्ती खास तौर से जाहिर हुई। अगर राष्ट्रपति आइज़नहावर हमारे देश आयें तो हमारी सरकार और हमारी जनता उनका हार्दिक स्वागत-सत्कार करेंगी **(देर तक तालियां)**। वह जिसे चाहें, साथ ले आयें। वे सब हमारे स्वागत-योग्य मेहमान होंगे। राष्ट्रपति सोवियत संघ का नक़्शा देखें और हमारे देश की वे जगहें चुनें जहां वह जाना चाहेंगे। हमारा तो देश बहुत बड़ा है। इसमें बहुत-सी दिलचस्प जगहें हैं जो देखने और घूमने लायक़ हैं। राष्ट्रपति आइज़नहावर की यात्रा निर्विवाद रूप से हमारे दोनों देशों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। निश्चय ही संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की जनताएं इसे स्वीकृति देंगी। हम यह सुझाव प्रतिफल की शर्त के बिना पेश कर रहे हैं। अपनी ओर से हम किसीको अपनी यात्राओं से परेशान नहीं करेंगे **(हॉल में सजीवता। तालियां)**।

हम समझते हैं कि राजनयिकों और सार्वजनिक नेताओं की मेल-मुलाक़ातों, वार्ताओं और एक दूसरे के यहां आने-जाने से राज्यों में अच्छे रिश्ते बढ़ते हैं और ऐसा मौसम बनता है जो शरीर और आत्मा को सुखद लगता है और भविष्य के विचार से डरे बिना जीने, युद्ध का क़िस्सा ख़त्म करने और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व क़ायम करने के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करता है **(तालियां)**।

जनसाधारण शीत युद्ध नहीं चाहते, इसलिए कोई कारण नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की किन्हीं 'गुत्थियों' को अनसुलझा छोड़ा

जाये। उनका तो सुलझाव होना चाहिए। सबसे ऊपर मेरे मन में जो बात है, वह है जर्मनी के साथ शान्ति-सन्धि सम्पन्न करने और बर्लिन समस्या हल करने की बात। अगर हमारे प्रस्तावों के अनुसार ये समस्याएं हल की जायें तो उससे किसी भी एक पक्ष को कोई भौतिक अनुकूलता नहीं मिल जायेगी। परन्तु इसके बावजूद शीत युद्ध समाप्त करने, निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी समस्याएं हल करने और ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध क़ायम करने के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिनसे विवादों को निपटाने के साधन के रूप में युद्ध का प्रयोग असंभव हो जायेगा।

विदेश-सेक्रेटरी डलेस कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के साथ वार्ता के समय कोई छूट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उससे शीत युद्ध की समाप्ति नहीं, बल्कि शीत युद्ध में सोवियत संघ की जीत हो जायेगी। इसके जवाब में हम श्री डलेस से कहते हैं: हम किसीसे कोई छूट देने के लिए नहीं कहते; हम तो पारस्परिक सौमनस्य क़ायम करने और सामान्य विवेक की बात मनवाने की कोशिश करते हैं। सोवियत संघ शीत युद्ध में न अपनी विजय चाहता है, न संयुक्त राज्य अमेरिका की। तिसपर शीत युद्ध में तो जीत की गुंजाइश ही नहीं होती। फिर भी वह सबके लिए ख़तरा बना हुआ है। पल भर के लिए मान लीजिये कि शीत युद्ध में सोवियत संघ को कोई अनुकूल स्थिति प्राप्त हो गयी है और संयुक्त राज्य अमेरिका असफल हो रहा है, उस सूरत में शीत युद्ध ख़त्म तो नहीं हो जायेगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका हारी बाज़ी जीतने की इच्छा से अपनी नीति जारी रखने की कोशिश करेगा।

अगर जीतने की धुन किसीपर सवार हो जाये तब तो शीत युद्ध का कोई अन्त ही न होगा या वह सशस्त्र युद्ध में परिणत हो जायेगा जो और भी बुरी बात होगी। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें

शीत युद्ध समाप्त करने के अपने संकल्प का परिचय दें। सबसे ऊपर उन्हें यह बात समझने का परिचय देना चाहिए कि हम सब एक ही ग्रह में रह रहे हैं जो वर्त्तमान इंजीनियरिंग के लिहाज़ से काफ़ी सीमित आकार का है, इसलिए सतर्कता से काम लेना होगा और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व क़ायम रखने का भरसक प्रयत्न करना होगा।

हम तो बस, यह चाहते हैं कि शीत युद्ध का शीघ्र अन्त हो। और अगर आप ज़िद करते हैं, श्री डलेस, तो शीत युद्ध समाप्त करने की ख़ातिर हम इस 'युद्ध' में, जो जनता का कोई हित नहीं कर रहा है, आपकी 'जीत' स्वीकार करने को तैयार हैं। चलिये, सज्जनो, इस 'युद्ध' में अपने ही को 'विजेता' समझ लीजियेगा। ऐसे ही सही, यह पचड़ा फ़ौरन ख़त्म कीजियेगा **(हॉल में सजीवता। तालियां)।**

भिन्न भिन्न सामाजिक प्रणालियोंवाले राज्यों के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के रास्ते में जो भी बात अड़चन बनी हुई हो, उसे झाड़-बुहारकर रास्ते से हटा देना चाहिए। जब जूता काटता है और सैनिक को फ़ौजी अदा के साथ चलने नहीं देता, तो सैनिक या तो मोज़े ठीक कर लेता है या जूते बदल लेता है।

राजनीति में भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। जिन बातों से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बिगड़ने की आशंका हो और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व में अड़चन पेश आये, हमें उनका सफ़ाया कर देना चाहिए। आज पश्चिमी जर्मनी के पुन:शस्त्रीकरण की नीति ऐसी ही एक अड़चन है। जर्मनी से शान्ति-सन्धि करने के लिए सोवियत संघ के प्रस्ताव रखने पर डलेस को यह कहने का बहाना मिल गया कि सोवियत संघ शीत युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शान्ति-सन्धि सम्पन्न होने पर जीतता कौन, हारता कौन? जीतते हैं वे लोग, जो शान्ति क़ायम रखना चाहते हैं, और हार उनकी होती है जो शान्ति नहीं चाहते। इसलिए शान्ति-सन्धि शीत युद्ध की कोई चाल नहीं, बल्कि सभी

सभी राष्ट्रों का समान ध्येय है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ने शान्ति-सन्धि का मसविदा तैयार करने में हमसे आगे बढ़कर पहल कर ली होती तो हम न चिढ़ते, न यह शक करते कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्वार्थी, चालें चल रहा है, न ही वार्ता से कन्नी काटने का बहाना ढूंढ़ते।

जर्मनी के साथ शान्ति-सन्धि का मसविदा पेश करके सोवियत संघ ने पहलक़दमी का परिचय दिया। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को हमारे मसविदे पर कोई टीका-टिप्पणी करनी हो या अगर शान्ति-सन्धि में वह कोई ख़ास शर्तें सम्मिलित करने का सुझाव देना चाहता हो, तो अपना दृष्टिकोण प्रकट करने से उसे कोई नहीं रोकता। ख़ास इसी बात के लिए शान्ति-सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया है।

इस कारण हम संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों के राजनयिकों से अपील करते हैं कि वे सोवियत प्रस्तावों को सही ढंग से परखें। सोवियत प्रस्तावों का तो उद्देश्य शान्ति को सुदृढ़ करना है।

पश्चिमी बर्लिन का ही प्रश्न लीजिये। डलेस कहते हैं कि पश्चिमी बर्लिन का समर्पण नहीं किया जाना चाहिए। हम पूछें: किसके हाथ समर्पण? क्या, सोवियत प्रस्तावों में कोई ऐसी बात है जिसमें पश्चिमी बर्लिन के समर्पण का ज़िक्र हो?

अगर पश्चिमी बर्लिन जर्मन जनवादी जनतन्त्र के बीचोंबीच उपद्रवों और झड़पों का अखाड़ा न होता तो बर्लिन समस्या नाम की चीज़ ही न होती। लेकिन आज पश्चिमी बर्लिन की स्थिति ऐसी है कि वहां कोई भी अनहोनी बात हो सकती है। उसकी तुलना बारूदख़ाने में पडे जलते पलीते से की जा सकती है या विलम्बित विस्फोटवाले बम से, जिसकी मेकैनिज़्म किसी भी क्षण विस्फोट करा सकती है। आख़िर ऐसी हालत हम बनाये रखें ही क्यों? क्या यह अच्छा न होगा कि हम पलीता बुझा दें, विलम्बित विस्फोटवाला बम हटा दें? इस बात का और कोई हल ढूंढ़ना मुश्किल होगा जो दोनों

जर्मन राज्यों के हित में हो और साथ ही साथ दूसरे सम्बन्धित राष्ट्रों के लिए अपमानजनक या हानिकारक न हो। पश्चिमी बर्लिन को आज़ाद शहर में परिणत करना ऐसा हल है। यह एक ऐसा हल है जिससे शहर के जीवन की चिरप्रचलित परिपाटी में कोई अन्तर नहीं आयेगा और आवश्यक गारंटियों की व्यवस्था होने पर शहर के अन्दरूनी मामलों में बाहर की दखलन्दाज़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी।

इसलिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ पश्चिमी बर्लिन के लिए ऐसा दर्जा निर्धारित करने में सहयोग करने को तैयार हैं जो उस स्वतन्त्र शहर के नियत विकास, जिन देशों से वह सम्बन्ध क़ायम रखना चाहे उनके साथ उसके सम्बन्ध और उसके लिए और इन देशों के लिए पारस्परिक आवागमन की सुविधा की गारंटी दे। स्वतन्त्र शहर के दर्जे की रक्षा करने में संयुक्त राष्ट्रसंघ के भाग लेने पर भी हम राज़ी हैं और यह किस रूप में हो, इस बात पर विचार करने को तैयार हैं। स्वभावतः ऐसे प्रस्ताव और उनकी क्रियान्विति के तरीक़े जर्मन जनवादी जनतन्त्र की शरकत से निर्धारित किये जाने चाहिए, क्योंकि बर्लिन उसके प्रदेश में है। हमारी राय में पश्चिमी बर्लिन के स्वतन्त्र, निःसैनीकृत शहर बन जाने से दूसरे विवादास्पद प्रश्नों के निपटारे के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इससे यूरोप की सुरक्षा और उसके फलस्वरूप सारे संसार की सुरक्षा सुनिश्चित हो जायेगी।

शायद मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, लेकिन यह प्रश्न ही ऐसा है जिसका ज़िक्र हमें तब तक बार बार करना होगा जब तक कि सभी सम्बन्धित पक्ष स्थिति की गंभीरता को न समझ लें, खूब तर्क-वितर्क कर यह ठीक ठीक न जान लें कि ऐसी स्थिति बनी रहने देने के क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं और प्रश्न के सही निपटारे पर सहमत न हो जायें। ऐसा निपटारा करना सोवियत संघ का लक्ष्य है और इसके पूरा

होने तक वह अपने प्रयास में शिथिलता नहीं आने देगा (**देर तक तालियां**)।

साथियो, हमारी कांग्रेस के मंच से जर्मन जनता से यह अपील करने की मुझे अनुमति दीजिये कि वह ऐसे प्रस्तावों का समर्थन करे जिनका उद्देश्य यूरोप में शान्ति तथा जनताओं की सुरक्षा सुदृढ़ करना है (**ज़ोर की तालियां**)।

पिछले पचास साल के दौरान में दो बार जर्मन साम्राज्यवादियों ने जर्मन जनता को विश्वयुद्ध के भयानक नरमेध में झोंका था। बहुत-से देशों की जनता को इस युद्ध में शरीक होना पड़ा। लेकिन हमारे देश की जनता और जर्मन जनता को सबसे भारी क्षति पहुंची। खून और आंसू की कैसी नदियां बहीं, हमारे देशों का कैसा भारी विध्वंस हुआ!

हिटलर ने राष्ट्रवादी, अंधराष्ट्रवादी प्रचार के सहारे दूसरे विश्वयुद्ध की तैयारी की और युद्ध छेड़ा। उसने जर्मन जनता के दिमाग़ में यह बात कूट कूटकर भरी कि जर्मनी और सबसे बढ़कर है, जर्मन लोग शासक जाति के हैं, जर्मनी के लिए 'जीने का स्थान' विस्तृत करना ज़रूरी है, कम न बेश उराल तक। ख़ैर, हम सब जानते हैं कि हिटलर के अभियानों का क्या अन्त हुआ। जर्मनों ने यूरोप के लोगों पर मुसीबत का क़हर ढाया, लेकिन आख़िर उन्होंने मुंह की खायी। दुर्भाग्यवश आज पश्चिमी जर्मनी के सबसे आक्रमणप्रिय राजनीतिज्ञ हिटलर के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। ज़ाहिर है, इतिहास का सबक़ उनके दिमाग़ में नहीं आया और वे तीसरी बार कोशिश करके जर्मन जनता को लूट-मार की लड़ाई के लिए उभाड़ रहे हैं।

साम्राज्यवादी शासक समाजवादी देशों की जनताओं के प्रति विद्वेष के मारे अंधे हो रहे हैं—उन जनताओं के प्रति, जो अपनी अर्थ-व्यवस्था और संस्कृति का सफल विकास कर रही हैं और अपना जीवन-स्तर ऊंचा कर रही हैं। ये साम्राज्यवादी लोग इतिहास का बहाव

रोकना, बल्कि उसे पीछे की ओर मोड़ना चाहते हैं और इसके लिए मुख्य रूप से जर्मनों पर निर्भर कर रहे हैं। लेकिन आणविक और उद्जन-शस्त्रों के दिनों में, राकेट-इंजीनियरिंग के दिनों में ऐसी कोशिशें तो सहज पागलपन होंगी। इसके फलस्वरूप इतना ही नहीं होगा कि करोड़ों लोग मौत के मुंह में जायेंगे, बल्कि समूचे राष्ट्र और राज्य नेस्त-नाबूद हो जायेंगे। ऊपर से, समाजवादी देशों के विरुद्ध आक्रमण में पश्चिमी जर्मनी के भाग लेने के परिणामस्वरूप उसकी ऐसी स्थिति हो जायेगी कि जमा करके रखे हुए उद्जन-शस्त्रों का काफ़ी हिस्सा सबसे पहले जर्मन धरती पर वार करेगा और फटेगा।

पश्चिमी जर्मनी अपने विकास में कौनसा रुख अपनायेगा — राष्ट्रों के बीच सशस्त्र भिड़न्त के अखाड़े क़ायम रखने का या इन अखाड़ों को खत्म करने का, ताकि राज्यों के बीच, चाहे उनकी सामाजिक प्रणाली कुछ भी हो, मैत्री सम्बन्ध स्थापित होने का रास्ता साफ़ हो सके — यह तय करने की ज़िम्मेदारी तो जर्मन कामगारों, किसानों, बुद्धिजीवियों और साथ ही पश्चिमी जर्मन पार्टियों के नेताओं एवं जर्मन संघात्मक जनतन्त्र के राजनयिकों पर है। हम आशा करते हैं कि ये लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे।

अध्यवसायी एवं प्रतिभाशाली जर्मन जनता ने संसार को कई महान विचारक एवं प्रमुख वैज्ञानिक, कवि और संगीतकार दिये हैं। जर्मन जनता ने शक्तिशाली उद्योग स्थापित किया है और अपने लिए ऊंचा जीवन-स्तर सुनिश्चित कर रही है। यह सब वह कर पायी है विदेशी प्रदेश पर क़ब्ज़ा किये बिना ही, जैसे कि करने के लिए हिटलर और गोएबेल्स ने उसे उभाड़ा था। क्या, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि जर्मन जनता को अपना भविष्य शान्तिपूर्ण श्रम से निर्मित करना चाहिए, न कि लड़ाई के मैदान पर? और अगर वर्तमान तनाव दूर किया जाय और जर्मन संघात्मक जनतन्त्र की सरकार सोवियत संघ, चीनी जनवादी जनतन्त्र और अन्य समाजवादी देशों के साथ, संसार के सभी देशों के साथ,

आर्थिक सम्बन्ध पनपने की सुविधा दे तो जर्मन लोगों को अपनी कुशलता का उपयोग करने के और भी अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। वे अपनी अर्थ-व्यवस्था का विकास कर सकेंगे, जीवन-स्तर ऊंचा कर सकेंगे और अपने राष्ट्र की भौतिक और आत्मिक सम्पत्ति बेहद बढ़ा सकेंगे।

दुर्भाग्यवश पश्चिमी जर्मनी के चान्सलर श्री आदिनावर की नज़र दूसरी ओर लगी हुई है। वह तो शीत युद्ध और बल-प्रदर्शन की नीति का अनुसरण जारी रहने का आसरा लिये बैठे हैं। चान्सलर साहब, आप हाथ में बांस लिये, नदी-किनारे पर बैठे इन्तज़ार कर रहे हैं कि फ़लां मछली आपका लासा खुरचेगी, लेकिन, जनाब, आप जो मछली चाहते हैं, वह तो इस नदी में रहती ही नहीं **(हॉल में हंसी। तालियां)।** आप वह ख्वाब देख रहे हैं जो सच नहीं होने का। अब तो छोड़िये यह सपना!

श्री आदिनावर घोषणा करते हैं कि जर्मन संघात्मक जनतन्त्र सोवियत संघ के साथ सहयोग नहीं करेगा जब तक कि हमारा देश इस सहयोग की क़ीमत अदा नहीं करेगा। हेर कान्ज़लर, महाशय, राजनीति के मामलों में आपको टुटपुंजिये पंसारी की तरह बातें नहीं करनी चाहिए। हम आपके क़र्ज़दार तो नहीं हैं, हमें आपको कुछ नहीं देना है। हम तो चाहते हैं, आप यह समझें कि पूर्व और पश्चिम के अपने पड़ोसियों के साथ शान्तिपूर्ण सहयोग करने से बढ़कर जर्मन संघात्मक जनतन्त्र के लिए और कोई विवेकयुक्त नीति नहीं हो सकती और पूर्वी जर्मनी की समाजवादी प्रणाली को ख़त्म करना न आपके बस की बात है, न अपने मित्रों की सहायता से ही आप ऐसा कर सकते हैं **(ज़ोर की तालियां)।**

पूर्वी जर्मनी के जर्मन पुरानी जीवन-प्रणाली अपनाना नहीं चाहते। उनके हितों के प्रति हमारा दृष्टिकोण सौमनस्य का दृष्टिकोण है। हमने जर्मन जनवादी जनतन्त्र की सहायता की है और भविष्य में भी करते रहेंगे। यह अनुमान करना तर्कसंगत होगा कि पूर्वी जर्मनी के जर्मन अपने मुक़ाम पर यह समझते हैं कि पश्चिमी जर्मनी की मौजूदा प्रणाली का ख़ात्मा

करना उनके लिए सिद्धान्ततः सही होगा। लेकिन प्रश्न को इस रूप में पेश करना यथार्थ नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन तो स्वयं जनता द्वारा लागू किये जाते हैं। इस मामले में ख़रीद-फ़रोख़्त का तो सवाल ही नहीं उठता।

लोगों को यथार्थवादी राजनीति की ठोस धरती पर पैर जमे रखना चाहिए – उस राजनीति की, जो इतिहास के किसी निर्दिष्ट क्रम के अनुरूप हो। अगर यह बात न समझी जाये, अगर कोई नदी की रौ में अवश ही बहता जाये, जीवन के उच्छ्वास-निःश्वास और स्पन्दन अनुभव न करे, तो करोड़ों लोगों को मुसीबत उठानी पड़ सकती है। हम आपके प्रस्ताव सुनने को तैयार है। अगर आपके प्रस्ताव युक्तिसंगत हों तो हम आपके साथ एक मेज के गिर्द बैठने, आपके और अपने प्रस्तावों की छानबीन करके समझौते का कोई परस्पर-सम्मत आधार ढूंढने और फिर उस समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं।

लेकिन अगर आप यह शर्त लगायें कि जर्मन जनवादी जनतन्त्र का अस्तित्व मिटाकर उसे शेष हिस्से में विलीन कर दिया जाये, जर्मन जनवादी जनतन्त्र के श्रमिक जनों की सामाजिक उपलब्धियां ख़त्म कर दी जायें तो वह एक ऐसी शर्त होगी जिसपर हम विचार तक नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते तो हम अपने ऊपर ऐसा काम लेते जो हमारे अधिकार-क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि यह तो दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप होगा।

प्रत्येक राष्ट्र को अपने आप यह निर्णय करना चाहिए कि कौनसी सामाजिक प्रणाली उसके उपयुक्त होगी। इसका निर्णय वह कब करे, यह तो उसका अपना मामला है। अगर दोनों जर्मन राज्यों के जर्मन लोग आपस में तय कर लें कि आम चुनाव किये जायें तो हम तथाकथित स्वतन्त्र चुनावों का विरोध नहीं करते जिनकी पश्चिमी देशों में इतनी चर्चा है। लेकिन शर्त यह कि कोई तीसरा पक्ष इसमें दख़लन्दाज़ी न करे। हम तो यह अनुमान कर सकते हैं कि किसी समय जर्मन लोग पश्चिमी जर्मनी की पूंजीवादी प्रणाली ख़त्म करने के लिए स्वतन्त्र चुनाव करना चाहेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि

चान्सलर आदिनावर यह बात नहीं मानते, फिर भी, ऐसा विकल्प सम्भव है **(तालियां)**। परन्तु यह बात जर्मनों को खुद ही तय करनी चाहिए।

स्वतन्त्र चुनावों के बारे में एक शब्द। पश्चिमी राष्ट्रों के शासक वर्ग इन चुनावों को अपने ही ढंग से समझते हैं। आपको याद होगा कि १९५४ के जेनेवा-सम्मेलन में इस आशय का समझौता सम्पन्न हुआ कि दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम में देश को शान्तिपूर्ण ढंग से एक करने के उद्देश्य से स्वतन्त्र चुनाव किये जायें। लेकिन दक्षिणी वियतनाम की कठपुतली सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से इन चुनावों को भंग कर दिया।

साथियो, अब मैं एक ऐसे विषय की चर्चा करना चाहूंगा जिसे हम एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न मानते हैं। मेरा आशय आणविक और उद्जन-शस्त्रों के परीक्षण बन्द करने से है।

पिछली गर्मियों में जेनेवा में विशेषज्ञों का एक सम्मेलन हुआ। नाभिकीय विस्फोटों का पता लगाने और इस बात की गारंटी देने पर इस सम्मेलन में विचार हुआ कि नाभिकीय परीक्षण बन्द करने के बारे में अगर समझौता हुआ तो वह सभी सम्बन्धित पक्षों द्वारा पूर्णतः क्रियान्वित किया जायेगा। सोवियत संघ का दृष्टिकोण यह रहा है कि नाभिकीय परीक्षण चाहे कहीं भी हों, उनका पता लगाना सर्वथा सम्भव है। सम्मेलन के निष्कर्षों ने इस विचार की पुष्टि की। सबसे अधिकारी विशेषज्ञों ने, जिनमें सोवियत, अमेरिकी और ब्रिटिश विशेषज्ञ थे, अणु एवं उद्जन बमों के विस्फोटों का पता लगाने के लिए एक नियन्त्रण-प्रणाली लागू करने के व्यावहारिक सुझाव तैयार किये थे।

विशेषज्ञों के सफल काम से हम सन्तुष्ट हुए। जेनेवा सम्मेलन ने सर्वसम्मति से जो निष्कर्ष और सुझाव स्वीकार किये थे, सोवियत सरकार ने उन्हें पूर्णतः मान लिया। हमें ऐसा भान हुआ कि नाभिकीय परीक्षण सदा के लिए बन्द करने के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन से अनायास और अविलम्ब समझौता सम्पन्न करने में हम समर्थ होंगे।

दुर्भाग्यवश बात कुछ और ही हुई। परीक्षण बन्द करने पर समझौता तैयार व सम्पन्न करने के लिए सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों की जेनेवा वार्ता शुरू हुए इधर तीन महीने से भी ऊपर हो चुका है। फिर भी कोई प्रगति नहीं हो रही। जिस ढंग से यह वार्ता हो रही है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वार्ता के हमारे साथी समझौता न होने देने पर तुले हुए हैं।

किन कारणों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं? कारण तो बहुत हैं।

सबसे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन की पूरी सहायता से कुछ कोशिशें की हैं जो विशेषज्ञ-सम्मेलन के उपयोगी कार्य पर पानी फेरने के बराबर हैं। अमेरिकी सरकार ने पहले तो विशेषज्ञों के निष्कर्ष स्वीकार किये थे, लेकिन बाद में अचानक ही ऐलान कर दिया कि कुछ 'नये विवरण' प्राप्त हुए हैं जिनके अनुसार भूमि के गर्भ में होनेवाले विस्फोटों का पता लगाना पहले के अनुमान से कहीं अधिक कठिन हो गया है। असली बात तो इसकी बिल्कुल उलटी है। ज्यों ज्यों समय बीतता है त्यों त्यों पता लगाने की टेकनीक सुधरती जा रही है और हर प्रकार के नाभिकीय विस्फोट का पता लगाना और आसान होता जा रहा है।

हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि विशेषज्ञों की सिफ़ारिशों की फिर से छानबीन करने का यह सब बखेड़ा अणु एवं उद्जन-शस्त्रों के परीक्षण बन्द करने के बारे में समझौता सम्पन्न होने से रोकने के इरादे से खड़ा किया गया है।

परीक्षण बन्द करने सम्बन्धी सन्धि की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए नियन्त्रण-व्यवस्था स्थापित करने पर हो रही वार्ता के दौरान में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जो मांगें पेश कर रहे हैं, यही समझना पड़ता है कि उनके भी पीछे यही उद्देश्य है।

आप स्वयं ही निर्णय कीजिए – वे क्या चाहते हैं! वे चाहते हैं कि विस्फोटों का पता लगाने के लिए जो नियन्त्रण-चौकियां क़ायम करने का

प्रस्ताव है, उन सबमें केवल विदेशी कर्मचारी होने चाहिए और विदेशी निरीक्षकों को सन्धिवाले राज्यों के प्रदेश में जहां चाहें बेरोकटोक घूमने की छूट होनी चाहिए। अमेरिका व ब्रिटेन ऐसी भी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिसमें नियन्त्रण-कमीशन, जिसके अधीन ये चौकियां और निरीक्षक काम करेंगे, पश्चिमी प्रतिनिधियों के यन्त्रचालित-से बहुमत के बल पर ऐसे निश्चय लागू कर सकता है जो सोवियत संघ के सुरक्षा सम्बन्धी हितों के प्रतिकूल होंगे।

हम पूछते हैं: यह मांग किस अंश में उस प्रस्ताव से भिन्न है जो राष्ट्रपति आइज़नहावर ने पेश किया था—कि अमेरिकियों को सोवियत संघ के समूचे प्रदेश के ऊपर स्वच्छन्द उड़ानें भरने और फ़ोटो उतारने का मौक़ा दिया जाना चाहिए? या फिर तथाकथित 'बरूच योजना' से यह किस बात में भिन्न है? सोवियत संघ समेत सभी देशों में आणविक विखण्डन-योग्य वस्तुओं के उत्पादन पर अमेरिकी एकाधिकारों का नियन्त्रण लागू करने की कल्पना दर असल इसी 'बरूच योजना' में पहले-पहल की गयी थी। आपको याद होगा, ये प्रस्ताव ठुकरा दिये गये थे। ठीक इसी प्रकार हम उस ढंग के प्रस्ताव आज भी ठुकराते हैं, क्योंकि हम किसीको सोवियत संघ की सार्वभौमिकता की सुरक्षा का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दे सकते। यह बात तो हमें कभी मान्य नहीं होगी। इस समय जेनेवा में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधिमण्डल जो मांगें पेश कर रहे हैं, उन्हें पूरा करने का मतलब तो यह होगा कि हम अपने प्रदेश में पश्चिमी राष्ट्रों की सर्वांगीण जासूसी कार्रवाई का जाल बिछने दें।

हां, कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रस्तावक संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन अपने प्रदेशों में भी तो ऐसी ही नियन्त्रण-व्यवस्था क़ायम की जाने की अनुमति देते हैं। हो सकता है, यह सच हो। लेकिन हमारा तो कोई सामरिक उद्देश्य है ही नहीं, इसलिए हमें उनके प्रदेशों की गश्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के इर्द-गिर्द हमारा

कोई फ़ौजी अड्डा तो नहीं है—न मेक्सिको में, न कैनाडा में और न संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी अन्य पड़ोसी देश में।

आम तौर पर किसी विदेशी इलाक़े में सोवियत संघ का कोई फ़ौजी अड्डा नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि ऐसे अड्डों की, खासकर अपने प्रदेश से बड़ी बड़ी दूरियों पर, स्थापना और कुछ नहीं, लड़ाई की तैयारी होती है, आक्रमण की तैयारी होती है। चूंकि पश्चिमी राष्ट्र हमारे चारों ओर अपने फ़ौजी अड्डों का घेरा क़ायम कर चुके हैं, इसलिए अब वे फ़ौजी गश्त के लिए हमारे ही इलाक़े में अड्डे क़ायम करना और सोवियत प्रदेश के ऊपर उड़ानें भरने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं ताकि इस गश्त के आधार पर हमारे देश के ख़िलाफ़ अपने फ़ौजी अड्डों को काम में लाने का ऐन मौक़ा चुन सकें। तुर्रा यह कि इन योजनाओं को पूरा करने में वे हमारी सहायता की अपेक्षा रखते हैं। आप तो कमाल करते हैं, सज्जनो! **(हॉल में सजीवता। तालियां)।**

अगर किसी राज्य के नेता अपने देश के हितों का, अपनी जनता की सुरक्षा का ख़्याल रखते हों, अगर उन्हें पागल कुत्ते ने न काटा हो, तो वे ऐसी मांगें कहीं मान सकते हैं? इन्हें मानना तो देशद्रोह होगा!

हम तो ऐसी मांगों को, जैसी पश्चिमी राष्ट्र पेश कर रहे हैं, बुरी नीयतवाली ज़िदबाज़ी मानते हैं। अगर पश्चिमी राष्ट्र कहते हैं कि उनकी नीयत बुरी नहीं है तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि अपनी ज़िदबाज़ी से बाज़ आयें और ऐसी कारस्तानियां होने न दें जिनसे हमारे मन में शक पैदा हो।

हम नाभिकीय परीक्षणों की बन्दी पर उचित नियन्त्रण के हामी हैं। चालू जेनेवा सम्मेलन में ख़ुद सोवियत संघ ने इस तरह के नियन्त्रण के बारे में प्रस्ताव पेश किये हैं। लेकिन हम पश्चिमी राष्ट्रों को नियन्त्रण की आड़ में अपने देश की सार्वभौमिकता का उल्लंघन करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन अपनी युक्ति-विरुद्ध मांगें छोड़ दें तो सोवियत संघ विदेशी प्रतिनिधियों को

शरकत से नियन्त्रण-चौकियों का काम कारगर ढंग से चलाने तथा यान्त्रिक उपकरण की स्थापना व संचालन की आवश्यक व्यवस्था करने को तैयार हैं।

यह तो सुविदित है कि वर्त्तमान समय में, अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण न होने पर भी, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन द्वारा किये जानेवाले नाभिकीय विस्फोट छिपे नहीं रहते, उनका पता लग ही जाता है। इनके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका में होनेवाले विस्फोटों का पता सोवियत संघ के प्रदेश में स्थापित नियन्त्रण-उपकरणों के सहारे लग जाता है और हमारे विस्फोट अमेरिका में दर्ज हो जाते हैं। अब तो यह प्रस्ताव है कि किसी देश की सीमा के भीतर होनेवाले विस्फोटों का पता लगाने के लिए उसी देश में स्थापित नियन्त्रण-चौकियों से काम लिया जाय और ऐसी चौकियों का एक व्यापक जाल-सा बिछा दिया जाय। लेकिन पश्चिमी राष्ट्र तो यह मांग कर रहे हैं कि एक प्रकार की अप्रत्याशित जांचें हों और उनके निरीक्षकों को सोवियत संघ के समूचे प्रदेश में बेरोकटोक घूमने-फिरने की छूट हो।

क्या, इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि ऐसी नियन्त्रण-व्यवस्था का प्रधान, फ़ौजी गश्त का मुखिया बन जायेगा? जिस इलाक़े में भी उसे दिलचस्पी हो, वह हर वक़्त यह कह सकेगा कि उस इलाक़े में विस्फोट होने का उसे शक है, और उस इलाक़े का निरीक्षण करने के लिए जांच-दल भेज सकेगा। कोई भी राजनीतिज्ञ या राजनयिक, निहायत भोला-भाला शख़्स भी, यह जानता होगा कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। इसके तो बुरे ही नतीजे निकलेंगे: सन्धिवाले राष्ट्रों में मनमुटाव पैदा होगा।

हम अपने लिए कोई अपवादात्मक स्थिति नहीं मांगते। हम जिस एक बात की मांग करते हैं वह तो यही है कि शर्तें हमारे और पश्चिमी राष्ट्रों के लिए सचमुच एक-सी हों। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन — यानी नाटो का फ़ौजी गुट्ट — अपने लिए ऐसी अनुकूल शर्त्तें चाहते हैं जो सोवियत संघ के हितों के प्रतिकूल हैं।

एक दूसरे पर नियन्त्रण किस हद तक जा सकेगा, यह तो दो राज्यों के आपस के विश्वास की मात्रा से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। आपस का विश्वास जितना ही अधिक हो, व्यापक नियन्त्रण पर सहमत होना उतना ही आसान होगा। लेकिन हां, अगर पूरा पूरा विश्वास हो तब तो नियन्त्रण की ज़रूरत ही नहीं रहेगी।

जब सोवियत संघ के चारों ओर नाटो के अनगिनत फ़ौजी अड्डे क़ायम हों, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बनाये हुए नाटो, बग़दाद सन्धि वग़ैरह आक्रमणकारी फ़ौजी गुट्टों के सदस्य-राष्ट्र सोवियत संघ व दूसरे समाजवादी देशों से साधारण व्यापारिक सम्बन्धों तक पर प्रतिबन्ध लगा रहे हों, तब असीमित नियन्त्रण के अधिकार का दावा करना क्या उचित है? हमपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम राजनीतिक मक़सद साधने के लिए व्यापार से काम ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका ही वह देश है जिसने कोरे राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर समाजवादी देशों से व्यापार करना छोड़ ही-सा दिया है। और यह तब, जब अमेरिका के आर्थिक हितों के लिए व्यापार बढ़ाना आवश्यक है, जब पश्चिमी राष्ट्रों के कारोबारी हल्क़े व्यापार बढ़ाने के हक़ में हैं।

तो, साथियो, अणु और उद्‌जन-शस्त्रों के परीक्षण बन्द करने के सिलसिले में स्थिति यह है। जेनेवा वार्ता के हमारे साथी जान-बूझकर ऐसे प्रस्ताव पेश कर रहे हैं जिन्हें हम मान नहीं सकते। ज़ाहिर है, ऐसा करने से वे इस समस्या के हल होने में उसी तरह अड़चन डालना चाहते हैं जिस तरह उन्होंने अप्रत्याशित हमला रोकने की समस्या के सिलसिले में अड़चन डाली थी। दर असल उस मामले का तो निपटारा उन्होंने खटाई में डाल दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि नाभिकीय परीक्षण बन्द करने के मामले में भी वे इसी तरह टालमटोल करते रहना और इस बीच वार्ता-भंग के लिए जनमत तैयार करना चाहते हैं। मतलब यह कि आख़िर इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का भी निपटारा वे रोकना चाहते हैं।

अगर मेरे ये अनुमान ग़लत साबित हों तो मुझे तो ख़ुशी ही होगी। जहां तक सोवियत संघ से सम्बन्ध है, नाभिकीय शस्त्रों के परीक्षण बन्द करने पर जितनी जल्दी सम्भव हो समझौता सम्पन्न करने की हमारी इच्छा को मैं फिरेक बार पुष्ट करना चाहता हूं। हम इस प्रश्न के बारे में किसी भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं जो युक्तिसंगत शर्तों पर आधारित हो और जिसमें विस्फोटों के आवश्यक नियन्त्रण की निश्चित व्यवस्था हो।

साथियो, कांग्रेस के प्रतिनिधियों के भाषणों और भ्रातृ कम्यूनिस्ट व कामगार पार्टियों के प्रतिनिधिमण्डलों के नेताओं के स्वागत-भाषणों से सम्पूर्ण मतैक्य, अन्तर्राष्ट्रीय दृढ़ एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट एवं श्रमिक आन्दोलन सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर विचारों की एकता व्यक्त हुई। कांग्रेस के वक्ताओं ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आधार पर भ्रातृ-पार्टियों की एकता और दृढ़ता का ज़िक्र किया और कहा कि भ्रातृ-पार्टियां संशोधनवाद को वर्त्तमान परिस्थितियों में सबसे बड़ा ख़तरा मानकर उसके विरुद्ध अविचलित संघर्ष जारी रखे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि कम्यूनिस्ट और कामगार पार्टियों के सम्मेलन के घोषणा-पत्र की थीसिस सही थी।

हमारी कांग्रेस की कार्यवाही में सबने बड़ी रुचि ली। अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट आन्दोलन और सभी प्रगतिशील जनों ने उसका समर्थन किया। लेकिन यूगोस्लाविया के संशोधनवादी इससे बेहद झुंझला उठे हैं, तो वह उनके दृष्टिकोण के अनुरूप ही है। यूगोस्लाव पत्र-पत्रिकाओं में कई लेख छपे हैं जिनमें संशोधनवादी राजनीति को उचित ठहराने, यूगोस्लाविया से सहयोग के सोवियत संघ के प्रयासों को यूगोस्लाव जनता से छिपाने और यूगोस्लाविया और समाजवादी देशों के सम्बन्धों में उत्पन्न वास्तविक स्थिति का विकृत चित्रण करने की भद्दी कोशिशें की गयी हैं। अपनी संशोधनवादी नीति से यूगोस्लाव नेता श्रमिक जनता के बुनियादी हितों के लिए हो रहे संघर्ष में श्रमिक वर्ग की क्रान्तिकारी शक्तियों में फूट डाल रहे हैं।

यूगोस्लाव नेताओं की संशोधनवादी नीति का क्या परिणाम निकला है, इस सम्बन्ध में हमारी उक्ति के जवाब में वे कोई भी तर्कसंगत बात नहीं कह सके हैं। वे अपने रवैयों की कमज़ोरी खुद अनुभव करते हैं। यही कारण है कि वे धांधलेबाज़ी का सहारा ले रहे हैं, जो उनकी पसन्द की तरक़ीब है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे है कि सोवियत संघ उनके अन्दरूनी मामलों में दख़लन्दाज़ी कर रहा है। लेकिन यह झूठा इल्ज़ाम है। यह तो सब जानते हैं कि हम दूसरे देशों और पार्टियों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति पर अडिग हैं। अपनी कांग्रेस में हम फिरेक बार इसकी बहुत ही निश्चित घोषणा कर चुके हैं।

लेकिन ज़रा देखिए तो कि यूगोस्लाव संशोधनवादी समाजवादी देशों की एकता को नुक़सान पहुंचाने की कोशिश में कैसे निन्दनीय और उत्तेजक तरीक़ों का आसरा ले रहे हैं। जैसे कि हमारी रिपोर्ट में कहा गया था, यूगोस्लाव संशोधनवादी हर तरह की झूठी गप्पें गढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी और चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी में मतभेद हैं। पिछले कुछ दिनों में तो वे और आगे बढ़ गये हैं और अपनी मनगढ़न्त बातों को प्रमाणित करने की धुन में एक 'भारी-भरकम गवाह' तथा 'सोवियत संघ और चीनी जनवादी जनतन्त्र के बीच मतभदों' सम्बन्धी प्रश्नों के विशेषज्ञ को घसीट लाये हैं। यह विशेषज्ञ हैं अमेरिकी सेनेटर ह्यूबर्ट हम्फ़्री **(हॉल में सजीवता)**। आपको याद होगा, यह सेनेटर हाल में सोवियत संघ आये थे और उनसे मेरी बातचीत हुई थी। गुल-गपाड़ा और सनसनी पैदा करने के फेर में इन हम्फ़्री महोदय ने अपनी तक़रीरों व लेखों में ऐसी बेपर की उड़ायी है कि कुछ पूछिये मत। ढेर सारी गप्पें हांकी हैं उन्होंने, जैसे यह गप कि वह राष्ट्रपति आइज़नहावर के नाम सोवियत सरकार का एक विशेष सन्देश ले गये थे (ऐसी तो कोई बात विल्कुल नहीं हुई) और यह कि मैंने उन्हें दो महत्त्वपूर्ण रहस्य बताये थे। वाह वाह, रहस्य सुनाने के लिए मुझे श्री हम्फ़्री से बढ़कर और कोई नहीं मिल सकता था! **(हॉल में सजीवता)**। सोवियत संघ और

चीनी जनवादी जनतन्त्र के सम्बन्धों के बारे में क़िस्से गढ़ते वक़्त तो सेनेटर हम्फ़्री ने ख़याली घोड़े एकदम बेलगाम छोड़ दिये। इसमें तो उन्होंने मनगढ़न्त क़िस्सों के माहिर बैरन मुन्चासन को भी मात कर दिया।

तो यूगोस्लाव संशोधनवादियों ने अब इस माहिर को अपना गवाह बना लिया है। जो आदमी कम्यूनिज़्म के ख़िलाफ़ अपने बीस साल के संघर्ष की ख़ुद ही शेख़ी बघारता है, मैंने उससे किसी तरह की अन्तरंग की बात की होगी, इसकी कल्पना मात्र से हंसी ही आ सकती है। राजनीति की – मार्क्सवाद-लेनिनवाद की तो पूछना ही क्या – ज़रा भी जानकारी रखनेवाला व्यक्ति समझ सकता है कि कम्यूनिस्ट पार्टियों की नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर, अपने अन्यतम मित्रों – चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रमुखों – के साथ हमारे सम्बन्धों पर हम्फ़्री जैसे आदमी से अन्तरंग की बातें करना कितनी कल्पनातीत बात है।

ज़ाहिर है, यूगोस्लाव संशोधनवादियों का हाल इस क़दर बेहाल हो रहा है कि वे हर तरह की अंटशंट गप्पों से काम ले रहे हैं।

इससे मुझे ज़ारशाही रूस में गप्पी अख़बार बेचनेवाले ढीठ लोगों की तरक़ीब याद आती है। अख़बारवाला दौड़ता चला आता और चिल्लाता:

"अजीबोग़रीब वाक़या! औरत ने गलमुच्छोंवाली लड़की पैदा की!.." **(हॉल में हंसी)।**

अनुभव का कच्चा पाठक झट से अख़बार ले लेता और उस वाक़या की ख़बर के लिए सारा अख़बार छान मारता। मगर कहीं उसे वह ख़बर न मिलती। लेकिन अख़बारवाले को इससे क्या लेना-देना? उसका काम अख़बार बेचना था, उसे तो वह कर चुका **(हॉल में सजीवता)।**

मुझे लगता है कि सेनेटर हम्फ़्री और यूगोस्लाव जो गप्पें प्रसारित करते हैं वे गप्पी अख़बार बेचनेवालों से मिलते-जुलते हैं।

यूगोस्लाविया की श्रमिक जनता के निम्न जीवन-स्तर के बारे में जब कुछ कहा जाता है, तब यूगोस्लाव नेता बेहद झल्ला उठते हैं।

कांग्रेस में रिपोर्ट पेश की जाने के बाद यूगोस्लाव पत्र-पत्रिकाओं ने यूगोस्लाविया की श्रमिक जनता के जीवन-स्तर सम्बन्धी प्रकाशित विवरणों का प्रतिवाद करने की कोशिश की। लेकिन आख़िर तथ्यों का कहीं प्रतिवाद किया जा सकता है? हमारे इस आशय के वक्तव्य की पुष्टि में कि यूगोस्लाव श्रमिक जनता का जीवन-स्तर नहीं बढ़ रहा, बहुत-से और आंकड़ों का हवाला दिया जा सकता है।

मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि यूगोस्लाविया में उपभोक्ता-वस्तुओं और म्युनिसिपल सेवाओं के मूल्य हाल में फिरेक बार काफ़ी बढ़ाये गये। हालांकि वेतन भी साथ साथ बढ़ाये गये, तो भी वेतन-वृद्धि भाव-वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई। इससे यह साबित होता है कि जनता का जीवन-स्तर और घटा। लेकिन समाजवादी शिविर के देशों में तो जनता की सुख-सुविधा निरन्तर बढ़ रही है। इन तथ्यों से कोई इन्कार नहीं कर सकता।

जो लोग आंकड़ों का हवाला देकर यह प्रभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं कि यूगोस्लाव जनता का जीवन-स्तर ऊंचा है, उनसे हम कह सकते हैं: लोगों से पूछिए कि कैसे वे अपने ख़ुद के अनुभव से अपना भौतिक स्तर आंकते हैं,—आया वह बढ़ रहा है या घट रहा है, और अगर वह बढ़ रहा है तो समाजवादी शिविरवाले देशों के धड़ाधड़ बढ़ते हुए जीवन-स्तर की तुलना में कितना। जनसाधारण इस प्रश्न का खरा जवाब देंगे। हम यूगोस्लाविया की जनताओं के प्रति सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं जिनका जीवन-स्तर समाजवादी देशों के मुक़ाबले में सचमुच बहुत नीचा है। नेताओं की नीति की क़ीमत इन जनताओं को अदा करनी पड़ रही है।

हमारी कांग्रेस में यूगोस्लाव श्रमिक जनता के प्रति मैत्री के जो उद्‌गार व्यक्त किये गये, यूगोस्लाव अख़बार उनके बारे में चुप्पी साध रहे हैं। फिर भी मैं दुबारा घोषणा कर सकता हूं कि यूगोस्लाविया की भ्रातृ-जनताओं और यूगोस्लाव कम्यूनिस्टों के लिए, भूमिगत और पार्टीज़ान संघर्ष के वीरों के लिए, हमारे मन में स्निग्धतम मैत्री की भावना विद्यमान

है। सोवियत संघ साम्राज्यवाद के विरुद्ध और शान्ति की खातिर संघर्ष सम्बन्धी प्रश्नों पर यूगोस्लाविया के साथ राजकीय स्तर पर सहयोग करने का प्रयत्न जारी रखेगा। जिन प्रश्नों पर हमारी नीतियां एक-सी हों, उन सबमें सोवियत संघ यूगोस्लाविया से सहयोग करेगा।

ये हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न, जिनकी अपने उपसंहार-भाषण में चर्चा करना मैंने उचित समझा **(तालियां)**।

साथियो, २१ वीं कांग्रेस क[illegible] निर्माण का शानदार कार्यक्रम स्वीकार कर रही है। हमारी पार्टी और बहादुर सोवियत जनता को महान कार्य करने हैं। सप्तवर्षीय योजना की पूर्त्ति हमारे देश को इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचायेगी कि मरियल पूंजीवाद के मुक़ाबले में कम्यूनिज्म की श्रेष्ठता के बारे में किसीको कोई शक नहीं रहेगा **(देर तक तालियां)**।

हम सब उस पीढ़ी के लोगों पर उचित ही गर्व करते हैं जिसने अमर लेनिन के नेतृत्व में अविश्वसनीय कठिनाइयों पर क़ाबू पाकर हमारी गरिमामय कम्यूनिस्ट पार्टी को जन्म दिया, उसके नेतृत्व में महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति में विजय पायी और इस प्रकार इतिहास में नया युग प्रवर्तित किया **(ज़ोर की तालियां)**। हमें उस पीढ़ी के लोगों पर गर्व है जिसने समाजवाद के भव्य भवन की नींव रखी और पहली ईंटें चुनी **(ज़ोर की तालियां)**। हमारे समसामयिकों का क[illegible]य है कि संसार के सबसे न्यायपूर्ण समाज – कम्यूनिस्ट समाज – का निर्माण करने के मानव-जाति के स्वप्न को साकार करें **(ज़ोर की तालियां)**।

सदियां गुज़र जायेंगी, लेकिन हमारे वीरतापूर्ण युग की – समाजवादी और कम्यूनिस्ट निर्माण के युग [illegible]–गरिमा कभी नहीं घटेगी **(देर तक ज़ोर की तालियां)**।

आगे बढ़ो, साथियो, लेनिन के पथ पर, कम्यूनिज़्म की विजय की ओर! **(तूफ़ानी तालियों की गड़गड़ाहट। सभी सभासदों द्वारा खड़े होकर अभिनन्दन)**।